भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

अगस्त 2025

खंड 79 अंक 8

संपादक समिति
इंद्रनील भट्टाचार्य
अनुजित मित्रा
रेखा मिश्र
अनुपम प्रकाश
सुनील कुमार
स्नेहल हेरवाडकर
पंकज कुमार
वी. धन्या
श्वेता कुमारी
अनिर्बन सान्याल
सुजाता कुंडू

संपादक
आशीष थॉमस जॉर्ज

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के
निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा
मासिक आधार पर प्रकाशित की जाती है।
इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए
बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है।
हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए
लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2025

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः उत्पादन की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन की सदस्यता के लिए कृपया 'हाल के प्रकाशन' खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को
https://bulletin.rbi.org.in पर देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (अगस्त 4-6, 2025)

गवर्नर का वक्तव्य: अगस्त 6, 2025 1

मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 मौद्रिक नीति समिति का संकल्प 4 से 6 अगस्त 2025 7

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य 11

भाषण

एफआईबीएसी 2025 सम्मेलन में उद्घाटन भाषण 13
श्री संजय मल्होत्रा

एक अंतरसंबंधित वित्तीय प्रणाली में विनियमों पर पुनर्विचार 19
श्री एम. राजेश्वर राव

वंजी से विकसित भारत तक: विश्वास, प्रौद्योगिकी और परिवर्तन पर बैंकिंग 29
श्री स्वामीनाथन जे

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति 35

निजी कॉरपोरेट निवेश: 2024-25 में वृद्धि और 2025-26 का परिदृश्य 67

भारत के बचत परिदृश्य में बदलाव लाते इक्विटी म्यूचुअल फंड 81

ईवी नीतियां और दोपहिया ईवी अपनाना: भारतीय राज्यों से साक्ष्य 95

बागवानी विविधीकरण: कृषि सुदृढ़ता की ओर एक मार्ग 109

वर्तमान सांख्यिकी **125**

हाल के प्रकाशन **179**

मौद्रिक नीति वक्तव्य
2025-26 (4-6 अगस्त)

गवर्नर का वक्तव्य

*गवर्नर का वक्तव्य**

संजय मल्होत्रा

नमस्कार, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, पारसी नववर्ष और गणेश चतुर्थी के इस माह में सभी को बधाई। यह पवित्र और शुभ माह हम सभी के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सौभाग्य लेकर आए।

मानसून का मौसम अच्छा चल रहा है। हम त्योहारों के मौसम के भी करीब पहुँच रहे हैं, जो आमतौर पर आर्थिक गतिविधियों में अधिक उत्साह और उछाल लाता है। यह अनुकूल घरेलू माहौल, सरकार और रिज़र्व बैंक की अनुकूल नीतियों के साथ, निकट भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ कुछ हद तक कम हुई हैं, तथापि वैश्विक व्यापार संबंधी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। मध्यम अवधि में भी, बदलती विश्व व्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी अंतर्निहित शक्ति, मज़बूत बुनियादी ढाँचे और आरामदायक बफर के समर्थन से उज्ज्वल संभावनाओं से युक्त है। अवसर मौजूद हैं, और हम नीति-निर्माण के बहु-आयामी किन्तु सुसंगत दृष्टिकोण के माध्यम से अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर, नीति निर्माताओं को धीमी संवृद्धि और अवस्फीति की धीमी होती गति का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में तो मुद्रास्फीति में भी वृद्धि देखी जा रही है। जैसे-जैसे स्थिति स्थिर होती जाएगी और नई वैश्विक व्यवस्था में एक नया संतुलन उभरेगा, नीति निर्माताओं के लिए धीमी संवृद्धि, अड़ियल मुद्रास्फीति और बढ़े हुए सार्वजनिक ऋण स्तरों वाले विश्व में आगे बढ़ना एक कठिन कार्य होगा।

रिज़र्व बैंक में, मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी से उत्पन्न हुई गुंजाइश का लाभ उठाते हुए, हमने संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक और दूरदर्शी उपाय किए हैं। हमारे पास उपलब्ध विभिन्न साधनों के समन्वित उपयोग से वर्तमान नरमी के चक्र में मौद्रिक नीति संचरण में तेज़ी लाने में मदद मिली है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4, 5 और 6 अगस्त को हुई जिसमें नीतिगत रेपो दर पर विचार-विमर्श और निर्णय लिया गया। उभरते समष्टि आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों तथा संभावना का विस्तृत आकलन करने के बाद, एमपीसी ने सर्वसम्मति से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया; परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.25 प्रतिशत पर तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 5.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेंगी। एमपीसी ने तटस्थ रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया।

एमपीसी ने कहा कि, यद्यपि हेडलाइन मुद्रास्फीति पहले के अनुमान से काफी कम है, लेकिन इसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों, विशेषतया सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव है। दूसरी ओर, मूल मुद्रास्फीति, जैसा कि अनुमान था, 4 प्रतिशत के आसपास स्थिर बनी हुई है। इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही से मुद्रास्फीति में वृद्धि का अनुमान है। संवृद्धि मजबूत है और पहले के अनुमानों के अनुसार है, तथापि हमारी आकांक्षाओं से कम है। प्रशुल्क (टैरिफ) की अनिश्चितताएँ अभी भी विकसित हो रही हैं। मौद्रिक नीति संचरण अभी भी जारी है। फरवरी 2025 से 100 आधार अंकों की दर कटौती का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अभी भी सामने आ रहा है।

अतः, कुल मिलाकर, वर्तमान समष्टि आर्थिक परिस्थितियाँ, संभावनाएं और अनिश्चितताएँ, 5.5 प्रतिशत की नीतिगत रेपो दर को जारी रखने और ब्याज दरों में की गई अग्रिम कटौती का ऋण बाज़ारों और व्यापक अर्थव्यवस्था तक आगे संचरण का इंतज़ार करने की माँग करती हैं। तदनुसार, एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। एमपीसी ने उपयुक्त मौद्रिक नीति मार्ग निर्धारित करने के लिए आने वाले आँकड़ों और उभरती घरेलू संवृद्धि-मुद्रास्फीति गतिकी पर कड़ी निगरानी रखने का भी संकल्प लिया। तदनुसार, सभी सदस्यों ने तटस्थ रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

* गवर्नर का वक्तव्य- 06 अगस्त 2025

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

संवृद्धि

घरेलू संवृद्धि स्थिर है और व्यापक तौर पर हमारे आकलन के अनुरूप ही विकसित हो रही है, तथापि कुछ उच्च-आवृत्ति संकेतकों ने मई-जून में मिश्रित संकेत दिए हैं। ग्रामीण उपभोग सुदृढ़[1] बना हुआ है, जबकि शहरी उपभोग में बहाली, विशेष रूप से विवेकाधीन व्यय, मंद[2] है। सरकारी पूंजीगत व्यय में तेजी से समर्थित स्थिर निवेश[3], आर्थिक गतिविधियों को समर्थन दे रहा है।

आपूर्ति पक्ष पर, स्थिर दक्षिण-पश्चिम मानसून[4] खरीफ की बुवाई[5] को बढ़ावा दे रहा है, जलाशयों के स्तर[6] को फिर से भर रहा है और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा, सेवा गतिविधियाँ स्थिर बनी हुई हैं, तथापि कुछ उच्च-आवृत्ति संकेतकों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है।[7] सेवा पीएमआई[8] जुलाई 2025 में बढ़कर 11 महीने के उच्चतम स्तर 60.5 पर पहुँच गई। निर्माण गतिविधि में सुदृढ़ता जारी है।[9] तथापि, विद्युत और खनन के कारण औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि धीमी और असमान रही।[10] जबकि विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)[11] पहली तिमाही में उच्च रहा, वहीं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)[12] में नरमी देखी गई।

संवृद्धि की संभावना के संबंध में सामान्य से बेहतर दक्षिण-पश्चिम मानसून, न्यूनतर मुद्रास्फीति, बढ़ता क्षमता उपयोग और अनुकूल वित्तीय परिस्थितियाँ, घरेलू आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही हैं। मज़बूत सरकारी पूंजीगत व्यय[13] सहित अनुकूल मौद्रिक, विनियामक और राजकोषीय नीतियों से भी माँग में वृद्धि होनी चाहिए। निर्माण और व्यापार क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि के साथ, आने वाले महीनों में सेवा क्षेत्र में भी तेजी बनी रहने की आशा है। तथापि, चल रही टैरिफ घोषणाओं और व्यापार वार्ताओं के बीच, बाह्य माँग की संभावनाएँ अनिश्चित बनी हुई हैं। लंबे समय से चले आ रहे भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक अनिश्चितताओं और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियाँ संवृद्धि की संभावना के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पहली तिमाही में 6.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.3 प्रतिशत रहेगी। 2026-27 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

मुद्रास्फ़ीति

सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति लगातार आठवें महीने घटकर जून में 77 महीने के निचले स्तर 2.1 प्रतिशत पर आ

1 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान ट्रैक्टर की बिक्री और खुदरा दोपहिया वाहनों की बिक्री में क्रमशः 9.2 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

2 नीलसनआईक्यू रिटेल ऑडिट सेवा के अनुसार, 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान एफएमसीजी की बिक्री में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 8.4 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पहली तिमाही के दौरान यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस अवधि के दौरान घरेलू हवाई यात्री यातायात में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3 केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान 52.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की मजबूत वृद्धि हुई। पूंजीगत वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई और पूंजीगत वस्तुओं के आयात में 2025-26 की पहली तिमाही में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4 4 अगस्त 2025 तक संचयी दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) वर्षा दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 4 प्रतिशत अधिक है।

5 1 अगस्त 2025 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल पिछले वर्ष के इसी क्षेत्रफल से 5.1 प्रतिशत अधिक है।

6 31 जुलाई 2025 तक जलाशय का स्तर पूर्ण क्षमता के 69 प्रतिशत पर था, जो पिछले वर्ष के स्तर के साथ-साथ दशकीय औसत 46 प्रतिशत से भी अधिक था।

7 जून 2025 में ई-वे बिल में 19.3 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई और जून-जुलाई 2025 में टोल संग्रह में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मई में 16.4 प्रतिशत की वृद्धि के बाद, जून-जुलाई 2025 में सकल जीएसटी संग्रह में 6.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। घरेलू हवाई माल ढुलाई में जून 2025 में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई; बंदरगाह माल ढुलाई में 2025-26 की पहली तिमाही में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई; वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में पहली तिमाही में 0.6 प्रतिशत की गिरावट आई।

8 पीएमआई सेवाएं मई के 58.8 से बढ़कर जून 2025 में 60.4 और जुलाई में 60.5 हो गई।

9 2025-26 की पहली तिमाही में इस्पात की खपत में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा इस अवधि के दौरान सीमेंट उत्पादन में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

10 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान खनन और विद्युत उत्पादन में क्रमशः 3.0 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत की गिरावट आई।

11 विनिर्माण पीएमआई जुलाई 2025 में 16 महीने के उच्चतम स्तर 59.1 पर पहुंच गई, जो विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत गति का संकेत है।

12 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान विनिर्माण आईआईपी में 3.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

13 केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार, केंद्र सरकार के प्रभावी पूंजीगत व्यय (पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता सहित) में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

गई।[14] यह मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में तेज गिरावट के कारण हुआ, जिसका नेतृत्व बेहतर कृषि गतिविधि और विभिन्न आपूर्ति पक्ष उपायों ने किया। खाद्य मुद्रास्फीति ने फरवरी 2019 के बाद से जून में (-) 0.2 प्रतिशत पर अपना पहला नकारात्मक प्रिंट दर्ज किया। सब्जियों और दालों में दोहरे अंकों की अपस्फीति ने इस संकुचन को बढ़ावा दिया।[15] उच्च आवृत्ति वाले मूल्य संकेतक जुलाई में भी खाद्य कीमतों में कम मूल्य गति जारी रहने का संकेत देते हैं। ईंधन समूह की मुद्रास्फीति जून में लगातार दो महीनों में घटकर 2.6 प्रतिशत दर्ज की गई।[16] मूल मुद्रास्फीति[17], जो फरवरी-मई के दौरान 4.1-4.2 प्रतिशत की सीमित दायरे के भीतर रही, जून में बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो गई, जिसका आंशिक कारण स्वर्ण की कीमतों में निरंतर वृद्धि थी।

2025-26 के लिए मुद्रास्फीति की संभावना जून में अपेक्षा से अधिक सौम्य हो गई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की स्थिर प्रगति, मजबूत खरीफ बुवाई, पर्याप्त जलाशय स्तर और खाद्यान्नों के पर्याप्त बफर भंडार[18] के साथ बड़े अनुकूल आधार प्रभावों ने इस नरमी में योगदान दिया है। तथापि, प्रतिकूल आधार प्रभावों और नीतिगत कार्रवाइयों से उत्पन्न मांग पक्ष कारकों के प्रभाव में आने के कारण, सीपीआई मुद्रास्फीति 2025-26 की चौथी तिमाही और उसके बाद 4 प्रतिशत से ऊपर जाने की संभावना है। इनपुट कीमतों पर किसी भी बड़े नकारात्मक आघात को छोड़कर, मूल मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान 4 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर रहने की संभावना है। मौसम संबंधी आघात मुद्रास्फीति की संभावना के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति अब 3.1 प्रतिशत अनुमानित है, जो दूसरी तिमाही में 2.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.1 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत रहेगी। 2026-27 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.9 प्रतिशत अनुमानित है (चार्ट 2)। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

बाह्य क्षेत्र

भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2023-24 में जीडीपी के 0.7 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में जीडीपी का 0.6 प्रतिशत रह गया, जिसका कारण उच्च पण्य व्यापार घाटे के बावजूद मज़बूत सेवा निर्यात और मज़बूत विप्रेषण प्राप्तियाँ रहीं। 2025-26 की पहली तिमाही में पण्य व्यापार घाटा और बढ़ गया। विश्व सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 के लगभग 2 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 4.3 प्रतिशत हो गई है, जो मज़बूत सॉफ़्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात के कारण है। मज़बूत सेवा निर्यात[19] और मज़बूत विप्रेषण प्राप्तियों से चालू वित्त वर्ष के दौरान चालू खाता घाटा (सीएडी) के धारणीय स्तर पर बने रहने की आशा है।

बाह्य वित्तपोषण के संदर्भ में, भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) अप्रैल-मई 2025-26 के दौरान मज़बूत रहा। तथापि, इस अवधि के दौरान अधिक जावक एफ़डीआई के कारण निवल एफ़डीआई में कमी आई।[20] ईएमई में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफ़पीआई) का अंतर्वाह मई और जून 2025 में मज़बूत बना रहा।[21] तथापि, ऋण क्षेत्र में बहिर्वाह के कारण 2025-26 में अब तक (अप्रैल-31 जुलाई) भारत में निवल एफ़पीआई का बहिर्वाह 0.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया है।[22] दूसरी

[14] सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति अप्रैल के 3.2 प्रतिशत से घटकर जून 2025 में 2.1 प्रतिशत (जनवरी 2019 के बाद सबसे कम) हो गई, जिसमें लगभग 110 आधार अंकों की संचयी गिरावट देखी गई। यह कमी मुख्य रूप से सब्जियों, दालों और अनाज की कीमतों में और गिरावट के कारण आई, जिसके परिणामस्वरूप सीपीआई खाद्य समूह में फरवरी 2019 के बाद पहली बार जून में (-)0.2 प्रतिशत अपस्फीति दर्ज की गई। ईंधन समूह की मुद्रास्फीति भी अप्रैल के 2.9 प्रतिशत से घटकर जून में 2.6 प्रतिशत हो गई। तथापि, मूल मुद्रास्फीति, फरवरी से मई के दौरान 4.1 से 4.2 प्रतिशत के बीच व्यापक तौर पर स्थिर रहने के बाद, जून 2025 में बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो गई।

[15] जून 2025 में सब्जियों की कीमतों में 19.0 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि दालों की कीमतों में 11.8 प्रतिशत की गिरावट आई।

[16] ईंधन समूह की मुद्रास्फीति भी अप्रैल के 2.9 प्रतिशत से घटकर जून में 2.6 प्रतिशत रह गई।

[17] खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर सीपीआई हेडलाइन।

[18] 16 जुलाई 2025 तक, भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं का भंडार बफर मानदंडों से 1.3 गुना (पिछले 4 वर्षों में सर्वाधिक भंडार) तथा चावल का भंडार बफर मानदंडों से 3.9 गुना है।

[19] अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून 2025-26 के दौरान भारत का सेवा निर्यात 10.1 प्रतिशत बढ़ा, जबकि इसी अवधि में सेवा आयात में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में निवल सेवा निर्यात में 20.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[20] सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह अप्रैल-मई 2025-26 में 5 प्रतिशत बढ़कर 15.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 15.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। निवल एफडीआई अंतर्वाह अप्रैल-मई 2025-26 में 2.2 प्रतिशत घटकर 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

[21] जून 2025 के दौरान ईएमई में निवल पोर्टफोलियो अंतर्वाह 42.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि मई 2025 में यह 16.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान)।

[22] अप्रैल-जुलाई 2025 के दौरान इक्विटी खंड में 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह हुआ, जबकि ऋण खंड में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह हुआ।

ओर, बाह्य वाणिज्यिक उधारों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक निवल अंतर्वाह देखा गया। अनिवासी जमाओं के अंतर्गत अंतर्वाह भी सकारात्मक रहा, तथापि इसमें कुछ कमी देखी गई।[23] 1 अगस्त 2025 तक, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 688.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थीं, जो 11 महीने से अधिक के पण्य आयात को पूरा करने के लिए पर्याप्त थीं।[24] कुल मिलाकर, भारत का बाह्य क्षेत्र आघात-सह बना हुआ है।[25] हमें अपनी बाह्य वित्तपोषण आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करने का विश्वास है।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

प्रणालीगत चलनिधि, जैसा कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के अंतर्गत निवल स्थिति द्वारा मापा जाता है, पिछली एमपीसी के बाद से औसतन ₹3.0 लाख करोड़ प्रतिदिन के हिसाब से अधिशेष में रही है, जबकि पिछले दो महीनों के दौरान औसत दैनिक अधिशेष ₹1.6 लाख करोड़ था।[26] आगे बढ़ते हुए, जैसे ही पिछली नीति में घोषित सीआरआर कटौती सितंबर से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी, यह चलनिधि की स्थिति को और मजबूत करेगी।

बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि ने मौजूदा नरमी चक्र के दौरान नीतिगत रेपो दर में कटौती का मुद्रा[27], बॉण्ड[28] और ऋण बाजारों तक संचरण को सुदृढ़ किया है। ऋण बाजार में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) में नए रुपया ऋणों के लिए 71 आधार अंकों की गिरावट आई है (जिसमें से 55 आधार अंकों की गिरावट ब्याज दर में कमी के कारण है) और फरवरी 2025 से जून 2025 तक बकाया रुपया ऋणों के लिए 39 आधार अंकों की गिरावट आई है। जमा पक्ष पर, इसी अवधि के दौरान नई जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में 87 आधार अंकों की कमी आई है। इसके अलावा, उधार दरों में संचरण सभी क्षेत्रों में व्यापक रहा है।

आगे भी, रिज़र्व बैंक अपने चलनिधि प्रबंधन में चुस्त और लचीला बना रहेगा। हम बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने का प्रयास करेंगे ताकि अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताएँ पूरी हो सकें और मुद्रा बाज़ारों और ऋण बाज़ारों में संचरण सुचारू रहे।

एक आंतरिक कार्य दल ने रिज़र्व बैंक के मौजूदा चलनिधि प्रबंधन ढांचे (एलएमएफ) की समीक्षा की है, जो फरवरी 2020 से लागू है। दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसे सार्वजनिक परामर्श के लिए शीघ्र ही आरबीआई की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। भारित औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर) संपार्श्विक खंडों में अन्य एक दिवसीय मुद्रा बाज़ार दरों (टीआरईपीएस और बाज़ार रेपो) के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध पाई गई है। इसके अलावा, डबल्यूएसीआर को विभिन्न परिपक्वताओं में अन्य मुद्रा बाज़ार लिखतों को संकेत प्रेषित करने में भी प्रभावी पाया गया है। अतः, दल ने मौद्रिक नीति के परिचालन लक्ष्य के रूप में एक दिवसीय डब्ल्यूएसीआर को जारी रखने की सिफारिश की है। दल ने अन्य बातों के साथ-साथ, नीतिगत दर पर परिचालन लक्ष्य दर को बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न अवधियों के रेपो और रिवर्स रेपो परिचालनों के लिए परिवर्तनीय दर नीलामी तंत्र को जारी रखने की भी सिफारिश की है।

वित्तीय स्थिरता

वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की पूंजी पर्याप्तता, चलनिधि, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता से संबंधित प्रणाली-स्तरीय

---

[23] भारत में बाह्य वाणिज्यिक उधारों के अंतर्गत निवल अंतर्वाह अप्रैल-जून 2025-26 के दौरान बढ़कर 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि एक वर्ष पूर्व यह 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अनिवासी जमाओं में अप्रैल-मई 2025-26 के दौरान 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है।

[24] चार तिमाहियों की अवधि (2024-25 की पहली तिमाही से 2024-25 की चौथी तिमाही) के दौरान वास्तविक पण्य आयात (बीओपी आधार पर) और मार्च 2025 के अंत तक कुल बाह्य ऋण के लगभग 94 प्रतिशत के आधार पर।

[25] भारत का जीडीपी की तुलना में चालू खाता घाटा अनुपात 2023-24 के 0.7 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 0.6 प्रतिशत रह गया। भारत का जीडीपी की तुलना में बाह्य ऋण अनुपात मार्च 2024 के अंत में 18.5 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 के अंत में 19.1 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान जीडीपी की तुलना में निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति अनुपात (-) 10.1 प्रतिशत से बढ़कर (-) 8.7 प्रतिशत हो गया।

[26] अप्रैल और मई के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत औसत दैनिक निवल अवशोषण क्रमशः ₹1.5 लाख करोड़ और ₹1.8 लाख करोड़ रहा। एलएएफ के अंतर्गत औसत दैनिक निवल अवशोषण जून 2025 में बढ़कर ₹2.82 लाख करोड़ और जुलाई 2025 में ₹3.12 लाख करोड़ हो गया। एसडीएफ के अंतर्गत दैनिक औसत अवशोषण अप्रैल-मई 2025 के ₹2.06 लाख करोड़ से बढ़कर जून-जुलाई के दौरान ₹2.17 लाख करोड़ हो गया।

[27] मौजूदा नरमी चक्र (4 अगस्त तक) में संचयी नीतिगत रेपो दर में 100 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती के सापेक्ष, डब्ल्यूएसीआर में 108 बीपीएस की कमी आई। फरवरी की नीति के बाद से, 3-माह के खजाना बिल दर में 110 बीपीएस, एनबीएफसी द्वारा जारी 3-माह के सीपी में 161 बीपीएस और 3-माह के सीडी दर में 170 बीपीएस की गिरावट आई है।

[28] फरवरी की नीति के बाद से, 5-वर्षीय और 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों (6.79 जीएस बेंचमार्क) पर प्रतिफल में क्रमशः 63 आधार अंक और 28 आधार अंक की गिरावट आई है। इसी अवधि में, 5-वर्षीय एएए कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल में 56 आधार अंकों की गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान, भारतीय बॉण्ड बाजार वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक रहा।

वित्तीय मानदंड स्वस्थ बने हुए हैं।[29] जून 2025 के अंत में बैंकिंग प्रणाली के लिए ऋण जमा अनुपात (सीडी अनुपात) 78.9 प्रतिशत था, जो मोटे तौर पर एक वर्ष पहले के समान ही था। इसी प्रकार, एनबीएफसी के प्रणाली-स्तरीय मानदंड भी सुदृढ़ हैं, जिनमें पर्याप्त पूँजी स्थिति और बेहतर जीएनपीए अनुपात शामिल हैं।[30]

2024-25 के दौरान बैंक ऋण में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालाँकि यह 2023-24 की 16.3 प्रतिशत की वृद्धि दर से धीमी है, लेकिन यह 2024-25 से पहले की दस वर्षों की अवधि में दर्ज की गई 10.3 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से अधिक है। इसके अलावा, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान गैर-खाद्य बैंक ऋण का प्रवाह ₹21.4 लाख करोड़ से लगभग ₹3.4 लाख करोड़ घटकर लगभग ₹18 लाख करोड़ हो गया, गैर-बैंक स्रोतों से प्रवाह ने इस कमी की भरपाई कर दी।[31] इस प्रकार, भले ही पिछले वर्ष बैंक ऋण की संवृद्धि दर धीमी रही, लेकिन वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का समग्र प्रवाह 2023-24 में ₹33.9 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹34.8 लाख करोड़ हो गया। यह प्रवृत्ति चालू वित्त वर्ष में भी जारी है।[32] चूंकि मुद्रा बाजारों में संचरण तेजी से हुआ है, इसलिए बड़े निगमों ने धन जुटाने के लिए वाणिज्यिक पत्र और कॉरपोरेट बॉण्ड जैसे बाजार-आधारित लिखतों पर अधिक भरोसा किया है, जिससे बैंक ऋण पर उनकी निर्भरता कम हो गई है।[33] साथ ही, जैसे-जैसे बड़े निगमों की लाभप्रदता बढ़ी है, उनके आंतरिक संसाधन व्यवसाय विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।

अतिरिक्त उपाय

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं यह रेखांकित करना चाहता हूँ कि आरबीआई के लिए, भारत के नागरिकों का हित और कल्याण सर्वोपरि है। भारत के लोग, जिनमें समाज के सबसे निचले तबके के लोग भी शामिल हैं, ही हमारे अस्तित्व का आधार हैं। इस संबंध में, मैं उपभोक्ता-केंद्रित तीन घोषणाएँ करना चाहता हूँ।

पहला, जन-धन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर, बड़ी संख्या में खातों की पुनः-केवाईसी की आवश्यकता हो गई है। बैंक ग्राहकों के घर-द्वार पर सेवाएँ प्रदान करने के प्रयास में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर रहे हैं। नए बैंक खाते खोलने और पुनः-केवाईसी के अलावा, शिविरों में वित्तीय समावेशन और ग्राहक शिकायत निवारण के लिए सूक्ष्म बीमा और पेंशन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

दूसरा, हम बैंक खातों तथा मृत बैंक ग्राहकों के सुरक्षित अभिरक्षा या सुरक्षित जमा लॉकरों में रखी वस्तुओं के संबंध में दावों के निपटान की प्रक्रिया को मानकीकृत करेंगे। इससे निपटान अधिक सुविधाजनक और सरल हो जाने की आशा है।

तीसरा, हम आरबीआई रिटेल-डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की कार्यक्षमता का विस्तार कर रहे हैं ताकि खुदरा निवेशक व्यवस्थित निवेश योजनाओं के माध्यम से खजाना बिलों में निवेश कर सकें।

समापन टिप्पणी

अब मैं अपनी अंतिम टिप्पणी करता हूँ। चुनौतीपूर्ण बाह्य परिवेश के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था मूल्य स्थिरता के साथ

[29] एससीबी मानदंड: जून 24 और जून 25 के बीच बकाया ऋण और जमा में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 9.9 प्रतिशत और 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जून 2025 में प्रणाली-स्तरीय जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 17.44 प्रतिशत था, जो विनियामक न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर था। गैर-निष्पादित ऋणों के अनुपात में और सुधार हुआ (जून 2025 में जीएनपीए अनुपात 2.24 प्रतिशत जबकि जून 2024 में 2.67 प्रतिशत, जून 2025 में एनएनपीए अनुपात 0.53 प्रतिशत जबकि जून 2024 में 0.60 प्रतिशत)। जून 2025 के अंत तक 132.80 प्रतिशत के एलसीआर के साथ चलनिधि बफर मजबूत था। जून 2025 में वार्षिक आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) क्रमशः 1.34 प्रतिशत और 12.70 प्रतिशत रहा। जून 2025 के लिए शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.24 प्रतिशत (जून 2024 में 3.54 प्रतिशत) था।

[30] एनबीएफसी मानदंड: जून 2025 में एनबीएफसी का कुल सीआरएआर 25.78 प्रतिशत और टियर I सीआरएआर 23.83 प्रतिशत था, जो न्यूनतम विनियामक आवश्यकताओं से काफी ऊपर था। जीएनपीए अनुपात जून 2024 में 2.47 प्रतिशत से बढ़कर जून 2025 में 2.21 प्रतिशत हो गया है, जबकि एनएनपीए अनुपात भी जून 2024 में 1.08 प्रतिशत से बढ़कर जून 2025 में 0.95 प्रतिशत हो गया है। इस क्षेत्र के लिए आरओए जून 2024 में 3.23 प्रतिशत से थोड़ा कम होकर जून 2025 में 3.11 प्रतिशत हो गया है। एनआईएम जून 2024 में 4.82% से थोड़ा कम होकर जून 2025 में 4.40% हो गया है।

[31] गैर-बैंकों (घरेलू और विदेशी स्रोतों सहित) से संसाधनों का कुल प्रवाह 2023-24 में ₹12.5 लाख करोड़ से ₹4.3 लाख करोड़ बढ़कर 2024-25 में ₹16.8 लाख करोड़ हो गया।

[32] 11 जुलाई 2025 तक बैंक ऋण में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह वृद्धि 14.0 प्रतिशत थी। बैंक ऋण में मंदी के बावजूद, वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह अप्रैल-जुलाई 2025-26 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग समान स्तर पर बना रहा।

[33] गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र, वित्त वर्ष 2025-26 (जून तक) में बढ़कर 0.78 लाख करोड़ हो गए, जबकि एक वर्ष पहले यह 0.30 लाख करोड़ था। गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी कॉर्पोरेट बांड एक वर्ष पहले के 0.09 लाख करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 (जून तक) में बढ़कर 0.95 लाख करोड़ हो गए।

स्थिर संवृद्धि पथ पर अग्रसर है। मौद्रिक नीति ने मूल्य स्थिरता के प्राथमिक उद्देश्य से समझौता किए बिना संवृद्धि को समर्थन देने के लिए सौम्य मुद्रास्फीति परिदृश्य द्वारा सृजित नीतिगत गुंजाइश का उचित उपयोग किया है। हमारी हालिया नीतिगत कार्रवाइयों का व्यापक अर्थव्यवस्था में प्रसारण अभी जारी है।

चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना उचित स्थान प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, इसलिए सभी क्षेत्रों में मजबूत नीतिगत ढांचे, न केवल मौद्रिक नीति तक सीमित है, बल्कि इसकी यात्रा में महत्वपूर्ण होंगे। हम, अपनी ओर से, आने वाले आंकड़ों और संवृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता के विकास के आधार पर सुविधाजनक मौद्रिक नीति प्रदान करने में चुस्त और सक्रिय बने रहेंगे। हमेशा की तरह, हमारे पास स्पष्ट, सुसंगत और विश्वसनीय संचार होगा जो कार्य के लिए आवश्यक कार्यों पर आधारित होगा।

धन्यवाद। नमस्कार और जय हिन्द।

मौद्रिक नीति वक्तव्य
2025-26 (4-6 अगस्त)

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प
अगस्त 4-6, 2025

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2025-26 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प*

मौद्रिक नीति निर्णय

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 56वीं बैठक 4 से 6 अगस्त 2025 तक श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एमपीसी के सदस्य डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. पूनम गुप्ता और डॉ. राजीव रंजन बैठक में शामिल हुए।

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के पश्चात, एमपीसी ने मौद्रिक नीति रेपो दर को 5.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.25 प्रतिशत पर यथावत् बनी रहेगी तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.75 प्रतिशत पर बनी रहेगी। यह निर्णय संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के लिए +/- 2 प्रतिशत के दायरे में 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति संभावना

वैश्विक परिवेश चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। यद्यपि, वित्तीय बाज़ार में अस्थिरता और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ हाल के महीनों में अपने चरम से कुछ कम हुई हैं, लेकिन फिर भी व्यापार वार्ता संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वैश्विक संवृद्धि में ऊर्ध्वगामी संशोधन किया गया है, लेकिन अभी भी यह मंद है। अवस्फीति की गति धीमी हो रही है, फिर भी कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी जा रही है।

घरेलू संवृद्धि आघात-सह बना हुआ है और मोटे तौर पर हमारे आकलन के अनुरूप ही विकसित हो रहा है। ग्रामीण माँग से समर्थित निजी उपभोग और सरकारी पूंजीगत व्यय में तेज़ी से समर्थित स्थिर निवेश, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपूर्ति पक्ष पर, स्थिर दक्षिण-पश्चिम मानसून खरीफ की बुवाई को बढ़ावा दे रहा है, जलाशयों के स्तर को फिर से भर रहा है और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा, सेवा क्षेत्र और निर्माण गतिविधियाँ मज़बूत बनी हुई हैं। हालाँकि, औद्योगिक क्षेत्र में संवृद्धि धीमी और सभी क्षेत्रों में असमान रही, जिसकी वजह बिजली और खनन क्षेत्र रहे।

जहाँ तक संवृद्धि की संभावना का प्रश्न है, सामान्य से बेहतर दक्षिण-पश्चिम मानसून, न्यून मुद्रास्फीति, बढ़ता क्षमता उपयोग और अनुकूल वित्तीय परिस्थितियाँ घरेलू आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही हैं। मज़बूत सरकारी पूंजीगत व्यय सहित सहायक मौद्रिक, विनियामक और राजकोषीय नीतियों से भी माँग में वृद्धि होनी चाहिए। आने वाले महीनों में निर्माण और व्यापार में निरंतर वृद्धि के कारण सेवा क्षेत्र में भी तेजी बनी रहने की उम्मीद है। हालाँकि, चल रही टैरिफ संबंधी घोषणाओं और व्यापार वार्ताओं के बीच, बाह्य माँग की संभावनाएँ अनिश्चित बनी हुई हैं। लंबे समय से चले आ रहे भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक अनिश्चितताओं और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियाँ संवृद्धि की संभावना के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जोकि पहली तिमाही में 6.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2026-27 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है (चार्ट 1)। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति लगातार आठवें महीने घटकर जून 2025 में 77 महीनों के निचले स्तर 2.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) पर आ गई। यह मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों में सुधार और विभिन्न आपूर्ति-पक्ष उपायों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट के कारण हुई। फरवरी 2019 के बाद से खाद्य मुद्रास्फीति पहली बार जून में (-) 0.2 प्रतिशत पर नकारात्मक रही। उच्च-आवृत्ति मूल्य संकेतक इस वर्ष जुलाई तक भी खाद्य कीमतों में गिरावट की गति जारी रहने का संकेत देते हैं। मूल मुद्रास्फीति, जो फरवरी-मई के दौरान 4.1-4.2 प्रतिशत के

* 6 अगस्त 2025 को जारी।

चार्ट 1: वास्तविक जीडीपी वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) का तिमाही अनुमान

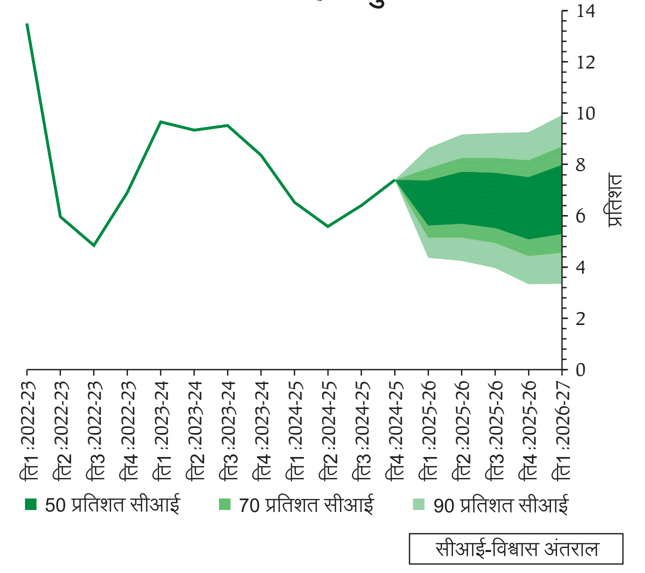

चार्ट 2: सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) का तिमाही अनुमान

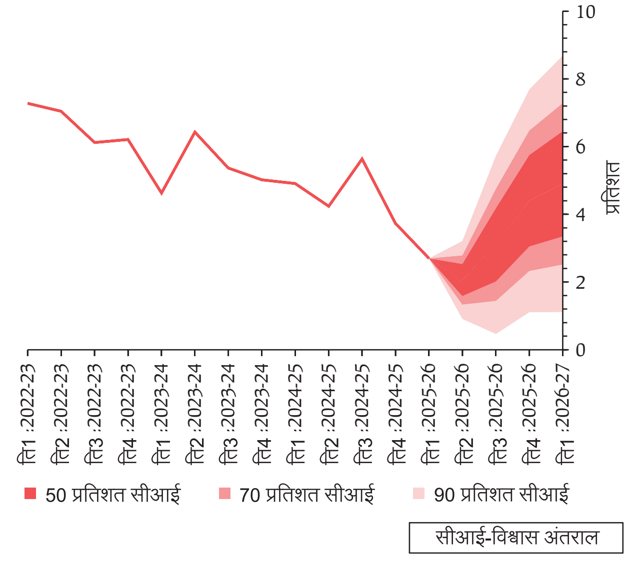

सीमित दायरे में रही, जून में बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो गई, जिसका एक कारण स्वर्ण की कीमतों में लगातार वृद्धि भी है।

2025-26 के लिए मुद्रास्फीति की संभावना जून में अपेक्षा से अधिक सौम्य हो गया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की स्थिर प्रगति, खरीफ की बेहतर बुवाई, पर्याप्त जलाशय स्तर और खाद्यान्नों के पर्याप्त बफर स्टॉक के साथ बड़े अनुकूल आधार प्रभावों ने इस नरमी में योगदान दिया है। हालाँकि, प्रतिकूल आधार प्रभावों और नीतिगत कार्रवाइयों से उत्पन्न मांग पक्ष के कारकों के प्रभाव में आने के कारण, सीपीआई मुद्रास्फीति का 2025-26 की चौथी तिमाही और उसके बाद 4 प्रतिशत से ऊपर जाने की संभावना है। इनपुट कीमतों पर किसी भी बड़े नकारात्मक आघातों को छोड़कर, मूल मुद्रास्फीति का वर्ष के दौरान 4 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर रहने की संभावना है। मौसम संबंधी आघात, मुद्रास्फीति की संभावना के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति अब 3.1 प्रतिशत अनुमानित है, जोकि दूसरी तिमाही में 2.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.1 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत रहने की संभावना है। 2026-27 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.9 प्रतिशत अनुमानित है (चार्ट 2)। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

मौद्रिक नीति संबंधी निर्णयों का औचित्य

एमपीसी ने कहा कि निकट भविष्य में मुद्रास्फीति की संभावना पहले के अनुमान से कहीं अधिक सौम्य हो गई है, और इस वर्ष औसत सीपीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य से काफी नीचे रहने की आशा है। यह मुख्य रूप से कम खाद्य मुद्रास्फीति के कारण है, जो जून में अपस्फीतिकारी क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। हालाँकि, 2025-26 की चौथी तिमाही से सीपीआई मुद्रास्फीति का 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर जाने की संभावना है। इसके अलावा, मूल मुद्रास्फीति दिसंबर-जनवरी 2024-25 के दौरान दर्ज किए गए 3.6 प्रतिशत के हालिया निम्नतम स्तर से लगातार बढ़ रही है और इस वर्ष पहली तिमाही में औसतन 4.3 प्रतिशत रही। कीमती धातुओं को छोड़कर मूल मुद्रास्फीति में भी वृद्धि देखी गई है और यह पहली तिमाही में औसतन 3.4 प्रतिशत रही।

आगामी त्यौहारी सीजन में कुछ तेजी आने की आशा के साथ संवृद्धि दर अच्छी बनी हुई है और यह 2025-26 के लिए 6.5 प्रतिशत के हमारे आकलन के अनुरूप विकसित हो रही है।

इस प्रकार, हेडलाइन मुद्रास्फीति पहले के अनुमान से काफी कम है, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों, विशेषकर सब्जियों की कीमतों में अस्थिरता है। दूसरी ओर, मूल मुद्रास्फीति, अनुमान के अनुसार, 4 प्रतिशत के आसपास स्थिर बनी हुई है। इस वित्तीय

वर्ष की अंतिम तिमाही से मुद्रास्फीति में वृद्धि का अनुमान है। हालाँकि पहले के अनुमानों के अनुरूप संवृद्धि दर मजबूत है और लेकिन यह हमारी आकांक्षाओं से कम है। प्रशुल्क (टैरिफ़) संबंधी अनिश्चितताएँ अभी भी उभर रही हैं। मौद्रिक नीति का संचरण अभी भी जारी है। फरवरी 2025 से दरों में होने वाली 100 बीपीएस की कटौती का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अभी भी स्पष्ट नहीं है।

अतः, कुल मिलाकर, वर्तमान समष्टि आर्थिक स्थितियां, संभावना और अनिश्चितताएं 5.5 प्रतिशत की नीतिगत रेपो दर को जारी रखने तथा अग्रिम दर कटौती का ऋण बाजारों और व्यापक अर्थव्यवस्था में आगे संचरण हेतु प्रतीक्षा की मांग करती हैं। तदनुसार, एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो दर को यथावत् रखने के लिए वोट किया। एमपीसी ने उचित मौद्रिक नीति मार्ग निर्धारित करने के लिए प्राप्त आंकड़ों और उभरती घरेलू संवृद्धि-मुद्रास्फीति गतिकी पर कड़ी निगरानी रखने का संकल्प लिया। तदनुसार, सभी सदस्यों ने तटस्थ रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त 20 अगस्त 2025 को प्रकाशित किया जाएगा।

एमपीसी की अगली बैठक 29 सितंबर से 1 अक्तूबर 2025 तक निर्धारित है।

मौद्रिक नीति वक्तव्य
(4-6 अगस्त) 2025-26

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) विनियमन; (ii) वित्तीय बाजारों से संबंधित विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

I. विनियमन

1. बैंकों के मृत ग्राहकों के जमा खातों के संबंध में दावों के निपटान हेतु प्रक्रिया का मानकीकरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत, जमा खातों, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं या सुरक्षित जमा लॉकरों के संबंध में नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इसका उद्देश्य ग्राहक की मृत्यु होने पर दावों का शीघ्र निपटान, वस्तुओं की वापसी या सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री की रिलीज करने के कार्य को सुगम बनाना और परिवार के सदस्यों को होने वाली कठिनाइयों को कम करना है। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, बैंकों को उत्तरजीवियों/ नामित व्यक्तियों/ कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए दावों के शीघ्र और झंझट-रहित निपटान हेतु एक सरलीकृत प्रक्रिया अपनानी होगी। ये प्रक्रियाएँ अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग होती हैं। ग्राहक सेवा मानकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बैंकों को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ों को मानकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जनता से परामर्श के लिए एक परिपत्र का मसौदा शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

II. वित्तीय बाजार

2. ख़जाना-बिलों में निवेश और पुनर्निवेश के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में स्वचालित बोली प्रक्रिया सुविधाओं की शुरूआत

रिटेल डायरेक्ट योजना के अंतर्गत खुदरा निवेशकों को रिज़र्व बैंक में अपने गिल्ट खाते खोलने में सुविधा प्रदान करने के लिए नवंबर 2021 में रिटेल डायरेक्ट पोर्टल का लोकार्पण किया गया था। यह योजना खुदरा निवेशकों को प्राथमिक नीलामी में सरकारी प्रतिभूतियाँ (जी-सेक) खरीदने के साथ-साथ द्वितीयक बाजार में जी-सेक खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है। योजना के शुभारंभ के बाद से, उत्पाद और भुगतान विकल्पों के संदर्भ में कई नई सुविधाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें मई 2024 में एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी शामिल है।

निवेशकों को अपने निवेश की व्यवस्थित योजना बनाने में सक्षम बनाने के लिए, रिटेल डायरेक्ट में ख़जाना बिलों (टी-बिल) के लिए एक स्वचालित बोली-प्रक्रिया सुविधा शुरू की गई है, जिसमें निवेश और पुनर्निवेश दोनों विकल्प शामिल हैं। यह नई सुविधा निवेशकों को ख़जाना बिलों की प्राथमिक नीलामी में बोलियों को स्वचालित रूप से लगाने में मदद करती है।

भाषण

एफआईबीएसी 2025 सम्मेलन में उद्घाटन भाषण
श्री संजय मल्होत्रा

एक अंतरसंबंधित वित्तीय प्रणाली में विनियमों पर पुनर्विचार
श्री एम. राजेश्वर राव

वंजी से विकसित भारत तक: विश्वास, प्रौद्योगिकी और परिवर्तन पर बैंकिंग
श्री स्वामीनाथन जे

एफआईबीएसी 2025 सम्मेलन में उद्घाटन भाषण*

श्री संजय मल्होत्रा

इस साल एफआईबीएसी के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारे वित्तीय अर्थ-जगत के जाने-माने विचारक और भागीदारों को हमारे देश की आर्थिक स्थिति के समक्ष आने वाली महत्वपूर्ण और वर्तमान चुनौतियों पर बातचीत करने के लिए एक साथ लाता है। सम्मेलन का विषय "नए रास्ते बनाना" बहुत प्रासंगिक और स्थानीय है क्योंकि हम टैरिफ और भूराजनैतिक अनिश्चितताओं की नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन में होने वाली चर्चाएँ बहुत फायदेमंद होंगी और सभी भागीदारों, विशेषकर व्यापार विनियामकों और सरकारों को गहरी समझ और -गाइडेंस देंगी। यह और भी ज़रूरी है क्योंकि हम 2047 तक विकसित भारत के अपने सफ़र में योगदान देना चाहते हैं। मैं इस वार्षिक सम्मेलन को आयोजित करने के लिए एफआईसीसीआई और आईबीए की तारीफ़ करता हूँ।

I. भारत की सुदृढ़ता और स्थिरता की कहानी

हमने दस दिन पहले अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आज़ादी के बाद से हमने बहुत तरक्की की है। हमारी तरक्की कई क्षेत्रों में फैली हुई है – शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, अवसंरचना, विज्ञान और तकनीक, रक्षा, अभिशासन, वित्त आदि। भारतीय अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ी है। यह मजबूती और उम्मीद की निशानी बनी हुई है। पिछले कुछ सालों में पहले कभी न हुई मुश्किलों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की सफलताएं प्रशंसनीय हैं और उन्हें सब जानते हैं।

आज भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान मजबूत समष्टि-आर्थिक संरचना से होती है। कोविड के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने ज़ोरदार वापसी की और पिछले चार सालों (2021-22 से 2024-25) में लगभग 8 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की। इसे मुश्किल वैश्विक आर्थिक स्थिति के बीच मजबूत घरेलू मांग – निजी उपभोग और नियत निवेश दोनों – से सहायता मिली। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। हम आने वाले सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण लागू होने के बाद मुद्रास्फीति का स्तर आम तौर पर कम हुआ है। इस साल जुलाई में हेडलाइन मुद्रास्फीति आठ साल के सबसे निचले स्तर 1.6 प्रतिशत पर दर्ज किया गया।

कोविड के बाद प्रति-चक्रीय राजकोषीय प्रतिक्रिया के बाद, जिसमें व्यय की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया है, भारत की राजकोषीय स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा और जीडीपी अनुपात 2025-26 में जीडीपी के 9.2 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर 4.4 प्रतिशत होने का बजट है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय, जिसमें राज्यों को पूंजी अनुदान सहयोग राशि शामिल है, 2025-26 के लिए जीडीपी का 4.3 प्रतिशत बजट में है। कॉरपोरेट तुलनपत्र मजबूत हैं। बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं, उनके पास काफी चलनिधि बफर्स, मजबूत आस्ति गुणवत्ता और ठीक-ठाक लाभप्रदता है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उद्योग, विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र को मेरी बधाई।

पिछले दस वर्षों में भारत का विदेशी व्यापार क्षेत्र भी काफी मजबूत हुआ है। हाल के वर्षों में चालू खाता घाटा (सीएडी) धारणीय सीमा के अंदर रहा है - यह 2024-25 में जीडीपी का 0.6 प्रतिशत था। अधिक व्यापारिक कारोबार घाटे के बावजूद यह ऐसा मजबूत सेवाएं निर्यात और मजबूत धन प्रेषण प्राप्तियों की वजह से है। पूंजीगत प्रवाह आम तौर पर सीएडी से ज़्यादा रहा है, जिससे हमारे आरक्षित विदेशी मुद्रा में बढ़ोतरी हुई है, जो 15 अगस्त, 2025 तक 695 बिलियन यूएसडी था, जिससे 11 महीने से अधिक का व्यापारिक आयात कवर हो सकता है।

* 25 अगस्त 2025 को एफआईबीएसी 2025 सम्मेलन, मुंबई, में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा का उद्घाटन भाषण।

सक्रिय राजकोषीय और मौद्रिक नीति, संरचनात्मक सुधार, भौतिक और डिजिटल संरचना में बड़े पैमाने पर सुधार, बेहतर अभिशासन और बढ़ी हुई उत्पादकता और प्रतियोगिता, इन सभी ने इस शानदार प्रदर्शन में योगदान दिया है।

हम एक अहम मोड़ पर हैं क्योंकि हम बढ़ते व्यापारिक अनिश्चितता और लगातार भूराजनैतिक तनाव वाले उतार-चढ़ाव वाले वैश्विक आर्थिक माहौल में आगे बढ़ रहे हैं। हमें विकास की सीमाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम सभी को आने वाली चुनौतियों से निपटने और आगे आने वाले मौकों का फ़ायदा उठाने के लिए अपनी कोशिशें बढ़ानी होंगी। आज़ादी के दीवानों की कई पीढ़ियों ने हमें एक आज़ाद भारत, एक स्वतंत्र भारत दिया। अब हमें एक समृद्ध भारत, एक खुशहाल भारत के लिए काम करने की ज़रूरत है। इस पृष्ठभूमि में, मैंने सोचा कि यह बताना सही होगा कि हमें अपने आर्थिक विकास को और आगे बढ़ाने के लिए मिलकर क्या करने की ज़रूरत है। मैंने इसे पाँच बड़े क्षेत्रों में बांटा है – मौद्रिक नीति, विनियमन, वित्तीय समावेशन, ग्राहक सेवा और तकनीक।

II. मौद्रिक नीति

आर्थिक खुशहाली में मौद्रिक नीति की भूमिका बहुत ज़रूरी है। हाल के वर्षों में, कई आघातों के बावजूद, भारत में समष्टि-आर्थिक स्थिरता का एक बड़ा कारण महंगाई में कमी रहा है। खाने की चीज़ों की कीमतों में तेज़ उछाल, तेल की अस्थिर कीमतें, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें और भूराजनैतिक तनाव महंगाई को काफी बढ़ा सकते थे। हालांकि, रिज़र्व बैंक के सक्रिय नीतिगत उपायों, जिसमें समय पर ब्याज दर समायोजन और चलनिधि प्रबंधन शामिल हैं, के साथ-साथ सरकार के समझदारी भरे आपूर्ति जनित उपायों ने कीमतों के दबाव को आम तौर पर रोकने में मदद की है। स्थिर महंगाई की उम्मीदों ने भी स्थिर उपभोग पैटर्न को सपोर्ट किया है और निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। कीमतों में स्थिरता के मामले में मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य ने भारत के समष्टि-आर्थिक ढांचा की मजबूती में काफी योगदान दिया है। साथ ही, रिज़र्व बैंक ने संवृद्धि के उद्देश्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया है। उदाहरण के लिए, कोविड से पहले, जब संवृद्धि धीमी हो रही थी, और हाल के महीनों में, जब महंगाई कम थी और संवृद्धि को सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर कम कर दिया था। हम संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता के मुख्य उद्देश्य के साथ मौद्रिक नीति जारी रखेंगे।

III. बैंकों और एनबीएफसी का विनियमन

विनियमन का महत्व

ऋण के अन्य स्रोतों में वृद्धि के बावजूद, आरबीआई द्वारा विनियमित बैंक, एनबीएफसी, एचएफसी और एआईएफआई अभी भी वास्तविक अर्थव्यवस्था की लगभग 73 प्रतिशत ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जबकि बैंक लगभग 53 प्रतिशत प्रदान करते हैं। यह अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के निरंतर महत्व को दर्शाता है।

इन संस्थाओं को विनियमित करने के हमारे प्रयास का यह उद्देश्य रहा है कि सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ बनी रहे और निरंतर विकास करे। यहाँ मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि विनियमन घर्षण के समान हैं। यदि घर्षण बहुत कम है, तो व्यक्ति चलते-चलते गिर जाएगा और यदि यह बहुत अधिक है, तो प्रगति बाधित होगी। विनियम वित्तीय स्थिरता और जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक घर्षण प्रदान करते हैं। हालाँकि, कठोर विनियमन अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा डाल सकते हैं। विनियम निर्माण की कला सुरक्षा और विकास के बीच सही संतुलन - "उचित मात्रा में घर्षण" - खोजने में निहित है। वास्तव में इस संतुलन, या इष्टतम विनियम की खोज ही आरबीआई में हमारा निरंतर प्रयास है।

विनियम निर्माण के प्रति हमारा दृष्टिकोण

हमारा विनियामकीय ढाँचा पाँच सिद्धांतों या विशेषताओं पर आधारित है:

ए. पहला, हम धीरे-धीरे निर्देशात्मक से मुख्यतः सिद्धांत-आधारित हो गए हैं।

बी. दूसरा, हमने विनियमन की लागत और लाभों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने के लिए आनुपातिकता के विचार को अपनाया है। प्रभाव विश्लेषण इसका एक अभिन्न अंग है।

सी. तीसरा, हम अपने दृष्टिकोण में परामर्शात्मक हैं। हम समझते हैं कि हमें सभी हितधारकों के दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है। हम उद्योग, संघों, बैंकों, एनबीएफसी और अन्य विनियमित संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। हमने अपने हितधारकों के साथ सीधे संपर्क के लिए 'कनेक्ट टू रेगुलेट' की भी शुरुआत की है। बेहतर विनियम-निर्माण हेतु प्रतिक्रिया और सुझाव देने में हम आपका सक्रिय सहयोग चाहते हैं।

डी. चौथा, हम साक्ष्य-आधारित होने का प्रयास करते हैं। हम अपनी बातचीत और संपर्क के साथ-साथ अपनी पर्यवेक्षी टीमों के माध्यम से भी जानकारी एकत्र करते हैं। कुछ विनियमित संस्थाएँ हमारी ओर से मांगी गई जानकारी को बोझ महसूस कर सकती हैं। लेकिन, विनियम-निर्माण के लिए जानकारी महत्वपूर्ण है। हम इस संबंध में आपकी सहायता चाहते हैं।

ई. पाँचवाँ, हम चुस्त-दुरुस्त हैं और संदर्भ, नई जानकारी की उपलब्धता और बदलते परिदृश्य के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। संदर्भ बदलने और लागत-लाभ संतुलन के उलट होने पर, जरूरत पड़ने पर, हमने कठोर नियमों में ढील देने में कोई संकोच नहीं किया है।

व्यवहार में हम जो करते हैं, उसे अब हाल ही में जारी "विनियमों के निर्माण हेतु ढाँचा" के माध्यम से संस्थागत रूप दे दिया गया है, जो इस दृष्टिकोण को संहिताबद्ध करता है, जिस पर मैंने अभी प्रकाश डाला है।

हाल के दिनों में विनियामकीय विकास

इस कैलेंडर वर्ष में प्रवेश करते हुए, हमने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के संचालन में सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए उनके लिए लागू विवेकपूर्ण मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया है; जोखिम कम होने पर हमने एनबीएफसी को दिए जाने वाले ऋणों के लिए लागू जोखिम भार को बहाल किया है। इसी प्रकार, सरकारी गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदों के लिए प्रावधान आवश्यकता की समीक्षा उनकी संप्रभु प्रकृति को देखते हुए की गई। हमने वंचित क्षेत्रों को ऋण बढ़ाने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशानिर्देशों को अद्यतित किया है। हमने रन-ऑफ कारकों को युक्तिसंगत बनाया है, जिससे महत्वपूर्ण रूप से समग्र प्रणाली के लिए एलसीआर में लगभग 6 प्रतिशत अंकों का संचयी सुधार होगा। इसी प्रकार, हमने वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), सह-ऋण, गैर-निधि-आधारित सुविधाओं, परियोजना वित्त और स्वर्ण ऋणों में निवेश के लिए व्यापक रूप से युक्तिसंगत विनियामकीय ढांचा तैयार किया है। ये उदाहरण हैं कि हम अपने विनियम-निर्माण में कैसे चुस्त, परामर्शी, साक्ष्य-उन्मुख, सिद्धांत-आधारित और आनुपातिक रहे हैं।

प्रस्तावित विनियम

आगे बढ़ते हुए, हम इसी दृष्टिकोण को जारी रखेंगे। हमारा ध्यान त्रिविध होगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हम वित्तीय स्थिरता को मजबूत करना जारी रखेंगे। हमारा इरादा 1.4.2027 से बाज़ार, ऋण और परिचालन जोखिम के लिए बेसल III दिशानिर्देशों को लागू करने का है, जिसके लिए ऋण जोखिम और ईसीएल से संबंधित मसौदा दिशानिर्देश जल्द ही जारी करने का प्रस्ताव है। व्यवसाय प्रपत्र परिपत्र को भी जल्द ही अंतिम रूप देने की योजना है।

दूसरा, हम व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमने पहले ही विनियमित संस्थाओं द्वारा हमें प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न को युक्तिसंगत बना दिया है। हम विभिन्न श्रेणियों की विनियमित संस्थाओं के लिए सभी विनियमों को समेकित करने की प्रक्रिया में हैं। सिद्धांत-आधारित ढाँचा बनाने के अपने प्रयास में, हमने संबंधित संस्थाओं के बोर्ड को नीतियाँ बनाने की स्वायत्तता दी है। हालाँकि विस्तृत नीति-निर्माण का काम बैंक के निर्णय पर छोड़ने का इरादा था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप विनियमित संस्थाओं के बोर्ड पर अत्यधिक बोझ पड़ गया है। इसलिए, हम उन समष्टि नीतियों को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें विनियमित संस्थाओं के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, और प्रक्रियात्मक और नियमित

मामलों को प्रबंधन पर छोड़ रहे हैं ताकि बोर्ड को रणनीतिक और महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए गुणवत्तापूर्ण समय मिल सके।

तीसरा, हम उत्पादक क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण का विस्तार करने और मध्यस्थता की लागत को कम करने के उपायों की जाँच कर रहे हैं।

जैसा कि पहले घोषणा की गई थी, हम एक विनियामक समीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं जिसका कार्य प्रत्येक विनियम की व्यापक, वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और संरचित तरीके से समीक्षा करना होगा। समीक्षा का उद्देश्य प्रत्येक विनियम का दक्षता, लागत और लाभ के संदर्भ में उसके प्रभाव, वर्तमान संदर्भ और बाजार की वास्तविकताओं में उसकी आवश्यकता, विशेष रूप से विभिन्न विनियमों में एकरूपता और स्पष्टता; और अनसुलझे या उभरते जोखिमों की संभावना आदि के मूल्यांकन पर केंद्रित होगा। प्रकोष्ठ अपने कार्य को इस प्रकार व्यवस्थित करेगा कि प्रत्येक विनियम की समीक्षा प्रत्येक 5-7 वर्षों में कम से कम एक बार की जाए। यह प्रकोष्ठ प्रमुख वित्तीय क्षेत्र के उद्योग निकायों के साथ बातचीत करेगा।

IV. वित्तीय समावेशन

आर्थिक विकास अधूरा है अगर वह समावेशी न हो। हम इस कहावत में विश्वास करते हैं, "अगर आप तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अकेले चलें; अगर आप दूर जाना चाहते हैं, तो साथ चलें"। हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा, खासकर उन लोगों को जो आर्थिक रूप से सबसे निचले पायदान पर हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति की है, जैसा कि आरबीआई द्वारा निर्मित वित्तीय समावेशन (एफआई) सूचकांक में परिलक्षित होता है, जो वित्तीय समावेशन के तीन आयामों, 'पहुँच', 'उपयोग' और 'गुणवत्ता' पर आधारित है। उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, एफआई-सूचकांक उपयोग और गुणवत्ता में और सुधार की गुंजाइश की ओर इशारा करता है, साथ ही पहुँच में कमियों पर भी ध्यान खींचता है।

हमें याद रखना चाहिए कि हमारे देश के सभी लोगों के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी है, जिनमें से लगभग दो-तिहाई ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हालाँकि, हमने 5 किलोमीटर के दायरे में लगभग सभी गाँवों तक बैंकिंग पहुँच प्रदान की है, तथापि इसे और बढ़ाने की गुंजाइश है। व्यवसाय संवाददाता (बीसी) हमारे देश के कम आबादी वाले क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करने का एक प्रभावी माध्यम हैं। वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और पहुँच में सुधार के लिए इस माध्यम को मज़बूत करने की आवश्यकता है। न केवल उन्हें बढ़ाने की गुंजाइश है, बल्कि उन्हें प्रशिक्षित करने और उनके द्वारा प्रदान की जा सकने वाली सेवाओं की संख्या का विस्तार करने की भी आवश्यकता है। एक ओर, यह बीसी को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और टिकाऊ बनाएगा; दूसरी ओर, इससे सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार होगा।

वित्तीय समावेशन के उद्देश्य और वित्तीय सेवाओं तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों ने 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। मैं सभी बैंकों से आग्रह करता हूँ कि वे इन शिविरों के माध्यम से पुनः-केवाईसी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे को बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएँ। मैं हमारे तत्वावधान में संचालित वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और वित्तीय साक्षरता के लिए बने केंद्रों (सीएफएल) के लिए भी आपका सहयोग चाहता हूँ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जो रोजगार, निर्यात और उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई के लिए ऋण में कमी काफ़ी ज़्यादा है। बैंकों और एनबीएफसी को इन उद्यमों के लिए औपचारिक ऋण को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रयास करने चाहिए। इस प्रयास में उन्हें यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) जैसी सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना का लाभ उठाना चाहिए।

V. ग्राहक सेवा

उपभोक्ता से ही हम हैं या यूं कहें कि हमारा अस्तित्व उन्हीं पर टिका है। किसी भी कारोबार के सतत विकास के लिए ग्राहक-केंद्रीयता महत्वपूर्ण है।

आचरण संबंधित विनियमन

रिज़र्व बैंक में, हम ग्राहक-केंद्रीयता के उद्देश्य से पूरी लगन से आगे बढ़ते हैं। की फैक्ट स्टेटमेंट और हमारे विनियमों में स्पष्ट

आचरण से संबंधित पहलुओं को एकीकृत करना इस संबंध में कुछ उदाहरण हैं। हाल ही में पूर्व-भुगतान शुल्क पर संशोधित दिशानिर्देश और मृत ग्राहकों के संबंध में दावों के निपटान पर मसौदा दिशानिर्देश भी हमारे 'ग्राहक पहले' दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

आरई द्वारा उपभोक्ता सेवा

इसी तरह, विनियमित संस्थाओं को उत्कृष्ट और निर्बाध सेवा एवं अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे ग्राहक खुश रहें। उन्हें पारदर्शी, निष्पक्ष और उत्तरदायी होने की आवश्यकता है। जबकि डिजिटलीकरण एक कुंजी है, मानवीय पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए प्रशिक्षण, विशेष रूप से व्यवहार संबंधी पहलुओं पर जोर देने की आवश्यकता है।

मैंने पहले भी बैंकों से केवाईसी टच प्वाइंट पर सीकेवाईसीआर के उपयोग को सक्षम बनाने का आग्रह किया था। मैंने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि भारतीय रिज़र्व बैंक के ओमबड्समैन को प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या बहुत अधिक है। यह भी उम्मीद की गई थी कि प्रत्येक आरई में एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र होगा, जहां अधिकारियों को उपभोक्ता हित में निर्णय लेने के लिए उपयुक्त रूप से सशक्त बनाया गया हो। मैं विनियमित संस्थाओं से इन क्षेत्रों में और सुधार करने का आह्वान करता हूं।

इसके अतिरिक्त, हम आरई के स्तर पर आंतरिक ओमबड्समैन रूपरेखा की समीक्षा करने की प्रक्रिया में हैं, ताकि इसे और मजबूत किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतों का समाधान संस्थान के भीतर ही प्रभावी ढंग से किया जाए। हम एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में आरबी-आईओएस की प्रभावशीलता, पारदर्शिता और ग्राहक-केंद्रीयता बढ़ाने के लिए इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। इसके अलावा, हम ओमबड्समैन रूपरेखा के तहत दिए गए मुआवजे की संगतता और पर्याप्तता को बढ़ाने का प्रयोजन रखते हैं। हम उन सेवाओं के समूह का विस्तार करने की भी योजना बना रहे हैं, जिनका समय पर प्रावधान नहीं करने से जुर्माना राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

उपभोक्ता का विश्वास न केवल विनियमित इकाई के लिए बल्कि बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और सुदृढ़ता के लिए भी महत्वपूर्ण है। विश्वास स्थापित करने और बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक है कि विनियमित संस्थाएं (आरई) पीड़ित ग्राहकों की शिकायतों का न्यायसंगत, पारदर्शी, समय पर और किफायती तरीके से सक्रिय रूप से निवारण करने के लिए एक मजबूत और प्रभावी तंत्र स्थापित करें। उन्हें समय-समय पर शिकायतों के प्रकारों का आकलन करना चाहिए, मूल कारण विश्लेषण करना चाहिए तथा उत्पाद डिजाइन, प्रक्रियाओं और कर्मचारी आचरण में प्रणालीगत सुधारात्मक उपायों को लागू करना चाहिए। यह भी सुझाव दिया जाता है कि ग्राहक संतुष्टि से संबंधित केपीआई को प्रमुख पदाधिकारियों के निष्पादन मूल्यांकन और परिवर्तनीय वेतन में शामिल किया जाए।

VI. ऋण और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी का उपयोग किसी भी कारोबार के लिए अनिवार्य है। यह निर्णय लेने और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए मुख्य साधन बन गया है, जो दक्षता बढ़ाने की अपनी पारंपरिक भूमिका से कहीं आगे बढ़ गया है। विनियमित संस्थाओं को इसके अंगीकरण में तेजी लाने की आवश्यकता है क्योंकि वे ऋण में वृद्धि और लागत कम करने का प्रयास रहे हैं।

आरबीआई ने भी अपने सभी कार्यों में प्रौद्योगिकी को अपनाया है। एकाउंट एग्रीगेटर (एए) पारितंत्र ग्राहकों को उनके वित्तीय डेटा पर नियंत्रण देने के साथ सशक्त बना रहा है। यूएलआई ऋण वितरण को सहज बना रहा है, जिससे यह वास्तव में परिवर्तनकारी हो रहा है। हम इन प्लेटफॉर्मों को और मजबूत करेंगे। हमने विनियमित संस्थाओं की सेवाओं में सुधार के लिए 'प्रवाह' प्लेटफॉर्म को कार्यान्वित किया है। हम एआई और एमएल सहित प्रौद्योगिकी को अपनाना जारी रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारी विनियमित संस्थाएं भी इसमें निवेश करेंगी।

VII. निष्कर्ष

अंत में, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि भले ही हम अलग-अलग पक्षों पर प्रतीत हो सकते हैं - विनियमित संस्थाएं वृद्धि में बढ़ोतरी लाने की कोशिश कर रही हैं तथा विनियामक, स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम दोनों का उद्देश्य एक ही है। हम एक ही टीम में हैं और हमारा एक ही साझा विजन है: विकसित भारत। वित्तीय स्थिरता और वृद्धि के बीच कोई खींचतान नहीं है। वित्तीय स्थिरता और मूल्य स्थिरता, वृद्धि को बाधित नहीं करती हैं। बल्कि, वे धारणीय वृद्धि के लिए आवश्यक हैं।

मैं विनियमित संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ ताकि वित्तीय मध्यस्थता की दक्षता और प्रभावशीलता को बेहतर बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे देश के लोगों तक समुचित लाभ पहुँचें। इसी तरह, मांग पक्ष पर, मैं उद्योग जगत से साहसपूर्वक निवेश करने और हमारे राष्ट्र को परिभाषित करने वाली उद्यमशीलता की भावना का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। ऐसे समय में, जब बैंकों और कॉरपोरेट्स के तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर हैं, उन्हें एक साथ आना चाहिए और निवेश चक्र बनाने के लिए जिंदादिल होना चाहिए जो इस समय बहुत जरूरी है।

अंत में, अपनी-अपनी भूमिकाओं में, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जिन लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें कभी भी नज़रअंदाज़ न करें। यह थोड़ा-बहुत उपदेशात्मक लगने के बावजूद, मुझे यह कहना होगा कि यदि आपके मन में कोई संदेह है, तो गांधीजी के जंतर/सीख या अंत्योदय की सोच को अपनाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें कि आपके कार्य हमारे देश के सबसे कमजोर व्यक्ति को कैसे प्रभावित करेंगे।

मैं सम्मेलन की महती सफलता की कामना करता हूं।

धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।

*एक अंतरसंबंधित वित्तीय प्रणाली में विनियमों पर पुनर्विचार**

श्री एम. राजेश्वर राव

'वित्तीय बाजार विनियमन पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम' के प्रतिभागियो, प्राध्यापको, देवियो और सज्जनो। आप सभी को नमस्कार!

सबसे पहले मैं आईआईएम, कोझिकोड को मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। नीति विशेषज्ञों से लेकर वित्तीय परिदृश्य के महत्वपूर्ण हितधारकों तक की इस वैविध्यपूर्ण सभा को संबोधित करना मेरे लिए खुशी की बात है। कार्यक्रम की विषयवस्तु बैंकों, प्रतिभूति फर्मों और बीमा संस्थाओं सहित वित्तीय बाजारों में कार्यरत विविध संस्थाओं के विनियामक ढाँचे से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है।

वित्तीय बाजारों में मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियाँ, विदेशी मुद्रा, इक्विटी, कमोडिटी और डेरिवेटिव जैसे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इन उत्पादों का व्यापार द्विपक्षीय रूप से, काउंटर पर, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या अधिकतर एक्सचेंजों पर होता है। ये संस्थाएँ विविध हैं, और इनमें से कई बाजारों में सक्रिय हैं। संस्थाओं की प्रकृति और/या उनकी गतिविधियों के आधार पर इनका विनियमन विभिन्न विनियामकों द्वारा किया जाता है। बाज़ार एक प्रकार की बाज़ार गतिविधियों से दूसरे प्रकार की बाज़ार गतिविधियों में फैलने वाले जोखिमों से परस्पर जुड़े हुए हैं, जो वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसलिए, आज अपने वक्तव्य में, मैं बाज़ार और संस्थाओं के विनियमनों की आवश्यकता और उनके परस्पर प्रभाव, विनियामकों द्वारा प्रयुक्त टूल्स और तेज़ी से विकसित होते और परस्पर जुड़े वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनियमन तैयार करने में आने वाली चुनौतियों पर कुछ दृष्टिकोण साझा करना चाहूँगा; और आगे की राह पर कुछ विचार साझा करके अपनी बात समाप्त करूँगा।

भारत में वित्तीय क्षेत्र के विनियमनों की भूमिका और विकास

इसकी शुरुआत करने के लिए भारत में वित्तीय क्षेत्र के विनियमनों के विकास पर बात करना आवश्यक है। इसकी शुरुआत 1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना के साथ हुई थी। 1949 में बैंक के कार्यक्षेत्र का विस्तार वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण को शामिल करने के लिए किया गया था। इसके बाद 1964 में इसे गैर-बैंकिंग संस्थाओं[2], जिन्हें अब सामान्यतः गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) कहा जाता है, तथा उसके बाद 1966 में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को विनियमित करने और पर्यवेक्षण करने का अधिकार दिया गया।

वर्ष 1991 अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वर्ष में प्रमुख आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और विकास हुआ। वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत एक तरह से वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के साथ हुई। निजी बैंकों का प्रवेश, बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की शुरुआत, समिति की सिफारिशों के आधार पर पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर अधिक निगरानी रखने के लिए रिज़र्व बैंक को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान करना इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत मील के पत्थर थे। इसके साथ ही मौद्रिक नीति ढाँचे[5] में बाद

* भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा 18 अगस्त 2025 को भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड (आईआईएमके) में वित्तीय बाजार विनियमन पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) एमडीपी कार्यक्रम में दिया गया उद्घाटन भाषण। चांदनी त्रेहन सलूजा और नीलेश ज्ञानोबा गावडे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए आभार।

1 https://rbi.org.in/history/Brief_Chro1935to1949.html

2 1963 का अधिनियम 055: बैंकिंग कानून (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1963 (https://www.casemine.com/act/in/5a979d964a93263ca60b70c7)

3 आरबीआई अधिनियम, 1934 का अध्याय IIIबी।

4 https://rbi.org.in/history/Brief_Fun_UrbanCoopBanks.html

5 1998 से 2009 तक तदर्थ टी-बिलों के माध्यम से स्वचालित मुद्रीकरण को समाप्त करने से लेकर बहु-संकेतक दृष्टिकोण तक, जिसके बाद 2013 से 2016 तक मौद्रिक नीति को निर्देशित करने वाले नाममात्र आधार के रूप में मुद्रास्फीति को लागू करने की पूर्व-शर्तों के साथ एक संक्रमण काल और उसके बाद, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा: https://rbi.org.in/commonman/english/Scripts/speeches.aspx?Id=3161

में हुए बदलाव, विनिमय नियंत्रण व्यवस्था का उदारीकरण और भुगतान एवं निपटान प्रणालियों के साथ-साथ मुद्रा, विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजारों को विनियमित करने की शक्तियाँ रिज़र्व बैंक को प्रदान किए जाने से समग्र रूप से रिज़र्व बैंक में विनियमन निर्माण के दृष्टिकोण में बदला आया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को वर्ष 1992[6] में प्रतिभूति बाजार के विनियमन और विकास का वैधानिक दायित्व सौंपा गया। इसके बाद के दशकों में बीमा और पुनर्बीमा क्षेत्रों के विनियमन की देखरेख के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और पेंशन निधियों के लिए पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के रूप में नए वित्तीय क्षेत्र विनियामकों की स्थापना हुई। हाल ही में, अर्थात 2020 में, भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के भीतर वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और संस्थानों को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) का गठन किया गया। सामूहिक रूप से, ये विनियामक भारत की वित्तीय प्रणाली को एक अधिक लचीले, बाजार-संचालित और उपभोक्ता-केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और साथ ही देश के टिकाऊ आर्थिक विकास को भी सुगम बनाते हैं।

विनियमन बनाने संबंधी दृष्टिकोण

न्यूनतम विनियमनों के साथ वित्तीय बाजारों के विनियमन के प्रति बाजार-उन्मुख *अहस्तक्षेप* दृष्टिकोण इस धारणा पर आधारित है कि स्व-विनियमन प्रभावी होगा। हालाँकि, कुछ अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया है, जिनका तर्क है कि विनियमन न केवल आवश्यक है, बल्कि अनिवार्य भी है। उनका तर्क है कि स्वाभाविक रूप से स्व-सुधार करने वाले बाजारों का विचार एक तथ्यात्मक घटना से ज़्यादा एक वैचारिक सोच है, और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता, पारदर्शिता और प्रणालीगत जोखिमों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी बेहद ज़रूरी है। नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "फ्रीफॉल: फ्री मार्केट्स एंड द सिंकिंग ऑफ़ द ग्लोबल इकोनॉमी" में लिखा है, “उस संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्व-नियमन - जिसे वित्तीय उद्योग ने बढ़ावा दिया और जिसे मैं एक विरोधाभास मानता हूँ - कारगर नहीं है (“The crisis has made it clear that self-regulation – which the financial industry promoted and which I view as an oxymoron – doesn’t work.”)।" बार-बार यह सिद्ध हो चुका है कि वित्तीय विनियमन न केवल बाजार की विफलताओं को रोकने के लिए, बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और व्यापक अर्थव्यवस्था की स्थिरता और लचीलेपन को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, खासकर संकट के समय में। यह आम गलत धारणा कि विनियमन स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक बाधाएँ लगाता है, गलत है। सोच-समझकर तैयार किए गए विनियमों पर आधारित एक सुविचारित वित्तीय निगरानी ढाँचा न केवल समान अवसर सुनिश्चित करता है, बल्कि टिकाऊ संवृद्धि और विकास को भी बढ़ावा देता है।

हम वित्तीय प्रणालियों को कैसे विनियमित करते हैं[7]

विनियमन-निर्माण के विशिष्ट तरीकों पर गहराई से विचार करने से पहले, वित्तीय प्रणाली विनियमन के व्यापक ढाँचों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि वित्तीय निगरानी के वैकल्पिक मॉडल प्रचलन में हैं।

वित्तीय प्रणालियों के लिए विनियामक निगरानी संरचना को मोटे तौर पर **तीन मुख्य मॉडलों** में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला मॉडल **‘क्षेत्रीय या पारंपरिक मॉडल’** के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रत्येक वित्तीय क्षेत्र प्राधिकरण विशिष्ट वित्तीय क्षेत्र, अर्थात् बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियाँ और बाज़ार अखंडता के विवेकपूर्ण और आचरण संबंधी दोनों पहलुओं के लिए ज़िम्मेदार होता है। भारत, ब्राज़ील, हांगकांग और मेक्सिको जैसे देशों ने इस दृष्टिकोण को अपनाया है और यह दुनिया भर में सबसे अधिक

[6] सेबी की स्थापना 1988 में प्रतिभूति बाजार के विनियमन हेतु एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी।

[7] https://www.bis.org/fsi/publ/insights8.htm और https://www.researchgate.net/publication/290574692_Approaches_to_Financial_System_Regulation_An_International_Comparative_Survey

इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडल बना हुआ है। हालाँकि, वित्तीय समूहों के साथ व्यवहार करते समय ऐसे मॉडल में चुनौतियाँ आती हैं, जिनकी गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थानों के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती हैं। इस तरह की कमियों को पूरक व्यवस्थाओं को लागू करके सुचारु किया जा सकता है, जैसे कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र विनियामकों (एफएसआर) द्वारा अपनाई गई व्यवस्थाएँ, जिनकी चर्चा मैं बाद में करूँगा।

एक वैकल्पिक दृष्टिकोण **'एकीकृत मॉडल'** है, जहाँ एक ही एजेंसी वित्त उद्योग में विनियमन सहित सभी निरीक्षण कार्यों की देखरेख करती है। वित्तीय निरीक्षण संरचना में सुधारों के परिणामस्वरूप सिंगापुर ने 1984 में इस मॉडल को अपनाया था। बाद में स्कैंडिनेवियाई देशों ने भी इसी तरह के मॉडल अपनाए, जिसके बाद ब्रिटेन ने 1997 में एक एकल वित्तीय सेवा प्राधिकरण (एफएसए) की स्थापना की। इसके अलावा, रूस, जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने भी अपनी वित्तीय संरचना में इस मॉडल को अपनाया है। हालाँकि यह दृष्टिकोण वित्तीय क्षेत्र की निगरानी के लिए एक सुसंगत और सुव्यवस्थित ढाँचा प्रदान करता है जिससे एकीकृत निर्णय लेने, कम विनियामक मध्यस्थता और बेहतर समन्वय संभव होता है, यह कुछ परिचालनिक चुनौतियाँ भी प्रस्तुत कर सकता है जैसे कि विनियामक विफलता के संभावित एकल बिंदु का जोखिम, क्षेत्रीय विषय पर ध्यान का कमजोर होना और विभिन्न उप-क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में लचीलेपन में कमी।

तीसरे मॉडल में ज़िम्मेदारियों को या तो विनियामक और पर्यवेक्षी लक्ष्यों के अनुसार या क्षेत्रों के अनुसार समूहीकृत करना शामिल है, अर्थात आंशिक रूप से **एकीकृत दृष्टिकोण। 'ट्विन पीक्स'** (Twin Peaks) मॉडल इसका एक उदाहरण है, जहां दो अलग-अलग एजेंसियां सभी प्रकार के वित्तीय संस्थानों के लिए विवेकपूर्ण निरीक्षण और व्यवसाय के संचालन का प्रबंधन करती हैं। इस मॉडल को सबसे पहले 1997 में ऑस्ट्रेलिया में अपनाया गया था, इसके बाद 2002 में नीदरलैंड में और उसके बाद कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया। वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद यूके ने एफएसए को दो संस्थानों में विभाजित करके एकीकृत मॉडल को ट्विन पीक्स मॉडल के साथ बदलने के लिए अपने विनियामक ढांचे का पुनर्गठन किया। एक - वित्तीय संचलन प्राधिकरण जो बाजार के संचलन पर केंद्रित है, और विवेकपूर्ण विनियमन प्राधिकरण (सेंट्रल बैंक के तत्वावधान में) जो बैंकों, बिल्डिंग सोसाइटियों, क्रेडिट यूनियनों, बीमा कंपनियों और प्रमुख निवेश फर्मों के विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। ट्विन पीक्स मॉडल विभिन्न प्रकार के वित्तीय संस्थानों के विवेकपूर्ण या व्यावसायिक संचलन निरीक्षण में उत्पन्न होने वाली संभावित सहक्रियाओं पर आधारित है, लेकिन इसमें एकीकृत मॉडल की तरह ही क्षेत्रीय विषय पर ध्यान की कमी और क्षेत्रीय मॉडल की तरह समन्वय संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

द्वी-एजेंसी मॉडल आंशिक रूप से एकीकृत मॉडल का एक और उदाहरण है, जहाँ एक एजेंसी बैंकों और बीमा कंपनियों की शोधन क्षमता और व्यावसायिक संचालन, दोनों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए ज़िम्मेदार होती है, और दूसरी एजेंसी बाज़ार की अखंडता और प्रतिभूति व्यवसाय के लिए ज़िम्मेदार होती है। यह वर्तमान में फ्रांस, इटली, मलेशिया, सऊदी अरब आदि जैसे क्षेत्राधिकारों में लागू है।

संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) और यूरोपीय संघ (ईयू) के मॉडल की अपनी विशिष्टताएँ हैं। जहाँ अमेरिका में संघीय और राज्य स्तर पर विभिन्न एजेंसियों को कार्य सौंपे गए हैं, वहीं यूरोपीय संघ में यूरो क्षेत्र के सभी देश महत्वपूर्ण बैंकों के लिए एक ही विवेकपूर्ण पर्यवेक्षी प्राधिकरण साझा करते हैं। हाल ही में, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, वित्तीय निरीक्षण ढाँचे में समष्टि-विवेकपूर्ण नीति और समाधान कार्य जोड़े गए, जिनमें अपनाए गए मॉडल के प्रकार के आधार पर अलग-अलग एजेंसियाँ शामिल हो भी सकती हैं और नहीं भी।

प्रत्येक मॉडल में तालमेल और संभावित हितों के टकराव तथा चुनौतियों के बीच संतुलन स्थापित करना शामिल है। वित्तीय निरीक्षण मॉडल अपनाने का निर्णय वित्तीय क्षेत्र की संरचना और विकास, कानूनी, सांस्कृतिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था

संबंधी विचारों के साथ-साथ वित्तीय संकटों से निपटने जैसे पिछले अनुभवों पर निर्भर करता है। मॉडल चाहे जो भी हो, किसी भी वित्तीय निरीक्षण संरचना की एक प्रमुख विशेषता यह है कि केंद्रीय बैंक प्राथमिक या प्रमुख प्राधिकरण बना रहता है। अन्य विनियामक संस्थाओं के साथ समन्वय में इसका नेतृत्व समग्र वित्तीय निरीक्षण संरचना की सुसंगतता, लचीलेपन और विश्वसनीयता को सुदृढ़ करता है।

अब मैं विनियमन-निर्माण प्रक्रिया के लिए विनियामकों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोणों पर चर्चा करूँगा। हालाँकि विनियमन के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण पर अलग-अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन कोई भी दृष्टिकोण 'सभी के लिए एक जैसा' नहीं होता। प्रभावी विनियमन के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु विनियामक विभिन्न दृष्टिकोणों और साधनों का उपयोग करते हैं।

'सिद्धांत' बनाम 'नियम' बनाम 'परिणाम-आधारित विनियमन'

सिद्धांत-आधारित विनियमन गुणात्मक होता है और अंतर्निहित उद्देश्य की व्याख्या के साथ उच्च-स्तरीय कथनों का उपयोग करता है। यह एक विनियमित संस्था (आरई) को निर्देशात्मक नियमों से बाध्य हुए बिना नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करके नवाचार करने का लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालाँकि, यह व्यक्तिपरक व्याख्या के लिए खुला है और इसलिए आरई और पर्यवेक्षकों दोनों के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर सकता है, जिससे प्रवर्तन और जवाबदेही सीमित हो जाती है। यह उपभोक्ता संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी कम प्रभावी हो सकता है, जहाँ स्पष्ट और कार्रवाई योग्य निर्देश आवश्यक हैं। एक बैंकिंग विनियामक के रूप में रिज़र्व बैंक के संदर्भ में, दबावग्रस्त आस्ति समाधान हेतु विवेकपूर्ण ढाँचा[8] सिद्धांत-आधारित विनियमन का एक उदाहरण है।

दूसरी ओर, नियम-आधारित विनियमन के लिए आरई को विशिष्ट, निर्देशात्मक आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक होता है। इससे बेहतर स्पष्टता, अनुपालन और एकरूपता आती है, क्योंकि यह आरई और उपभोक्ता, दोनों के लिए विनियमों की समझ को सरल बनाता है। हालाँकि, यह केवल अनुपालन कर देने वाली मानसिकता को जन्म दे सकता है, जिसके परिणामस्वरूप आरई अक्षरशः अनुपालन करते हैं, लेकिन मूल भावना से नहीं। जटिल और गतिशील मुद्दों से निपटने में, जहाँ सूक्ष्म निर्णय की आवश्यकता होती है, विनियमित संस्थाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पर मास्टर निर्देश - लक्ष्य और वर्गीकरण[9] को बैंक द्वारा जारी नियम-आधारित विनियमन का एक उदाहरण माना जा सकता है।

हाल ही में प्रमुखता प्राप्त करने वाला एक अन्य दृष्टिकोण परिणाम-आधारित विनियमन है, जो विशिष्ट प्रक्रियाओं और साधनों को निर्धारित करने के बजाय वांछित परिणामों पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण वांछित परिणाम "क्या" निर्धारित करता है, जबकि इसे "कैसे" प्राप्त किया जाए, इस पर लचीला होता है। डिजिटल ऋण पर आरबीआई के निर्देश[10], ऋण दरों या विधियों जैसी बारीकियों में जाने के बजाय, वांछित परिणाम, अर्थात उधारकर्ताओं के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता पर ज़ोर देते हैं।

आज के गतिशील वित्तीय परिदृश्य की जटिलताओं को देखते हुए, नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए एक सक्षम और प्रभावी विनियामक वातावरण बनाने के लिए इन दृष्टिकोणों के बीच सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

गतिविधि बनाम इकाई आधारित विनियमन

गतिविधि-आधारित विनियमन विशिष्ट गतिविधियों के लिए विनियामक दायित्वों को निर्धारित करता है, भले ही वह गतिविधि कोई भी इकाई कर रही हो। यह "समान गतिविधि, समान जोखिम, समान नियम" के सिद्धांत पर काम करता है। 'बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं पर जारी निर्देश' को गतिविधि-आधारित विनियमन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

इसके विपरीत, इकाई-आधारित विनियमन का उद्देश्य इकाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए गतिविधियों के लचीलेपन को मजबूत करना है। इस दृष्टिकोण में अभिशासन, विवेकपूर्ण और आचरण संबंधी आवश्यकताएँ शामिल हैं, जिन्हें पर्यवेक्षी हस्तक्षेपों द्वारा सुदृढ़ किया जाता है। यह देखते हुए कि किसी इकाई का

[8] https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11580&Mode=0

[9] https://rbi.org.in/scripts/NotificationUseraspx?Id=12799&fn=2754&Mde=0

[10] https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12848&Mode=0

[11] https://www.rbi.org.in/scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=10425

समग्र लचीलापन उसकी गतिविधियों की संरचना से निर्धारित होता है, इकाई-आधारित विनियमन लक्षित प्रतिबंध लगाते हैं - जो ऐसे विनियमन की एक अनिवार्य विशेषता है। पूँजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड इकाई-आधारित विनियमन की प्रकृति के होते हैं।

विभिन्न विनियामक क्षेत्रों को देखते हुए, और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विनियामक अक्सर एक मिश्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं जो गतिविधि-आधारित और इकाई-आधारित विनियमन, दोनों के तत्वों को एकीकृत करता है। इस तरह का एक अनुकूलित विनियामक ढांचा निगरानी तंत्र की व्यापकता और लचीलेपन को बढ़ाता है। यह विनियामकों को बाजार के घटनाक्रमों और उभरते जोखिमों पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है, जिससे समग्र विनियामक ढाँचा मज़बूत होता है और एक सुदृढ़, स्थिर और समावेशी वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा मिलता है।[12]

'नियम-आधारित' बनाम 'जोखिम-आधारित' दृष्टिकोण[13]

नियम-आधारित विनियमन, जोखिम के स्तर को विचार में लिए बिना विनियामक निर्देशों के पालन पर केंद्रित है। हालाँकि यह कभी-कभी लाभदायक होता है, लेकिन इस दृष्टिकोण में आनुपातिकता के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सभी संस्थाओं में वित्तीय स्थिरता या उपभोक्ता संरक्षण संबंधी समान जोखिम नहीं होता है।

जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाने से विनियामक ऐसे विनियम बना पाते हैं जो आज के गतिशील वित्तीय परिवेश में प्रभावी और आनुपातिक दोनों हों। इससे सीमित विनियामक और पर्यवेक्षी संसाधनों को इष्टतम तरीके से निर्देशित करने में भी मदद मिलती है और साथ ही नवाचार और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)[14] के लिए आरबीआई द्वारा जारी पैमाना-आधारित विनियमन[14] और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी)[15] के लिए संशोधित विनियामक ढाँचे को जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के हालिया उदाहरण माना जा सकता है।

[12] https://www.fsb.org/uploads/P160724-2.pdf and https://www.bis.org/fsi/fsipapers19.pdf
[13] https://www.fsb.org/uploads/P160724-2.pdf
[14] https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=12550
[15] https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12416&Mode=0

'बाज़ार' बनाम 'इकाई' विनियमन

बाज़ार-आधारित विनियमन वित्तीय बाज़ारों की समग्र संरचना और कार्यप्रणाली पर केंद्रित होता है, जबकि इकाई-आधारित विनियमन व्यक्तिगत वित्तीय संस्थानों के विवेकपूर्ण मानदंडों, संचलन, शोधन क्षमता और आंतरिक जोखिम प्रबंधन से संबंधित होता है। हालाँकि प्रत्येक वित्तीय क्षेत्र विनियामक (एफएसआर) अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए या आईएफएससीए का अपना विशिष्ट विनियामक क्षेत्राधिकार होता है, फिर भी उनके कई आरई की गतिविधियाँ एक-दूसरे के सीमाक्षेत्र में आ जाती हैं। अपनी गतिविधियों के आधार पर, ये संस्थाएँ कई विनियामक ढाँचों के अंतर्गत आ सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अलग-अलग निगरानी और परिचालन जटिलताएँ बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए, सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में भाग लेने वाली कोई म्यूचुअल फ़ंड या बीमा कंपनी या कॉरपोरेट बॉण्ड बाज़ार में भाग लेने वाला कोई बैंक। ऐसे ओवरलैप को दूर करने के लिए, वित्तीय क्षेत्र विनियामक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहे हैं।

विनियमन निर्माण में चुनौतियाँ

विनियमन निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, जो मौजूदा विनियमों में जोखिमों या कमियों की पहचान करने, उन्हें दूर करने के विकल्पों के मूल्यांकन और अंततः एक उपयुक्त एवं प्रभावी विनियमन तैयार करने से शुरू होती है, जिसका उद्देश्य संस्था और वित्तीय प्रणाली (विवेक, लचीलापन और स्थिरता) के लिए जोखिमों का समाधान करना और/या उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और संस्थाओं के बीच निष्पक्ष संचलन सुनिश्चित करना (संचलन संबंधी मुद्दे) है। इस मार्ग पर चलते हुए, विनियामकों को अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं उनमें से कुछ पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

नवाचार और स्थिरता में संतुलन[16]

वित्तीय क्षेत्र में नवाचार ने परिवर्तनकारी बदलाव लाए हैं। हालाँकि, नवाचार की तीव्र गति विनियामकीय कमियों या अस्पष्ट क्षेत्रों को भी जन्म देती है। नवाचार अक्सर नए व्यावसायिक मॉडल

[16] https://rbi.org.in/Scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1453

और तृतीय पक्षों के साथ साझेदारी का रूप लेते हैं, जो वित्तीय क्षेत्र विनियामक के विनियामकीय दायरे से बाहर होते हैं। विनियामक का काम इन खामियों को दूर करने के लिए ऐसे नियम बनाना है जो नवाचार को प्रोत्साहित करें, लेकिन वित्तीय प्रणाली को स्थिर और लचीला बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा कवच प्रदान करें। इसलिए विनियामक अधिक चुस्त और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपना रहे हैं - जैसे कि विनियामक सैंडबॉक्स का विकास और नए सहभागियों को विनियामक ढांचे में एकीकृत करने के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ संवाद बढ़ाना, तथा साथ ही वित्तीय स्थिरता का भी ध्यान रखना।

उभरते जोखिमों और प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बनाए रखना

विनियामकों को गतिशील रूप से बदलते बाजारों के साथ तालमेल बनाए रखने और उभरते जोखिमों और प्रौद्योगिकियों से निपटने की आवश्यकता है। इसके लिए विनियामकों को ऐसे दृष्टिकोण विकसित करने होंगे जो यह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं के साथ उचित व्यवहार किया जाता है और साथ ही नवाचार के लिए मार्ग खुला रखते हुए वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। मैं विनियामकों के सामने आने वाली चुनौतियों के दो उदाहरण देना चाहूँगा।

(I) जलवायु जोखिम

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न केवल स्थिरता की ओर संक्रमण की आवश्यकता है, बल्कि जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों को विनियामक ढाँचे में एकीकृत करना भी आवश्यक है। दुनिया भर के विनियामक इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या जलवायु जोखिम के लिए एक अलग ढाँचा आवश्यक है या इसे मौजूदा जोखिम श्रेणियों में ही समाहित किया जाना चाहिए। इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि जलवायु जोखिम निगरानी को स्तंभ 2 (पर्यवेक्षी समीक्षा) का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, या स्तंभ 1 (पूँजी और चलनिधि आवश्यकताएँ) का। यह विषय मानक निर्धारण निकायों, उद्योग और अन्य हितधारकों का ध्यान आकर्षित करता रहता है। पर्यावरणीय प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए सही संतुलन बनाने की आवश्यकता है।[17]

[17] https://www.bis.org/review/r231115f.pdf

(II) उभरती प्रौद्योगिकियाँ

नई प्रौद्योगिकियाँ व्यवसाय को आसान बनाती हैं, परिचालन और अनुपालन लागत कम करती हैं, लेकिन साथ ही विनियमन के लिए चुनौतियाँ भी लाती हैं। इन प्रौद्योगिकियों के विनियमन में तीन मुख्य चुनौतियाँ हैं: (i) उभरती प्रौद्योगिकियों पर निर्भर व्यावसायिक मॉडलों की अप्रत्याशित प्रकृति, (ii) डेटा गोपनीयता, सुरक्षा, स्वामित्व और नियंत्रण, और (iii) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की जटिलता।[18] नए व्यावसायिक मॉडलों का एक उदाहरण है बैंकिंग-एज़-ए-सर्विस (बीएएएस) मॉडल है, जो वित्तीय उत्पादों के वितरण के पैमाने और गति को बढ़ाता है, लेकिन साथ ही वह व्यावसायिक संचलन के महत्वपूर्ण जोखिम भी पैदा कर सकता है। विनियामकों के सामने एक दुविधा है: क्या ऐसे वित्तीय नवाचारों के होने से पहले एक ढाँचा तैयार किया जाए या बाजारों को विकसित होने दिया जाए, जिससे अप्रत्याशित प्रणालीगत जोखिमों और उपभोक्ता शोषणकारी प्रथाओं का जोखिम बढ़ जाता है।[19] इसके अतिरिक्त, विनियामकों को प्रभावी विनियमन तैयार करने में क्षमता संबंधी बाधाओं और कानूनी जटिलताओं से निपटना होगा।

यहाँ भी, हमने इन उभरते तकनीकी क्षेत्रों में फिनटेक (उधार सेवा प्रदाताओं के रूप में) और विनियमित संस्थाओं (आरई) के बीच साझेदारी को शामिल करने वाले डिजिटल ऋण संबंधी दिशानिर्देश, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) की शुरुआत आदि जैसे विनियम बनाते समय सतर्क रुख अपनाया है। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एफआरईई-एआई) के उत्तरदायी और नैतिकतायुक्त सक्षमीकरण हेतु एक मजबूत, व्यापक और अनुकूलनीय ढाँचा विकसित करने हेतु एक समिति का गठन किया था[20] जिसने वित्तीय क्षेत्र में एआई को अपनाने के लिए एक सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

विनियामकीय बोझ कम करना और अनुपालन सुनिश्चित करना

हालाँकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है, अभी भी और सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है। विनियामकीय बोझ और अनुपालन लागत,

[18] https://digitalregulation.org/3004297-2/

[19] https://www.bis.org/review/r231115f.pdf

[20] https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=1306

विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए, खासकर छोटे विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए चुनौतियाँ पेश करते हैं। विनियामकों को न केवल विनियमित संस्थाओं (आरई) के बोझ और अनुपालन लागत को कम करने के लिए एक नाज़ुक संतुलन बनाने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इससे बाज़ारों के कुशल संचालन में बाधा न आए। रिज़र्व बैंक ने समय के साथ कुछ पहलों की शुरुआत की है जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा:

ए. अनुपालन बोझ को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 1999 में एक विनियामक समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) का गठन किया था, जिसके बाद 2021 में दूसरे आरआरए (आरआरए2.0) की स्थापना की गई। आरआरए2.0 के कारण कुल 1,673 परिपत्रों को वापस लिया गया या निरस्त किया गया, और 78 रिटर्न को समाप्त/ऑनलाइन रूपांतरित/विलय किया गया।

बी. नीति निर्माण और समीक्षा में आम जनता और हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने और इस प्रक्रिया को और अधिक परामर्शकारी बनाने के लिए आरबीआई की वेबसाइट पर 'कनेक्ट टू रेगुलेट' (Connect 2 regulate) प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया गया है।

सी. 'प्रवाह' (PRAVAAH) (विनियामक एप्लीकेशन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए प्लेटफ़ॉर्म) एक सुरक्षित और केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल है जिसके ज़रिए कोई भी व्यक्ति या संस्था रिज़र्व बैंक को भेजे गए किसी भी संदर्भ पर प्राधिकृतीकरण, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। इसका उद्देश्य विनियामक अनुमोदन प्रदान करने से संबंधित प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाना है।

डी. सहभागी और उत्तरदायी विनियमन निर्माण को औपचारिक रूप देने और पारदर्शिता बढ़ाने और परामर्शात्मक दृष्टिकोण के प्रति रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए 7 मई 2025 को विनियम निर्माण हेतु व्यापक ढाँचा जारी किया गया था। यह रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमों के प्रारूपण, संशोधन और समीक्षा के लिए व्यापक सिद्धांत निर्धारित करता है।

ई. रिज़र्व बैंक एक विनियामक समीक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने की प्रक्रिया में है जो हर पाँच से सात वर्षों में सभी विनियमों की समीक्षा करेगा।

डेटा, क्षमता और संसाधन की कमी

विनियामकों का ध्यान लगातार आकर्षित करने वाला एक और क्षेत्र है नई नीतियों को प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए लगने वाले सटीक डेटा का अभाव। वित्तीय प्रौद्योगिकियों के तेज़ी से विकास के कारण उत्पन्न डेटा की मात्रा में तेज़ी से वृद्धि हुई है, हालाँकि, ऐसी जानकारी की व्यापकता, विश्वसनीयता और सटीकता के संबंध में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। हालाँकि विनियामक स्वयं को नवीनतम उपकरणों और कौशल से लैस कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकताएँ जिस गति से विकसित हो रही हैं वह अविश्वसनीय है। इसके लिए विनियामकों के भीतर निरंतर क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

अंतर-विनियामक समन्वय

जैसा कि पहले बताया गया है, भारतीय वित्तीय क्षेत्र में विविधता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें विभिन्न संस्थाएँ शामिल हैं जो कई वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसआर) द्वारा अभिशासित हैं और प्रत्येक अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत संस्थाओं के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए सुसंगत नीति निर्माण को सुगम बनाने हेतु सुदृढ़ और प्रभावी अंतर-विनियामक समन्वय की आवश्यकता है। इस चुनौती का समाधान करने के लिए, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों (एफएसआर) द्वारा 'प्रमुख विनियामक' सिद्धांत के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत वित्तीय समूहों के लिए निगरानी हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत ऐसे वित्तीय समूहों के साथ संयुक्त पर्यवेक्षण और आवधिक द्विपक्षीय/बहुपक्षीय चर्चाएँ अपनाए गए कुछ उपाय हैं।

वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) और रिज़र्व बैंक गवर्नर की अध्यक्षता वाली इसकी उप-समिति, जिसमें सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं के प्रमुख

[21] प्रमुख प्रक्रियाओं में शामिल हैं: (क) विनियमन के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए एक मसौदा और विषय विवरण जारी करके सार्वजनिक परामर्श, (ख) प्रभाव विश्लेषण (जहाँ तक संभव हो), (ग) प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया का सामान्य विवरण जारी करना, और (घ) घोषित उद्देश्यों, प्राप्त अनुभव, परिवर्तित परिवेश में प्रासंगिकता और अनावश्यकता को कम करने की संभावना जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवधिक समीक्षा।

प्रतिनिधित्व करते हैं, वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से जोखिमों के संयुक्त मूल्यांकन के लिए एक मंच प्रदान करती है और उन मामलों में अंतर-विनियामक समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जहाँ वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बीच ओवरलैप होता है। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म भारत में वित्तीय क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए अंतर-विनियामक समन्वय को और मज़बूत करने में मदद करते हैं।

हालाँकि, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं, जैसे तकनीकी फर्मों और विनियमित संस्थाओं के बीच बढ़ती साझेदारी, जहाँ गतिविधियाँ किसी भी वित्तीय विनियामक प्राधिकरण (एफएसआर) के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो सकती हैं, जिससे विनियमित संस्थाओं को इन गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जोखिमों से निपटना कई बार विनियामकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है और इसके लिए अंतराराष्ट्रीय विनियामकों/पर्यवेक्षकों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता होती है ताकि वे किसी प्रणालीगत संकट का कारण न बनें। गुप्तता, गोपनीयता और प्रवर्तन से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए, यह विनियामकों के लिए एक जटिल क्षेत्र बना हुआ है।

आगे की राह

सिद्धांत और परिणाम-आधारित दृष्टिकोण

कोई भी विनियामक दृष्टिकोण आदर्श नहीं हो सकता, हालाँकि, सिद्धांत और परिणाम-आधारित विनियमन आमतौर पर परिपक्व बाजारों के लिए अधिक उपयुक्त पाया जाता है। फिर भी, विकसित अर्थव्यवस्थाएँ भी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नियम-आधारित ढाँचे का उपयोग करती हैं। हम, रिज़र्व बैंक के रूप में धीरे-धीरे सिद्धांत और परिणाम-आधारित विनियमों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह विनियमित संस्थाओं को अपने कार्यों के संचालन के लिए परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करते हैं और उनकी गतिविधियों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ढालते हैं, साथ ही उनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए विनियामक ढाँचे का पालन भी करते हैं।

दूरदर्शी और सक्रिय दृष्टिकोण

विनियामकों को अक्सर विनियम बनाते समय जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो जाता है। उभरते जोखिमों से निपटने के लिए लचीलापन सुनिश्चित करने हेतु सूक्ष्म और अनुकूलनीय रणनीतियों की आवश्यकता होती है। विनियामकों को एक ऐसी वित्तीय प्रणाली बनाने में मदद करने के लिए अधिक सक्रिय मानसिकता अपनानी चाहिए जो लचीली और अनुकूलनीय दोनों हो। सक्रिय होने का अर्थ है नवाचार को अपनाना और डेटा एवं प्रौद्योगिकी का पूर्ण लाभ उठाना। उन्हें अपनी आंतरिक और पर्यवेक्षी, दोनों तरह की दक्षता बढ़ाने, विनियामकीय जोखिम की समीक्षा करने और विनियामकीय प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का और अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता है। वित्तीय प्रणाली में हो रहे बदलावों से अवगत रहने के लिए विनियामकों को चाहिए कि वे तेज़ी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें और क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ सहयोग करें जो कि समय की मांग है।

विनियामकीय प्रभाव आकलन (आरआईए)

विनियामकीय प्रभाव आकलन (आरआईए) नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक साधन के रूप में तेजी से पहचाने जा रहे हैं, जो ऐसी नीतियों के निर्माण को सक्षम बनाते हैं जो साक्ष्यों पर आधारित हों, अपने उद्देश्य में स्पष्ट हों, डिज़ाइन में आनुपातिक हों और वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों के अनुकूल हों। ये साधन अनावश्यक अनुपालन बोझ और विनियामकीय कमियों से बचाव करते हुए, जनता का विश्वास बढ़ाते हुए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए संतुलन बनाने में उपयोगी हो सकते हैं। आरआईए के दो आवश्यक तत्व हैं: (i) विनियमों का लागत-लाभ विश्लेषण (कॉस्ट बेनिफिट), जिसका मूल्यांकन गुणात्मक या मात्रात्मक मापदंडों के माध्यम से या दोनों के मिश्रण के माध्यम से किया जा सकता है, और (ii) हितधारकों के व्यापक वर्ग के साथ परामर्श। इस दूसरे तत्व से पारदर्शिता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, और विनियमों की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में सुधार होता है, वहीं दूसरी ओर पहले वाले तत्व से संसाधनों का कुशल आवंटन सुनिश्चित करते हुए समस्या के समाधान हेतु इष्टतम समाधान निर्धारित करने में मदद मिलती है।

एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है विनियामक निर्देशों और रिपोर्टिंग तंत्रों की समयबद्ध समीक्षा करना ताकि उन्हें सुव्यवस्थित/तर्कसंगत बनाया जा सके और उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सके। ऐसी समयबद्ध समीक्षाएं न केवल अनुपालन आवश्यकताओं

को कम करती हैं, बल्कि विनियामकों को विकसित हो रही बाजार प्रथाओं और विकास के अनुरूप विनियमों की उपयुक्तता की समीक्षा करने का अवसर भी प्रदान करती हैं। विनियामकों को संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए और अनपेक्षित परिणामों से बचने के लिए पूर्वोपाय (ex-ante) और वास्तविक प्रभाव का आकलन करने और भविष्य के नियमों के डिजाइन को बेहतर बनाते हुए पाठ्यक्रम सुधार का समर्थन करने के लिए बाद के उपाय (ex-post) का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि कुल मिलाकर, यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनियमन "पहली बार में सही" हो और "समय के साथ सही बना रहे"।

अनुपालन में बेहतरी

विनियामकों को विनियमित संस्थाओं द्वारा अनुपालन बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि उनके लिए विनियमों का अनुपालन आसान हो सके। यह विनियमों को सरल बनाकर, उनकी स्पष्टता बढ़ाकर और अनावश्यकता व दोहराव को दूर करके किया जा सकता है। रिज़र्व बैंक विनियमों में स्पष्टता पर ज़ोर दे रहा है और विनियमित संस्थाओं के लाभ के लिए अपने विनियमों के एक भाग के रूप में उदाहरणों, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और दृष्टांतों को शामिल करना शुरू कर दिया है। विनियामक परिदृश्य का एक उच्च-स्तरीय अवलोकन प्रदान करने और विनियमित संस्थाओं की सामान्य समझ के लिए एक व्यापक संदर्भ बिंदु के रूप में सुविधा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने ‘एक नज़र में विनियम’[22] (रेग्यूलेशन्स एट ए ग्लांस) नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक विनियमन विभाग द्वारा जारी 8,000 से अधिक विनियमों को 30-35 विषयगत विषयों के अंतर्गत समेकित करने की प्रक्रिया में है। विनियामकों को विनियमित संस्थाओं की प्रतिक्रियाशीलता बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए ऐसी पहलों को जारी रखने की आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विनियामक सहयोग

संस्थाओं के अंतर-क्षेत्रीय संचालन को देखते हुए, वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसआर) के लिए अलग-थलग, क्षेत्र-विशिष्ट विनियमों से हटकर अंतर-कार्यात्मक सिद्धांत-आधारित विनियमों की ओर बढ़ना आवश्यक है। यह समन्वय नवाचार को बढ़ावा देगा और विनियमित संस्थाओं (आरई) को विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाएगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि उनके पास उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रोटोकॉल हों। इससे विनियामक मध्यस्थता को सीमित करने में भी मदद मिलेगी, साथ ही विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता से समझौता किए बिना अधिक कुशल विनियमन को सक्षम करने के लिए अंतर्दृष्टि, विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने हेतु विभिन्न क्षेत्राधिकारों के विनियामकों के बीच सहयोग आवश्यक है।[23] अंतरराष्ट्रीय मानक एक मूल्यवान संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करते हैं; हालाँकि, उन्हें स्थानीय संदर्भों और परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आज के विविध विनियामक परिदृश्य में ‘एक ही नियम सभी के लिए उपयुक्त’ दृष्टिकोण न तो व्यावहारिक है और न ही प्रभावी।

उपभोक्ता-केंद्रितता

हमें वित्तीय प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक, यानी उपभोक्ताओं पर विनियमनों के प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता है। विनियामक उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति सचेत रहे हैं। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें पारंपरिक दृष्टिकोणों से परे सोचना होगा। व्यवहारिक अर्थशास्त्र इस संबंध में एक शक्तिशाली साधन प्रदान करता है, जो उपभोक्ता व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह विनियामकों को नीतिगत साधनों के एक उन्नत समूह से सुसज्जित करता है, विशेष रूप से व्यवहारिक संकेत[24], जो बहुत कम अनुपालन लागत पर वांछित परिणाम प्राप्त करके पारंपरिक विनियामक ढाँचों का पूरक बन सकते हैं, और इस प्रकार एक अधिक कुशल और सामाजिक रूप से लाभकारी नीति विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।[25]

[22] https://rbi.org.in/Scripts/BS_Pआरईssआरईleasedisplay.aspx?prid=59862

[23] अंतरराष्ट्रीय विनियामक सहयोग – ओईसीडी द्वारा नीति वक्तव्य, अप्रैल 2020

[24] थैलर और सनस्टीन (2008, पृष्ठ 6) के अनुसार, एक आकस्मिकता (nudge) विकल्प संरचना का एक पहलू है जो लोगों के व्यवहार को बिना किसी विकल्प को प्रतिबंधित किए या उनके आर्थिक प्रोत्साहनों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए बिना, एक पूर्वानुमानित तरीके से बदलता है। केवल एक आकस्मिकता माने जाने के लिए ऐसा हस्तक्षेप आसान और सस्ते में टाला जाने योग्य होना चाहिए। आकस्मिकता अनिवार्य नहीं है।

[25] https://behaviouraleconomics.pmc.gov.au/blog/more-nudges-value-behavioural-economics-regulation

निष्कर्ष

विनियामक नीति को चाहिए कि वह वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता की महत्वपूर्ण आवश्यकता और नवाचार, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के बीच एक इष्टतम संतुलन बनाए। यद्यपि प्रणालीगत जोखिमों को कम करना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना आवश्यक है, लेकिन इससे रचनात्मकता, नवाचार या स्वस्थ बाजार गतिशीलता को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना नवाचार और प्रतिस्पर्धा पर अत्यधिक ज़ोर देने से वित्तीय अस्थिरता, संसाधनों का गलत आवंटन और अंततः व्यवस्था में विश्वास की कमी हो सकती है। अर्थव्यवस्था के विशाल आकार और विविधता, बढ़ती आकांक्षाओं और उच्च संवृद्धि एवं विकास को बनाए रखने के लिए पर्याप्त निवेश आवश्यकताओं को देखते हुए, यह सही संतुलन पाना भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विनियामकों को इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, “आप कभी नहीं जान सकते कि आपके कार्यों का क्या परिणाम होगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे, तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा।"

आपके साथ अपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। मैं सभी प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम में समृद्ध और सफल विचार-विमर्श की कामना करता हूँ।

वंजी से विकसित भारत तक: विश्वास, प्रौद्योगिकी और परिवर्तन पर बैंकिंग*

श्री स्वामीनाथन जे

करूर वैश्य बैंक परिवार - यहाँ उपस्थित चेयरपर्सन, बोर्ड के निदेशक-गण, शेयरधारक, एमडी सीईओ, कर्मचारीगण, अधिकारीगण, बैंक के ग्राहक और उनके परिवार-जन, देवियो और सज्जनो, अनिवरुक्कम वणक्कम। नमस्कारम। आप सभी का हार्दिक अभिवादन।

केवीबी के 109वें स्थापना दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर करूर में आपके साथ शामिल होना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। मैं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रमेश बाबू के इस स्नेहपूर्ण आमंत्रण के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

करूर एक ऐसा शहर है जहाँ इतिहास, वाणिज्य और चरित्र गहराई से जुड़े हुए हैं। संगम साहित्य में इसे ***'करुवूर'*** या ***'वंजी'*** के नाम से जाना जाता है—काव्य, व्यापार और शिल्पकला का एक समृद्ध केंद्र, जो प्रारंभिक चेर राजाओं की राजधानी रहा। उद्यमशीलता और सांस्कृतिक गौरव की यह भावना केवीबी जैसी संस्थाओं के माध्यम से जीवित है।

दूरदर्शिता के साथ स्थापना[1]

आज का दिन केवल बीते समय को याद करने के प्रतीकात्मक एक औपचारिक समारोह नहीं है। यह दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय का उत्सव है—यह उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि है जिन्होंने अनिश्चितता के बावजूद एक स्थायी संस्था का निर्माण करने का निर्णय लिया।

1916 में, जब प्रथम विश्व युद्ध के कारण व्यवधान और कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थीं, तब करूर के दो दूरदर्शी व्यक्ति, श्री एम.ए. वेंकटराम चेट्टियार और श्री अथी कृष्ण चेट्टियार एक साथ आए और विश्वास और सामुदायिक सेवा पर आधारित एक बैंक की स्थापना की।

संस्थापकों ने पूरे क्षेत्र में यात्रा की, कभी-कभी वे अमरावती नदी को डोली से पार कर ज़मींदारों और व्यापारियों से अपील करते थे और हिचकिचाते निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए अपनी व्यक्तिगत गारंटी देते थे। आर्बुथनॉट दुर्घटना[2] जैसी वित्तीय विफलताओं की यादें अभी भी ताज़ा थीं, और बैंकिंग में जनता का विश्वास कमज़ोर था। फिर भी, संस्थापकों की ईमानदारी और दृढ़ता ने जीत हासिल की। 22 जून 1916 को ₹1.20 लाख की चुकता पूँजी के साथ केवीबी का औपचारिक पंजीकरण हुआ, जो उनके मूल लक्ष्य से कहीं अधिक थी। संयोगवश, पहली शेयरधारक भगवती गायत्री देवी थीं, जो आज भी बैंक और उसके ग्राहकों पर अपना आशीर्वाद बनाए हुई हैं।

बैंक की संस्थापक टीम ने इसके ढांचे में दूरदर्शी सिद्धांतों को शामिल किया: उन्होंने स्वेच्छा से एक ऐसा प्रावधान शामिल किया जो निदेशकों को बैंक से ऋण लेने से रोकता था—एक सुरक्षा उपाय जो दशकों बाद बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ एक वैधानिक आवश्यकता बन गया। उन्होंने कर्मचारियों को शेयर आवंटित करके बैंक के भविष्य में कर्मचारियों की भागीदारी की भी परिकल्पना की—स्टॉक विकल्पों के विचार के प्रचलन में आने से बहुत पहले। प्रत्येक प्रबंधक के पास 50 शेयर, अधिकारियों के पास 20 शेयर और कैशियर को, उनकी प्रमुख भूमिका को दर्शाते हुए, 40 शेयर आवंटित किए जाने थे।

जो कार्य उन्होंने विवेक और उद्देश्य के साथ शुरू किया था, वह आज ₹1.86 लाख करोड़ के संस्थान के रूप में विकसित हो चुका है, जो उनके मूल्यों, दूरदर्शिता और सामुदायिक उद्यम में अटूट विश्वास का प्रमाण है।

---

* शुक्रवार को करूर वैश्य बैंक के 109वें स्थापना दिवस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. का संबोधन.

[1] श्रीराम, वी, करूर वैश्य बैंक, शताब्दी पुस्तक, https://www.kvb.co.in/docs/kvb-history-book-part1.pdf (20 जुलाई 2025 को एक्सैस किया गया) से सामग्री पर आधारित।

[2] 1906 की आर्बुथनॉट दुर्घटना औपनिवेशिक भारत की सबसे कुख्यात बैंकिंग विफलताओं में से एक थी। मद्रास स्थित एक प्रमुख ब्रिटिश फ़र्म, आर्बुथनॉट एंड कंपनी का अव्यवहार्य कुप्रबंधन के कारण पतन हो गया, जिससे व्यापक रूप से अफरा-तफरी मच गई। पेंशनभोगियों और अधिकारियों, यहाँ तक कि मद्रास के गवर्नर सहित हजारों जमाकर्ताओं ने अपनी बचत गँवा दी। इस घटना ने विदेशी बैंकों में विश्वास को बुरी तरह से कम कर दिया और 1907 में इंडियन बैंक की स्थापना को प्रेरित किया।

विकसित भारत के लिए बैंकिंग: उद्देश्य और तत्परता के साथ अनुकूलन

केवीबी का 109वां वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापक वित्तीय प्रणाली में व्यापक परिवर्तन के दौर में आ रहा है। जैसे-जैसे राष्ट्र विकसित भारत 2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है, बैंकों से न केवल ऋण का विस्तार करने, बल्कि समावेशी विकास को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और ज़िम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देने में एक गहन भूमिका निभाने का भी आह्वान किया जा रहा है ।

मुझे यकीन है कि केवीबी ने इस दिशा में पहले ही सार्थक कदम उठा लिए हैं। लेकिन आगे की यात्रा और भी अधिक तत्परता, दूरदर्शिता और उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की मांग करेगी।

केवीबी जैसे बैंक किस प्रकार आगे का रास्ता तय कर सकते हैं, इस बारे में सोचते हुए मुझे तिरुक्कुरल की एक पंक्ति याद आती है, जो विचारशील कार्रवाई के लिए शाश्वत मार्गदर्शन का खजाना है:

"பொருள் கருவி காலம் வினை-யிடனொடு
ஐந்தும் இருள்தீர எண்ணிச் செயல்"

(Poruḷ karuvi kāalam viṉai-yiṭaṉodu aindhum
iruḷtheera eṇṇi cheyal)

शाब्दिक अर्थ[3]:

"धन, साधन, समय, निष्पादन और स्थान- इन पाँच बातों पर उचित विचार करने के बाद ही कोई कार्य करें।"

संत तिरुवल्लुवर हमें बताते हैं: "बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी अनिश्चितता को दूर करने और स्पष्टता के साथ कार्य करने के लिए पांच चीजों - संसाधन, उपकरण, समय, कार्य और स्थान या संदर्भ - पर विचार करने के बाद ही कार्य करता है।"

मेरे विचार से, यह केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं है—यह एक व्यावहारिक ढाँचा है, जो आधुनिक बैंकिंग के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इन पाँच तत्वों ने केवीबी की अब तक की यात्रा को आकार दिया है, और ये इसके भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। तो आइए हम इनमें से प्रत्येक पर विचार करें—दर्शन के रूप में नहीं, बल्कि एक मज़बूत, चुस्त और जिम्मेदार बैंकिंग संस्थान की आधारशिला के रूप में।

पोरुल (धन/संसाधन): अनुशासन के साथ शक्ति का प्रयोग

बैंकिंग में, संसाधन केवल वित्तीय पूँजी नहीं हैं। वे इससे कहीं ऊपर हैं। इनमें लोग, प्रणालियाँ, संस्थागत स्मृति, ग्राहक विश्वास और प्रतिष्ठा शामिल हैं। सुदृढ़ संसाधन प्रबंधन का तात्पर्य निर्णयों की गुणवत्ता और परिणामों की स्थिरता से है।

विनियामकीय सीमाओं को पूरा करना या प्रमुख आंकड़ों में सुधार करना ही पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इन वित्तीय संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है—चाहे वे समावेशी ऋण, दीर्घकालिक निवेश, या विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले व्यावसायिक मॉडल का समर्थन करते हों। प्रत्येक रुपये में केवल ब्याज नहीं, बल्कि उद्देश्य भी होना चाहिए।

उतने ही महत्वपूर्ण वे कम मूर्त, लेकिन कम आवश्यक नहीं, संसाधन हैं जो बैलेंस शीट में शामिल नहीं होते। इनमें वे लोग शामिल हैं जो हर दिन ग्राहकों से जुड़ते हैं, आंतरिक नियंत्रण जो निर्णय लेते हैं और जोखिम प्रबंधन करते हैं, और संस्थागत मूल्य जो आंतरिक संस्कृति को आकार देते हैं।

एक बार स्थापित हो जाने पर, किसी बैंक की प्रतिष्ठा उसकी सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक बन जाती है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बदलती ग्राहक अपेक्षाओं के माहौल में, आगे बढ़ने का रास्ता ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में निहित है जो विश्वास, निष्ठा और दीर्घकालिक मूल्य को बढ़ावा देता है।

करुवी (उपकरण/साधन): ज़िम्मेदार नवाचार के साथ आगे बढ़ना

बैंकिंग के उपकरण तेज़ी से विकसित हुए हैं—पासबुक और लेज़र से लेकर कोर बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म, मोबाइल ऐप, रियल-टाइम भुगतान प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक।

[3] तिरुकुरल 675: रेव्ह डॉ. जी. यू. पोप, रेव्ह डब्ल्यू. एच. डू, रेव्ह जॉन लाज़रस और श्री एफ. डब्ल्यू. एलिस द्वारा अंग्रेजी अनुवाद और व्याख्या। प्रोजेक्ट मदुरै पर उपलब्ध। https://www.projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0153.html

ये उपकरण यह निर्धारित करते हैं कि सेवाएँ कैसे प्रदान की जाती हैं, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, और धीरे-धीरे, जोखिमों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। इस परिवेश में, किसी बैंक की तकनीकी क्षमताएँ अब केवल परिचालन संबंधी सहायक नहीं रह गई हैं; वे रणनीतिक विभेदक बन गई हैं।

हालाँकि, हर उपकरण ज़िम्मेदारी के साथ आता है। डिजिटल अपनाने की गति और पैमाने के साथ-साथ साइबर सुरक्षा, डेटा गवर्नेंस और नैतिक सुरक्षा उपायों में भी उतना ही मज़बूत निवेश ज़रूरी है। हाल के वैश्विक और घरेलू अनुभवों ने दिखाया है कि अगर समय रहते तकनीकी कमियों को दूर नहीं किया गया, तो वे प्रणालीगत कमजोरियों का कारण बन सकती हैं।

जिम्मेदारी से विस्तार करने की चाह रखने वाले बैंकों के लिए, उपकरण आधुनिक, चुस्त और निरंतर विकसित होने वाले होने चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका प्रबंधन सुचारु होना चाहिए। तकनीक को कभी भी संगठन की प्रबंधन क्षमता से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन को इस संवाद का नेतृत्व करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जोखिम, अनुपालन और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों में गति बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन और दृश्यता उपलब्ध हो।

कालम (समय): यह जानना कि कब कार्य करना है

बैंकिंग में, समय का सही होना सफलता और छूटे हुए अवसर के बीच, लचीलेपन और पछतावे के बीच का अंतर हो सकता है। चाहे ऋण देना हो, नए बाज़ारों में प्रवेश करना हो, या पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करना हो, सही समय पर और सही निर्णय लेने की क्षमता जरूरी है।

समय का सही आकलन करने के लिए संदर्भगत जागरूकता की भी आवश्यकता होती है। आर्थिक चक्र, ब्याज दरों में बदलाव, नियामक परिवर्तन, भू-राजनीतिक घटनाक्रम और यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन—ये सभी इस बात को प्रभावित करते हैं कि निर्णय कब और कैसे लिए जाने चाहिए। किसी तनाव को जल्दी पहचानने में देरी, या बाज़ार के संकेतों पर जल्दबाज़ी में प्रतिक्रिया देने के दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।

लेकिन समय का मतलब सिर्फ़ बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि किसी संस्था को कब आंतरिक रूप से बदलने की जरूरत है—कब प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना है, कब नेतृत्व को नया रूप देना है, कब रुकना और समेकित करना है, और कब आगे बढ़ने के लिए साहसिक कदम उठाने हैं। इतिहास उन संस्थाओं को पुरस्कृत करता है जो जल्दी काम करती हैं, न कि उन्हें जो उत्तम काम करती हैं।

केवीबी के संस्थापकों ने ऐसे ही क्षण में कदम उठाया। युद्ध और आर्थिक अनिश्चितता के बीच, 1916 में बैंक स्थापित करने का उनका निर्णय साहसिक, सामयिक और सामुदायिक जरूरतों के अनुरूप था। समय और संवेदनशीलता की यही समझ अब बैंक को अपने अगले चरण में मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

विनय (कार्य/निष्पादन): विचार को क्रियान्वयन में परिवर्तित करना - बोर्डरूम से शाखा तक

रणनीति का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि उसे अमल में न लाया जाए। एक बैंक के लिए, इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि शीर्ष स्तर के इरादे ज़मीनी स्तर पर नतीजों में दिखाई दें। बोर्डरूम में बनाई गई नीतियों को शाखा में सार्थक अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। सबसे मज़बूत ढाँचे—चाहे वे जोखिम, ऋण, तकनीक या अनुपालन से संबंधित हों—तभी प्रभावी होते हैं जब ग्राहक इंटरफ़ेस पर उनका क्रियान्वयन होता है।

प्रभावी कार्रवाई के लिए स्पष्टता, समन्वय और जवाबदेही ज़रूरी है। चाहे कोई नया उत्पाद लॉन्च करना हो, किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करना हो, या अनुपालन सुधार लागू करना हो, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लक्ष्यों को कितनी अच्छी तरह से संप्रेषित किया जाता है, भूमिकाएँ कितने स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाती हैं, और परिणामों पर कैसे नज़र रखी जाती है।

हालाँकि, तीव्र प्रतिस्पर्धी दबावों और अल्पकालिक सफलता की चाहत से प्रेरित होकर, कुछ बैंकों और एनबीएफसी के प्रबंधन का मानना है कि साध्य साधन को उचित ठहराता है। रचनात्मक लेखांकन, विनियमों की उदार व्याख्या, सौम्य नीतिगत ढाँचे और अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण जैसी प्रथाएँ कुछ बोर्डरूम में सामान्य हो रही हैं—जिसके लिए पर्यवेक्षी हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। हालाँकि ऐसे उदाहरण सीमित हो सकते हैं, लेकिन इनसे बैंकिंग प्रणाली की अखंडता में जनता का विश्वास कम होने का खतरा है।

इसलिए, बोर्डरूम से लेकर शाखा तक—ऐसी प्रणालियों, लोगों और प्रक्रियाओं के साथ विकास को आगे बढ़ाना ज़रूरी है जो नैतिक प्रथाओं के अनुरूप हों और नैतिकता उनमें निहित हो।

इदान / इदाम (संदर्भ/स्थान): प्रदेश को समझना

प्रत्येक संस्था एक व्यापक परिवेश में कार्य करती है—आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और भौगोलिक। सबसे अधिक लचीले बैंक वे होते हैं जो अपने संदर्भ के प्रति गहराई से जागरूक रहते हैं और लगातार उसके अनुकूल ढलते रहते हैं।

केवीबी को लंबे समय से अपनी सामुदायिक जड़ों से ताकत मिलती रही है। अर्ध-शहरी और ग्रामीण बाजारों के प्रति इसके रुझान और स्थानीय व्यवसायों व परिवारों की जरूरतों से इसके गहरे जुड़ाव ने इसकी पहचान और ग्राहक संबंधों को आकार दिया है।

हालाँकि, संदर्भ कभी स्थिर नहीं रहता। बदलती जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, डिजिटल पहुँच, प्रवासन पैटर्न और क्षेत्रीय बदलाव लगातार परिचालन परिवेश को नया रूप दे रहे हैं। जैसे-जैसे भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, बैंकों से लगातार अनुकूलन करने का आह्वान किया जाएगा—ताकि वे अधिक आकांक्षी, मोबाइल और डिजिटल रूप से जुड़ी आबादी को सेवा प्रदान कर सकें।

भौगोलिक संकेंद्रण सुपरिचय ला सकता है, लेकिन यह जोखिम भी लाता है। क्षेत्रीय मंदी और नीतिगत बदलाव संकेंद्रित पोर्टफोलियो को और तीव्रता से प्रभावित कर सकते हैं। बैंकों को लगातार यह आकलन करना चाहिए कि क्या उनका शाखा नेटवर्क, सेक्ट्रल मिक्स और ऋण जोखिम उनके आसपास की उभरती वास्तविकताओं के अनुरूप हैं।

नये बाजारों या उत्पाद खंडों में विस्तार से आशा की किरण जगती है, लेकिन इसके लिए लोगों, प्रक्रियाओं और स्थानीय ज्ञान के संदर्भ में क्षमता निर्माण की भी आवश्यकता होती है।

सबसे प्रभावी बैंक वे होते हैं जो न केवल अपनी खूबियों को समझते हैं, बल्कि उस क्षेत्र को भी समझते हैं जिसमें वे काम करते हैं। केवीबी जैसे समृद्ध विरासत और परंपरा वाले बैंक के लिए, व्यापक विविधीकरण के साथ गहन स्थानीय अंतर्दृष्टि को संतुलित करने की क्षमता, विकास के अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस गतिशील परिवेश में, नवाचार और अनुकूलनशीलता को अपनाते हुए अपनी सामुदायिक जड़ों के प्रति समर्पित रहना ही वास्तव में "स्मार्ट वे टू बैंक"[4] को परिभाषित करेगा।

निष्कर्ष: आगे की राह के लिए अंतिम विचार

अंत में, मैं तिरुक्कुरल के उन शब्दों पर लौटता हूँ जिन्होंने आज मेरे विचारों को दिशा दी। ये हमें याद दिलाते हैं कि स्थायी सफलता संयोग या पैमाने पर नहीं, बल्कि सावधानीपूर्वक विचार और सुविचारित कार्यों पर आधारित होती है। संसाधनों का उपयोग अनुशासन के साथ किया जाना चाहिए। उपकरण आधुनिक और सुव्यवस्थित होने चाहिए। समय का निर्धारण जागरूकता से होना चाहिए। कार्य को उद्देश्य को परिणाम में बदलना चाहिए। और हर कदम पर संदर्भ को निर्णय लेने का मार्गदर्शन करना चाहिए।

आज अपने संबोधन में, मैंने अपने 37 वर्षों के अनुभव को—एक बैंकर के रूप में और हाल ही में, एक बैंकिंग पर्यवेक्षक के रूप में—विवेकशील तिरुवल्लुवर द्वारा प्रदान किए गए शाश्वत ढाँचे में समेटने का प्रयास किया है। उनके शब्द न केवल व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, बल्कि संस्थागत उद्देश्य की भी बात करते हैं।

अपनी स्थापना के बाद से 109 वर्षों में, केवीबी ने इन सिद्धांतों का कई तरीकों से—शांतिपूर्वक, दृढ़तापूर्वक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से—सम्मान किया है। लेकिन आगे का रास्ता अधिक जटिल, अधिक प्रतिस्पर्धी और अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। इस परिवेश में नेतृत्व करने वाली संस्थाएँ वे नहीं होंगी जो सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी, बल्कि वे होंगी जो स्पष्टता, साहस और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगी।

रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण से, हम उम्मीद करते हैं कि केवीबी जैसे बैंक निरंतर विकास करते रहेंगे—अभिशासन और ग्राहक सेवा में मानक स्थापित करते रहेंगे, अपने आश्वासन कार्यों को सशक्त बनाते रहेंगे, और तकनीक का उपयोग न केवल दक्षता के

[4] "स्मार्ट वे टू बैंक" करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन है।

लिए, बल्कि समावेशन के लिए भी करते रहेंगे। प्रत्येक बैंक बोर्ड और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है कि वे उत्तरदायी सेवा, विश्वसनीय प्रणालियाँ और ज़िम्मेदार नेतृत्व के माध्यम से कड़ी मेहनत कर अर्जित विश्वास को और गहरा बनाएँ।

इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर पूरे केवीबी परिवार—पूर्व और वर्तमान—को मेरी हार्दिक बधाई। भविष्य का निर्माण विवेकपूर्ण नवाचार, ज़िम्मेदारी के साथ विकास और अखंडता के साथ नेतृत्व पर हो।

नंद्री। धन्यवाद और शुभकामनाएँ। जय हिंद!!

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

निजी कॉरपोरेट निवेश: 2024-25 में वृद्धि और 2025-26 का परिदृश्य

भारत के बचत परिदृश्य में बदलाव लाते इक्विटी म्यूचुअल फंड

ईवी नीतियां और दोपहिया ईवी अपनाना: भारतीय राज्यों से साक्ष्य

बागवानी विविधीकरण: कृषि सुदृढ़ता की ओर एक मार्ग

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

अमेरिकी व्यापार नीतियों पर जारी अनिश्चितता ने जुलाई और अगस्त के दौरान वैश्विक समष्टि-आर्थिक परिदृश्य को आकार दिया। जुलाई में घरेलू आर्थिक गतिविधियाँ सभी क्षेत्रों में मिश्रित रहीं। समय पर मानसून की प्रगति ने खरीफ की बुवाई को बढ़ावा दिया है। औद्योगिक गतिविधियाँ धीमी रहीं, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार हुआ और सेवा क्षेत्र ने विकास की गति को बनाए रखा। जुलाई में लगातार नौवें महीने हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई। घरेलू आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय स्थितियाँ अनुकूल और सहायक रहीं। एसएंडपी द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार भविष्य में पूंजी प्रवाह और सॉवरेन प्रतिफल के लिए शुभ संकेत है।

परिचय

अमेरिकी व्यापार नीतियों पर जारी अनिश्चितता ने जुलाई और अगस्त के दौरान वैश्विक व्यापक आर्थिक परिदृश्य को आकार दिया। यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और जापान ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते किए हैं, जबकि अगस्त में ब्राज़ील, कनाडा, भारत और स्विट्ज़रलैंड पर और भी ज़्यादा शुल्क लगाए गए। अपने जुलाई 2025 के विश्व आर्थिक परिदृश्य (डबल्यूईओ) अपडेट में, आईएमएफ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वैश्विक विकास अनुमानों में वृद्धि के बावजूद, वैश्विक विकास परिदृश्य के लिए जोखिम ऋणात्मक दिशा में प्रबल है।

वैश्विक विनिर्माण गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतक जुलाई में संकुचन के दौर में लौट आए। नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विश्व व्यापार की मात्रा में भी कमी आई। फिर भी, सेवा क्षेत्र के मज़बूत विस्तार से समर्थित वैश्विक आर्थिक गतिविधियाँ स्थिर रहीं। अनिश्चित माँग स्थितियों को दर्शाते हुए, औद्योगिक धातुओं की कीमतें धीमी रहीं, भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और ओपेक प्लस द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के निर्णय के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति स्थिर रही, जिसके कारण कई केंद्रीय बैंकों ने जुलाई में नीतिगत दरों पर रोक लगा दी। इसके बाद अगस्त में, विकास संबंधी चिंताओं के कारण कुछ केंद्रीय बैंकों ने अपनी नीतिगत दरें कम कर दीं।

वैश्विक शेयर बाजारों में अलग-अलग रुझान देखने को मिले। अमेरिका और चीन के शेयर बाजारों में तेजी अगस्त में भी जारी रही। अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों के बाद जापानी शेयर सूचकांकों में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया, जबकि यूरोप के शेयर सूचकांक सीमित दायरे में रहे। राजकोषीय ऋण संबंधी चिंताओं के कारण जुलाई में अमेरिकी खजाना प्रतिफल में बढ़ोतरी हुई। अगस्त में अब तक, कमजोर रोजगार आंकड़ों, अपेक्षा से कम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति, थोक मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि और फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की जुलाई बैठक के विवरण जारी होने के कारण प्रतिफल में दोतरफा बदलाव देखा गया है।

घरेलू आर्थिक गतिविधि के विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतकों ने जुलाई में मिश्रित रुझान दिखाया, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ई-वे बिल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए और जीएसटी संग्रह में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन बिजली की मांग कम रही। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में सुदृढ़ता जारी रही। दक्षिण-पश्चिम मानसून की समय पर प्रगति ने खरीफ की बुवाई को बढ़ावा देने में मदद की है। जून में औद्योगिक गतिविधि धीमी रही, जिसमें खनन और बिजली शामिल थी। विनिर्माण और सेवा गतिविधि के प्रमुख संकेतकों ने जुलाई में निरंतर विस्तार दिखाया। गैर-तेल घाटा स्थिर रहने के साथ उच्च तेल घाटे के कारण जुलाई 2025 में पण्य व्यापार घाटा बढ़ गया। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

जुलाई में लगातार नौवें महीने हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई और यह जून 2017 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई, क्योंकि खाद्य पदार्थों में अपस्फीति

* यह लेख रेखा मिश्र, आशीष थॉमस जॉर्ज, शशि कांत, रजनी दहिया, बिश्वजीत मोहंती, श्रेया कंसल, दुर्गा जी, आस्था, यामिनी झांब, हरेंद्र कुमार बेहरा, अर्जित शिवहरे, हर्षिता यादव, देबप्रिया साहा, राधिका सिंह, साक्षी चौहान, सत्येन्द्र कुमार, सार्थक गुलाटी, प्रतिभा केडिया, पारस, निलावा दास, आरती सिन्हा, हरि प्रसाद ई, राजेश कावेड़िया, पुलस्त्य बंद्योपाध्याय, अमित पवार, युवराज कश्यप, मोनिका, दिलप्रीत शर्मा, खुशी सिन्हा और समृद्धि द्वारा तैयार किया गया है। डिप्टी गवर्नर डॉ. पूनम गुप्ता द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और टिप्पणियों को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है। जी. वी. नथनएल, बिनोद बिहारी भोई और सौम्या सुब्रा भादुड़ी की सहकर्मी समीक्षा को भी स्वीकार किया गया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

बढ़ी और कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई) में कमी आई। सब्जियों की कीमतों में गिरावट, कीमतों में मंद मौसमी वृद्धि और अनुकूल आधार प्रभावों के कारण, खाद्य कीमतों की गतिशीलता को प्रभावित कर रही थी। मांस और मछली, दालें और मसालों जैसे अन्य खाद्य उपसमूहों में अपस्फीति जारी रही और अनाज की मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। कोर मुद्रास्फीति में नरमी सेवा घटक में तीव्र गिरावट के कारण आई।

जुलाई और अगस्त (21 अगस्त तक) के दौरान कुल मिलाकर वित्तीय स्थितियाँ अनुकूल रहीं। अतिरिक्त चलनिधि के कारण, भारित औसत मांग दर – मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य – गलियारे के निचले आधे हिस्से में गतिशील रही। मुद्रा बाजार में एक दिवसीय दरें भारित औसत मांग दर के अनुरूप चलीं। नियत आय खंड में, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता और उसके बाद अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने को लेकर अनिश्चितताओं के बीच, जुलाई के मध्य से अगस्त के प्रारंभ तक 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में वृद्धि हुई। 14 अगस्त, 2025 तक भारत की सॉवरेन रेटिंग में एसएंडपी द्वारा किए गए उन्नयन से थोड़ी राहत मिली।[1] इसके बाद, अगस्त के तीसरे सप्ताह के दौरान प्रतिफल में वृद्धि हुई।

ऋण के मामले में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए ऋण में वृद्धि के कारण, जून 2025 में बैंक ऋण वृद्धि में मामूली सुधार हुआ। वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों के कुल प्रवाह में वृद्धि दर्ज की गई। बड़ी कंपनियों ने अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं को वाणिज्यिक पत्र और कॉरपोरेट बॉण्ड जैसे बाजार-आधारित साधनों के माध्यम से पूरा किया।

अगस्त की शुरुआत में कॉरपोरेट आय में गिरावट और भारतीय निर्यात पर अमेरिका द्वारा आयात शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा के कारण घरेलू शेयर बाजारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन उसके बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार और जीएसटी सुधारों की घोषणा को लेकर आशावाद के बीच इनमें तेजी आई। घरेलू संस्थागत निवेशकों, खासकर म्यूचुअल फंडों से लगातार निवेश ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की निवल बिकवाली के प्रभाव को कम करने में मदद की।

जून में सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। फिर भी, एफडीआई के प्रत्यावर्तन और बाह्य एफडीआई दोनों में वृद्धि के कारण निवल एफडीआई अंतर्वाह धीमा रहा। भारत का बाह्य क्षेत्र मामूली चालू खाता घाटे और 11 महीनों के आयात को कवर करने वाले विदेशी मुद्रा भंडार के साथ सुदृढ़ बना रहा। एसएंडपी द्वारा भारत के लिए सॉवरेन रेटिंग में सुधार – जो कि तेज आर्थिक वृद्धि, बढ़ी हुई मौद्रिक नीति विश्वसनीयता और राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर आधारित है – भविष्य में उधारी लागत में कमी, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और विदेशी पूंजी प्रवाह में वृद्धि का कारण बन सकता है।

इस पृष्ठभूमि में, लेख का शेष भाग चार खंडों में विभाजित है। खंड II वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेज़ी से विकसित हो रहे घटनाक्रमों को समाहित करता है। खंड III घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन प्रस्तुत करता है। खंड IV भारत की वित्तीय स्थितियों का सार प्रस्तुत करता है, जबकि खंड V में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

II. वैश्विक स्थिति

जुलाई में, वैश्विक समष्टि आर्थिक परिवेश मुख्यतः व्यापार शुल्क घोषणाओं और कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों से संबंधित अमेरिकी आयात शुल्क दरों पर जारी अनिश्चितताओं से प्रभावित हुआ। जहाँ यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और जापान ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते किए हैं, वहीं अगस्त में ब्राज़ील, कनाडा, भारत और स्विट्ज़रलैंड पर और भी ज़्यादा टैरिफ लगाए गए (चार्ट II.1)।

विश्व आर्थिक परिदृश्य (डबल्यूईओ) के जुलाई 2025 के अपने अपडेट में, आईएमएफ ने 2025 और 2026 के लिए अपने वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के पूर्वानुमानों को

[1] एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक निम्नतर सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'बीबीबी-' से बढ़ाकर 'बीबीबी' कर दिया है, जबकि अल्पकालिक रेटिंग को 'ए-3' से बढ़ाकर 'ए-2' कर दिया है।

चार्ट II.1: अमेरिका द्वारा घोषित नए टैरिफ

(प्रतिशत में)

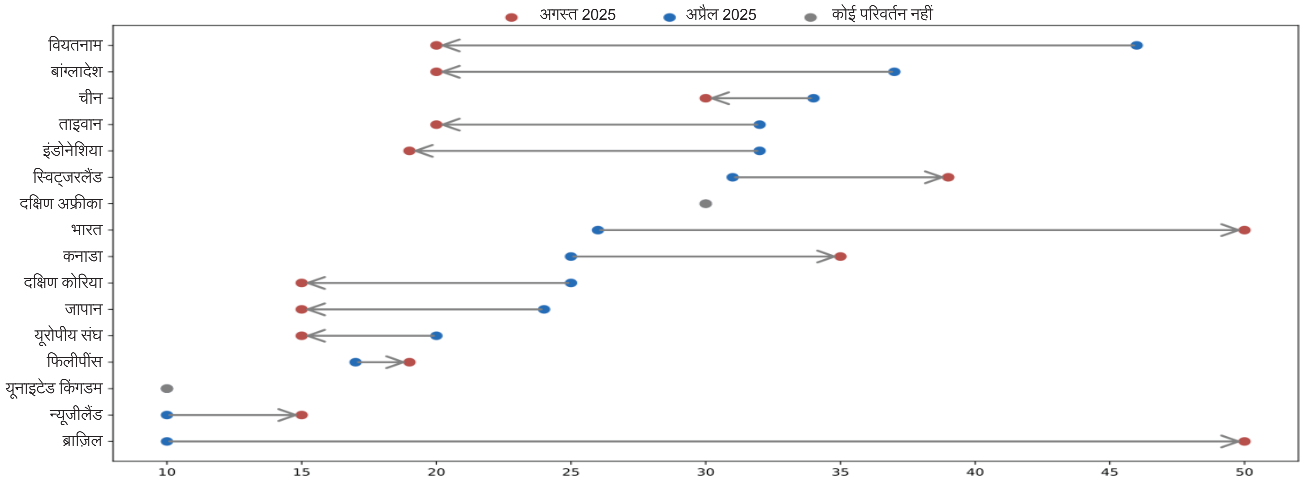

टिप्पणी: 1. इन देशों की रैंकिंग 02 अप्रैल, 2025 को अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के क्रम में दर्शाई गई है।
2. अगस्त के टैरिफ में अमेरिका द्वारा आयात टैरिफ की घोषणा के साथ-साथ व्यापार सौदों के बाद लगाए गए नए टैरिफ भी शामिल हैं।
स्रोत: व्हाइट हाउस और रॉयटर्स।

अपने अप्रैल के अनुमानों की तुलना में ऊपर की ओर संशोधित किया है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरो क्षेत्र के नेतृत्व में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के लिए वृद्धि पूर्वानुमानों में 0.1 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की गई, जबकि उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) की वृद्धि को 0.4 प्रतिशत अंकों से ऊपर की ओर संशोधित किया गया, जो चीन और भारत के लिए मजबूत अनुमानों से प्रेरित था (सारणी II.1)। अमेरिकी व्यापार नीति के रुख पर बनी अनिश्चितताओं को देखते हुए, वैश्विक विकास परिदृश्य के लिए जोखिमों का संतुलन नीचे की ओर झुका हुआ माना गया।

अमेरिकी टैरिफ संबंधी अनिश्चितता और भू-राजनीतिक दबावों के कारण जुलाई में वैश्विक अनिश्चितता बनी रही। अमेरिका में आर्थिक और व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक अप्रैल के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से नीचे आ गए हैं, लेकिन गिरावट की गति कुछ धीमी हुई है।[2] जुलाई के अंत में उन्नत

[2] आर्थिक नीति अनिश्चितता (ईपीयू) सूचकांक भविष्य की आर्थिक नीतियों से जुड़ी अनिश्चितता के स्तर को मापता है, जो प्रमुख समाचार पत्रों के लेखों में "अर्थव्यवस्था", "नीति" और "अनिश्चितता" जैसे विशिष्ट कीवर्ड की आवृत्ति से प्राप्त होता है। व्यापार नीति अनिश्चितता सूचकांक सरकारी व्यापार नीति निर्णयों की अप्रत्याशितता को मापता है। विश्व अनिश्चितता सूचकांक (डब्ल्यूयूआई) की गणना इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की विभिन्न देशों की रिपोर्टों में "अनिश्चित" (या इसके विभिन्न रूप) शब्द के प्रतिशत की गणना करके की जाती है।

सारणी II.1: आईएमएफ के जीडीपी वृद्धि अनुमान - चुनिंदा एई और ईएमडीई

अनुमान	2025		2026	
अनुमान का महीना	जुलाई 2025	अप्रैल 2025	जुलाई 2025	अप्रैल 2025
विश्व	**3.0**	**2.8**	**3.1**	**3.0**
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ	**1.5**	**1.4**	**1.6**	**1.5**
यूएस	1.9	1.8	2.0	1.7
यूके	1.2	1.1	1.4	1.4
यूरो क्षेत्र	1.0	0.8	1.2	1.2
जापान	0.7	0.6	0.5	0.6
उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ	**4.1**	**3.7**	**4.0**	**3.9**
उभरता हुआ और विकासशील यूरोप	*1.8*	*2.1*	*2.2*	*2.1*
रूस	0.9	1.5	1.0	0.9
उभरता हुआ और विकासशील एशिया	*5.1*	*4.5*	*4.7*	*4.6*
भारत#	6.4	6.2	6.4	6.3
चीन	4.8	4.0	4.2	4.0
लैटिन अमेरिका और कैरेबियन	*2.2*	*2.0*	*2.4*	*2.4*
मेक्सिको	0.2	–0.3	1.4	1.4
ब्राजील	2.3	2.0	2.1	2.0
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका	*3.2*	*2.6*	*3.4*	*3.4*
उप -सहारा अफ्रीका	4.0	3.8	4.3	4.2
दक्षिण अफ्रीका	1.0	1.0	1.3	1.3

टिप्पणी: #: भारत का डेटा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के आधार पर है, जबकि अन्य सभी देशों के लिए यह कैलेंडर वर्षों के आधार पर है।
स्रोत: आईएमएफ का विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट, जुलाई 2025।

चार्ट II.2: वैश्विक अनिश्चितता संकेतक

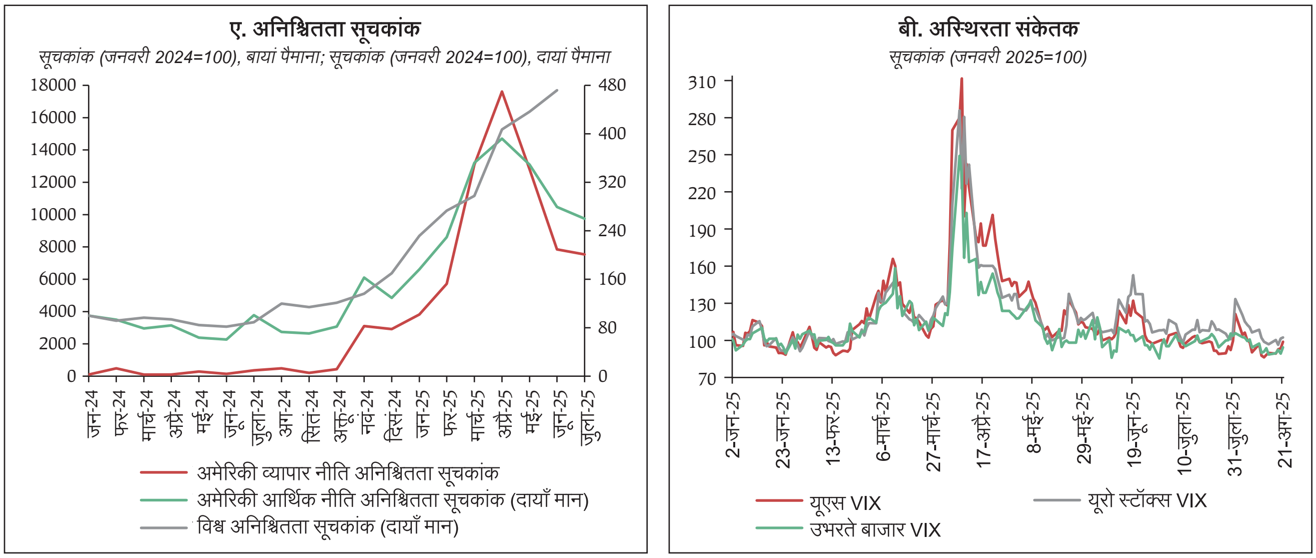

स्रोत: ब्लूमबर्ग: www.PolicyUncertainty.com; और विश्व अनिश्चितता सूचकांक डेटाबेस।

अर्थव्यवस्थाओं में कुछ अस्थायी वृद्धि के बावजूद, अगस्त में वित्तीय बाजार में अस्थिरता कम हुई, जो बाजार की बेहतर धारणा को दर्शाता है (चार्ट II.2ए और II.2बी)।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) जुलाई में सात महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, जो उत्पादन और नए कारोबार में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से सेवाओं में विस्तार के कारण हुआ, इस क्षेत्र का पीएमआई दिसंबर 2024 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई संकुचनकारी हो गया, जो उत्पादन में गिरावट का संकेत देता है क्योंकि उच्च टैरिफ की आशंका में उत्पादन में अग्रिम वृद्धि का प्रभाव कम हो गया और कंपनियाँ व्यापार नीतियों पर स्पष्टता की प्रतीक्षा करती रहीं हैं (सारणी II.2)।

जुलाई में पीएमआई रीडिंग प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उन्नत विनिर्माण उद्यमों (ईएमडीई) के लिए विस्तार क्षेत्र में रही। प्रमुख उन्नत विनिर्माण उद्यमों (ईएमडीई) में, भारत ने व्यावसायिक गतिविधियों में मजबूत विस्तार दर्ज करना जारी रखा। इसके विपरीत, ब्राज़ील और रूस में संकुचन जारी रहा (चार्ट II.3ए)। अमेरिका, चीन, जापान और यूरोज़ोन सहित

सारणी II.2: वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक

	जुला-24	अग-24	सितं-24	अक्तू-24	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25
पीएमआई समग्र	52.5	52.9	51.9	52.3	52.4	52.6	51.8	51.5	52.1	50.8	51.2	51.7	52.4
पीएमआई विनिर्माण	49.7	49.6	48.7	49.4	50.1	49.6	50.1	50.6	50.3	49.8	49.5	50.4	49.7
पीएमआई सेवाएं	53.3	53.9	52.9	53.1	53.1	53.8	52.2	51.5	52.7	50.8	52.0	51.8	53.4
पीएमआई निर्यात क्रयादेश	49.7	49.0	48.5	48.9	49.3	48.7	49.6	49.7	50.1	47.5	48.0	49.1	48.5
पीएमआई निर्यात क्रयादेश: विनिर्माण	49.4	48.4	47.5	48.3	48.6	48.2	49.4	49.6	50.1	47.3	48.0	49.2	48.2
पीएमआई निर्यात क्रयादेश: सेवाएं	50.6	50.8	51.6	50.7	51.3	50.3	50.2	50.2	50.1	48.2	47.9	48.7	49.3

<<संकुचन -- विस्तार>>

टिप्पणियाँ: 1. क्रय प्रबंधक सूचकांक, जो कि एक प्रसार सूचकांक है, पिछले महीने की तुलना में प्रत्येक चर में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, और यह प्रत्येक चर में वृद्धि/सुधार, गिरावट/कमी अथवा कोई परिवर्तन नहीं हुई है की स्थिति को दर्शाता है। 50 से अधिक का पीएमआई मान विस्तार को दर्शाता है: 50 से कम का मान संकुचन को दर्शाता है; और =50 का मान 'कोई परिवर्तन नहीं' को दर्शाता है।

2. हीटमैप अप्रैल 2023 से जुलाई 2025 तक के डेटा पर लागू किया जाता है। मानचित्र रंग कोडिकृत है - लाल सबसे कम मूल्य को दर्शाता है, पीला 50 (या कोई परिवर्तन नहीं मूल्य) को दर्शाता है, और हरा प्रत्येक पीएमआई शृंखला में उच्चतम मूल्य को दर्शाता है।

स्रोत: एसएंडपी ग्लोबल।

चार्ट II.3: क्रय प्रबंधकों का सूचकांक: विभिन्न क्षेत्राधिकारों में तुलना

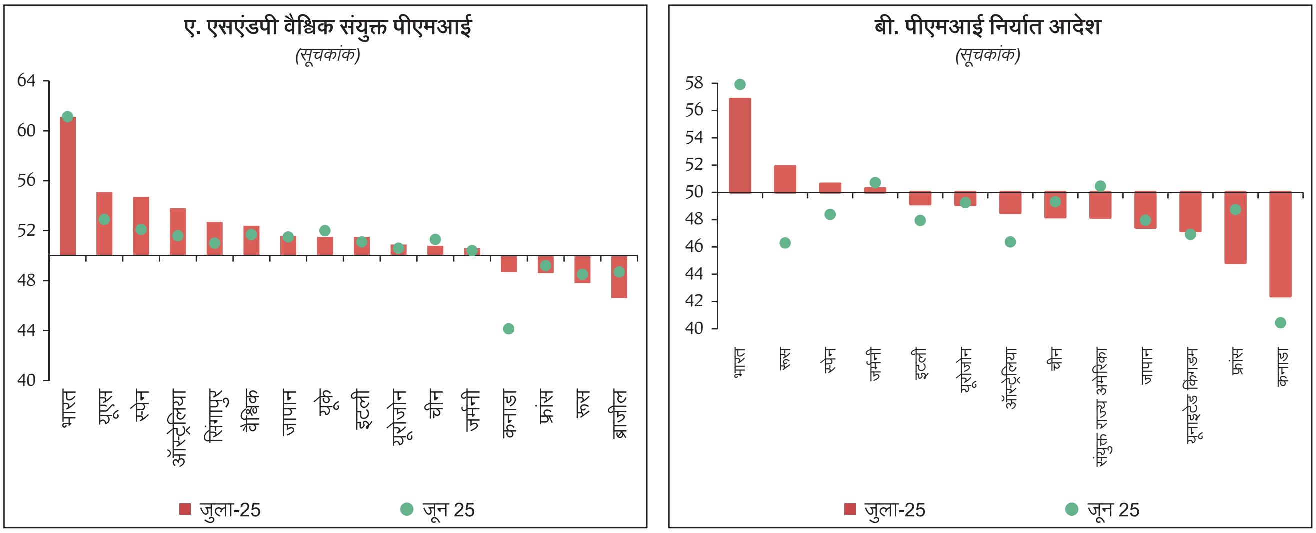

टिप्पणी : 50 का स्तर गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं होने का संकेत देता है, जबकि 50 से ऊपर का स्तर विस्तार का संकेत देता है और 50 से नीचे का स्तर संकुचन का संकेत देता है।
स्रोत: एसएंडपी ग्लोबल।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में, सामान्यतः, नए निर्यात ऑर्डरों में संकुचन देखा गया, लेकिन भारत ने मजबूत विस्तार दर्ज किया (चार्ट II.3बी)। वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक अपने ऐतिहासिक औसत के करीब के स्तर पर आ गया (अनुलग्नक चार्ट A1)।

ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति और कमजोर समष्टि-आर्थिक खंडों के कारण जुलाई में पण्य की कीमतें मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहीं। मांस और वनस्पति तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ वैश्विक खाद्य कीमतें अपने दो साल के उच्चतम स्तर से ऊपर पहुंच गईं, जिसे अनाज, डेयरी और चीनी (चार्ट II.4 ए) द्वारा आंशिक रूप से ऑफसेट किया गया।[3] जुलाई से कच्चे तेल की कीमतें स्थिर हो गईं क्योंकि व्यापक संघर्ष की आशंका कम हो गई और ओपेक प्लस ने अगस्त में संभावित आपूर्ति में वृद्धि का संकेत दिया। चीन में कमजोर विनिर्माण गतिविधि और अमेरिका में

चार्ट II.4: पण्य और खाद्य कीमतें

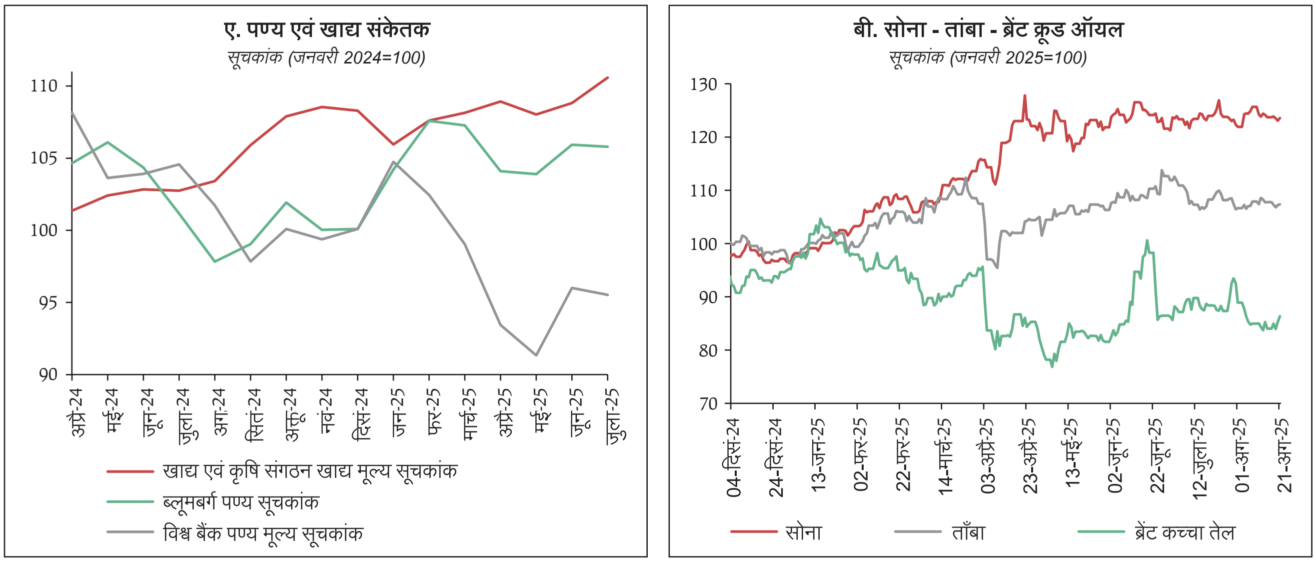

स्रोत: खाद्य एवं कृषि संगठन: ब्लूमबर्ग: और विश्व बैंक पिंक शीट।

[3] जुलाई 2025 के लिए खाद्य और कृषि संगठन के खाद्य मूल्य सूचकांक के अनुसार।

बढ़ती आवक के कारण कच्चे तेल की कीमतें भी कम हुईं। जुलाई में सोने की कीमतें मोटे तौर पर स्थिर रहीं, लेकिन बुलियन टैरिफ अनिश्चितता और यूएस फेड द्वारा नीतिगत दर में कटौती की बढ़ती उम्मीद के मद्देनजर अगस्त की शुरुआत में बढ़ गई । इसके बाद इसमें नरमी आई, जिसे आयात शुल्क से स्वर्ण बुलियन को छूट दिए जाने संबंधी स्पष्टता से सहायता मिली (चार्ट II.4ए और 4बी)।

जुलाई में अमेरिका और यूरो क्षेत्र में सीपीआई मुद्रास्फीति स्थिर रही। अमेरिका में सीपीआई मुद्रास्फीति जुलाई में 2.7 प्रतिशत पर स्थिर रही, हालांकि कोर मुद्रास्फीति छह महीने के उच्च स्तर 3.1 प्रतिशत पर पहुंच गई। यूरो क्षेत्र में, हेडलाइन मुद्रास्फीति 2.0 प्रतिशत पर स्थिर रही, जो लगातार दूसरे महीने मुद्रास्फीति को यूरोपीय सेंट्रल बैंक के आधिकारिक लक्ष्य के अनुरूप चिह्नित करती है। यूके में मुद्रास्फीति जनवरी 2024 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जबकि जापान की मुद्रास्फीति आठ महीने के निचले स्तर पर आ गई (चार्ट II.5ए)। प्रमुख ईएमडीई में, ब्राजील में मुद्रास्फीति कम हुई, हालांकि लक्ष्य से ऊपर रही। चीन में अपस्फीति का दबाव बना हुआ है जबकि रूस लक्ष्य से काफी ऊपर मुद्रास्फीति से जूझ रहा है । दक्षिण अफ्रीका की वार्षिक मुद्रास्फीति दर जुलाई में बढ़ी, जो लगातार दूसरी मासिक वृद्धि है (चार्ट II.5बी)।

जुलाई-अगस्त में इक्विटी बाज़ार की गतिविधियों ने कॉरपोरेट आय परिणामों और अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में प्रगति का अनुसरण किया, हालाँकि आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में अनिश्चितता ने अस्थिरता पैदा की। जुलाई के अधिकांश समय में अमेरिकी इक्विटी बाज़ारों में वृद्धि हुई, जिसे 2025 की दूसरी तिमाही में सुदृढ़ कॉरपोरेट आय और व्यापार वार्ताओं के बारे में आशावाद का समर्थन प्राप्त हुआ (चार्ट II.6ए)। जुलाई के अंत में महीने भर की बढ़त गायब हो गई क्योंकि जुलाई के लिए उम्मीद से कमज़ोर अमेरिकी गैर-कृषि पेरोल डेटा और जून के डेटा में भारी गिरावट ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया। यूरोप में सुस्त कॉरपोरेट आय के बीच स्टॉक्स यूरोप 600 ने गति खो दी। हालाँकि यूरोपीय संघ-अमेरिका व्यापार समझौते के बाद तेजी आई, लेकिन यूरोपीय संघ के लिए इस समझौते के वास्तविक लाभों पर बनी अनिश्चितताओं के कारण यह अल्पकालिक थी। इसके विपरीत, जापान में इक्विटी सूचकांकों में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के बाद, तथा उसके बाद दूसरी तिमाही में मजबूत जीडीपी वृद्धि और अगस्त में मजबूत कॉरपोरेट परिणामों के कारण तीव्र वृद्धि दर्ज की गई।

अमेरिका में 10-वर्षीय खजाना प्रतिफल में जुलाई में बढ़ोतरी हुई, ऐसा जून में मुद्रास्फीति के अनुमान से अधिक

चार्ट II.5: हेडलाइन मुद्रास्फीति

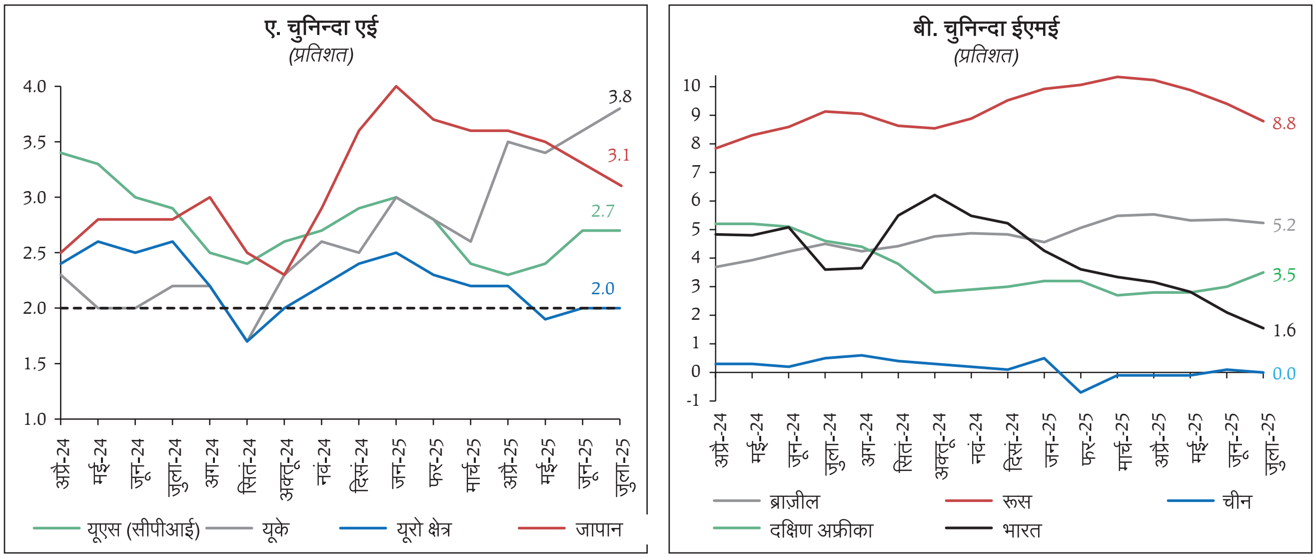

स्रोत: ब्लूमबर्ग और ओईसीडी।

चार्ट II.6: वैश्विक वित्तीय बाजार

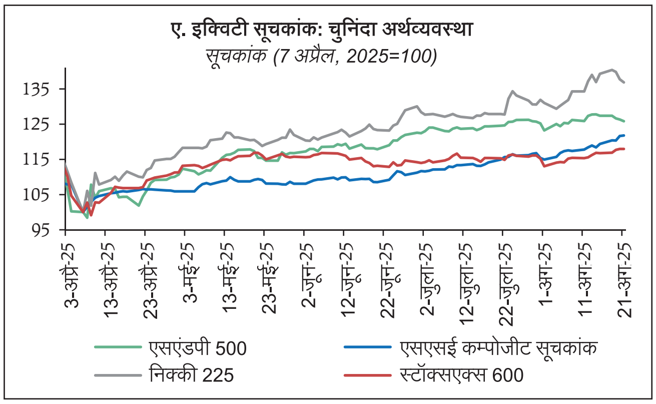

टिप्पणी : इक्विटी बाजारों का प्रतिनिधित्व अमेरिका के लिए एसएंडपी 500, चीन के लिए एसएसई कम्पोजिट सूचकांक, जापान के लिए निक्की 225 और यूरोप के लिए स्टॉक्सएक्स 600 द्वारा किया जाता है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

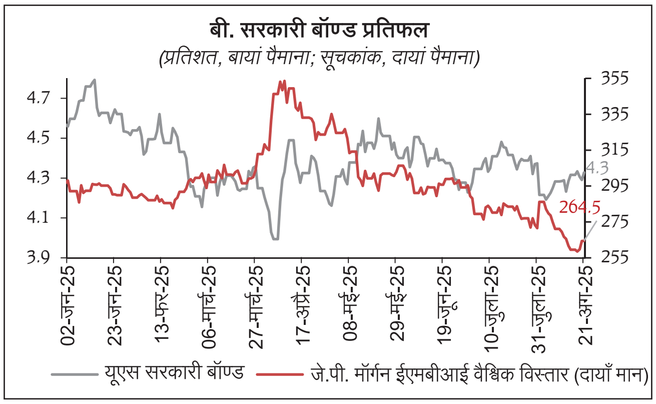

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

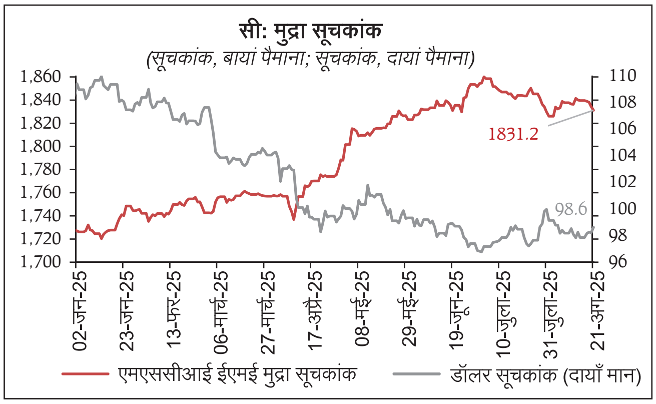

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

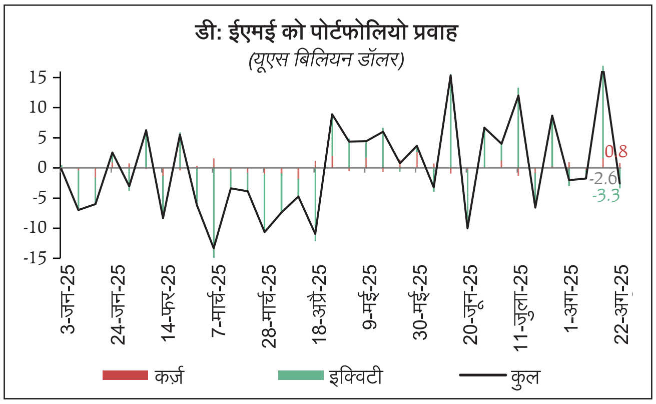

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान।

मजबूत होने और राजकोषीय स्थिति को लेकर बाजारों में बढ़ती बेचैनी के कारण हुआ, जिससे आसन्न दर में कटौती की उम्मीद कम हो गई। अगस्त में, प्रतिफल में दोतरफा बदलाव हुए। हालांकि शुरुआत में अमेरिका में उम्मीद से कमजोर रोजगार आंकड़ों और अनुमान से कम सीपीआई मुद्रास्फीति के कारण इसमें गिरावट आई, लेकिन इसके बाद उत्पादक मूल्य मुद्रास्फीति में उम्मीद से अधिक वृद्धि के बाद प्रतिफल में बढ़ोतरी हुई। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की जुलाई बैठक के कार्यवृत्त जारी होने के बाद प्रतिफल में कमी आई (चार्ट II.6बी)। कई अर्थव्यवस्थाओं के सुदृढ़ सूक्ष्म-आर्थिक स्थिति के कारण जुलाई और अगस्त में उभरते बाजार बॉण्ड पर जोखिम प्रीमियम में गिरावट आई, जिसमें कमजोर अमेरिकी डॉलर ने प्रसार संकुचन में और योगदान दिया। अमेरिकी डॉलर बीच-बीच में अस्थिर और कमजोर रहा अमेरिकी राजकोषीय गतिशीलता, कठोर वैश्विक वित्तीय स्थिति और असमान वैश्विक सुधार पर चिंताओं ने उभरते बाजारों में पूंजी प्रवाह में अस्थिरता को बढ़ा दिया (चार्ट II.6डी)।

केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत निर्णय संबंधित क्षेत्राधिकारों में वृद्धि-मुद्रास्फीति की गतिशीलता से प्रेरित होते रहे हैं। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने जुलाई में स्थिर कोर और सेवा मुद्रास्फीति के कारण नीतिगत दरों को लगभग अपरिवर्तित रखा। अगस्त में, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड ने अपनी नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कमी की। स्वीडन ने उच्च व्यापार अनिश्चितता के बीच अपनी प्रमुख नीतिगत दर को स्थिर रखा। ईएमडीई में, इंडोनेशिया, मेक्सिको और थाईलैंड ने भी अगस्त में प्रमुख नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कमी की। चीन ने लगातार तीसरे महीने अपनी बेंचमार्क उधार दर को स्थिर रखा (चार्ट II.7)।

चार्ट II.7: नीतिगत दरें

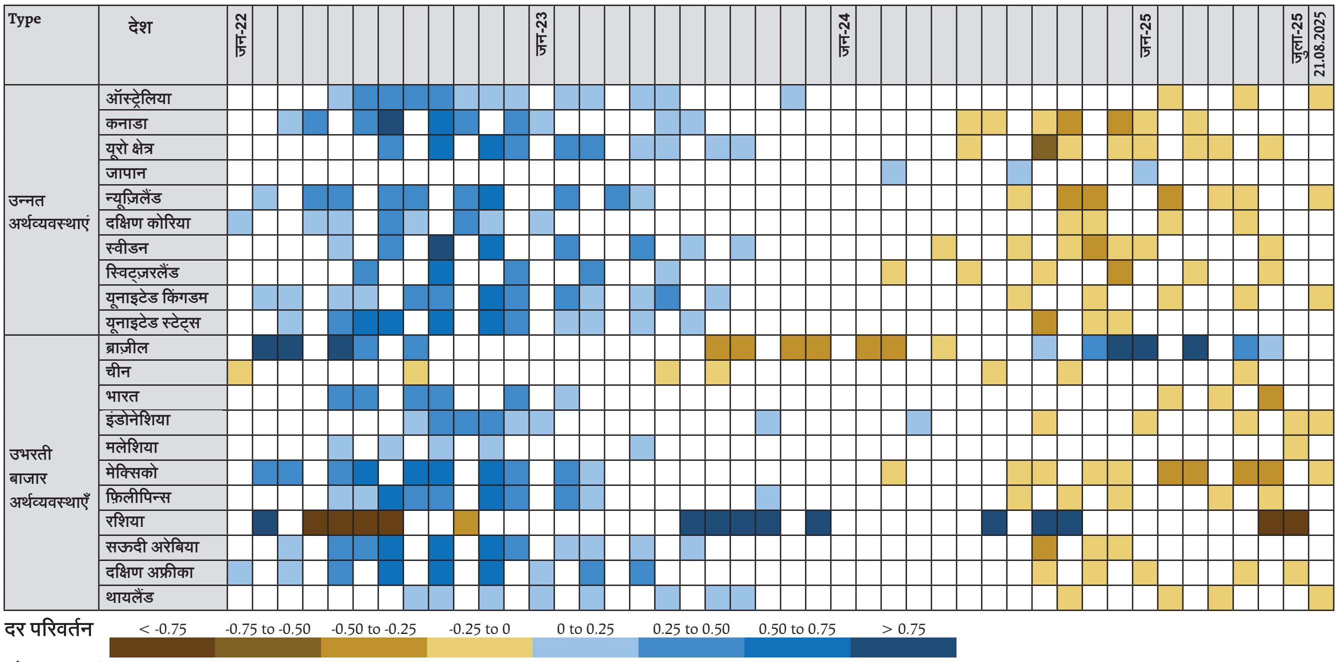

स्रोत: ब्लूमबर्ग

III. घरेलू घटनाक्रम

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रही। दक्षिण-पश्चिम मानसून की समय पर प्रगति ने खरीफ की बुवाई को बढ़ाने में मदद की है। बिजली और खनन क्षेत्र के कारण जून में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर सभी क्षेत्रों में असमान रही। जुलाई में विनिर्माण और सेवाओं का विस्तार जारी रहा। उपभोक्ता भावनाओं के दूरदर्शी सर्वेक्षणों से पता चलता है कि वर्तमान अवधि में उपभोक्ता विश्वास में सुधार हुआ है और भविष्य को लेकर आशावाद बढ़ा है (अनुलग्नक चार्ट ए3)। नरम खाद्य कीमतों और अनुकूल आधार प्रभावों से प्रेरित मुख्य मुद्रास्फीति में और कमी आने की संभावना है और यह दूसरी तिमाही में 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे रहेगी। इस संदर्भ में, मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान समष्टि आर्थिक स्थितियों, दृष्टिकोण और अनिश्चितताओं के साथ-साथ फरवरी 2025 से की गई संचयी 100 आधार अंकों की दर कटौती को ध्यान में रखते हुए, 6 अगस्त 2025 के अपने संकल्प में रेपो दर को 5.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। मौद्रिक नीति समिति ने आने वाले आंकड़ों और विकसित घरेलू विकास-मुद्रास्फीति गतिशीलता पर सतर्क रहते हुए, उचित मौद्रिक नीति पथ का निर्धारण करते हुए तटस्थ रुख जारी रखने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया।

सकल मांग

जुलाई में समग्र आर्थिक गतिविधि के उच्च-आवृत्ति संकेतकों ने मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत की है। त्योहारों से पहले की इन्वेंट्री में वृद्धि और बेहतर अनुपालन के कारण, जुलाई में जीएसटी ई-वे बिल रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँच गए। जीएसटी राजस्व में वृद्धि हुई और टोल संग्रह स्थिर रहा, हालाँकि जुलाई में बिजली की मांग और पेट्रोलियम खपत में गिरावट दर्ज की गई। समग्र आर्थिक गतिविधि के एक प्रमुख संकेतक, डिजिटल भुगतान ने मात्रा और मूल्य दोनों स्थिति में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की (सारणी III.1)।

जुलाई के दौरान, मौसमी कारकों और रनवे रखरखाव के कारण घरेलू हवाई यात्री यातायात में कमी के साथ शहरी माँग में कमी आई। यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में भी गिरावट आई। वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के कारण ग्रामीण माँग में मजबूती बनी रही। अनुकूल मानसून के कारण ट्रैक्टरों की खुदरा बिक्री

सारणी III.1: उच्च आवृत्ति संकेतक-आर्थिक गतिविधि

	जुला-24	अग-24	सितं-24	अक्तू-24	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25
जीएसटी ई-वे बिल	19.2	12.9	18.5	16.9	16.3	17.6	23.1	14.7	20.2	23.4	18.9	19.3	25.8
जीएसटी राजस्व	10.3	10.0	6.5	8.9	8.5	7.3	12.3	9.1	9.9	12.6	16.4	6.2	7.5
टोल संग्रह	9.4	6.8	6.5	7.9	11.9	9.8	14.8	18.7	11.9	16.6	16.4	15.5	14.8
बिजली की मांग	4.0	-5.0	-0.8	-0.4	3.7	5.1	1.3	2.4	5.7	2.8	-4.8	-2.3	2.0
पेट्रोलियम की खपत	10.7	-3.1	-4.4	4.1	10.6	2.0	3.0	-5.2	-3.1	0.2	0.7	1.4	-4.0
जिनमें से पेट्रोल	10.5	8.6	3.0	8.7	9.6	11.1	6.7	5.0	5.7	5.0	9.2	6.8	5.9
डीज़ल	4.5	-2.5	-1.9	0.1	8.5	5.9	4.2	-1.3	0.9	4.2	2.1	1.5	2.4
विमानन टरबाइन ईंधन	9.6	8.1	10.4	9.4	8.5	8.7	9.4	4.2	5.7	3.9	4.3	3.3	-2.3
डिजिटल भुगतान- मात्रा	36.7	34.9	36.3	40.3	30.1	33.1	33.0	26.7	30.8	30.0	29.2	28.3	29.0
डिजिटल भुगतान- मूल्य	22.1	16.7	21.5	27.5	9.5	19.6	18.6	9.5	17.3	18.4	12.6	17.4	16.9

<<संकुचन -- विस्तार>>

टिप्पणियाँ: 1. सभी संकेतकों के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
2. हीट मैप अप्रैल 2023 से जुलाई 2025 तक के डेटा के आधार पर है।
3. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक रंग ग्रेडिएंट स्कीम में परिवर्तित करता है, जिसमें लाल रंग न्यूनतम मानों को दर्शाता है और हरा रंग संबंधित डेटा शृंखला के उच्चतम मानों को दर्शाता है। डिजिटल भुगतान डेटा के लिए, शून्य वृद्धि को निचली सीमा माना जाता है।

स्रोत: वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन): आरबीआई: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए): और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार।

में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। खरीफ की बुवाई और भारी बारिश के कारण दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री में गिरावट आई। आगामी त्योहारी मौसम में बिक्री में तेज़ी आने की उम्मीद है। खरीफ की बुवाई में तेज़ी आने के कारण जुलाई में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार की घरेलू माँग में गिरावट आई (सारणी III.2)।

जुलाई में रोजगार की स्थितियाँ सुदृढ़ रहीं। ग्रामीण बेरोजगारी में कमी के कारण अखिल भारतीय बेरोजगारी दर घटकर 5.2 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण और शहरी[4] दोनों क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई। संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन मजबूत रहा, जैसा कि जून में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत रिकॉर्ड निवल वेतन वृद्धि में परिलक्षित होता है। नौकरी जॉबस्पीक सूचकांक के अनुसार, जुलाई में व्हाइट-कॉलर नौकरियों की सूची में सर्वाधिक वृद्धि यात्रा/आतिथ्य, बीमा और शिक्षा क्षेत्र में रहा। विनिर्माण और सेवा दोनों के लिए पीएमआई रोज़गार सूचकांक

सारणी III.2: उच्च आवृति संकेतक- ग्रामीण और शहरी माँग

		जुला-24	अग-24	सितं-24	अक्तू-24	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25
शहरी माँग	घरेलू हवाई यात्री यातायात	7.6	6.7	7.4	9.6	13.8	10.8	14.1	12.1	9.9	9.7	2.6	3.7	-2.1
	खुदरा यात्री वाहन बिक्री	14.0	-4.5	-18.8	32.4	-13.7	-2.0	15.5	-10.3	6.3	1.6	-3.1	2.5	-0.8
ग्रामीण माँग	खुदरा ट्रैक्टर बिक्री	-12.0	-11.4	14.7	3.1	29.9	25.8	5.2	-14.5	-5.7	7.6	2.8	8.7	11.0
	मनरेगा कार्य की मांग	-19.5	-16.0	-13.4	-7.6	3.9	8.2	14.4	2.8	2.2	-6.5	4.4	4.4	-12.3
	खुदरा दोपहिया वाहन बिक्री	17.7	6.3	-8.5	36.3	15.8	-17.6	4.2	-6.3	-1.8	2.3	7.3	4.7	-6.5

<<संकुचन -- विस्तार>>

टिप्पणियाँ: 1. सभी संकेतकों के लिए व-द-व वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
2. हीटमैप अप्रैल 2023 से जुलाई 2025 तक के डेटा पर लागू किया गया है।
3. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक रंग ग्रेडिएंट योजना में परिवर्तित करता है, जिसमें लाल रंग न्यूनतम मानों को दर्शाता है और हरा रंग संबंधित डेटा शृंखला के उच्चतम मानों को दर्शाता है।
4. जुलाई 2025 की वृद्धि दर के लिए घरेलू हवाई यात्री यातायात के आंकड़ों की गणना दैनिक आंकड़ों को एकत्रित करके की जाती है।

स्रोत: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण: ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फेडरेशन (एफएडीए): और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

[4] पीएलएफएस जुलाई 2025 मासिक बुलेटिन 18 अगस्त 2025 को जारी किया गया।

सारणी III.3: उच्च आवृत्ति संकेतक- रोजगार

	जुला-24	अग-24	सितं-24	अक्तू-24	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25
बेरोजगारी दर (पीएलएफएस: अखिल भारतीय)										5.1	5.6	5.6	5.2
बेरोजगारी दर (पीएलएफएस: ग्रामीण)										4.5	5.1	4.9	4.4
बेरोजगारी दर (पीएलएफएस: शहरी)										6.5	6.9	7.1	7.2
नौकरी जॉबस्पीक सूचकांक	11.8	-3.4	6.0	10.0	2.0	8.7	3.9	4.0	-1.5	8.9	0.3	10.5	6.8
पीएमआई रोजगार: विनिर्माण	53.7	53.5	52.1	53.3	52.9	53.4	54.8	54.5	53.4	54.2	54.9	55.1	53.3
पीएमआई रोजगार: सेवाएँ	53.5	53.1	53.4	54.3	56.6	55.5	56.3	56.2	52.5	53.9	57.1	55.1	51.4

<<संकुचन -- विस्तार>>

टिप्पणियाँ: 1. सभी पीएलएफएस संकेतक वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में हैं और 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए हैं।
2. नौकरी सूचकांक के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना की गई है।
3. हीटमैप अप्रैल 2023 से जुलाई 2025 तक के डेटा के आधार पर तैयार किया गया है।
4. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक रंग ग्रेडिएंट योजना में परिवर्तित करता है, जिसमें लाल रंग न्यूनतम मानों को दर्शाता है और हरा रंग संबंधित डेटा शृंखला के उच्चतम मानों को दर्शाता है।
5. सभी पीएमआई मान सूचकांक के रूप में दर्शाए जाते हैं। 50 से अधिक पीएमआई मान विस्तार, 50 से कम संकुचन और 50 'कोई परिवर्तन नहीं' दर्शाता है। पीएमआई हीटमैप में, लाल रंग न्यूनतम मान, पीला रंग 50 (या कोई परिवर्तन नहीं) और हरा रंग प्रत्येक पीएमआई शृंखला में उच्चतम मान दर्शाता है।

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार; इन्फो एज; और एसएंडपी ग्लोबल।

जुलाई में बढ़े, हालाँकि जून की तुलना में इसकी गति धीमी रही (सारणी III.3)।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों के अनुपात के रूप में, 2025-26 की पहली तिमाही के लिए केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में अधिक था (चार्ट III.1ए)।[5] यह बड़े पूंजीगत और राजस्व व्यय, और कम निवल कर राजस्व के कारण था।[6] पूंजीगत व्यय के फ्रंट-लोडिंग के कारण, पहली तिमाही में बजटीय लक्ष्य का 24.5 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो गया।[7]

चार्ट III.1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक (जून के अंत तक)

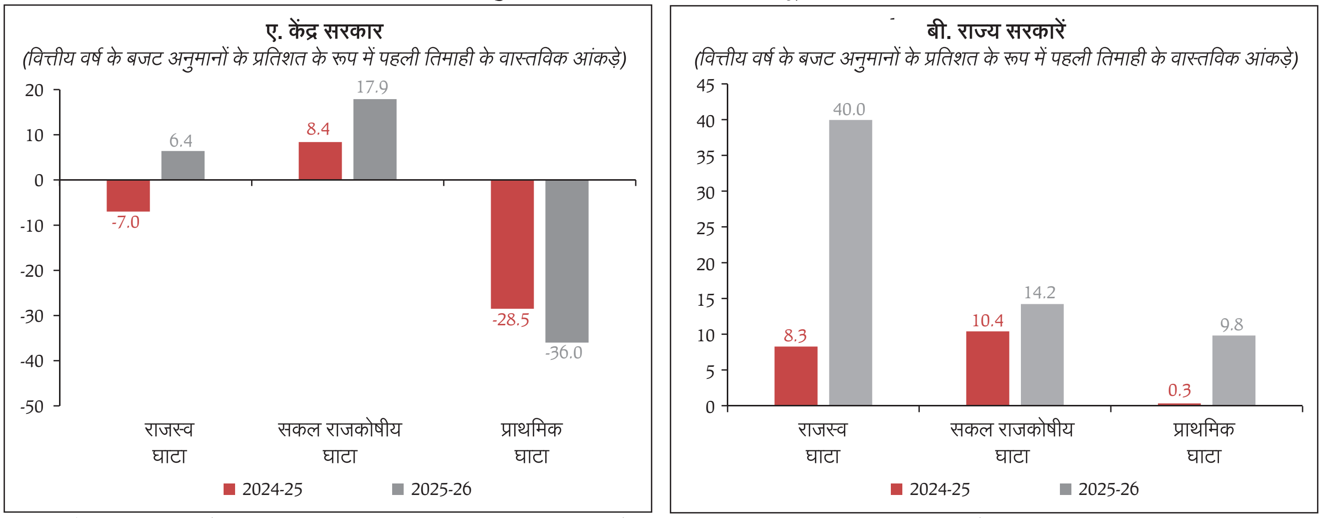

टिप्पणियाँ: 1. बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में दर्शाए गए ऋणात्मक राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा संख्या क्रमशः राजस्व अधिशेष और प्राथमिक अधिशेष दर्शाती है।
2. चार्ट III.1बी में आंकड़े 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित हैं।

स्रोत: महालेखा नियंत्रक; तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

5 महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार।
6 प्रत्यक्ष कर संग्रह कम होने के कारण। हालांकि, अप्रत्यक्ष करों में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण जीएसटी संग्रह में अधिक वृद्धि रही।
7 पूंजीगत व्यय के लिए बजटीय लक्ष्य का 16.3 प्रतिशत 2024-25 की पहली तिमाही में प्राप्त किया गया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा, वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों के अनुपात के रूप में, पिछले वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में भी अधिक रहा। ऐसा अधिक व्यय के साथ-साथ कम राजस्व प्राप्तियों के कारण हुआ (चार्ट III.1बी)। राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में वृद्धि में मंदी के कारण राजस्व प्राप्तियाँ कम हुईं। राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क जैसे गैर-जीएसटी राजस्व स्रोत मज़बूत रहे। व्यय के संदर्भ में, राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों ही मज़बूत रहे।

व्यापार

तेल घाटे में वृद्धि के कारण, व्यापारिक व्यापार घाटा जुलाई 2025 में बढ़कर 27.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले 24.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट III.2)। कुल व्यापार घाटे में तेल का हिस्सा एक वर्ष पहले की तुलना में बढ़ा है।[8] गैर-तेल घाटा लगभग 16.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर बना रहा।

पिछले दो महीनों में गिरावट के बाद व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई (अनुलग्नक चार्ट ए4)।[9] इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न और आभूषण, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों का प्रदर्शन अच्छा रहा, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों, लौह अयस्क और खाद्य तेल का योगदान ऋणात्मक रहा।

पिछले दो महीनों में गिरावट के बाद पण्य वस्तुओं के आयात में भी वृद्धि हुई (अनुलग्नक चार्ट ए5)।[10] इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम कच्चा तेल और उत्पाद, उर्वरक, कच्चा तेल और विनिर्मित उत्पाद, मशीनरी, विद्युत और गैर-विद्युतीय तथा सोने ने महीने के दौरान आयात वृद्धि को समर्थन दिया, जबकि कोयला, कोक और ब्रिकेट, दालें, तथा चमड़ा और चमड़ा उत्पादों ने समग्र आयात को नीचे खींच लिया।

चुनौतीपूर्ण वैश्विक व्यापार परिदृश्य के बावजूद सेवा व्यापार मज़बूत बना रहा। जून 2025 में, निवल सेवा निर्यात आय 19.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 16.2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई। सेवा निर्यात में तेज़ वृद्धि हुई, जो भारत के सेवा क्षेत्र की निरंतर मज़बूती को दर्शाता है। साथ ही, आयात में भी तेज़ी से वृद्धि हुई, जो सॉफ़्टवेयर सेवाओं और परिवहन सेवाओं के आयात में वृद्धि को दर्शाता है (चार्ट III.3)।[11]

चार्ट III.2: व्यापारिक व्यापार घाटा

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष, बायाँ पैमाना; बिलियन यूएस डॉलर, दायाँ पैमाना)

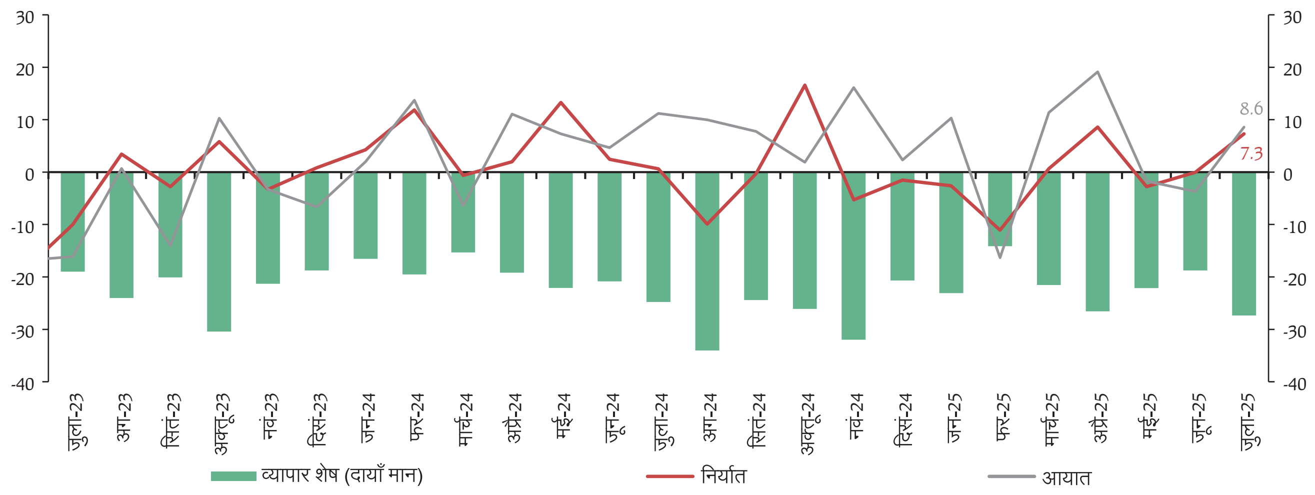

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएंडएस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[8] जुलाई में तेल व्यापार घाटा एक साल पहले के 8.7 अरब यूएस डॉलर से बढ़कर 11.2 अरब यूएस डॉलर हो गया। कुल व्यापार घाटे में तेल की हिस्सेदारी जुलाई में बढ़कर 41.1 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 35.1 प्रतिशत थी।

[9] जुलाई में 37.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर [7.3 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)]

[10] जुलाई में 64.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर [8.6 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)]

[11] जून 2025 में सेवाओं का निर्यात और आयात क्रमशः 32.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 15.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया।

चार्ट III.3: सेवा निर्यात और आयात का रुझान

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

स्रोत: आरबीआई।

सकल आपूर्ति

कृषि

दक्षिण-पश्चिम मानसून की समय पर प्रगति ने खरीफ की बुवाई बढ़ाने में मदद की है (चार्ट III.4)। [12] बुवाई क्षेत्र में वृद्धि मुख्यतः चावल और मक्का में हुई, जबकि तिलहन और कपास के रकबे में गिरावट आई। तुअर, जो दलहन के रकबे का 35 प्रतिशत है, में गिरावट देखी गई क्योंकि किसानों ने मक्का जैसी अधिक लाभदायक फसलों की ओर रुख किया।[13]

चार्ट III.4: *खरीफ* बुवाई क्षेत्रफल

(लाख हेक्टेयर, बायां पैमाना; प्रतिशत, दायां पैमाना)

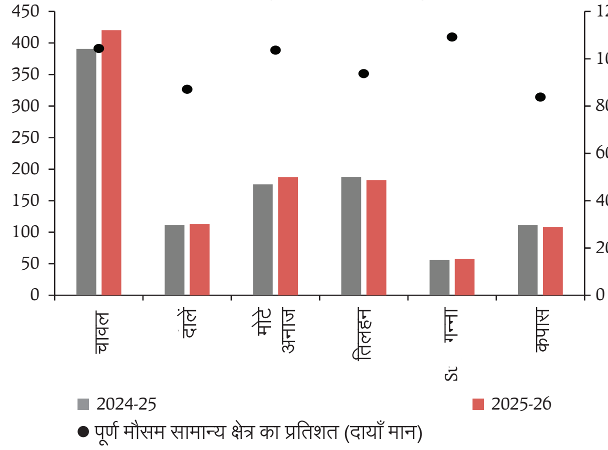

टिप्पणी: डेटा 22 अगस्त, 2025 तक का है

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

1 जून से 22 अगस्त, 2025 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर संचयी वर्षा सामान्य से 2 प्रतिशत अधिक रही। जलाशयों का स्तर पिछले वर्ष और दशकीय औसत से काफ़ी ऊपर रहा (चार्ट III.5)।

चावल और गेहूँ का संयुक्त सार्वजनिक भंडार मजबूत ख़रीद के समर्थन से आरामदायक बना रहा।[14]

उद्योग और सेवाएँ

सूचीबद्ध कंपनियों के लिए 2025-26 की पहली तिमाही के परिणाम

सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों[15] के 2025-26 की पहली तिमाही के परिणामों ने कॉरपोरेट क्षेत्र में सुस्त प्रदर्शन का संकेत दिया। सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों की बिक्री वृद्धि मुख्य रूप से पेट्रोलियम उद्योग, ऑटोमोबाइल, विद्युत मशीनरी और खाद्य उत्पादों में मंदी के कारण और धीमी हुई।[16] लगातार सुधार की अवधि के बाद, पहली तिमाही के दौरान आईटी फर्मों की बिक्री वृद्धि में भी गिरावट आई, जो

[12] 22 अगस्त 2025 तक *खरीफ* की बुवाई 1074 लाख हेक्टेयर थी, जो सामान्य क्षेत्र का लगभग 97.9 प्रतिशत थी।
[13] पिछले वर्ष की तुलना में अरहर की बुवाई में 1.8 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि मक्का की बुवाई में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
[14] 01 अगस्त 2025 तक सार्वजनिक स्टॉक बफर मानक का 2.1 गुना था।
[15] 3,079 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के तिमाही परिणामों पर आधारित।
[16] A2025-26 की पहली तिमाही के दौरान कुल बिक्री वृद्धि घटकर 5.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रह गई, जो पिछली तिमाही में 7.1 प्रतिशत थी।

चार्ट III.5: जलाशय भंडारण

(पूर्ण जलाशय स्तर का प्रतिशत)

टिप्पणी: डेटा 21 अगस्त 2025 तक का है।
स्रोत: केंद्रीय जल आयोग।

चार्ट III.6: सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियों की बिक्री वृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

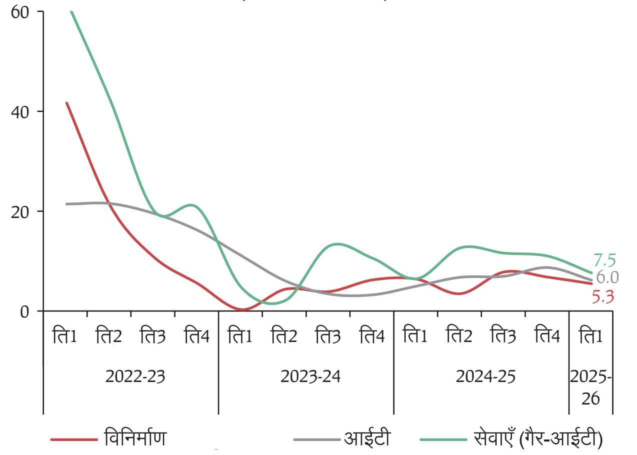

टिप्पणी: डेटा 3,079 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों (1,736 विनिर्माण, 198 आईटी, और 892 गैर-आईटी सेवाएं) के परिणामों पर आधारित है।
स्रोत: कैपिटलाइन डेटाबेस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

वैश्विक प्रतिकूलताओं के प्रभाव को दर्शाती है। गैर-आईटी सेवा कंपनियों की बिक्री वृद्धि भी धीमी रही (चार्ट III.6)।

धीमी बिक्री वृद्धि के बावजूद, व्यय में धीमी वृद्धि के कारण 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान विनिर्माण और सेवा कंपनियों के लिए परिचालन लाभ और मार्जिन स्थिर रहे (चार्ट III.7ए और III.7बी)।

2025-26 की पहली तिमाही के दौरान, सूचीबद्ध भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों[17] के राजस्व और निवल लाभ दोनों की वृद्धि में कमी आई (चार्ट III.8)। राजस्व में वृद्धि जारी रही, लेकिन इसकी गति धीमी रही। वेतन और मजदूरी व्यय में क्रमिक वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि हुई। कुछ कंपनियों की उच्च प्रावधान लागत और आस्ति गुणवत्ता में गिरावट ने

चार्ट III.7: सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियों की लाभप्रदता

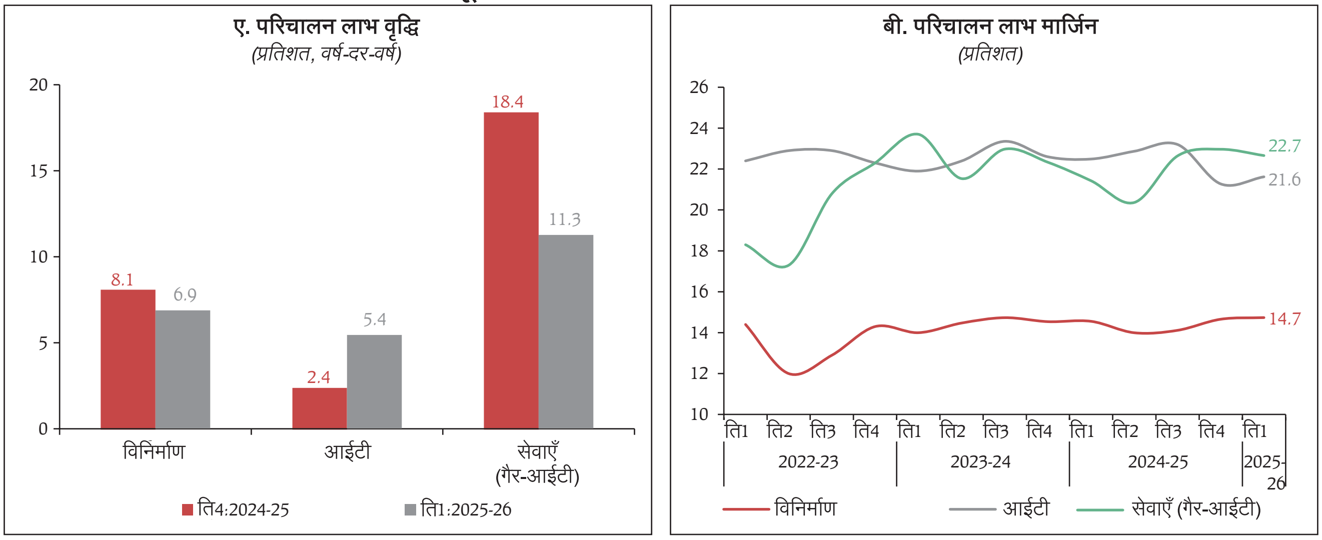

टिप्पणी: डेटा 3,079 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों (1,736 विनिर्माण, 198 आईटी, और 892 गैर-आईटी सेवाएं) के परिणामों पर आधारित है।
स्रोत: कैपिटलाइन डेटाबेस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[17] 349 कंपनियों के नमूने पर आधारित है, जो सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण का लगभग 84 प्रतिशत है।

चार्ट III.8: सूचीबद्ध वित्तीय कंपनियों का प्रदर्शन

(वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्रतिशत में)

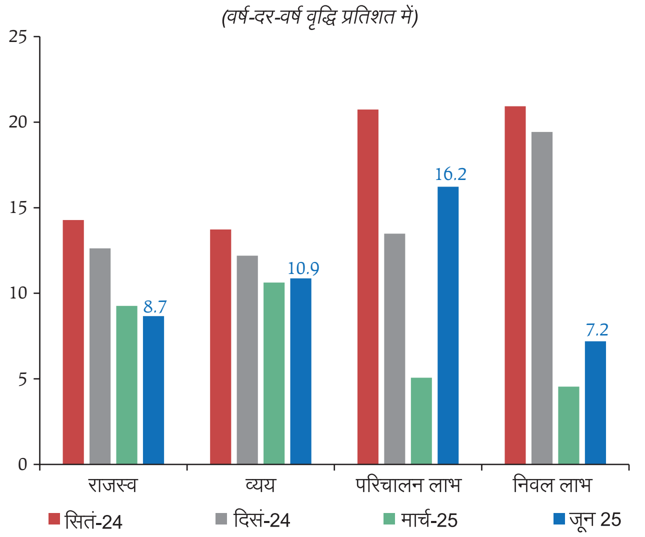

स्रोत: सीएमआईई प्रोवेस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.9: निजी कॉरपोरेट्स के निवेश इरादे

(₹ करोड़)

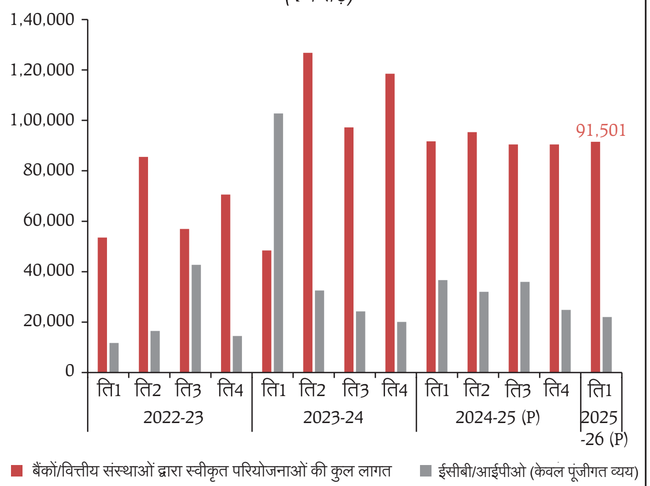

टिप्पणी: 2024-25 और 2025-26 की पहली तिमाही के आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से एकत्रित परियोजना वित्त पर आंकड़े; तथा आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

परिचालन लाभ की तुलना में निवल लाभ की धीमी वृद्धि में योगदान दिया।

निवेश के मोर्चे पर, चुनिंदा बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान स्वीकृत पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की कुल लागत में पिछली तिमाही की तुलना में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। लगभग 66 प्रतिशत निवेश ऊर्जा, निर्माण और आईटी सॉफ्टवेयर उद्योगों में केंद्रित था। पूंजीगत व्यय के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार और आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से जुटाई गई धनराशि पिछली तिमाही की तुलना में थोड़ी कम थी। कुल मिलाकर, निजी कंपनियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से पूंजीगत व्यय के लिए जुटाई गई धनराशि ने बढ़ी हुई अनिश्चितताओं के बावजूद स्थिर निवेश गतिविधि का संकेत दिया (चार्ट III.9)।

औद्योगिक गतिविधि के मासिक संकेतक

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में साल-दर-साल बदलाव के आधार पर मापी गई औद्योगिक गतिविधियों की वृद्धि जून 2025 में दस महीने के निचले स्तर पर आ गई। खनन और बिजली क्षेत्र में संकुचन जारी रहा, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हुई। जुलाई में, आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में वृद्धि धीमी रही और आठ में से चार क्षेत्रों में संकुचन हुआ, हालाँकि इस्पात और सीमेंट उद्योगों का प्रदर्शन अच्छा रहा।

जुलाई के उपलब्ध उच्च-आवृत्ति संकेतक विनिर्माण गतिविधि में विस्तार की ओर इशारा करते हैं, और इसका पीएमआई 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। तिपहिया और दोपहिया वाहनों के मजबूत उत्पादन के कारण ऑटोमोबाइल उत्पादन में एक साल में सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज की गई। शुरुआती बारिश और कम औद्योगिक उत्पादन के कारण पारंपरिक बिजली उत्पादन लगातार चौथे महीने धीमा रहा। इसके विपरीत, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन ने अपनी गति बनाए रखी। पूंजीगत वस्तुओं के आयात में जुलाई में तेजी आई (सारणी III.4)। आपूर्ति शृंखला का दबाव जुलाई 2025 में थोड़ा बढ़ा, लेकिन अपने ऐतिहासिक औसत स्तर से नीचे रहा (अनुलग्नक चार्ट A6)।

भारत सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है - जो ऊर्जा-सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।[18] भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है (चार्ट III.10)। इसके अलावा, भारत में त्वरित ई-मोबिलिटी के उपाय के रूप में, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को दो साल के लिए 31 मार्च, 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

[18] इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनेर्जी अजेंसी (आईआरईएनए)। नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी, जुलाई 2025।

सारणी III.4: उच्च आवृत्ति संकेतक- उद्योग

	जुला-24	अग-24	सितं-24	अक्तू-24	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25
आईआईपी हेडलाइन	5.0	0.0	3.2	3.7	5.0	3.7	5.2	2.7	3.9	2.6	1.9	1.5	
आईआईपी विनिर्माण	4.7	1.2	4.0	4.4	5.5	3.7	5.8	2.8	4.0	3.1	3.2	3.9	
आईआईपी पूंजीगत सामान	11.7	0.0	3.5	2.9	8.9	10.5	10.2	8.2	3.6	14.0	13.3	3.5	
पीएमआई विनिर्माण	58.1	57.5	56.5	57.5	56.5	56.4	57.7	56.3	58.1	58.2	57.6	58.4	59.1
पीएमआई निर्यात आदेश	57.2	54.4	52.9	53.6	54.6	54.7	58.6	56.3	54.9	57.6	56.9	60.6	57.3
पीएमआई विनिर्माण: भविष्य का आउटपुट	64.1	62.1	61.6	62.1	65.5	62.5	65.1	64.9	64.4	64.6	63.1	62.2	57.6
आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक	6.3	-1.5	2.4	3.8	5.8	5.1	5.1	3.4	4.5	1.0	1.2	2.2	2.0
बिजली उत्पादन: पारंपरिक	6.8	-3.8	-1.3	0.5	2.7	4.5	-1.3	2.4	4.8	-1.8	-8.2	-6.1	-0.9
बिजली उत्पादन: नवीकरणीय	14.2	-3.7	12.5	14.9	19.0	17.9	31.9	12.2	25.2	28.0	18.2	28.7	
ऑटोमोबाइल उत्पादन	16.8	4.4	10.1	10.0	8.0	1.3	9.4	2.3	6.5	-1.7	5.2	1.2	10.7
यात्री वाहन उत्पादन	1.2	0.7	-3.4	-4.0	6.5	9.2	3.7	4.5	11.2	10.8	5.4	-1.8	0.1
ट्रैक्टर उत्पादन	8.1	-1.0	2.7	0.4	24.7	20.9	23.7	-7.8	18.5	20.5	9.1	9.8	11.5
दोपहिया वाहनों का उत्पादन	21.1	4.9	12.9	13.3	8.8	-0.6	10.3	1.6	5.6	-4.1	4.7	1.4	12.3
तिपहिया वाहनों का उत्पादन	6.0	9.0	3.9	-6.7	-5.5	7.6	16.2	6.5	6.0	4.1	16.9	8.6	24.0
कच्चे इस्पात का उत्पादन	6.8	2.6	0.3	4.2	4.5	8.3	7.4	6.0	8.5	9.3	11.0	12.6	14.0
तैयार इस्पात का उत्पादन	6.9	2.7	0.7	4.0	2.8	5.3	6.7	6.7	10.0	6.6	7.0	10.9	13.8
पूंजीगत वस्तुओं का आयात	11.6	12.3	10.9	7.0	4.7	6.1	15.5	-0.5	8.6	21.5	14.3	2.6	12.2

<<संकुचन -- विस्तार>>

टिप्पणियाँ: 1. वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना सभी संकेतकों (पीएमआई को छोड़कर) के लिए की गई है।

2. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक रंग ग्रेडिएंट योजना में परिवर्तित करता है, जिसमें लाल रंग न्यूनतम मानों को दर्शाता है और हरा रंग संबंधित डेटा शृंखला के उच्चतम मानों के अनुरूप होता है।

3. हीटमैप अप्रैल 2023 से जुलाई 2025 तक के डेटा पर लागू किया गया है, आईआईपी और बिजली उत्पादन: नवीकरणीय को छोड़कर, जहां डेटा जून 2025 तक है।

4. सभी पीएमआई मान सूचकांक के रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं। 50 से अधिक पीएमआई मान विस्तार, 50 से कम संकुचन और 50 'कोई परिवर्तन नहीं' दर्शाता है। पीएमआई हीटमैप में, लाल रंग न्यूनतम मान, पीला रंग 50 (या कोई परिवर्तन नहीं) और हरा रंग प्रत्येक पीएमआई शृंखला में उच्चतम मान दर्शाता है।

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई); एसएंडपी ग्लोबल; केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), ऊर्जा मंत्रालय: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम): आर्थिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार; संयुक्त संयंत्र समिति; वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय; और ट्रैक्टर और मशीनीकरण संघ।

चार्ट III.10: सौर ऊर्जा क्षमता

(गीगावॉट)

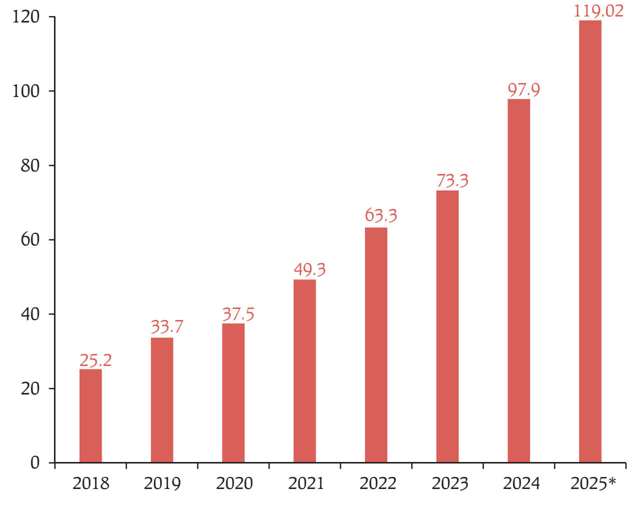

टिप्पणी:*: जुलाई 2025 तक की क्षमता।
स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)।

सेवा गतिविधि के मासिक संकेतक

भारत के सेवा क्षेत्र ने जुलाई में अपनी विकास गति बरकरार रखी, और पीएमआई सेवाओं में 11 महीनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई, जो मज़बूत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माँग के बल पर नए ऑर्डर और उत्पादन के कारण संभव हुई। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात स्थिर रहा, जबकि खुदरा वाणिज्यिक वाहन खंड में विस्तार हुआ। उर्वरक, पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक, तथा डिब्बा बंद कार्गो में उच्च वृद्धि के कारण बंदरगाह यातायात लगातार आठवें महीने बढ़ा। निर्माण क्षेत्र के संकेतकों - इस्पात खपत और सीमेंट उत्पादन - में वृद्धि मजबूत रही (सारणी III.5)।

सारणी III.5: उच्च आवृत्ति संकेतक- सेवाएँ

	जुला-24	अग-24	सितं-24	अक्तू-24	नवं-24	दिसं-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	अप्रै-25	मई-25	जून-25	जुला-25
पीएमआई सेवाएं	60.3	60.9	57.7	58.5	58.4	59.3	56.5	59.0	58.5	58.7	58.8	60.4	60.5
अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	8.8	11.1	11.2	10.3	10.7	9.0	11.1	7.7	6.8	13.0	5.0	3.4	5.4
घरेलू हवाई मालवाहक	8.8	0.6	14.0	8.9	0.3	4.3	6.9	-2.5	4.9	16.6	2.3	2.6	
अंतर्राष्ट्रीय हवाई मालवाहक	24.4	20.7	20.5	18.4	16.1	10.5	7.1	-6.3	3.3	8.6	6.8	-1.2	
बंदरगाह मालवाहक यातायात	5.9	6.7	5.8	-3.4	-5.0	3.4	7.6	3.6	13.3	7.0	4.3	5.6	4.0
खुदरा वाणिज्यिक वाहन बिक्री	5.9	-6.0	-10.4	6.4	-6.1	-5.2	8.2	-8.6	2.7	-1.0	-3.7	6.6	0.2
होटल कमरा बुकिंग	3.6	0.7	2.1	-5.3	11.1	-0.2	1.2	0.6	1.9	7.2	-2.8	-0.3	
पर्यटक आगमन	-1.3	-4.2	0.4	-1.4	-0.1	-6.6	-0.2	-8.6	-13.7	-3.8			
इस्पात की खपत	14.6	9.1	11.8	8.9	9.5	5.2	10.9	10.9	13.6	6.0	8.1	9.3	7.3
सीमेंट उत्पादन	5.1	-2.5	7.6	3.1	13.1	10.3	14.3	10.7	12.2	6.3	9.7	8.2	11.7

<<संकुचन -- विस्तार>>

टिप्पणियाँ: 1. वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (प्रतिशत में) की गणना सभी संकेतकों (पीएमआई को छोड़कर) के लिए की गई है।

2. हीटमैप प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा रेंज को एक रंग ग्रेडिएंट योजना में परिवर्तित करता है, जिसमें लाल रंग न्यूनतम मानों को दर्शाता है और हरा रंग संबंधित डेटा शृंखला के उच्चतम मानों को दर्शाता है।

3. हीटमैप, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मालवाहक और होटल कमरा बुकिंग को छोड़कर, अप्रैल 2023 से जुलाई 2025 तक के आधार पर तैयार किया गया है, जहां, आंकड़े जून 2025 तक के हैं। पर्यटकों के आगमन का नवीनतम आंकड़ा अप्रैल 2025 तक का है।

4. जुलाई 2025 की वृद्धि दर के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात के आंकड़ों की गणना दैनिक आंकड़ों को एकत्रित करके की जाती है।

5. सभी पीएमआई मान सूचकांक के रूप में दर्शाए जाते हैं। 50 से अधिक पीएमआई मान विस्तार, 50 से कम संकुचन और 50 'कोई परिवर्तन नहीं' को दर्शाता है। पीएमआई हीटमैप में, लाल रंग न्यूनतम मान, पीला रंग 50 (या कोई परिवर्तन नहीं) और हरा रंग प्रत्येक पीएमआई शृंखला में उच्चतम मान को दर्शाता है।

स्रोत: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए); भारतीय बंदरगाह संघ; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण: एचवीएस एनारॉक; पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार: संयुक्त संयंत्र समिति: आर्थिक सलाहकार कार्यालय; और एस एंड पी ग्लोबल।

मुद्रास्फीति

जुलाई में लगातार नौवें महीने हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई, जो जून 2017 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई। इसकी वजह खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि और कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) में नरमी रही।[19] अखिल भारतीय सीपीआई मुद्रास्फीति जून में 2.1 प्रतिशत की तुलना में जुलाई 2025 में 1.6 प्रतिशत रही (चार्ट III.11)। मजबूत अनुकूल आधार प्रभाव, जो आंशिक

चार्ट III.11: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और चालक

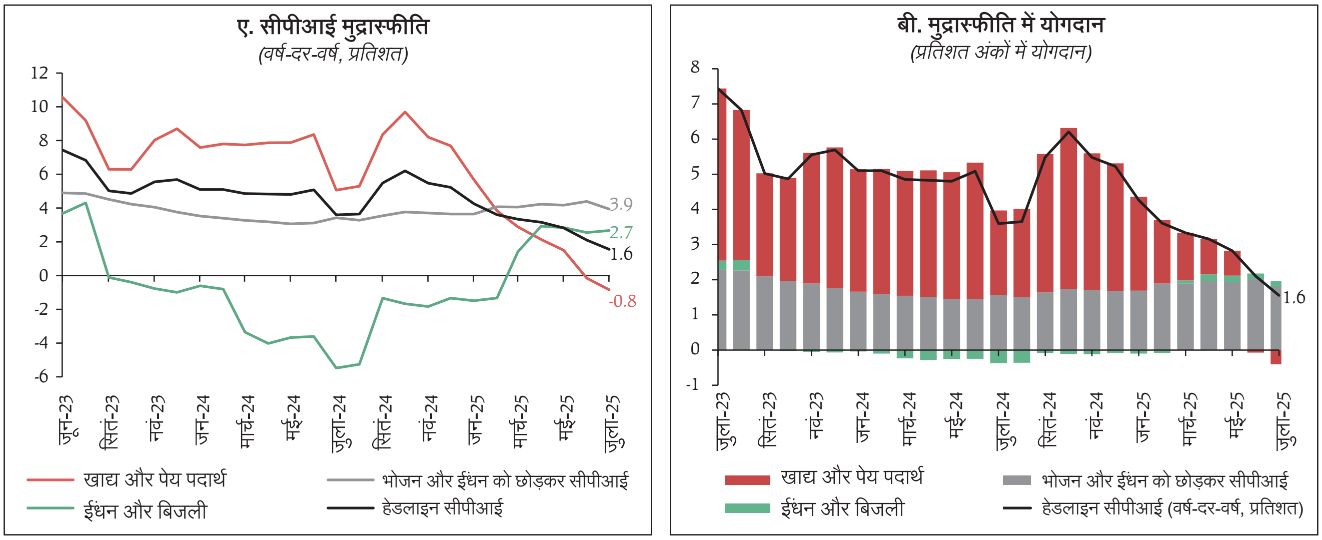

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[19] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 12 अगस्त 2025 को जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

चार्ट III.12: सीपीआई हेडलाइन: गति और आधार प्रभाव

(प्रतिशत बिंदु)

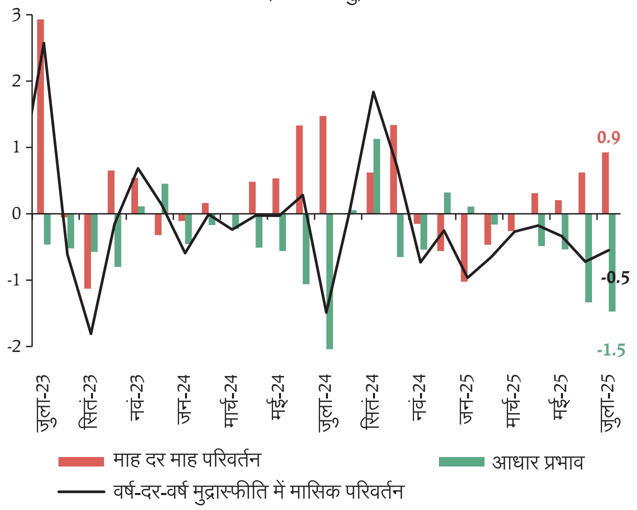

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

रूप से सकारात्मक मूल्य गति से संतुलित रहे, ने भी हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट में योगदान दिया (चार्ट III.12)।

सब्जियों, दालों, मसालों और मांस एवं मछली उप-समूहों में अपस्फीति के कारण खाद्य मुद्रास्फीति 78 महीनों में अपने निम्नतम स्तर पर आ गई।[20] अनाज, अंडे, दूध और उत्पादों, चीनी और मिष्ठान्नों में मुद्रास्फीति कम हुई, जबकि तेल और वसा, गैर-अल्कोहल पेय, फल और तैयार भोजन में मुद्रास्फीति बढ़ी (चार्ट III.13)।

जुलाई में ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई, जिसमें एलपीजी के लिए मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही, जबकि बिजली के लिए कम रही।[21] तथापि, केरोसिन की कीमतों में धीमी गति से अपस्फीति जारी रही।

कोर मुद्रास्फीति जून के 4.4 प्रतिशत से घटकर जुलाई 2025 में 3.9 प्रतिशत हो गई। मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्यतः परिवहन, संचार और शिक्षा उप-समूहों के कारण हुई, जबकि स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देखभाल तथा उससे संबंधित क्षेत्रों में मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हुई। कपड़ों और जूतों में मुद्रास्फीति में मामूली कमी दर्ज की गई, जबकि पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों, घरेलू सामान और सेवाओं, तथा आवास में मुद्रास्फीति अपरिवर्तित रही।

जुलाई में ग्रामीण और शहरी दोनों ही मुद्रास्फीति क्रमशः 1.2 प्रतिशत और 2.0 प्रतिशत तक कम हो गई। राज्य-स्तरीय मुद्रास्फीति दरें (-) 0.61 प्रतिशत और 8.89 प्रतिशत के बीच रहीं, जबकि अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत से कम रही (चार्ट III.14)।

चार्ट III.13: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

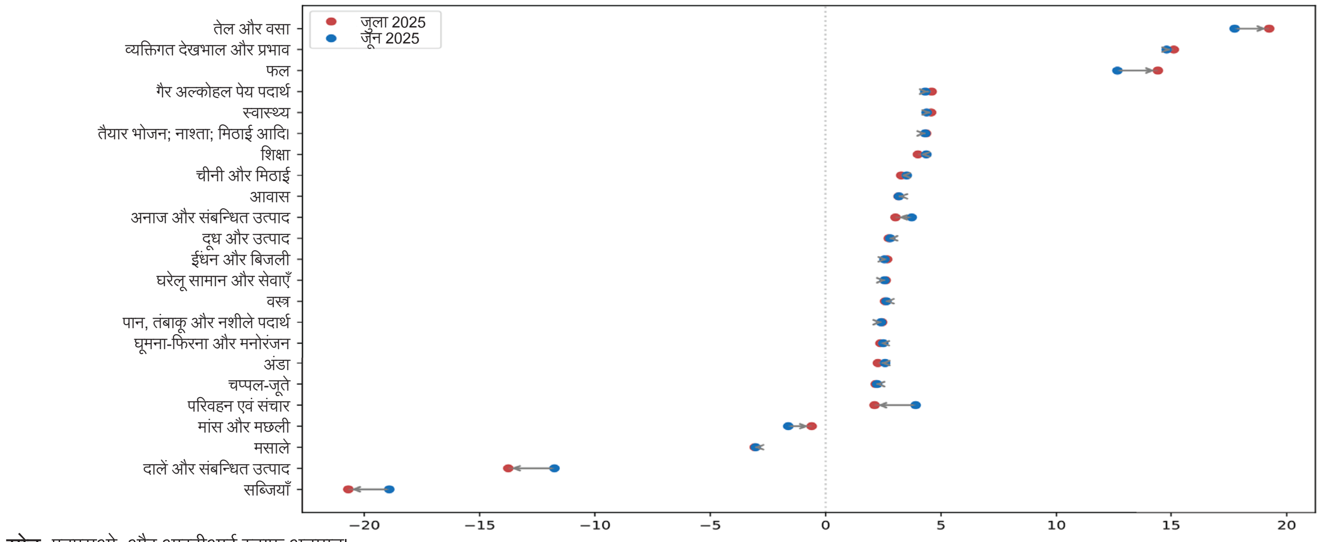

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[20] जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति (-)0.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी।

[21] जुलाई में ईंधन एवं प्रकाश उपसमूह में मुद्रास्फीति 2.7 प्रतिशत थी।

चार्ट III.14: मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण: जुलाई 2025 (सीपीआई-संयुक्त)

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

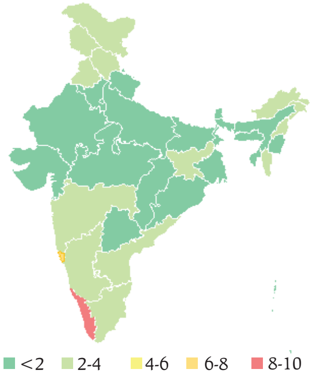

मुद्रास्फीति सीमा	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या
<2	20
2-4	14
4-6	1
6-8	1
8-10	1

मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या
गिरावट	32
स्थिर	0
बढ़ोतरी	5

नोट: मानचित्र केवल उदाहरण के लिए है।
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अगस्त के अब तक (22 तारीख तक) उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य आँकड़े अनाज की कीमतों में वृद्धि दर्शाते हैं। दालों में मिला-जुला रुख रहा, तुअर/ अरहर दाल की कीमतों में गिरावट और चना दाल की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई। खाद्य तेलों में, सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली और सोयाबीन तेलों की कीमतों में मजबूती आई, जबकि पाम तेल की कीमतें स्थिर रहीं। प्रमुख सब्जियों में, टमाटर की कीमतों में वृद्धि जारी रही। आलू और प्याज की कीमतें स्थिर रहीं (चार्ट III.15)।

अगस्त में पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा बिक्री कीमतें अपरिवर्तित रहीं। केरोसिन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जबकि रसोई गैस की कीमतें अपरिवर्तित रहीं (सारणी III.6)।

जुलाई के पीएमआई ने विनिर्माण और सेवाओं के लिए इनपुट कीमतों में वृद्धि की दर में क्रमिक वृद्धि दर्ज की। सेवाओं और विनिर्माण दोनों फर्मों के लिए विक्रय मूल्यों में भी वृद्धि हुई (अनुलग्नक चार्ट A7)।

चार्ट III.15: आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

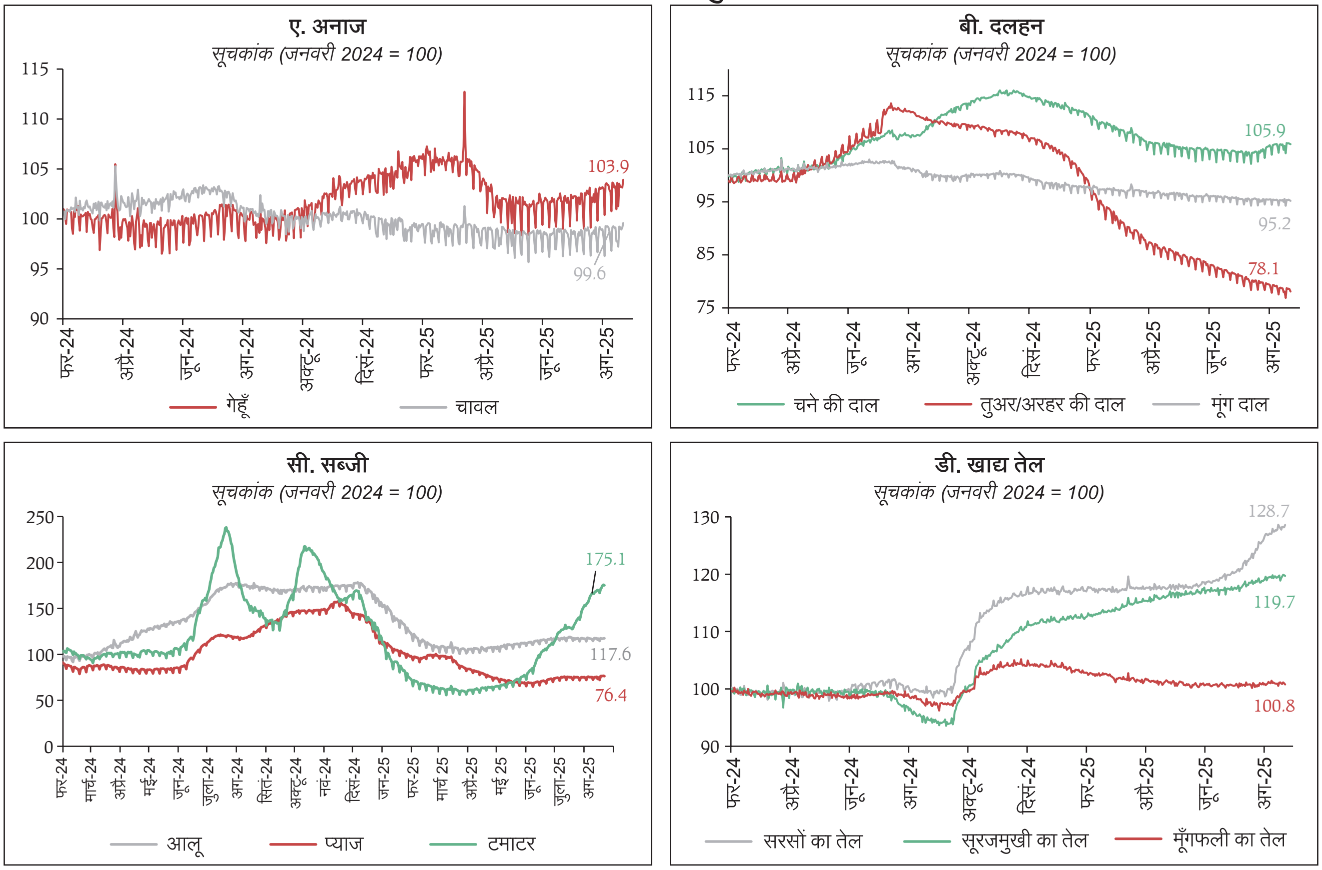

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी III.6: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

वस्तु	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		अग-24	जुला-24	अग-25 ^	जुला-25	अग-25 ^
पेट्रोल	₹/लीटर	100.97	101.12	101.12	0.0	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	90.42	90.53	90.53	0.0	0.0
केरोसिन (सब्सिडी वाला)	₹/लीटर	46.65	43.03	44.47	7.1	3.4
एलपीजी (गैर-सब्सिडी)	₹/सिलेंडर	813.25	863.25	863.25	0.0	0.0

टिप्पणियाँ: 1. ^ : 1-22 अगस्त, 2025 की अवधि के लिए।

2. केरोसिन के अलावा, ये कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसिन के लिए, ये कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाले मूल्यों का औसत दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट III.16: ग्रामीण नाममात्र मजदूरी

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

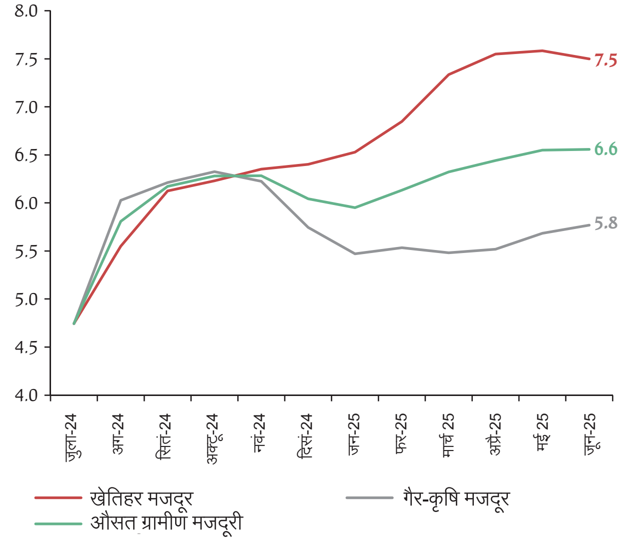

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय।

जून 2025 में ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी वृद्धि काफी हद तक स्थिर रही क्योंकि गैर-कृषि क्षेत्र की मजदूरी में बढ़ोतरी हुई, जबकि कृषि क्षेत्र में मजदूरी वृद्धि में मामूली सुधार देखा गया (चार्ट III.16)। गैर-कृषि मजदूरी वृद्धि में वृद्धि मुख्य रूप से झाड़ू लगाने/सफाई, हल्के मोटर वाहन और ट्रैक्टर चालकों, तथा राज मिस्त्री श्रमिकों जैसे व्यवसायों से प्रेरित थी।

IV. वित्तीय स्थितियाँ

जुलाई और अगस्त (21 अगस्त तक) के दौरान समग्र वित्तीय स्थितियाँ अनुकूल रहीं [चार्ट IV.1]।

चार्ट IV.1: भारत के लिए दैनिक वित्तीय स्थिति सूचकांक

(2012 से औसत मान से मानक विचलन)

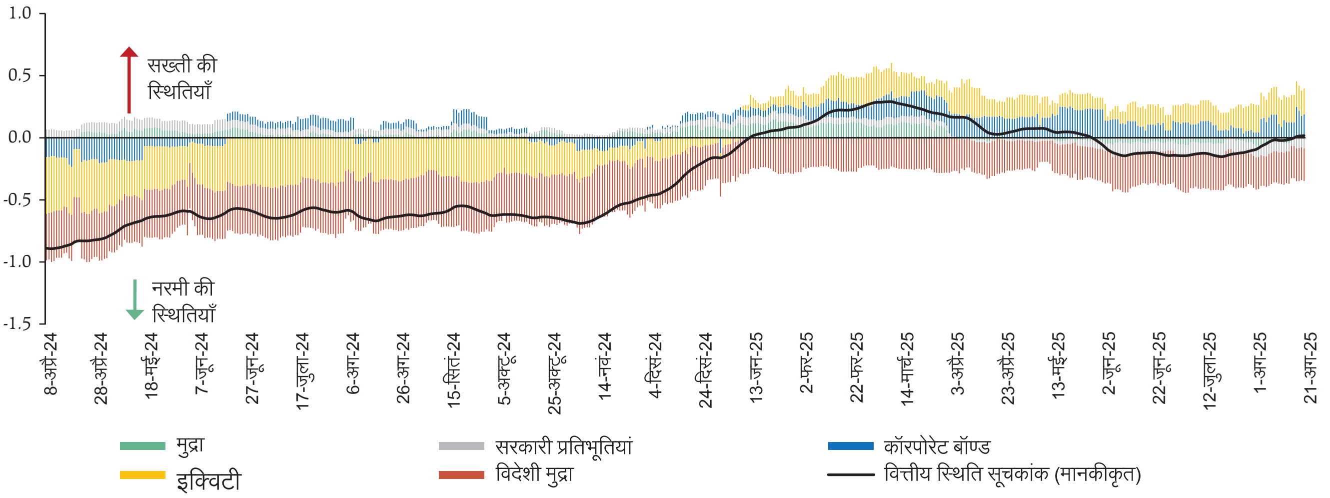

टिप्पणी: वित्तीय स्थिति सूचकांक अपने ऐतिहासिक औसत पर आधारित एक मीट्रिक प्रदान करता है: इस संदर्भ में, शून्य मान उस वित्तीय प्रणाली से मेल खाता है जो सूचकांक में शामिल सभी वित्तीय संकेतकों के ऐतिहासिक औसत स्तर पर कार्य कर रही है। परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए, मानकीकृत सूचकांक का उपयोग किया जाता है।[22]

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

[22] विस्तृत कार्यप्रणाली के लिए, बंद्योपाध्याय, पी., कुमार, ए., कुमार, पी. और भट्टाचार्य, आई. (2025), 'भारत के लिए वित्तीय स्थिति सूचकांक: एक उच्च आवृत्ति दृष्टिकोण'; भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, जून HTTPS://RBI.ORG.IN/SCRIPTS/BS_VIEWBULLETIN.ASPX?ID=23451 देखें।

जुलाई और अगस्त (21 अगस्त तक) के दौरान प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में रही, जो मुख्य रूप से उच्च सरकारी खर्च से प्रेरित थी। 16 जुलाई से 21 अगस्त, 2025 के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण ₹3.07 लाख करोड़ रहा, जो पिछले एक महीने की अवधि (चार्ट IV.2) की तुलना में मामूली कम है। इस अवधि के दौरान, अतिरिक्त चलनिधि को अवशोषित करने के लिए, जो एक दिवसीय मुद्रा बाजार दरों पर दबाव डाल रही थी, रिज़र्व बैंक ने 12 परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामियां (ओवरनाइट से 8-दिवसीय) संचालित कीं।[23] कर संबंधी बहिर्वाह के कारण अस्थायी चलनिधि की तंगी से निपटने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 2-दिवसीय और एक दिवसीय परिपक्वता वाली तीन परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामियां भी संचालित कीं। [24]

मुद्रा बाजार

पर्याप्त चलनिधि के बीच, भारित औसत कॉल दर – मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य – गलियारे के निचले आधे हिस्से में गतिमान रही। हालाँकि, यह दर बड़े जीएसटी बहिर्वाह के कारण 21 जुलाई से 23 जुलाई के दौरान सीमांत स्थायी सुविधा दर की ओर थोड़ी बढ़ गई। वीआरआरआर नीलामियों के माध्यम से अधिशेष चलनिधि अवशोषण के परिणामस्वरूप, भारित औसत कॉल दर और पॉलिसी रेपो दर के बीच का अंतर कम हो गया (चार्ट IV.3ए)।[25] संपार्श्विक खंडों में एकदिवसीय दरें – त्रिपक्षीय और बाजार रेपो – तथा बेंचमार्क सुरक्षित एकदिवसीय रुपया दर बड़े पैमाने पर गैर-संपार्श्विक दर के अनुरूप चलीं।[26] हाल ही में, रिज़र्व बैंक के मौजूदा चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह ने मौद्रिक नीति के परिचालन

चार्ट IV.2: चलनिधि परिचालन

(₹ लाख करोड़)

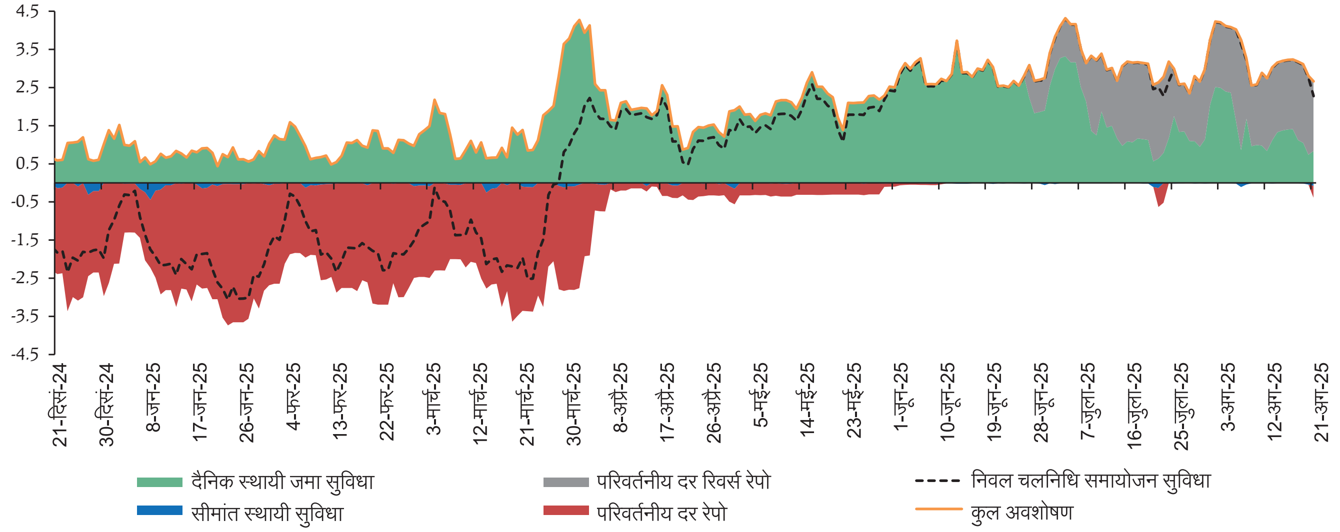

स्रोत: आरबीआई।

[23] तदनुसार, स्थायी जमा सुविधा के माध्यम से औसत अवशोषण 16 जुलाई से 21 अगस्त 2025 के दौरान कुल अवशोषण का 40.3 प्रतिशत रह गया, जबकि 16 जून से 15 जुलाई 2025 के दौरान यह 76.3 प्रतिशत था।

[24] औसतन 0.02 लाख करोड़ रु.

[25] भारित औसत माँग दर और रेपो दर के बीच का स्प्रेड 16 जुलाई से 14 अगस्त 2025 के दौरान (-) 6 बीपीएस तक कम हो गया, जो 16 जून से 21 जुलाई 2025 के दौरान (-)19 बीपीएस था।

[26] एमआईबीओआर बेंचमार्क समिति (अध्यक्ष: श्री रामानाथन सुब्रमण्यन) की सिफारिशों के अनुरूप, सुरक्षित मुद्रा बाजारों (बास्केट रेपो और त्रिपक्षीय रेपो दोनों) पर आधारित एक बेंचमार्क सुरक्षित एक-दिवसीय रुपया दर विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था। फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने दैनिक अंतराल पर इस दर का प्रकाशन शुरू कर दिया है।

चार्ट IV.3: नीति गलियारा और मुद्रा बाजार दरें

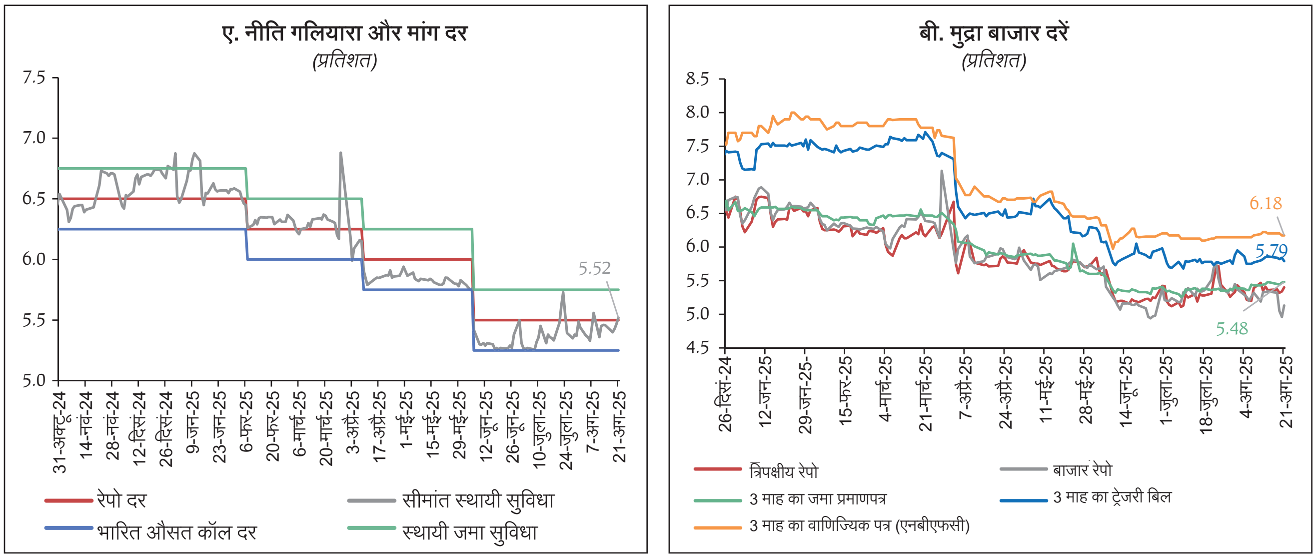

स्रोत: आरबीआई; भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड; और ब्लूमबर्ग।

लक्ष्य के रूप में भारित औसत कॉल दर को जारी रखने की सिफारिश की है।[27]

कुल मिलाकर, सावधि मुद्रा बाज़ार में ब्याज दरें मोटे तौर पर स्थिर रहीं (चार्ट IV.3बी)। [28] ट्रेजरी बिलों के लिए औसत प्रतिफल मामूली रूप से बढ़ी, जबकि वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों की दरें कम हुईं। [29]

सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार

निश्चित आय खंड में, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं को लेकर अनिश्चितताओं और मौद्रिक नीति में और ढील की उम्मीदों में कमी के बीच, 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल जुलाई के मध्य से अगस्त के प्रारंभ तक मज़बूत हुआ। 14 अगस्त, 2025 को एसएंडपी द्वारा भारत की राष्ट्रिक रेटिंग में सुधार की घोषणा के बाद, 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में कुछ समय के लिए कमी आई। इसके बाद, अगस्त के तीसरे सप्ताह में प्रतिफल में और वृद्धि हुई। औसत अवधि प्रीमियम (10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल और 91-दिवसीय ट्रेजरी बिल पर प्रतिफल के बीच का अंतर) 16 जून से 15 जुलाई, 2025 की तुलना में 16 जुलाई से 21 अगस्त, 2025 के दौरान 3 आधार अंकों से (बीपीएस) बढ़ा (चार्ट IV.4ए और IV.4बी)।

कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार

कॉरपोरेट बॉण्ड के प्रतिफल और साथ ही संबंधित जोखिम-मुक्त दरों पर उनका प्रसार आम तौर पर अवधि और रेटिंग स्पेक्ट्रम में बढ़ा (सारणी IV.1)[30]

धन और ऋण

नकद आरक्षित अनुपात में बदलावों के पहले दौर के प्रभाव को समायोजित करते हुए, प्रचलन में मुद्रा में वृद्धि के अनुरूप, आरक्षित मुद्रा वृद्धि, महीने के दौरान बढ़ी। त्योहारी सीज़न से

[27] भारित औसत माँग दर, संपार्श्विक खंडों में अन्य एक-दिवसीय मुद्रा बाजार दरों के साथ अत्यधिक सहसंबद्ध पाई गई है और विभिन्न परिपक्वताओं में अन्य मुद्रा बाजार लिखतों को संकेत प्रेषित करने में भी प्रभावी पाई गई है। अधिक जानकारी चलनिधि प्रबंधन ढाँचे की समीक्षा हेतु गठित आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट - जुलाई 2025 HTTPS://RBIDOCS.RBI.ORG.IN/RDOCS//PUBLICATIONREPORT/PDFS/IWG060820254255B36745A04F23A683956447CB227A.PDF में पाई जा सकती है।

[28] 16 जुलाई से 21 अगस्त 2025 की अवधि के दौरान 3 महीने के ट्रेजरी बिलों पर औसत प्रतिफल में 6 बीपीएस की वृद्धि हुई, जबकि एनबीएफसी द्वारा जारी 3 महीने के वाणिज्यिक पत्रों और 3 महीने के जमा प्रमाणपत्र के औसत प्रतिफल में 16 जून से 15 जुलाई 2025 की अवधि की तुलना में क्रमशः 1 बीपीएस और 3 बीपीएस की गिरावट आई।

[29] मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (एनबीएफसी द्वारा 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र पर प्रतिफल और 91-दिवसीय ट्रेजरी बिल के बीच का स्प्रेड) पिछली अवधि के 82 बीपीएस से घटकर चालू अवधि में 75 बीपीएस हो गया।

[30] जून 2025 तक कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गम ₹1.08 लाख करोड़ के उच्च स्तर पर रहा, जो मई 2025 में 0.95 लाख करोड़ था।

चार्ट IV.4: सरकारी प्रतिभूतियों के बाज़ार में गतिविधि

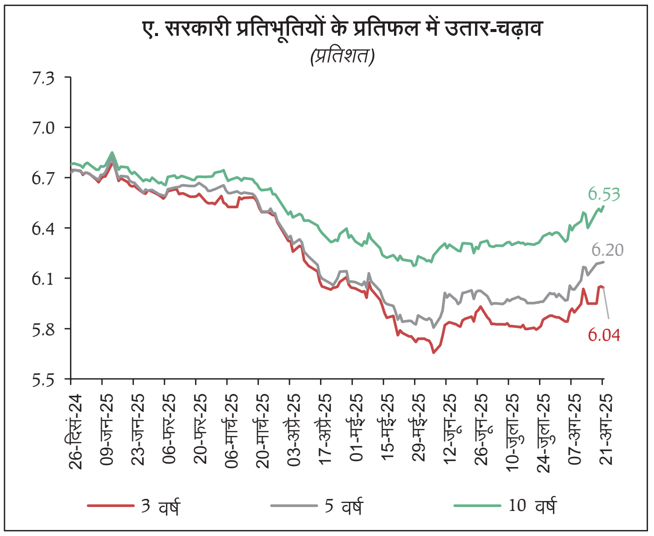

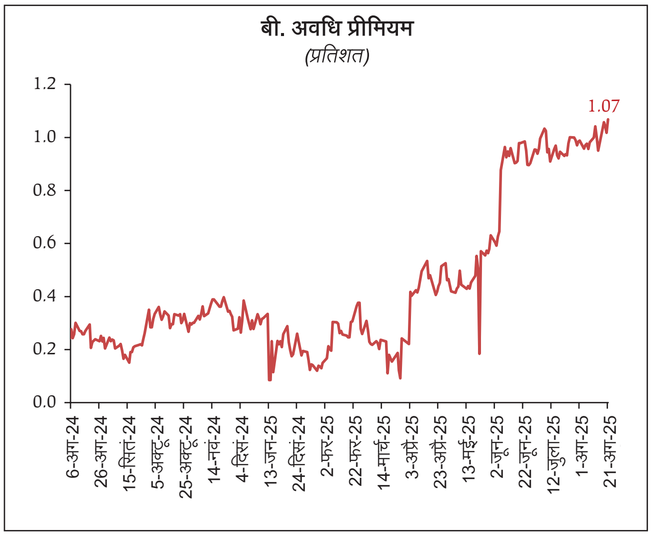

टिप्पणी: चार्ट बी में, सावधि प्रीमियम की गणना 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल और 91-दिवसीय खजाना बिल प्रतिफल के बीच के अंतर के रूप में की जाती है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग: एफआईएमएमडीए; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

पहले और ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वापसी के प्रभाव में कमी आने से पहले प्रचलन में मुद्रा में वृद्धि हुई। जुलाई के दौरान मुद्रा आपूर्ति (एम3) में वृद्धि मोटे तौर पर स्थिर रही (चार्ट IV.5)।[31, 32]

जुलाई में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि धीमी बनी रही, जबकि पिछले महीने की तुलना में इसमें मामूली वृद्धि हुई, जबकि जमा वृद्धि स्थिर रही (चार्ट IV.6 और अनुलग्नक चार्ट ए9)। 33 2025-26 के दौरान अब तक, जबकि गैर-खाद्य बैंक ऋण प्रवाह में गिरावट आई है, यह कमी गैर-बैंक स्रोतों से अधिक अंतर्वाह से काफी हद तक संतुलित रही। परिणामस्वरूप, बैंक ऋण में धीमी वृद्धि के बावजूद, वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों के कुल प्रवाह में वृद्धि दर्ज की गई। मुद्रा

सारणी IV.1: कॉरपोरेट बॉण्ड- दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें *(प्रतिशत)*			स्प्रेड *(बीपीएस)* (संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक)		
	16 जून 2025-15 जुलाई 2025	16 जुलाई 2025-20 अगस्त 2025	अंतर (बीपीएस में)	16 जून 2025-15 जुलाई 2025	16 जुलाई 2025-20 अगस्त 2025	अंतर (बीपीएस में)
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉरपोरेट बॉण्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	6.55	6.54	-1	95	92	-3
(ii) एएए (3-वर्ष)	6.91	6.97	6	95	97	2
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.13	7.13	0	96	93	-3
(iv) एए (3-वर्ष)	7.84	8.03	19	188	203	15
(v) बीबीबी- (3-वर्ष)	11.49	11.66	17	553	566	13

टिप्पणी: संबंधित अवधि के लिए प्रतिफल और स्प्रेड की गणना औसत के रूप में की गई है।
स्रोत: फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) और ब्लूमबर्ग।

[31] 15 अगस्त 2025 तक आरक्षित मुद्रा (सीआरआर के लिए समायोजित) में 8.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई [18 जुलाई 2025 तक 7.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)]। 15 अगस्त 2025 तक प्रचलन में मुद्रा में 8.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई [18 जुलाई 2025 तक 7.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)]।

[32] 8 अगस्त 2025 तक मुद्रा आपूर्ति में 9.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई [11 जुलाई 2025 तक 9.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)]। इसमें एक गैर-बैंक के किसी बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है (1 जुलाई 2023 से प्रभावी)।

[33] 8 अगस्त, 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि 10.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी [एक महीने पहले 9.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)]। 8 अगस्त 2025 तक जमा वृद्धि 10.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी [एक महीने पहले 10.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)]।

चार्ट IV. 5: आरक्षित मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति (एम$_3$) में वृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

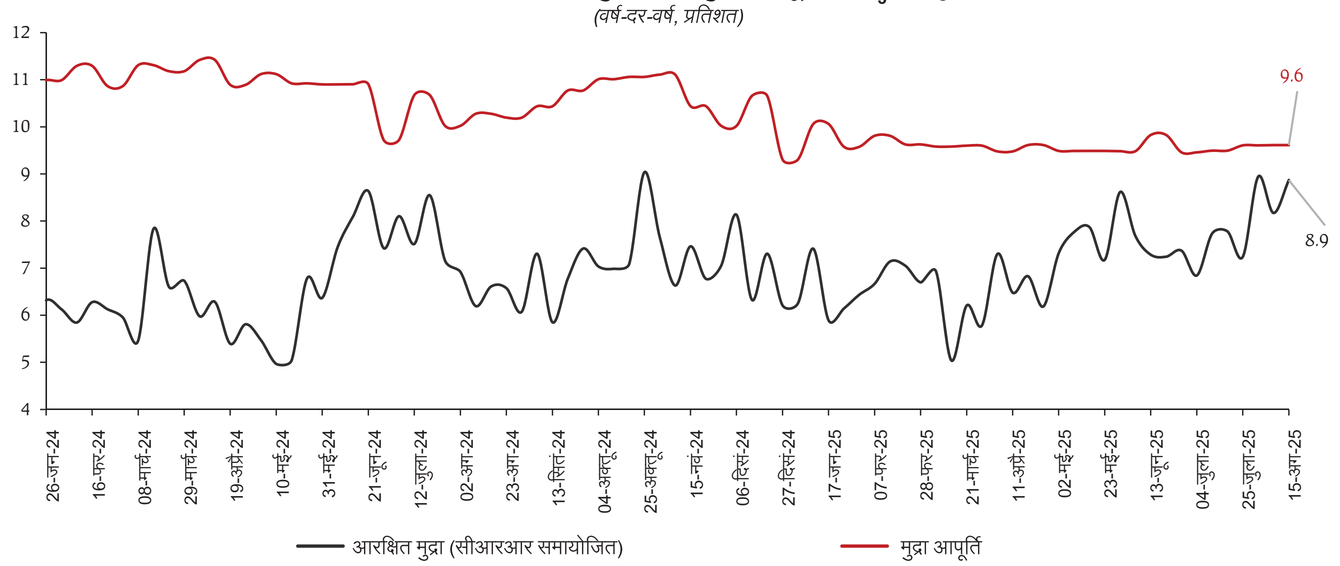

स्रोत: आरबीआई।

बाजारों में मौद्रिक नीति के तीव्र संचरण के साथ, बड़ी कंपनियाँ वित्तपोषण के लिए वाणिज्यिक पत्र और कॉरपोरेट बॉण्ड जैसे बाजार-आधारित लिखतों की ओर तेजी से मुड़ रही हैं, जिससे बैंक ऋण की माँग कम हो रही है।

जून में सभी प्रमुख क्षेत्रों में बैंक ऋण वृद्धि में मामूली सुधार दर्ज किया गया (अनुलग्नक चार्ट ए10)।[34,35] ऋण वृद्धि के प्राथमिक चालक, व्यक्तिगत ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इसे मुख्यतः आवास क्षेत्र जो व्यक्तिगत ऋणों के अंतर्गत

चार्ट IV.6: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक: ऋण और जमा वृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

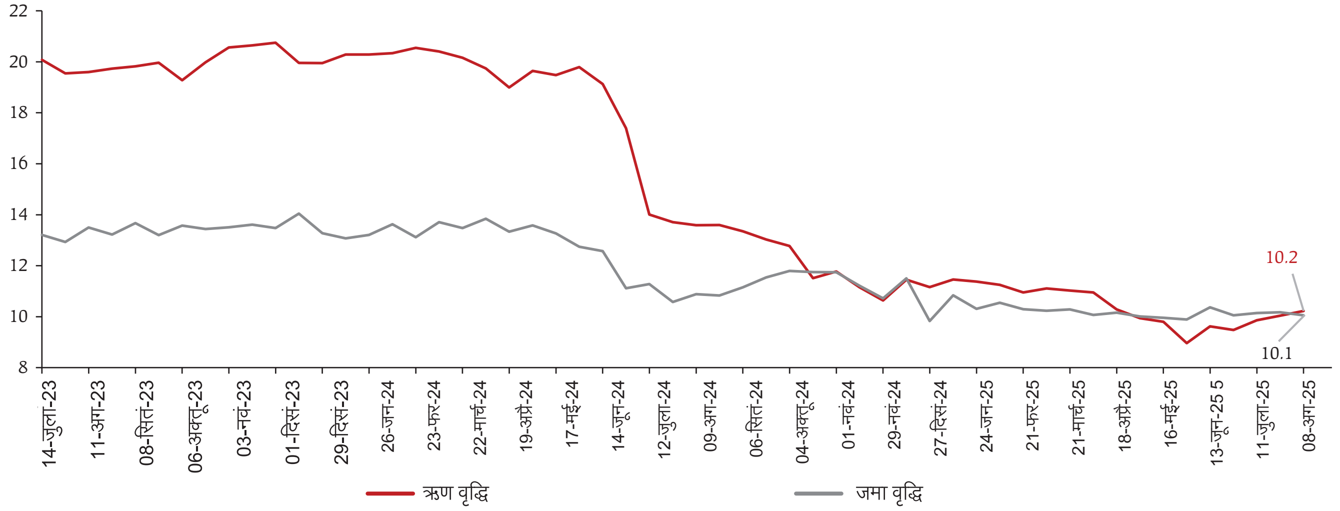

टिप्पणी: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के डेटा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। इस डेटा में एक बैंक में एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

स्रोत: पाक्षिक सेक्शन 42 रिटर्न्स, आरबीआई।

34 जून के अंत तक, गैर-खाद्य बैंक ऋण में वृद्धि 10.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही, जो मई 2025 में दर्ज 9.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) से अधिक है।

35 क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण आँकड़े क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं, जिसमें चुनिंदा बैंक शामिल हैं, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार तक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत प्रदान करते हैं। इस आँकड़े में किसी गैर-बैंक के किसी बैंक में विलय का प्रभाव शामिल नहीं है।

दिए गए ऋणों का लगभग आधा हिस्सा है, के माध्यम से समर्थन प्राप्त हुआ। साथ ही वाहन ऋण और अन्य व्यक्तिगत ऋणों में भी वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि एनबीएफसी को प्रदत्त बैंक ऋण सकारात्मक हो गया, जिससे पिछले महीने देखी गई गिरावट उलट गई। फिर भी, इन संस्थाओं ने मुद्रा और पूँजी बाजार के माध्यम से धन प्राप्त करना जारी रखा। औद्योगिक ऋण में भी सुधार देखा गया। जहाँ अवसंरचना क्षेत्र में संकुचन जारी रहा, वहीं एमएसएमई को प्रदत्त ऋण में तेज गति से वृद्धि हुई।

जमा और उधार दरें

फरवरी 2025 से जून 2025 के दौरान रेपो दर में हुई संचयी 100-आधार अंकों की कमी का प्रभाव अंतरण उधार और जमा दरों, विशेष रूप से नई जमा और ऋणों पर, मज़बूत रहा है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर में गिरावट आई है। जमा पक्ष पर, नए और बकाया जमा पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरें भी कम हुई हैं (सारणी IV.2)।

नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर में गिरावट निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधिक थी (चार्ट IV.7)। इसी प्रकार, जमा पक्ष में, निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संचरण अधिक था।

इक्विटी बाजार

जुलाई में सुस्त टैरिफ़ अनिश्चितता और 2025-26 की पहली तिमाही के मिश्रित कॉरपोरेट आय परिणामों के बीच इक्विटी बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। घरेलू संस्थागत निवेशकों, विशेष रूप से म्यूचुअल फंडों से लगातार अंतर्वाह के चलते इक्विटी से एफपीआई के बहिर्वाह के प्रभाव को कम करने में सहायता मिली। अगस्त की शुरुआत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के शेयरों में बढ़त के कारण हुआ मामूली सुधार भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को लेकर फैली नई अनिश्चितता के कारण फीका पड़ गया। भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार और जीएसटी सुधारों की घोषणा को लेकर उपजे आशावाद के बीच बाज़ारों में बाद में सुधार हुआ (चार्ट IV.8)।

वित्त के बाह्य स्रोत

जून में सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) चार वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया (चार्ट IV.9ए)। अमेरिका, साइप्रस और सिंगापुर ने कुल एफडीआई अंतर्वाह में तीन-चौथाई से अधिक का योगदान दिया। कंप्यूटर सेवाएँ, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र शीर्ष प्राप्तकर्ता क्षेत्र थे। हालाँकि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रत्यावर्तन और बाह्य

सारणी IV.2: बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंकों में भिन्नता)

अवधि		सावधि जमा दरें		उधार दरें				
	रेपो दर	डब्लयूएडी-टीडीआर-नया जमा	डब्लूयूएडी-टीडीआर-बकाया जमा	ईबीएलआर	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	डब्ल्यूएएलआर -नया रुपया उधार		डब्ल्यूए-एलआर-बकाया रुपया उधार
						समग्र	ब्याज दर प्रभाव #	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
सख्ती की अवधि मई 2022 से जनवरी 2025	+250	259	206	250	175	181	193	115
नरमी की अवधि फरवरी 2025 से जुलाई* 2025	-100	-87	-10	-100	-25	-71	-55	-39

टिप्पणी: ईबीएलआर पर डेटा 32 घरेलू बैंकों से संबंधित है।
*: डब्ल्यूएडीटीडीआर और डबल्यूएएलआर पर डेटा जून 2025 से संबंधित है। **#:** स्थिर मात्रा में।
डब्ल्यूएएलआर: भारित औसत उधार दर; **डब्ल्यूएडीटीडीआर:** भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर;
एमसीएलआर: निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर; **ईबीएलआर:** बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर।
स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.7: बैंक समूहों के बीच संचरण (फरवरी 2025 से जून 2025)

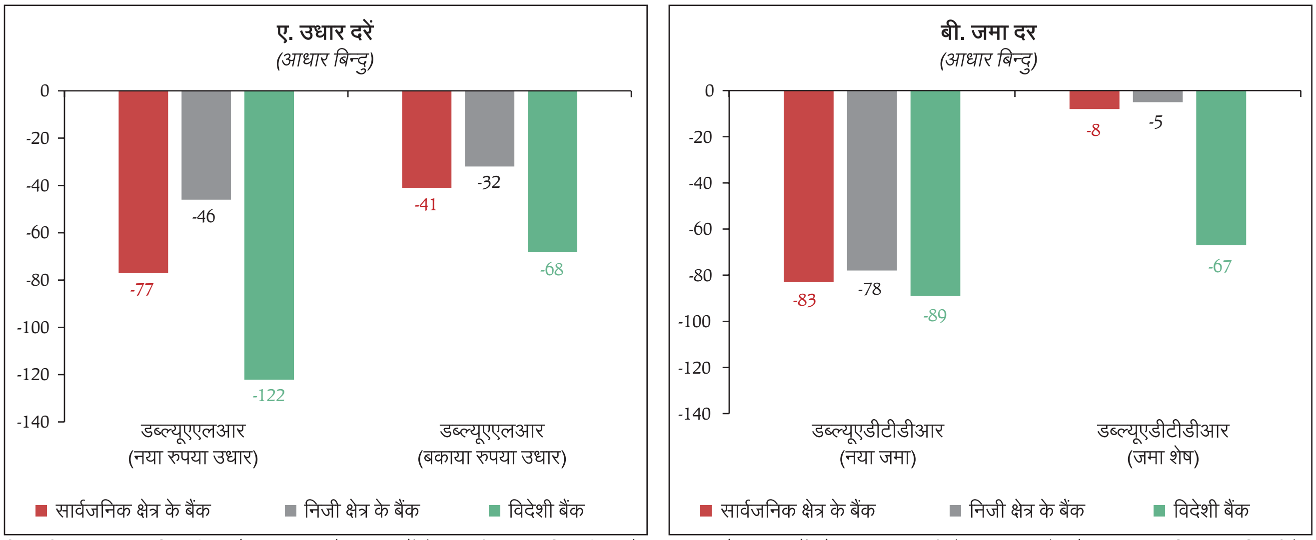

टिप्पणी: जून 2025 की भारित औसत उधार और जमा दरों से जनवरी 2025 की भारित औसत उधार और जमा दरों को घटाकर फरवरी से जून 2025 के दौरान संचरण की गणना की गई है।
स्रोत: आरबीआई।

एफडीआई दोनों में वृद्धि हुई। बाह्य एफडीआई के शीर्ष क्षेत्रों में वित्तीय, विनिर्माण, बीमा और व्यावसायिक सेवाएँ शामिल थीं, और प्रमुख गंतव्य सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात थे (चार्ट IV.9बी)। परिणामस्वरूप, निवल एफडीआई अंतर्वाह धीमा रहा।

जुलाई और अगस्त में एफपीआई ने निवल बहिर्वाह दर्ज किया, जिससे लगातार दो महीनों का अंतर्वाह उलट गया, क्योंकि वैश्विक व्यापार तनाव और अमेरिकी टैरिफ घोषणाओं के बाद जोखिम-मुक्ति के रुख के बीच इक्विटी बहिर्वाह में तेज़ी आई (चार्ट IV.10)। इसके विपरीत, ऋण खंड में मामूली निवल अंतर्वाह देखा गया, जिसे प्राथमिक ऋण निर्गमों और पूरी तरह

चार्ट IV.8: बीएसई सेंसेक्स और संस्थागत प्रवाह

(सूचकांक, बायाँ मान, ₹ हजार करोड़, दायाँ मान)

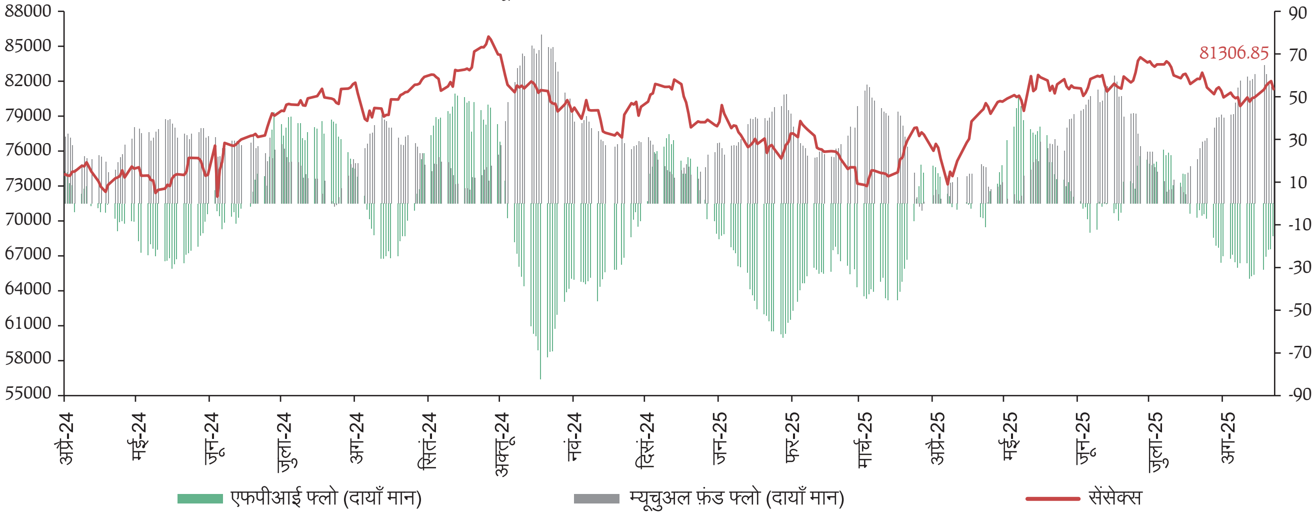

टिप्पणी: एफपीआई और एमएफ फ्लो को 15-दिवसीय रोलिंग सम आधार पर दर्शाया गया है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट IV.9: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

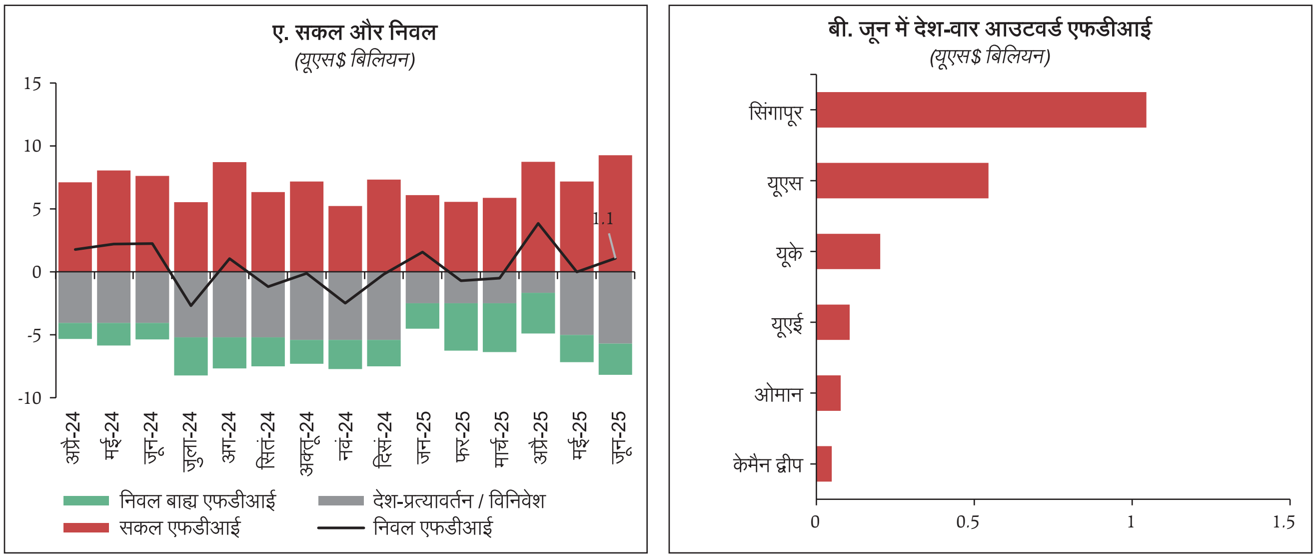

स्रोत: आरबीआई।

से सुलभ मार्ग के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में अंतर्वाह से समर्थन मिला।[36]

2025-26 की पहली तिमाही में बाह्य वाणिज्यिक उधारों के पंजीकरण में कमी आई, हालाँकि अंतर्वाह बहिर्वाह से अधिक रहा, जिसके परिणामस्वरूप निवल अंतर्वाह सकारात्मक रहा (चार्ट IV.11)। उल्लेखनीय है कि इस अवधि के दौरान पंजीकृत कुल बाह्य वाणिज्यिक उधारों का लगभग आधा हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए था।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त बना हुआ है, जो 11 महीने से अधिक के माल आयात और मार्च 2025 के अंत तक

चार्ट IV.10: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

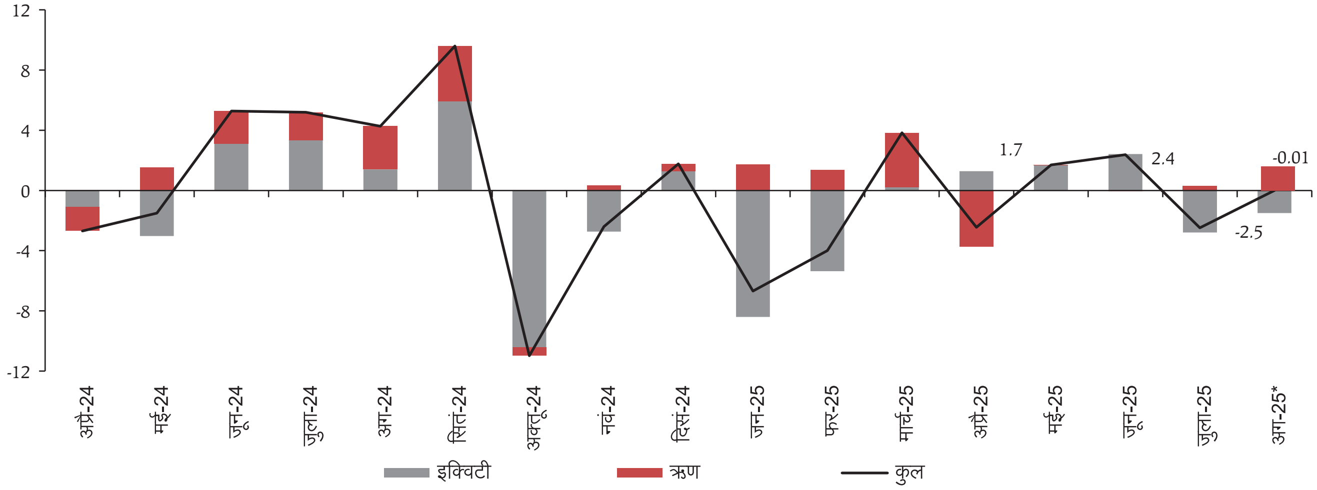

टिप्पणियाँ: 1. ऋण में हाइब्रिड लिखत के अंतर्गत निवेश भी शामिल है।
2. *डाटा 21 अगस्त तक का है।

स्रोत: नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)।

[36] पूर्णतः सुलभ मार्ग, आरबीआई द्वारा 1 अप्रैल, 2020 से शुरू किया गया एक अलग चैनल है, जो गैर-निवासियों को बिना किसी निवेश सीमा के भारत सरकार की निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने में सक्षम बनाता है।

चार्ट IV.11: बाहरी वाणिज्यिक उधार- पंजीकरण और प्रवाह

(यूएस $ बिलियन)

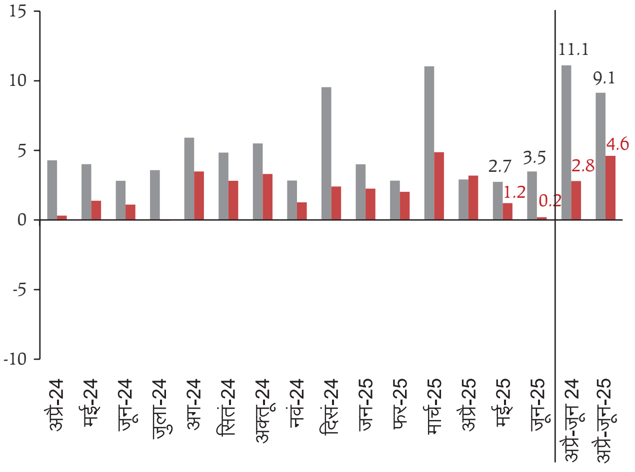

स्रोत: फॉर्म ईसीबी, आरबीआई।

चार्ट IV.12: भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ

(बिलियन अमेरिकी डॉलर, बायाँ स्केल, माह, दायाँ स्केल)

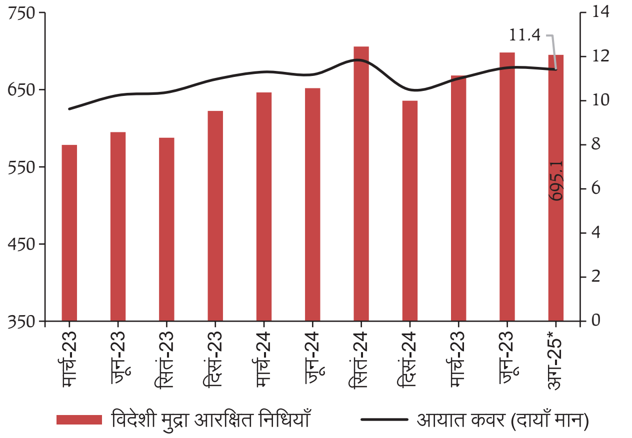

टिप्पणियाँ: 1. *15 अगस्त 2025 की स्थिति के अनुसार

2. भुगतान संतुलन के आंकड़ों के अनुसार, जून और अगस्त 2025 तक का आयात कवर डेटा 2024-25 के वार्षिक पण्य आयात पर आधारित है।

स्रोत: आरबीआई।

94 प्रतिशत से अधिक बकाया विदेशी ऋण के लिए कवर प्रदान करता है (चार्ट IV.12)।[37]

विदेशी मुद्रा बाजार

जुलाई में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में मामूली गिरावट आई, जो वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं और एफपीआई के बहिर्वाह को दर्शाता है (चार्ट IV.13)। इस गिरावट के बावजूद, रुपया महीने के दौरान प्रमुख ईएमडीई में सबसे कम अस्थिर मुद्राओं में से एक रहा। अगस्त में, एस&पी द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार की घोषणा के बाद, भारतीय रुपये ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कुछ बढ़त दर्ज की।

चार्ट IV.13: जुलाई 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले प्रमुख मुद्राओं में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत, माह-दर-माह, बायाँ मान, प्रतिशत, दायाँ मान)

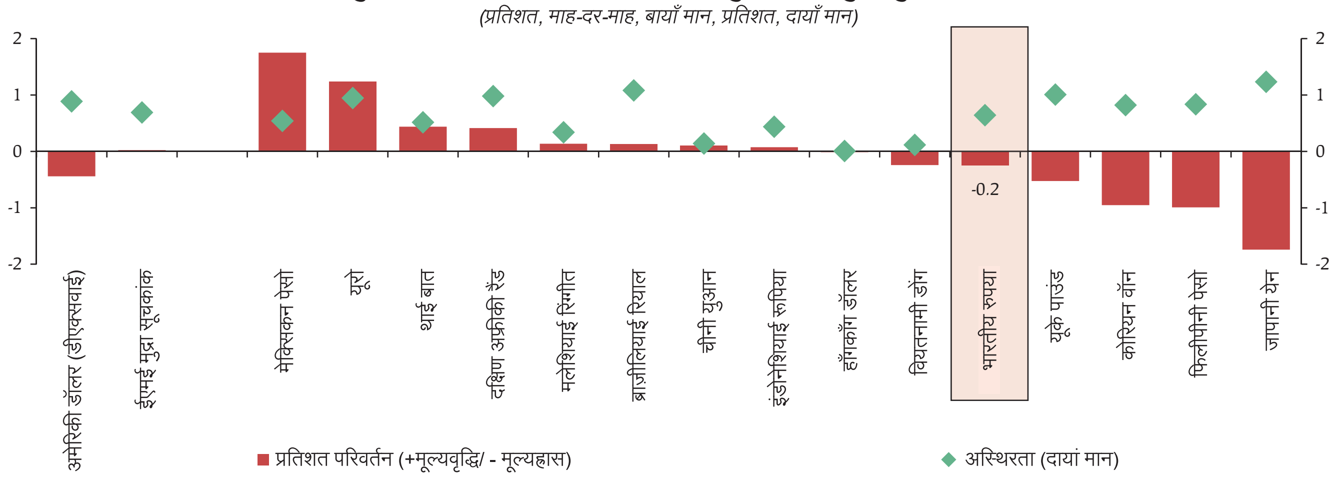

टिप्पणियां: 1. मूल्यवृद्धि/ मूल्यह्रास (माह-दर-माह) की गणना मासिक औसत विनिमय दरों का प्रयोग कर की गई है।

2. अमेरिकी डॉलर (डीएक्सवाई) प्रमुख मुद्रा समूह (यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कनाडाई डॉलर, स्वीडिश क्रोना, स्विस फ्रैंक) के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के उतार-चढ़ाव को मापता है।

3. जुलाई 2025 के लिए दैनिक विनिमय दर का प्रयोग कर प्रत्येक मुद्रा की अस्थिरता को चर(100*मानक विचलन/ माध्य मान) के गुणक के रूप में मापा गया है।

स्रोत: एफबीआईएल; थॉमसन रॉयटर्स; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान

[37] वस्तुओं और सेवाओं के लिए संयुक्त आयात कवर लगभग नौ महीने का था।

चार्ट IV.14: 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव

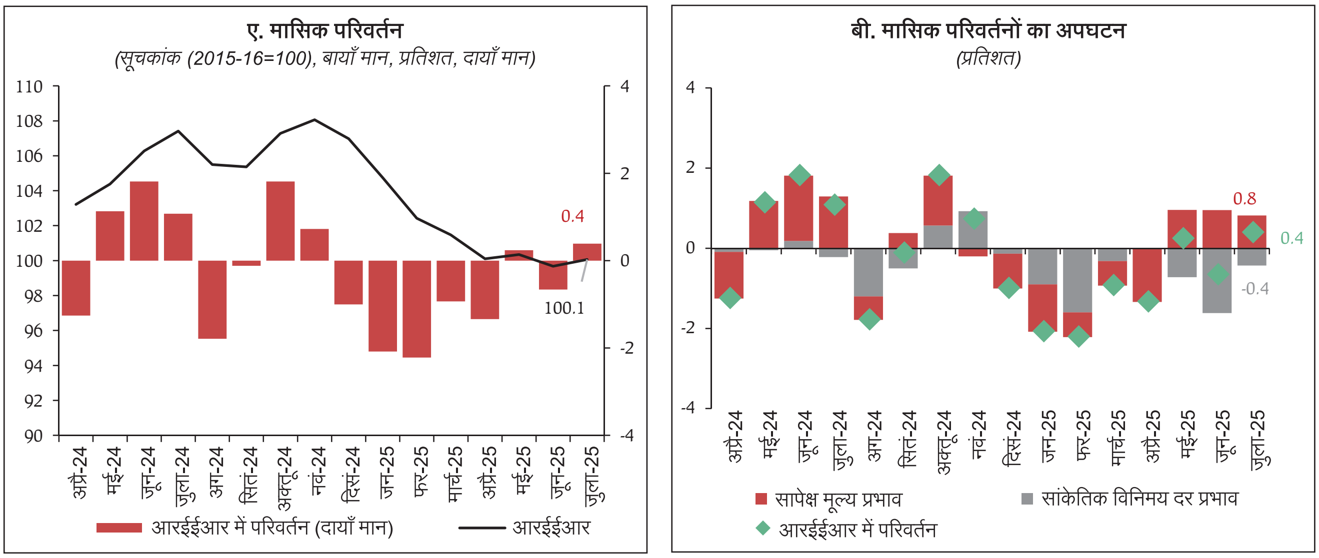

स्रोत: आरबीआई।

वास्तविक प्रभावी शर्तों में, जुलाई में भारतीय रुपये में वृद्धि हुई (चार्ट IV.14ए)। भारत की मुद्रास्फीति (माह-दर-माह आधार पर) उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की भारित औसत मुद्रास्फीति से अधिक थी, जो नाममात्र प्रभावी शर्तों में भारतीय रुपये के मूल्यह्रास से अधिक थी (चार्ट IV.14बी)।

V. निष्कर्ष

खरीफ कृषि मौसम के लिए अनुकूल वर्षा और तापमान की स्थिति शुभ संकेत हैं। वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में ग्रामीण माँग को बढ़ावा दे सकती है।38 अनुकूल वित्तीय स्थितियों, ब्याज दरों में कटौती के निरंतर प्रसार, सहायक राजकोषीय उपायों और बढ़ते घरेलू आशावाद के साथ, समग्र माँग को बनाए रखने के लिए वातावरण अनुकूल है। दूसरी ओर, भारत-अमेरिका व्यापार नीतियों से संबंधित निरंतर अनिश्चितताएँ नकारात्मक जोखिम पैदा कर रही हैं। निकट भविष्य के लिए मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण पहले के अनुमान से अधिक सौम्य हो गया है। अनुकूल आधार प्रभावों द्वारा समर्थित मंद खाद्य मूल्य दबावों से प्रेरित हेडलाइन मुद्रास्फीति के वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में धीरे-धीरे बढ़ने से पहले, दूसरी तिमाही में 4 प्रतिशत के लक्ष्य से और नीचे आने की संभावना है। कुल मिलाकर, इस वर्ष औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति के लक्ष्य से काफी नीचे रहने की उम्मीद है।39 आगे बढ़ते हुए, मौद्रिक नीति उपयुक्त मौद्रिक नीति पथ तैयार करने के लिए आने वाले आँकड़ों और विकसित हो रही घरेलू विकास-मुद्रास्फीति गतिशीलता पर कड़ी निगरानी बनाए रखेगी।

[38] 6 अगस्त 2025 के मौद्रिक नीति समिति के संकल्प में 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जिसमें पहली तिमाही में यह 6.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.3 प्रतिशत रहेगी। 2026-27 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया।

[39] 6 अगस्त 2025 के मौद्रिक नीति समिति के संकल्प में 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया, जिसमें दूसरी तिमाही में यह 2.1 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.1 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत रहेगी। 2026-27 की पहली तिमाही के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया।

अनुलग्नक

चार्ट ए1: वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक

टिप्पणी: सूचकांक रीडिंग सूचकांक के ऐतिहासिक औसत मान से मानक विचलन को मापता है।
स्रोत: फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क।

चार्ट ए3: उपभोक्ता विश्वास सूचकांक

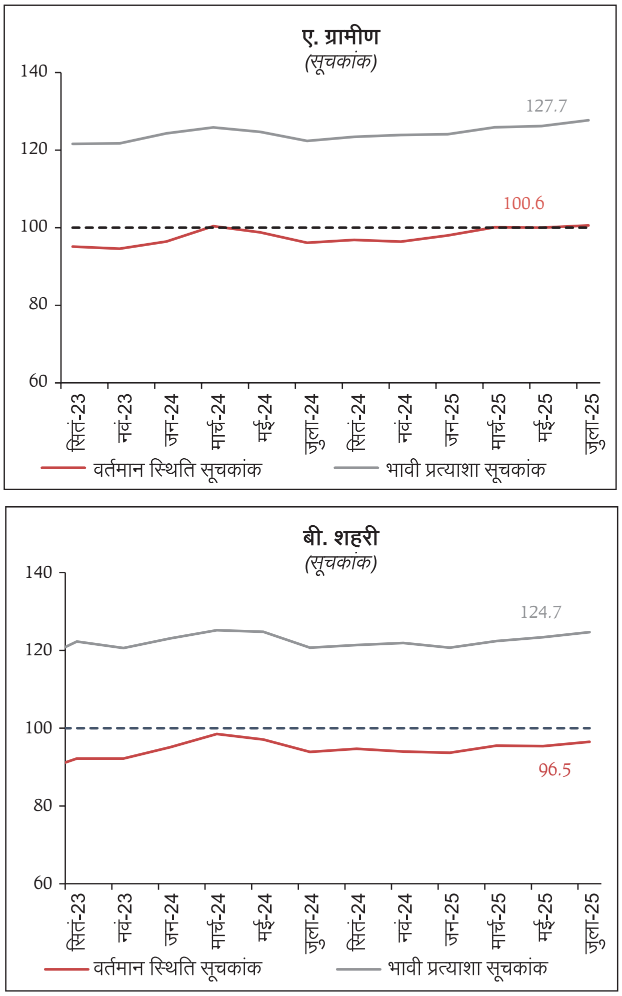

स्रोत: ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, आरबीआई।

चार्ट ए2: मुद्रास्फीति अंतराल (वास्तविक से लक्ष्य को घटाकर)
(प्रतिशत अंक)

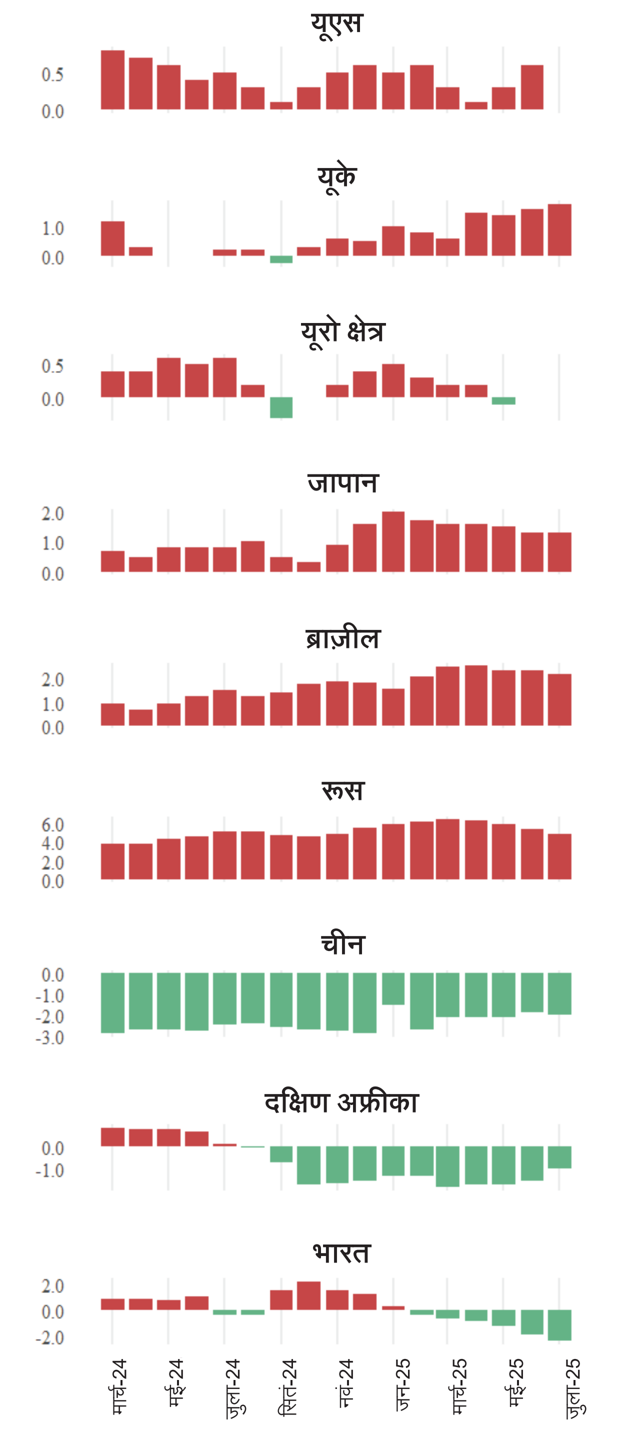

टिप्पणी: यूएस के लिए मुद्रास्फीति यूएस (पीसीई) डेटा पर आधारित है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

चार्ट ए4: भारत का पण्य निर्यात

ए. निर्यात में रुझान

(बिलियन अमेरिकी डॉलर, बायाँ मान, प्रतिशत में वृद्धि, दायाँ मान)

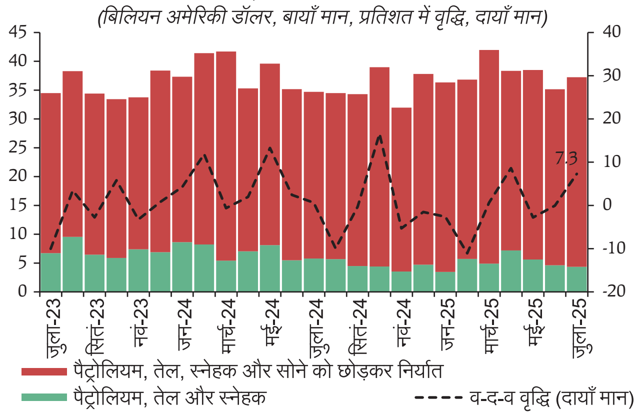

बी: निर्यात वृद्धि में अनुक्रमिक परिवर्तन का अपघटन

(प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष)

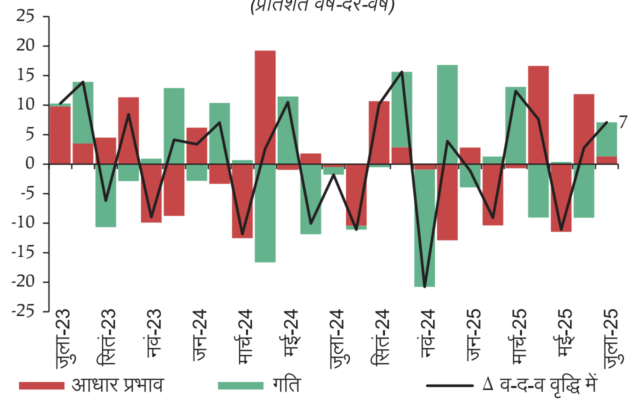

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई &एस; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट ए5: भारत का पण्य आयात

ए. आयात में रुझान

(बिलियन अमेरिकी डॉलर, बायाँ मान, प्रतिशत में वृद्धि, दायाँ मान)

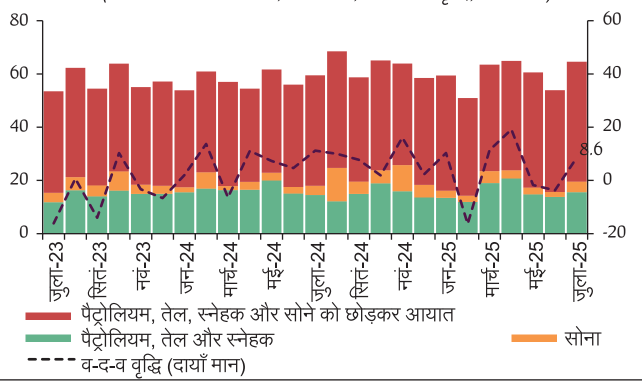

बी. आयात वृद्धि में अनुक्रमिक परिवर्तन का वियोजन

(बिलियन अमेरिकी डॉलर, बायाँ मान, प्रतिशत में वृद्धि, दायाँ मान)

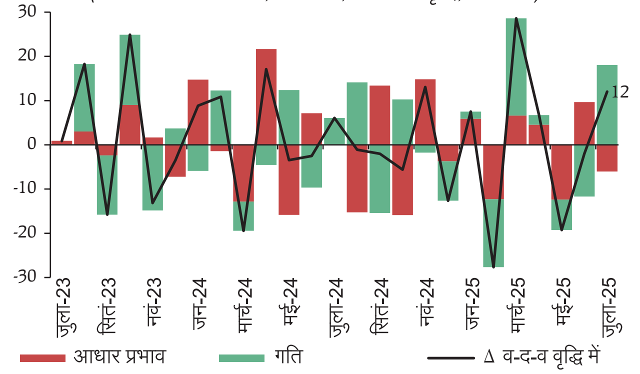

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई &एस; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान

चार्ट ए6: भारत के लिए आपूर्ति शृंखला दबाव का सूचकांक

(औसत मान से मानक विचलन)

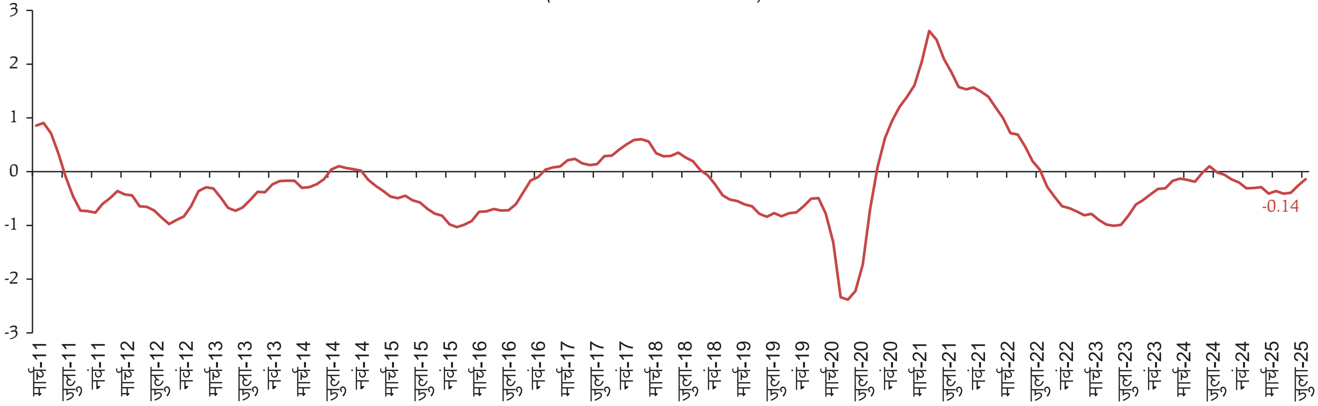

टिप्पणी: आईएसपीआई लंबी अवधि के औसत से प्रत्येक माह में आपूर्ति शृंखला के विचलन की ओर इंगित करता है। (समय-शृंखला मार्च 2005 से शुरू)

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान

चार्ट ए7: पीएमआई - इनपुट और आउटपुट मूल्य

टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में 'कोई परिवर्तन नहीं' और 50 से ऊपर की रीडिंग 'विस्तार और उसके विपरीत' की ओर संकेत करता है।
स्रोत: एस&पी

चार्ट ए8: परिवारों की औसत मुद्रास्फीति प्रत्याशा

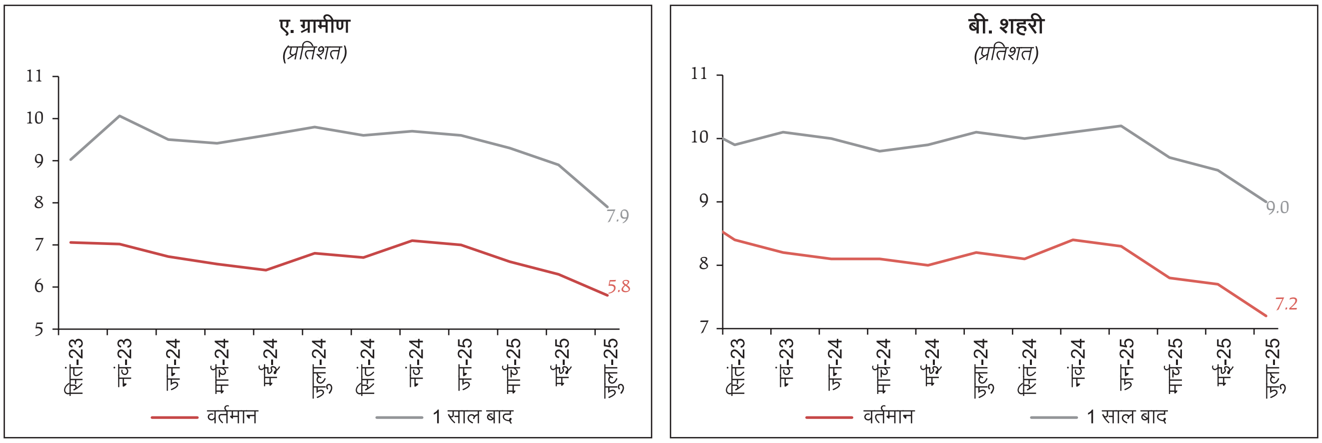

स्रोत: ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण; और परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण, आरबीआई।

चार्ट ए9: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक: ऋण और जमा वृद्धि

(प्रतिशत अंक)

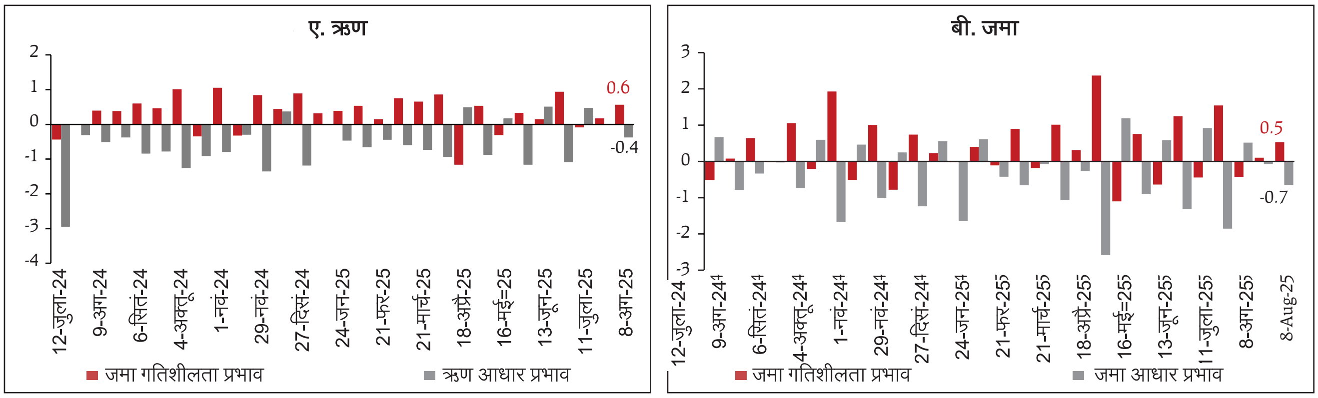

टिप्पणी: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के डेटा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का डेटा शामिल है। इस डेटा में एक गैर बैंक का बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।
स्रोत: पाक्षिक सेक्शन 42 रिटर्न्स, आरबीआई।

चार्ट ए10: बैंक ऋण का क्षेत्रीय परिनियोजन

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

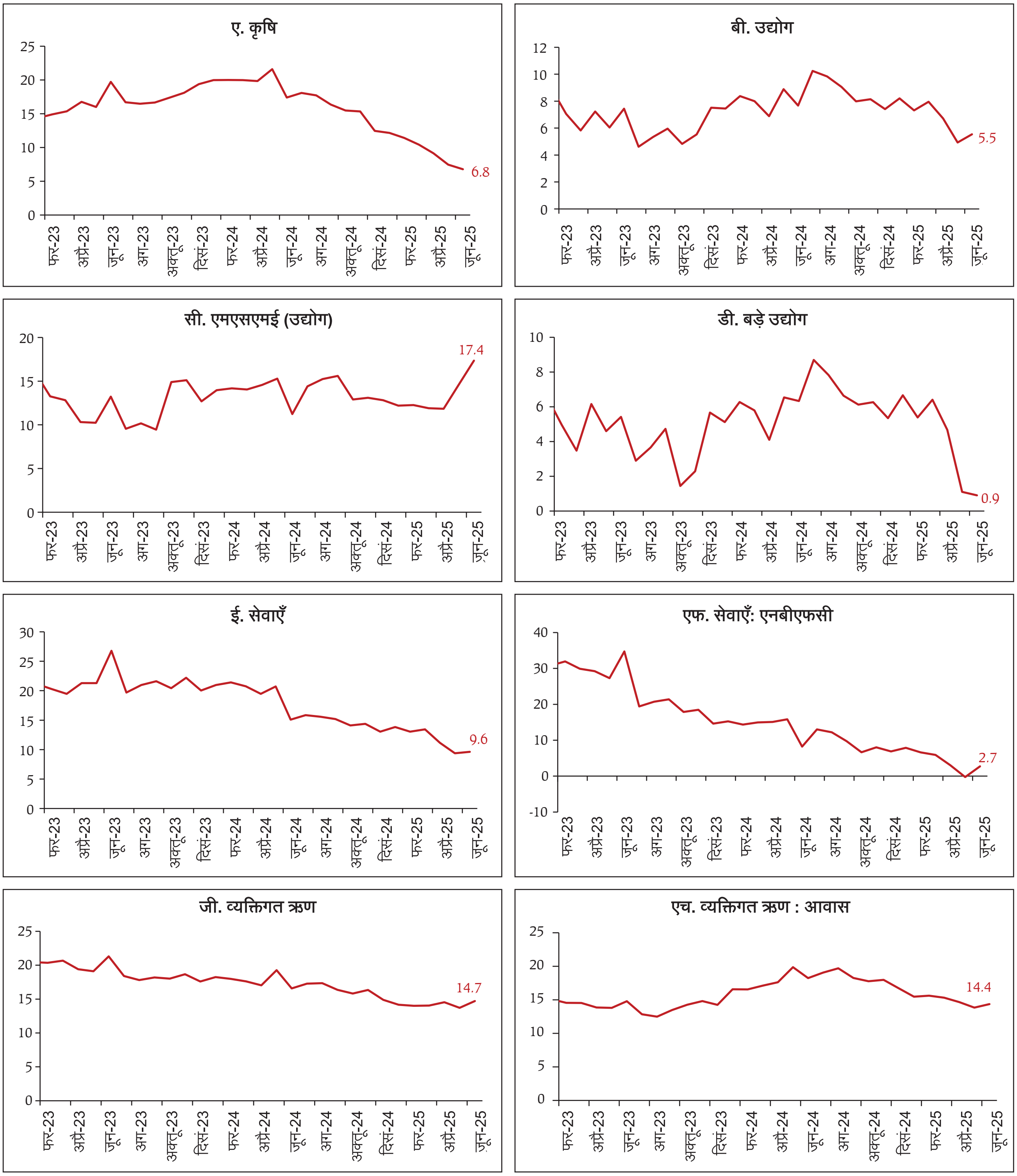

टिप्पणियाँ: 1. क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित है, जिसमें चुनिंदा बैंकों को शामिल किया गया है, जो सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत प्रदान करते हैं। डेटा अनंतिम हैं। एसआईबीसी रिटर्न के अंतर्गत शामिल बैंक समूह हैं: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और स्माल फ़ाइनेंस बैंक।

2. डेटा में किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय का असर शामिल नहीं है।

स्रोत: आरबीआई।

निजी कॉरपोरेट निवेश: 2024-25 में संवृद्धि और 2025-26 के लिए संभावना

स्निग्धा योगिन्द्रन, सुक्ति खांडेकर, राजेश बी कावेडिया और आलोक घोष द्वारा ^

यह आलेख बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के आधार पर 2024-25 के दौरान भारत में निजी कॉरपोरेट निवेश के इरादों और 2025-26 के लिए संभावनाओं की जांच करता है। बैंकों / एफआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत 2024-25 के लिए ₹3.68 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। यह निजी कॉरपोरेट्स के निवेश के प्रति आशावाद को इंगित करता है। सभी चैनलों के माध्यम से वित्तपोषित पाइपलाइन परियोजनाओं के आधार पर, पूंजीगत व्यय 2025-26 में बढ़कर ₹2.67 लाख करोड़ हो जाने की उम्मीद है, जो मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढाँचे, बेहतर बैलेंस शीट, बढ़ती क्षमता उपयोग, सुगम चलनिधि स्थिति, अवसंरचना को प्रोत्साहन और फरवरी 2025 से शुरू होने वाली 100-बीपीएस नीति दर में कटौती से समर्थित है।

परिचय

निजी कॉरपोरेट निवेश भारत के दीर्घकालिक विकास पथ में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक बना हुआ है। महामारी के वर्षों के दौरान सुस्त गतिविधियों के बाद, सहायक कारकों के संयोजन से निवेश चक्र में नई जान आ रही है। 2024-25 में, मजबूत जीडीपी वृद्धि, निरंतर अवस्फीति और परिणामस्वरूप अनुकूल मौद्रिक नीति रुख समष्टि आर्थिक पृष्ठभूमि की विशेषता रही। घरेलू अर्थव्यवस्था में 2024-25 में 6.5 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि के साथ लचीलापन जारी रहेगा, जिससे भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो मजबूत घरेलू माँग और सार्वजनिक अवसंरचना निवेश में निरंतर प्रगति से समर्थित है।

पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय कॉरपोरेट जगत बैलेंस शीट सुधार के दौर से गुज़रा है, जिसे डीलीवरेजिंग, बेहतर नकदी प्रवाह और कई क्षेत्रों में मजबूत लाभप्रदता से बढ़ावा मिला है (आरबीआई, एफएसआर, जून 2025)। बैंकिंग क्षेत्र की बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और प्रचुर चलनिधि ने ऋण परिवेश को और बेहतर बनाया है, जिससे क्षमता विस्तार के लिए वित्तपोषण तक आसान पहुँच संभव हुई है। उच्च-आवृत्ति संकेतकों में हालिया रुझान—जैसे पूंजीगत वस्तुओं का बढ़ता आयात, बेहतर क्षमता उपयोग और कॉरपोरेट बॉण्ड बाजारों में बढ़ता प्रवाह—विभिन्न कंपनियों में नए सिरे से निवेश की इच्छा का संकेत देते हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ, जैसे उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएँ, ऊर्जा संक्रमण निवेश और डिजिटल अवसंरचना विस्तार, कॉर्पोरेट्स को नए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

इस सुधार के बीच, इस आलेख का मुख्य उद्देश्य निजी कॉरपोरेट निवेश के उभरते परिदृश्य और उसकी निकट भविष्य की संभावनाओं का आकलन करना है। इस विश्लेषण को कई प्रश्न निर्देशित करते हैं: क्या निवेश की मंशा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? कौन से क्षेत्र और प्रदेश इस सुधार का नेतृत्व कर रहे हैं? पारंपरिक बैंक ऋण के अलावा वैकल्पिक वित्तपोषण माध्यमों की क्या भूमिका है?

चूँकि कॉरपोरेट बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने में समय लगता है, इसलिए कई देश कॉरपोरेट निवेश और संभावित योजना के निकट-अवधि के दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं। ऐसे सर्वेक्षण, निवेश की मात्रा और समय के बारे में प्रमुख जानकारी प्रदान करते हैं जिससे कंपनियों के निवेश इरादों का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सके, जिसकी निकट से मध्यम अवधि में साकार होने की उम्मीद है।

भारतीय संदर्भ में, रिज़र्व बैंक निवेश परिदृश्य का आकलन करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की निगरानी के माध्यम से निजी पूंजीगत

^ लेखक सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग से हैं। आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

व्यय योजनाओं पर नज़र रख रहा है। यह आलेख 2024-25 में निजी कंपनियों द्वारा शुरू की गई पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की विशेषताओं, वित्त पोषण पैटर्न, क्षेत्रीय और स्थानीय वितरण, और चरणबद्ध रूपरेखा का विश्लेषण करता है। पाइपलाइन परियोजनाओं[1] से परिकल्पित पूंजीगत व्यय, जो कार्यान्वयन के लिए पहले से शुरू की गई परियोजनाओं को संदर्भित करता है, का भी 2024-25 के लिए अनुमान लगाया गया है। यह आलेख निवेश इरादों का एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बैंक/एफआई प्रतिबंधों, बाहरी वाणिज्यिक उधार और इक्विटी निर्गम जैसे कई स्रोतों का उपयोग करता है। प्रस्तावित पूंजीगत व्यय के समय और संरचना पर केंद्रित होते हुए यह आलेख 2025-26 के लिए निवेश चक्र और इसके समष्टि आर्थिक निहितार्थों के बारे में मूल्यवान दूरदर्शी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

यह आलेख पाँच खंडों में संरचित है। खंड II में कार्यप्रणाली और धारणाओं का विवरण दिया गया है। खंड III में 2024-25 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा की गई है, जिसमें वित्तपोषण पैटर्न और क्षेत्रीय/स्थानीय वितरण शामिल है। खंड IV में चरणबद्ध रूपरेखा का मूल्यांकन और निवेश वृद्धि के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं और खंड V में अध्ययन का समापन किया गया है।

II. कार्यप्रणाली और धारणाएँ

निजी कॉरपोरेट निवेश के अल्प से मध्यम अवधि के परिदृश्य का आकलन करने के लिए, यह अध्ययन रंगराजन (1970)[2] द्वारा विकसित कार्यप्रणाली ढाँचे को अपनाता है। यह विश्लेषण तीन मुख्य डेटा स्रोतों पर आधारित है जो पूंजीगत परियोजनाओं के लिए विविध वित्तपोषण मार्गों को दर्शाते हैं: (i) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत निजी कॉरपोरेट पूंजीगत व्यय परियोजनाएँ, (ii) पूंजीगत व्यय से संबंधित बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), जिनमें विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) और रुपया-मूल्यवर्ग बॉण्ड (आरडीबी) शामिल हैं, और (iii) पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ), और अधिकार निर्गमों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि।

पूँजी निवेश की दोहरी गणना और उसके परिणामस्वरूप अति-अनुमान से बचने हेतु, यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक प्रयास किए गए हैं कि प्रत्येक परियोजना को डेटासेट में केवल एक बार ही शामिल किया जाए। यह रिज़र्व बैंक के आंतरिक डेटाबेस का उपयोग करके और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी को शामिल करके प्राप्त किया गया है, भले ही किसी परियोजना को कई स्रोतों से वित्त पोषित किया गया हो। यह अध्ययन विशेष रूप से उन परियोजनाओं पर केंद्रित है जिन्हें उपर्युक्त स्रोतों से वित्तपोषण प्राप्त हुआ है, जिनकी परियोजना लागत ₹10 करोड़ से अधिक है, और परियोजना में निजी कंपनियों की बहुलांश हिस्सेदारी है। केंद्र और/या राज्य सरकारों के पास बहुलांश हिस्सेदारी वाली परियोजनाएँ, और ट्रस्टों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शुरू की गई परियोजनाएँ इस अध्ययन के दायरे से बाहर हैं।

ये अनुमान इस धारणा के तहत निकाले गए हैं कि कंपनियाँ अपनी प्रत्याशित पूंजीगत व्यय योजनाओं का पालन करती हैं। हालांकि, इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये अनुमान विभिन्न कारणों से वास्तविक निवेशों से भिन्न हो सकते हैं, जैसे (ए) नियोजित निवेशों के समय या पैमाने में संशोधन, (बी) वित्तपोषण के पैटर्न में बदलाव—उदाहरण के लिए, ऋण या इक्विटी वित्तपोषण को आंतरिक स्रोतों या एफडीआई से प्रतिस्थापित करना, जो आरबीआई द्वारा एकत्र किए गए परियोजना वित्त डेटा में शामिल नहीं हैं, और (सी) नई परियोजनाओं का उदय या पहले की परियोजनाओं का रद्द होना। इसके अलावा, यह जानने की आवश्यकता है कि आलेख में प्रस्तुत विश्लेषण केवल उन पूंजीगत व्यय परियोजनाओं पर आधारित है जिनके लिए निजी कंपनियों ने वित्तपोषण के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से संपर्क किया था और तदनुसार, ये अनुमान निवेश गतिविधि के एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करते हैं और निजी कॉरपोरेट स्थिर पूंजी निर्माण के राष्ट्रीय लेखा-आधारित अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

[1] पाइपलाइन परियोजनाएँ वे परियोजनाएँ हैं जो पहले से ही कार्यान्वयन के लिए शुरू की जा चुकी हैं। पाइपलाइन परियोजनाओं से पूंजीगत व्यय किसी वर्ष के लिए परिकल्पित राशि होती है, जिसे उस वर्ष से पहले स्वीकृत किया गया हो।

[2] यह कार्यप्रणाली 19 दिसंबर, 1970 को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (ईपीडब्ल्यू), खंड संख्या 5, अंक संख्या 51, पृष्ठ 2049-2051 में डॉ. सी. रंगराजन द्वारा लिखित आलेख "फॉरकास्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द कॉर्पोरेट सैक्टर" में प्रकाशित हुई थी।

III. स्वीकृत/अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताएँ

2024-25 के दौरान, लगभग 907 परियोजनाओं को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सहायता मिली, जिनकी कुल लागत ₹3,67,973 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष स्वीकृत 944 परियोजनाओं की कुल लागत ₹3,91,003 करोड़ थी (अनुलग्नक सारणी ए1)।

2024-25 के दौरान, 448 निजी कंपनियों, जिन्होंने पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से कोई वित्तपोषण नहीं लिया था, ने पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से ईसीबी के माध्यम से ₹96,966 करोड़ जुटाए, जबकि 229 अन्य कंपनियों ने अपनी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के तहत घरेलू इक्विटी निर्गमों के माध्यम से ₹32,295 करोड़ जुटाए। कुल मिलाकर, 2024-25 के दौरान 1,584 परियोजनाओं की निवेश योजना बनाई गई, जिसमें ₹4,97,235 करोड़ के निवेश की मंशा थी, जबकि 2023-24 में ₹5,47,734 करोड़ के निवेश की मंशा वाली 1500 परियोजनाएं बनाई गई (अनुलग्नक सारणी ए1 - ए4)।

i) आकार-वार

2024-25 के दौरान, दस मेगा परियोजनाएँ (परियोजना लागत ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक) और 75 बड़ी परियोजनाएँ (₹1000 करोड़-₹5000 करोड़), बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत की गई, जिनकी कुल परियोजना लागत में क्रमशः 25.8 प्रतिशत और 37.2 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इन मेगा/बड़ी परियोजनाओं का पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध योजनाओं से विचलन मध्यम अवधि में समग्र पूंजीगत व्यय पैटर्न को प्रभावित कर सकता है (अनुलग्नक सारणी ए5)।

ii) उद्देश्य-वार

2024-25 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की कुल लागत में ग्रीन फील्ड (नई) परियोजनाओं में निवेश का हिस्सा सर्वाधिक लगभग 92 प्रतिशत रहा, जो पूर्व में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप है। ग्रीन फील्ड निवेश आम तौर पर कंपनियों के लिए नए और अतिरिक्त संसाधन और परिसंपत्तियाँ लाता है और सकल स्थिर पूँजी निर्माण (जीएफसीएफ) को बढ़ावा देता है। इस प्रकार, ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में अधिक निवेश भविष्य में निजी कंपनियों द्वारा संभावित क्षमता विस्तार की ओर इशारा करता है। मौजूदा परियोजनाओं[3] के विस्तार और आधुनिकीकरण में निवेश का कुल परियोजना लागत में 7.8 प्रतिशत हिस्सा रहा (अनुलग्नक सारणी ए6)।

iii) उद्योग-वार

2024-25 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का उद्योग-वार वितरण दर्शाता है कि अवसंरचना क्षेत्र[4] परियोजनाओं की

चार्ट 1: बैंक/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की समग्र लागत में प्रमुख उद्योगों का हिस्सा

(प्रतिशत)

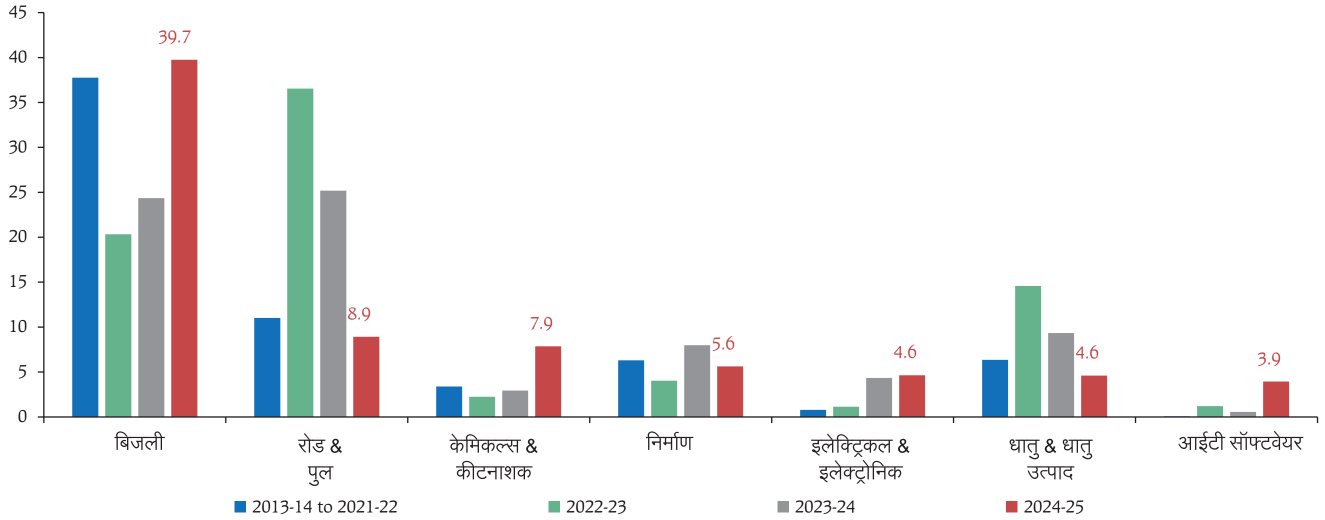

स्रोत: बैंक/ वित्तीय संस्थाओं से एकत्रित परियोजना- वित्त डेटा; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान

[3] मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण में निवेश आम तौर पर उत्पादन और/या इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी/प्रक्रियाओं के उन्नयन के लिए आवश्यक निवेश से संबंधित होता है।

कुल लागत में 50.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रमुख क्षेत्र बना रहा, जो मुख्य रूप से 'बिजली' में निवेश से प्रेरित है, उसके बाद 'सड़क और पुल' (अनुलग्नक सारणी ए7) का स्थान है। हालाँकि, परियोजनाओं की कुल लागत में अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं की हिस्सेदारी पिछले दस वर्षों में सबसे कम थी। अवसंरचना के अलावा, अन्य प्रमुख उद्योगों में, रसायन और कीटनाशक, निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपकरण, और धातु और धातु उत्पादों का भी परियोजनाओं की कुल लागत में बड़ा हिस्सा है (चार्ट 1 और अनुलग्नक सारणी 7)।

iv) राज्य-वार

स्थानीय कारक, जैसे कच्चे माल की पहुँच, आपूर्तिकर्ताओं की उपलब्धता, कुशल श्रम की उपलब्धता, पर्याप्त अवसंरचना का होना, बाजार का आकार, विकास क्षमता और माँग की स्थितियाँ, निवेश के लिए गंतव्य चुनने में महत्वपूर्ण रहते हैं। विश्लेषण के उद्देश्य से, इस आलेख में, कई राज्यों में फैली परियोजनाओं को "बहु-राज्य" परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं के राज्यवार वितरण से पता चला है कि शीर्ष पाँच राज्य, अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 2024-25 के दौरान परियोजनाओं की कुल लागत में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से सुधरी है (चार्ट 2 और अनुलग्नक सारणी ए8)।

IV. निवेश इरादों की चरणबद्ध रूपरेखा

वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध रूपरेखा, निजी निगमों के निकट-अवधि (एक वर्ष आगे) निवेश परिदृश्य को दर्शाती है। 2024-25 में स्वीकृत परियोजनाओं के समूह से चरणबद्ध रूपरेखा यह दर्शाती है कि कुल प्रस्तावित पूंजीगत व्यय का 39.3 प्रतिशत (₹1,44,782 करोड़) वर्ष 2024-25 के अंत तक निवेश करने की योजना थी, जबकि 35.2 प्रतिशत (₹1,29,591 करोड़) 2025-26 में और 25.4 प्रतिशत (₹93,600 करोड़) बाद की अवधि में खर्च करने की योजना है। 2024-25 तक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की चरणबद्ध रूपरेखा के आधार पर, परिकल्पित पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 के दौरान 0.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ ₹2,95,234 करोड़ दर्ज किया गया (अनुलग्नक सारणी ए1)।

निजी कंपनियों द्वारा ईसीबी और आईपीओ के माध्यम से जुटाए गए संसाधन उनकी निवेश गतिविधियों के वित्तपोषण

चार्ट 2: बैंक/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की समग्र लागत में प्रमुख राज्यों का हिस्सा
(प्रतिशत)

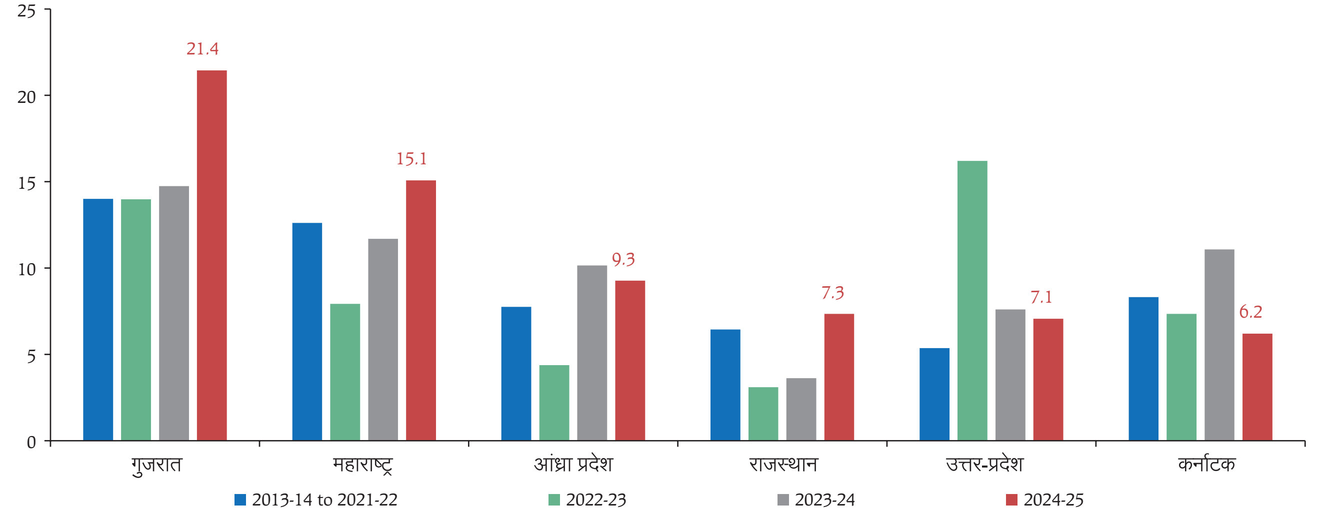

स्रोत: बैंक/ वित्तीय संस्थाओं से एकत्रित परियोजना- वित्त डेटा; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान

[4] अवसंरचना क्षेत्र में (ए) बिजली, (बी) दूरसंचार, (सी) बंदरगाह और हवाई अड्डे, (दी) भंडारण और जल प्रबंधन, (ई) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), औद्योगिक, जैव प्रौद्योगिकी और आईटी पार्क, और (एफ) सड़कें और पुल शामिल हैं।

के पूरक हैं। 2024-25 और उससे पहले की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से ईसीबी के माध्यम से जुटाई गई धनराशि से, 2024-25 के दौरान किए जाने वाले नियोजित पूंजीगत व्यय ₹1,00,747 करोड़ के मजबूत स्तर पर बने रहे, हालाँकि यह पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा। साथ ही, पूंजीगत व्यय के उद्देश्य से आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई धनराशि से नियोजित पूंजीगत व्यय 2024-25 में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर ₹18,943 करोड़ हो गया, हालाँकि कुल परिकल्पित पूंजीगत व्यय में इसका हिस्सा नगण्य रहा (अनुलग्नक सारणी ए2 और ए3)।

कुल मिलाकर, वित्त पोषण के विभिन्न चैनलों के आधार पर, जैसा कि पहले बताया गया है, 2024-25 में निजी कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा कुल ₹4,14,923 करोड़ का पूंजी निवेश किया जाना था, जो मोटे तौर पर पिछले वर्ष के दौरान नियोजित पूंजीगत व्यय के समान था। संदर्भ वर्ष से पहले के वर्षों में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत पाइपलाइन परियोजनाओं के आधार पर परिकल्पित पूंजीगत व्यय की चरणबद्ध रूपरेखा दर्शाती है कि परिकल्पित पूंजी निवेश 2024-25 में ₹1,68,204 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹1,91,073 करोड़ हो गया; जबकि वित्त पोषण के सभी चैनलों को मिलाकर, यह 2024-25 के ₹2,20,132 करोड़ की तुलना में 2025-26 में ₹2,67,432 करोड़ है (अनुलग्नक सारणी ए1 और ए4)।

V. निष्कर्ष

परियोजना वित्त डेटा का विश्लेषण निवेश के प्रति कम आशावाद की ओर इशारा करता है, जैसा कि पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 के दौरान परियोजनाओं की कुल लागत में कमी से परिलक्षित होता है। अवसंरचना क्षेत्र ने परिकल्पित पूंजी निवेश का बड़ा हिस्सा आकर्षित करना जारी रखा, जिसका नेतृत्व 'विद्युत' क्षेत्र कर रहा है। 2024-25 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में से, 39.3 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक निवेश करने की योजना थी, 35.2 प्रतिशत 2025-26 के लिए प्रदान किया गया है और शेष 25.4 प्रतिशत बाद के वर्षों में निवेश करने की परिकल्पना की गई है। तीनों चैनलों के माध्यम से वित्तपोषित पाइपलाइन परियोजनाओं की चरणबद्ध रूपरेखा बताती है कि परिकल्पित पूंजीगत व्यय 2024-25 के ₹2,20,132 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹2,67,432 करोड़ हो सकता है।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय कंपनियाँ नए वित्तीय वर्ष में बेहतर बैलेंस शीट, ज़्यादा नकदी भंडार, बेहतर लाभप्रदता और विविध वित्तपोषण स्रोतों तक बेहतर पहुँच के साथ प्रवेश कर रही हैं। अवसंरचना के लिए निरंतर नीतिगत प्रोत्साहन, निरंतर अवस्फीति, कम ब्याज दरों, सुगम चलनिधि स्थितियों और बढ़ते क्षमता उपयोग के साथ, निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दे रहे हैं।

भविष्य की ओर देखते हुए, निवेश परिदृश्य सतर्कतापूर्वक आशावादी बना हुआ है। जहाँ भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक अनिश्चितता और माँग में मंदी जैसे बाहरी जोखिम निवेश की भावना को प्रभावित कर सकते हैं, वहीं घरेलू बुनियादी ढाँचे मज़बूत दिखाई दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश की संरचना—मुख्यतः ग्रीनफ़ील्ड अवसंरचना परियोजनाओं द्वारा संचालित—न केवल चक्रीय सुधार, बल्कि संरचनात्मक क्षमता निर्माण का भी संकेत देती है। कंपनियों के इरादों को क्रियान्वयन में बदलने की क्षमता भारत के विकास के अगले चरण को आकार देने में महत्वपूर्ण होगी। इसलिए, परियोजना कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी और सहायक नीतिगत उपाय इस गति को स्थायी आर्थिक लाभ में बदलने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

संदर्भ:

C Rangarajan (1970). Forecasting Capital Expenditure in the Corporate Sector. *Economic and Political Weekly (EPW)*, Volume No. 5, Issue No. 51, Page 2049-2051.

RBI (2025). Financial Stability Report, June. Retrieved from https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/0FSRJUNE20253006258AE798B4484642AD861CC35BC2CB3D8E.PDF

सारणी ए1: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध निर्धारण

स्वीकृति वर्ष ↓	परियो-जनाओं की संख्या	स्वीकृति वर्ष में परियोजना लागत (₹ करोड़)	संशोधन/निरस्त करने के कारण परियोजना लागत^ (₹ करोड़)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	से आगे 2025-26
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
तक				1,70,603	93658	34172	14421	4722	1472								
2013-14																	
2014-15	326	87,601	87,253 (0.4)	14,920	34,589	25,765	9,535	1,246	162	1,036							
2015-16	346	95,371	91,781 (3.8)	3,787	7,434	37,517	28,628	8,079	4,964	1,152	220						
2016-17	541	1,82,807	1,79,249 (2.0)	1,352	3,952	25,388	71,186	41,075	21,643	8,566	4,001	2,086					
2017-18	485	1,72,831	1,68,239 (2.6)		620	15,184	12,445	63,001	41,436	22,767	10,202	2,342	242				
2018-19	409	1,76,581	1,59,189 (9.8)			569	6,862	11,000	59,973	47,080	21,248	9,759	2,663	35			
2019-20	320	2,00,038	1,75,83 (12.1)					4,049	14,524	53,978	58,556	28,116	14,114	2,299	194		
2020-21	220	75,558	75,558 (0.0)						2,491	3,709	29,013	26,166	9,711	3,867	601		
2021-22	401	1,43,314	1,42,111 (0.8)							3,610	10,543	59,622	44,306	18,447	3,541	1,646	396
2022-23	547	2,66,547	2,66,621 (0.0)							1,127	2,150	16,663	87,996	92,539	47,942	15,338	2,865
2023-24	944	3,90,978	3,91,003 (0.0)								2,235	6,783	39,455	1,63,608	1,15,926	44,499	18,497
2024-25	907	3,67,973										1,476	3,073	13,204	1,27,029	1,29,591	93,600
कुल योग &				**1,90,662**	**1,40,253**	**1,38,595**	**1,43,077**	**1,33,172**	**1,46,665**	**1,43,025**	**1,38,169**	**1,53,013**	**2,01,561**	**2,93,999**	**2,95,234**	**1,91,073**	**1,15,358**
प्रतिशत परिवर्तन					**-26.4**	**-1.2**	**3.2**	**-6.9**	**10.1**	**-2.5**	**-3.4**	**10.7**	**31.7**	**45.9**	**0.4**	**#**	

&: कॉलम का योग किसी विशेष वर्ष में परिकल्पित पूंजीगत व्यय को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न वर्षों में वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं को शामिल किया गया है। यह अनुमान पूर्व-निर्धारित है और इसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल हैं। ये वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए निवेशों से भिन्न हैं।

#: 2025-26 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2025-26 में स्वीकृत होने वाले संभावित प्रस्ताव का पूंजीगत व्यय अभी उपलब्ध नहीं है।

^: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संशोधन/निरस्तीकरण का प्रतिशत हैं।

सारणी ए2: ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी के माध्यम से वित्तपोषित पूंजीगत व्यय परियोजनाओं का चरणबद्ध विकास*

स्वीकृति वर्ष ↓	जारी किए गए LRN की संख्या	कुल दिया गया ऋण (₹ करोड़)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2025-26 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2013-14 तक			78,864	27,376	4,896											
2014-15	478	57,327		36,791	16,806	3,151	575	2	2							
2015-16	314	38,885			28,998	7,311	2,572	4								
2016-17	346	22,154				14,953	6,005	1,192	2	2						
2017-18	419	37,896					17,822	13,054	6,484	529	7					
2018-19	515	72,490						46,221	17,725	1,236	5,398	1,844	66			
2019-20	495	95,491							65,367	17,157	11,717	965	285			
2020-21	362	40,564								21,865	13,574	3,219	1,675	231		
2021-22	363	51,059								13	29,315	16,554	5,089	89		
2022-23	393	81,101										33,927	31,785	14,438	950	
2023-24	433	1,50,421											76,336	34,178	21,169	18,738
2024-25	448	96,966											12	51,811	40,660	4,483
कुल योग &			**78,864**	**64,167**	**50,700**	**25,415**	**26,974**	**60,473**	**89,580**	**40,802**	**60,011**	**56,509**	**1,15,248**	**1,00,747**	**62,779**	**23,221**
प्रतिशत परिवर्तन				**-18.6**	**-21.0**	**-49.9**	**6.1**	**124.2**	**48.1**	**-54.5**	**47.1**	**-5.8**	**103.9**	**-12.6**	**#**	

*: वे परियोजनाएँ जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सहायता नहीं मिली।
**: रुपया मूल्यवर्ग बॉण्ड (आरडीबी) को 2016-17 से शामिल किया गया है।
#: 2025-26 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2025-26 में निकाले जाने वाले संभावित प्रस्तावों का पूंजीगत व्यय अभी उपलब्ध नहीं है।
&: अनुमान पूर्व-निर्धारित है जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल है। ये वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए निवेश से भिन्न हैं।
LRN: ऋण पंजीकरण संख्या।

सारणी ए3: इक्विटी निर्गमों के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध निर्धारण*

के दौरान जारी की गई ↓	कंपनियों की संख्या	अनुमानित पूंजीगत व्यय (₹करोड़)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2025-26 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2013-14 तक			494	492	70											
2014-15	24	1,078		189	557	332										
2015-16	40	4,511		11	644	2,753	849	183	71							
2016-17	29	1,159			14	471	368	163	143							
2017-18	51	1,538					419	327	787	5						
2018-19	39	609						506	90	13						
2019-20	12	53						2	49	2						
2020-21	12	663								139	421	84	19			
2021-22	27	3,410								10	757	1,304	939	400		
2022-23	42	3,629										1,172	2,181	276		
2023-24	123	6,310										58	2,999	2,316	937	
2024-25	229	32,295											199	15,951	12,643	3,503
कुल योग &			**494**	**692**	**1,285**	**3,556**	**1,636**	**1,181**	**1,140**	**169**	**1,178**	**2,618**	**6,337**	**18,943**	**13,580**	**3,503**
प्रतिशत परिवर्तन				**40.1**	**85.7**	**176.7**	**-54.0**	**-27.8**	**-3.5**	**-85.2**	**597.0**	**122.2**	**142.1**	**198.9**	**#**	

*: वे परियोजनाएं जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी से सहायता नहीं मिली।
#: 2025-26 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2025-26 में लागू होने वाले प्रस्तावों का पूंजीगत व्यय अभी तक उपलब्ध नहीं है
।&: अनुमान पूर्व-निर्धारित है जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल है, वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए निवेश से भिन्न हैं।

सारणी ए4: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/आईपीओ/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी*/आईपीओ के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध निर्धारण

स्वीकृति का वर्ष ↓	कंपनियों या बैंकों/एफआई/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी/आईपीओ की संख्या	परयोजना लागत (₹ करोड़)	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2025-26 से आगे
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2013-14 तक			2,49,961	1,21,526	39,138	14,421	4,722	1,472								
2014-15	828	1,46,006	14,920	71,569	43,128	13,018	1,821	164	1,038							
2015-16	700	1,38,767	3,787	7,445	67,159	38,692	11,500	5,151	1,223	220						
2016-17	916	2,06,120	1,352	3,952	25,402	86,610	47,448	22,998	8711	4,003	2,086					
2017-18	955	2,12,265		620	15,184	12,445	81,242	54,817	30038	10,736	2,349	242				
2018-19	963	2,49,680			569	6,862	11,000	1,06,700	64895	22,497	15,157	4,507	101			
2019-20	827	2,95,582					4,049	14,526	119,394	75,715	39,833	15,079	2,584	194		
2020-21	594	1,16,785						2,491	3709	51,017	40,161	13,014	5,561	832		
2021-22	791	1,96,580							3,610	10,566	89,694	62,164	24,475	4,030	1,646	396
2022-23	982	3,51,351							1,127	2,150	16,663	1,23,095	1,26,505	62,656	16,288	2,865
2023-24	1,500	5,47,734								2,235	6,783	39,513	2,42,943	1,52,420	66,604	37,235
2024-25	1,584	4,97,235									1,476	3,073	13,415	1,94,791	1,82,895	1,01,586
कुल योग&			**270,020**	**2,05,112**	**1,90,580**	**1,72,048**	**1,61,782**	**2,08,319**	**2,33,745**	**1,79,139**	**2,14,202**	**2,60,688**	**4,15,583**	**4,14,923**	**2,67,432**	**1,42,082**
प्रतिशत परिवर्तन				**-24.0**	**-7.1**	**-9.7**	**-6.0**	**28.8**	**12.2**	**-23.4**	**19.6**	**21.7**	**59.4**	**-0.2**	**#**	

*: रुपया मूल्यवर्ग बॉण्ड (आरडीबी) को 2016-17 से शामिल किया गया है।

#: 2025-26 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2025-26 में स्वीकृत होने वाले प्रस्तावों का पूंजीगत व्यय अभी तक उपलब्ध नहीं है।

&: अनुमान पूर्व-निर्धारित है जिसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल है, वे वास्तव में प्राप्त/उपयोग किए गए निवेश से भिन्न हैं।

सारणी ए5: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का आकार-वार वितरण: 2013-14 से 2024-25

अवधि	परियोजनाओं की संख्या और हिस्सेदारी	₹100 करोड़ से कम	₹100 करोड़ से ₹500 करोड़	₹500 करोड़ से ₹1000 करोड़	₹1000 करोड़ से ₹5000 करोड़	₹5000 करोड़ और उससे अधिक	कुल
2013-14	परियोजनाओं की संख्या	306	115	25	21	5	**472**
	प्रतिशत शेयर	8.3	20.0	13.9	29.1	28.7	**100 (1,27,328)**
2014-15	परियोजनाओं की संख्या	223	65	18	19	1	**326**
	प्रतिशत शेयर	9.0	16.6	14.6	47.8	12.0	**100 (87,253)**
2015-16	परियोजनाओं की संख्या	214	76	34	21	1	**346**
	प्रतिशत शेयर	8.6	20.9	26.0	38.5	5.9	**100 (91,781)**
2016-17	परियोजनाओं की संख्या	287	180	29	40	5	**541**
	प्रतिशत शेयर	5.8	23.3	11.9	41.7	17.4	**100 (1,79,239)**
2017-18	परियोजनाओं की संख्या	263	149	28	42	3	**485**
	प्रतिशत शेयर	5.2	21.0	10.8	43.8	19.1	**100 (1,68,239)**
2018-19	परियोजनाओं की संख्या	220	110	39	36	4	**409**
	प्रतिशत शेयर	4.8	17.0	17.0	39.6	21.6	**100 (1,59,189)**
2019-20	परियोजनाओं की संख्या	150	84	45	36	5	**320**
	प्रतिशत शेयर	3.3	11.9	18.6	37.4	28.8	**100 (1,75,830)**
2020-21	परियोजनाओं की संख्या	128	52	15	24	1	**220**
	प्रतिशत शेयर	5.5	16.8	14.2	53.5	10.0	**100 (75,558)**
2021-22	परियोजनाओं की संख्या	201	125	37	36	2	**401**
	प्रतिशत शेयर	5.6	19.7	20.0	46.9	7.9	**100 (1,42,111)**
2022-23	परियोजनाओं की संख्या	267	158	50	64	8	**547**
	प्रतिशत शेयर	3.9	13.8	13.9	41.3	27.1	**100 (2,66,621)**
2023-24	परियोजनाओं की संख्या	484	265	107	77	11	**944**
	प्रतिशत शेयर	4.6	16.6	20.0	37.1	21.7	**100 (3,91,003)**
2024-25	परियोजनाओं की संख्या	502	234	86	75	10	**907**
	प्रतिशत शेयर	5.2	14.8	17.1	37.2	25.8	**100 (3,67,973)**

टिप्पणी: i . कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परियोजनाओं की कुल लागत (करोड़ रुपये में) दर्शाते हैं।
ii. प्रतिशत हिस्सा परियोजनाओं की कुल लागत में हिस्सेदारी है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत का कुल योग 100 नहीं हो सकता है।

सारणी ए6: 2013-14 से 2024-25 के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्देश्य-वार वितरण

अवधि	संख्या और परियोजनाओं का हिस्सा	नया	विस्तार & आधुनिकीकरण	विविधता	अन्य	कुल
2013-14	परियोजनाओं की संख्या	361	95	2	14	**472**
	प्रतिशत शेयर	65.2	20.1	-	14.7	**100 (1,27,328)**
2014-15	परियोजनाओं की संख्या	203	92	2	29	**326**
	प्रतिशत शेयर	39.4	14.7	0.2	45.7	**100 (87,253)**
2015-16	परियोजनाओं की संख्या	260	64	3	19	**346**
	प्रतिशत शेयर	73.6	14.3	0.1	12.0	**100 (91,781)**
2016-17	परियोजनाओं की संख्या	429	97	4	11	**541**
	प्रतिशत शेयर	78.6	9.9	0.1	11.3	**100 (1,79,249)**
2017-18	परियोजनाओं की संख्या	396	80	2	7	**485**
	प्रतिशत शेयर	89.0	9.5	0.1	1.5	**100 (1,68,239)**
2018-19	परियोजनाओं की संख्या	309	80	-	20	**409**
	प्रतिशत शेयर	76.8	19.3	-	3.9	**100 (1,59,189)**
2019-20	परियोजनाओं की संख्या	262	37	1	20	**320**
	प्रतिशत शेयर	79.8	13.7	-	6.4	**100 (1,75,830)**
2020-21	परियोजनाओं की संख्या	181	38	1	-	**220**
	प्रतिशत शेयर	94.1	5.9	-	-	**100 (75,558)**
2021-22	परियोजनाओं की संख्या	312	88	1	-	**401**
	प्रतिशत शेयर	89.1	10.8	0.1	0.0	**100 (1,42,111)**
2022-23	परियोजनाओं की संख्या	440	101	-	6	**547**
	प्रतिशत शेयर	93.1	6.1	-	0.8	**100 (2,66,621)**
2023-24	परियोजनाओं की संख्या	767	167	4	6	**944**
	प्रतिशत शेयर	89.1	8.7	0.1	2.2	**100 (3,91,003)**
2024-25	परियोजनाओं की संख्या	734	162	5	6	**907**
	प्रतिशत शेयर	91.6	7.8	0.1	0.5	**100 (3,67,973)**

टिप्पणी: i . कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परियोजनाओं की कुल लागत (करोड़ रुपये में) दर्शाते हैं।

ii. प्रतिशत हिस्सा परियोजनाओं की कुल लागत में हिस्सा है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत का योग 100 नहीं हो सकता।

iii. -: शून्य/नगण्य।

सारणी ए7: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का उद्योगवार वितरण : 2013-14 से 2024-25

Industry	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर
आधारभूत संरचना	87	39.7	74	48.9	108	72.0	204	62.5	150	51.7	122	60.3	99	61.5	63	74.3	95	56.3	135	60.0	245	55.5	207	50.6
i) पावर	70	35.1	65	42.2	92	57.1	170	45.4	117	36.5	78	26.8	47	32.9	35	49.3	58	29.0	53	20.3	139	24.4	146	39.7
ii) दूरसंचार	1	-	1	4.9	1	0.3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.6	-	-
iii) बंदरगाह और हवाई अड्डे	1	0.8	-	-	3	2.4	8	5.7	6	3.1	4	14.2	4	8.4	1	0.1	2	5.9	2	0.4	9	4.8	3	0.6
iv) भंडारण और जल प्रबंधन	5	1.1	2	0.6	4	4.2	6	3.7	2	0.4	13	5.7	4	0.4	5	1.2	2	0.2	3	0.8	4	0.0	8	0.2
v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क	8	1.5	3	0.9	1	0.4	2	0.4	9	1.6	11	3.2	8	1.3	5	2.2	3	1.1	8	1.9	10	0.5	8	1.2
vi) सड़कें और पुल	2	1.2	3	0.3	7	7.6	17	7.3	16	10.1	16	10.4	36	18.5	17	21.5	30	20.2	69	36.5	82	25.2	42	8.9
धातु और धातु उत्पाद	44	17.4	17	17.4	14	1.5	23	4.9	21	9.7	16	3.0	14	0.8	6	0.8	27	4.3	60	14.6	71	9.3	68	4.6
निर्माण	27	2.1	29	4.0	26	1.8	60	12.0	39	5.3	26	2.3	44	11.4	27	4.8	22	7.4	35	4.0	56	8.0	57	5.6
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स	9	2.0	7	0.2	2	0.2	9	0.2	6	0.2	1	0.1	4	-	1	0.1	5	4.0	9	1.1	15	4.4	28	4.6
खाद्य उत्पाद	43	1.8	34	2.9	26	1.8	38	0.9	47	2.8	28	1.4	32	1.9	20	1.5	25	1.7	40	2.5	107	3.0	86	2.6
रसायन और कीटनाशक	15	1.0	7	2.6	11	1.6	10	2.1	23	11.4	19	2.9	12	1.3	9	1.6	20	3.4	16	2.3	33	2.9	24	7.9
वस्त्र	58	10.3	50	4.1	49	4.8	57	4.1	54	3.7	27	3.4	11	0.5	15	1.8	56	4.5	42	2.8	58	2.2	38	1.2
परिवहन सेवाएं	14	0.5	5	0.6	10	1.2	12	0.4	16	4.1	5	0.2	14	1.4	1	0.1	19	2.5	21	0.6	35	2.1	46	2.1
कोक और पेट्रोलियम उत्पाद	1	0.5	1	3.4	2	2.0	2	0.5	1	0.4	-	-	3	8.0	-	-	7	1.0	17	1.1	28	1.6	23	1.8
सीमेंट	12	7.1	7	3.8	5	1.9	5	2.3	3	0.6	10	5.1	2	0.1	5	1.3	3	3.3	2	0.8	11	1.3	4	1.0
परिवहन उपकरण और पुर्जे	14	1.0	7	5.3	4	2.5	9	3.6	10	0.3	5	0.8	5	0.4	2	0.3	5	0.4	16	0.6	12	1.2	16	1.8
खनन और उत्खनन	1	0.6	2	0.1	10	2.7	4	0.4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0.1	7	1.8	11	1.2	9	2.2
होटल और रेस्तरां	22	2.2	15	1.1	16	1.1	12	0.8	29	2.9	26	1.9	16	1.7	4	2.9	12	0.9	13	0.4	58	1.1	61	1.5
दवाइयों	19	1.3	9	1.5	11	0.3	12	1.1	15	0.6	23	1.6	9	0.6	7	0.5	20	1.3	30	2.1	29	0.8	42	1.0
अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं	10	0.7	2	0.1	1	-	22	1.1	18	1.8	15	2.6	12	0.7	7	0.3	19	2.3	20	1.1	25	0.7	34	1.5
रबर और प्लास्टिक उत्पाद	9	0.3	8	0.8	4	0.5	8	0.2	10	2.5	5	0.5	5	0.3	17	2.1	12	0.8	13	0.8	24	0.7	35	1.9
आईटी सॉफ्टवेयर	3	0.1	1	-	1	-	-	-	1	-	2	0.7	1	-	-	-	2	0.6	4	1.2	4	0.6	10	3.9
अन्य*	84	11.4	51	3.2	46	4.1	54	2.9	41	2.0	79	13.3	37	9.3	36	7.6	51	5.1	67	2.3	122	3.5	119	4.2
कुल	**472**	**100**	**326**	**100**	**346**	**100**	**541**	**100**	**485**	**100**	**409**	**100**	**320**	**100**	**220**	**100**	**401**	**100**	**547**	**100**	**944**	**100**	**907**	**100**
कुल परियोजना लागत ₹ करोड़ में	**1,27,328**		**87,253**		**91,781**		**1,79,249**		**1,68,239**		**1,59,189**		**1,75,830**		**75,558**		**1,42,111**		**2,66,621**		**3,91,003**		**3,67,973**	

*: इसमें कागज़ और कागज़ उत्पाद, कृषि और संबंधित गतिविधियाँ, विद्युत और गैर-विद्युत मशीनरी का निर्माण, कांच और मिट्टी के बर्तन, चीनी और संबंधित उत्पाद, मनोरंजन, सेवाओं का व्यापार, मुद्रण और प्रकाशन, अन्य विनिर्माण और अन्य सेवाएँ जैसे उद्योग शामिल हैं।

टिप्पणी: i . प्रतिशत हिस्सा परियोजना की कुल लागत में हिस्सा है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत का योग 100 नहीं हो सकता।

ii. -: शून्य/नगण्य।

सारणी ए8: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार वितरण: 2013-14 से 2024-25

राज्य	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत शेयर
गुजरात	66	14.5	71	9.5	61	15.1	102	23.0	71	8.0	56	11.1	47	15.1	54	17.1	82	11.7	82	14.0	154	14.7	152	21.4
महाराष्ट्र	76	19.7	38	14.8	36	9.4	57	8.8	65	23.3	34	11.5	41	6.9	13	8.5	44	9.6	48	7.9	93	11.7	111	15.1
कर्नाटक	39	6.2	27	5.4	21	6.2	52	6.8	64	9.6	34	5.7	33	17.2	11	6.1	24	6.9	37	7.3	61	11.1	60	6.2
आंध्र प्रदेश	37	4.0	24	8.1	33	12.3	47	8.0	22	9.9	29	11.1	12	4.0	7	15.0	11	2.1	27	4.4	51	10.1	28	9.3
उतार प्रदेश।	21	1.1	20	5.4	15	2.5	22	3.7	30	2.4	28	4.8	24	5.4	30	13.7	33	12.7	45	16.2	69	7.6	78	7.1
ओडिशा	10	11.7	5	15.9	6	3.1	6	3.1	5	3.0	9	1.4	6	1.9	2	0.1	9	2.2	12	11.8	23	6.7	18	4.6
तेलंगाना	-	-	-	-	10	3.8	51	5.5	17	1.9	26	9.1	12	4.0	9	1.9	16	3.4	30	1.9	40	4.1	42	2.8
राजस्थान	24	1.4	29	11.1	10	0.9	23	2.8	33	6.3	21	7.7	23	3.8	21	17.1	32	12.6	22	3.1	61	3.6	45	7.3
झारखंड	4	0.3	2	0.7	5	0.3	1	0.0	3	0.3	2	0.5	4	9.4	1	0.2	6	0.8	12	1.9	17	3.4	7	1.3
मध्य प्रदेश	30	6.1	14	3.9	21	7.0	18	7.5	10	0.7	12	1.6	10	1.2	19	2.8	18	4.2	35	5.0	56	3.4	41	2.7
छत्तीसगढ	16	10.7	8	7.4	8	4.6	15	4.0	7	4.8	6	0.9	6	0.2	3	1.2	4	0.8	8	1.4	26	3.3	24	1.1
तमिलनाडु	33	5.4	27	2.9	26	9.3	23	4.4	28	6.6	32	12.8	28	8.3	7	0.7	40	8.8	44	4.7	83	3.0	73	4.7
बिहार	6	0.2	4	0.1	6	0.2	4	0.2	3	0.1	6	0.4	6	3.4	1	0.0	5	3.4	6	1.6	13	2.6	11	0.9
पश्चिम बंगाल	12	1.2	9	1.3	14	3.1	18	1.7	14	1.8	13	1.1	7	0.9	3	0.4	11	2.6	16	1.0	28	2.3	34	2.3
जम्मू और कश्मीर	10	5.2	2	0.1	9	0.2	3	0.1	8	2.0	11	0.4	3	0.3	5	0.2	5	0.2	23	3.1	36	1.9	54	3.8
पंजाब	28	1.5	6	0.3	11	1.7	29	2.1	31	2.2	15	1.9	9	0.8	4	0.7	15	2.2	21	2.5	34	1.6	28	1.5
हरयाणा	15	1.1	11	1.9	16	3.6	13	1.6	21	0.5	18	1.7	20	3.4	15	7.8	14	2.0	14	1.0	25	1.5	20	0.6
दिल्ली	5	0.4	2	0.1	1	0.1	5	0.3	6	1.2	8	1.3	3	0.5	2	0.1	3	0.6	12	0.4	10	1.2	14	0.3
असम	4	0.3	2	0.2	4	0.4	10	0.6	5	0.8	4	0.2	1	0.3	3	4.4	2	0.0	6	0.7	13	0.9	14	1.2
हिमाचल प्रदेश	3	1.8	3	0.1	8	1.4	1	0.0	8	2.3	7	0.3	6	0.1	4	0.2	7	1.2	11	2.2	10	0.3	9	0.1
केरल	3	0.0	4	0.2	4	0.1	6	2.7	3	0.1	6	0.9	3	1.0	-	-	5	4.2	12	0.9	11	0.2	12	0.3
गोवा	-	-	-	-	1	0.0	3	0.6	2	1.9	3	1.8	2	0.1	-	-	3	3.0	3	0.8	4	0.1	3	0.6
उत्तराखंड	5	0.1	5	0.2	2	0.1	11	0.4	6	0.4	9	0.4	5	0.1	2	0.1	2	0.4	5	0.1	8	0.1	14	0.3
बहु-राज्य #	21	6.9	10	9.5	13	13.5	17	11.8	16	7.5	15	9.8	8	11.7	2	1.4	7	4.0	10	5.5	12	4.4	9	4.5
अन्य*	4	0.2	3	0.9	5	1.1	4	0.3	7	2.4	5	1.7	1	0.0	2	0.3	3	0.3	6	0.3	6	0.3	6	0.1
कुल	**472**	**100**	**326**	**100**	**346**	**100**	**541**	**100**	**485**	**100**	**409**	**100**	**320**	**100**	**220**	**100**	**401**	**100**	**547**	**100**	**944**	**100**	**907**	**100**
परियोजनाओं की कुल लागत (करोड़ रुपये में)	**1,27,328**		**87,253**		**91,781**		**1,79,249**		**1,68,239**		**1,59,189**		**1,75,830**		**75,558**		**142,111**		**2,66,621**		**3,91,003**		**3,67,973**	

#: इसमें कई राज्यों की परियोजनाएँ शामिल हैं।

*: इसमें शेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

टिप्पणी: i . प्रतिशत हिस्सा परियोजना की कुल लागत में हिस्सा है। पूर्णांकन के कारण प्रतिशत का योग 100 नहीं हो सकता।

ii. -: शून्य/नगण्य।

भारत के बचत परिदृश्य में बदलाव लाते इक्विटी म्यूचुअल फंड

मयंक गुप्ता, सत्यम कुमार, अभिनंदन बोराद, सुब्रत कुमार सीत और प्रतिभा केडिया द्वारा ^

यह आलेख भारत में इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रवाह के निर्धारकों की जांच करता है तथा पिछले एक दशक में इक्विटी-उन्मुख आस्तियों की ओर खुदरा निवेशकों के व्यवहार में आए बदलाव पर प्रकाश डालता है। मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करते हुए, अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि बढ़ता वित्तीय समावेशन (डीमैट खातों द्वारा प्रदर्शित), सावधि जमा दरें, और कारोबारी विश्वास - इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रवाह को आकार देने वाले तीन सबसे प्रभावशाली कारक हैं। ग्रेंजर कॉज़ालिटी विश्लेषण से आगे पता चलता है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि इन प्रवाहों का पूर्वानुमान लगाने में मदद करती है, जो यह दर्शाता है कि आर्थिक प्रदर्शन निवेशकों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। यह आलेख भारत में खुदरा निवेशकों की बढ़ती समझ और दीर्घकालिक रुझान को रेखांकित करता है। हालिया वृद्धि के बावजूद, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग अपेक्षाकृत छोटा है, जो भविष्य में विस्तार की महत्वपूर्ण संभावनाओं का संकेत देता है।

परिचय

खुदरा निवेशक पारंपरिक बचत साधनों की तुलना में इक्विटी निवेश को अधिक पसंद कर रहे हैं, जो भारत में वित्तीय परिदृश्य को नया रूप दे रहा है। यदि इक्कीसवीं सदी के दौरान भारत के वित्तीय क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण विकास घटनाक्रमों का वर्णन करना हो, तो म्यूचुअल फंड (एमएफ) की उल्लेखनीय वृद्धि निःसंदेह एक प्रमुख बिंदु होगा। घरेलू क्षेत्र की सकल वित्तीय बचत में एमएफ की हिस्सेदारी 2011-12 के 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 6 प्रतिशत हो गई (चार्ट 1ए)। एमएफ, घरेलू निवेशकों के लिए इक्विटी बाज़ारों में निवेश करने का पसंदीदा माध्यम बनकर उभरे हैं [1] (चार्ट 1बी)।

पिछले कुछ दशकों में, भारत में म्यूचुअल फंड ने काफी लोकप्रियता हासिल की है, जिसका श्रेय आय के स्तर में वृद्धि, वित्तीय साक्षरता के बढ़ते स्तर, युवा जनसांख्यिकीय संरचना, डिजिटल पारितंत्र और इंटरनेट कनेक्टिविटी के व्यापक विकास तथा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के नेतृत्व में विपणन पहलों की सफलता को दिया जा सकता है, जिससे विश्वास का निर्माण हुआ है। एमएफ उद्योग की प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) मार्च 2010 के अंत में ₹6.1 लाख करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 के अंत में 17.1 प्रतिशत की संमिश्र वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर ₹65.7 लाख करोड़ हो गई है। भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के कारण हाल के समय में भारतीय इक्विटी बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता के बावजूद, सुनियोजित निवेश योजनाओं (एसआईपी) के माध्यम से मासिक प्रवाह नए सर्वोच्च स्तर दर्ज कर रहा है, जो जून 2025 में ₹27,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है।

म्यूचुअल फंड में शीर्ष 30 (T30[2]) शहरों[3] की तुलना में छोटे शहरों (30 या B-30 केंद्रों से परे) से नए एसआईपी खातों में उच्च वृद्धि के साथ-साथ ही महिलाओं की अधिक भागीदारी भी देखने को मिल रही है - उद्योग आस्तियों में उनकी हिस्सेदारी मार्च 2017 के 15 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2023 तक लगभग

^ लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। इस आलेख में व्यक्त विचार स्वयं लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

[1] वर्तमान घरेलू वित्तीय बचत आँकड़े, केवल प्राथमिक बाज़ार से इक्विटी में होने वाले प्रवाह को ही दर्शाते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2024) ने द्वितीयक बाजार के प्रवाह को शामिल करके और कतिपय पद्धतिगत सुधारों को लागू करके एक विस्तृत विश्लेषण किया। इन समायोजनों के बावजूद, निष्कर्ष बताते हैं कि म्यूचुअल फंडों में प्रवाह - प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों बाज़ारों के माध्यम से इक्विटी में होने वाले संयुक्त प्रवाह से काफी अधिक है।

[2] टी30 (टॉप-30) भारत के शीर्ष 30 भौगोलिक स्थानों को संदर्भित करता है और बी30 (बियोंड 30) शीर्ष 30 से इतर स्थानों को संदर्भित करता है। टी30 शहरों की सूची https://www.amfiindia.com/research-information/aum-data/listoftop30cities पर देखी जा सकती है।

[3] https://www.business-standard.com/markets/stock-market-news/sip-soars-beyond-city-limits-small-towns-lead-in-account-additions-123112600539_1.html

चार्ट 1: घरेलू बचत का वित्तीयकरण

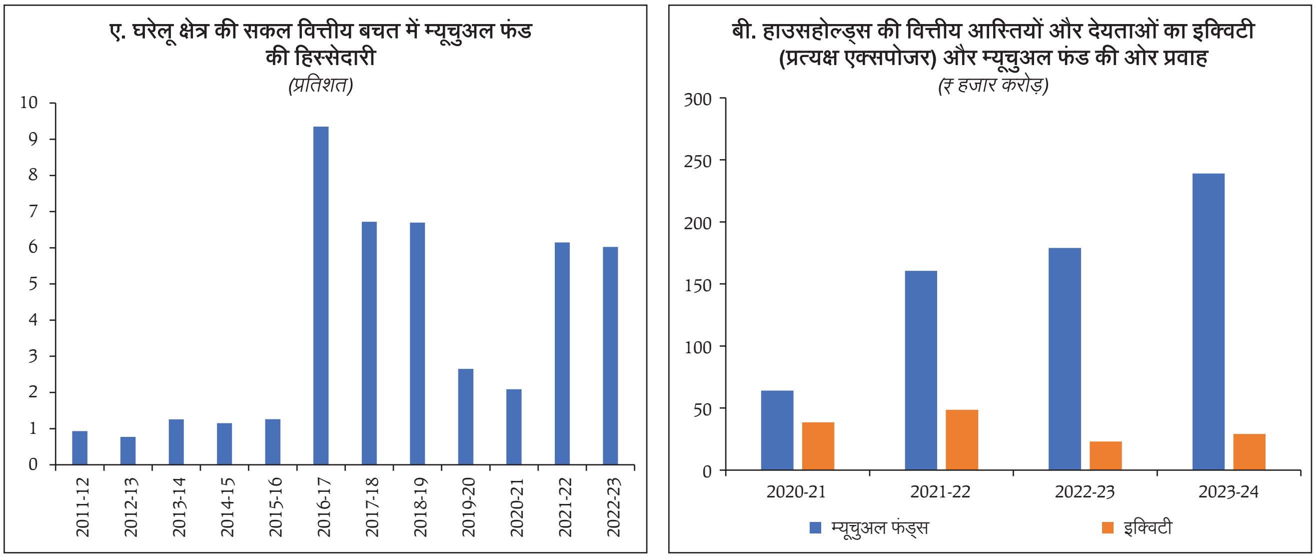

स्रोत: एमओएसपीआई, आरबीआई एवं लेखक की गणना।

21 प्रतिशत हो गई है। इस बदलाव का एक और उत्साहजनक पहलू यह है कि महिलाओं की भागीदारी की वृद्धि की गति छोटे शहरों में अधिक महत्वपूर्ण है - बी-30 शहरों में महिलाओं के फोलियो और आस्तियों की हिस्सेदारी इसी अवधि के दौरान 15 प्रतिशत और 17 प्रतिशत से बढ़कर क्रमशः 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत हो गई है।[4] भारत में एमएफ में महिला निवेशकों की प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) मार्च 2019 के ₹4.59 लाख करोड़ के दोगुने से अधिक हो कर मार्च 2024 में ₹11.25 लाख करोड़ हो गई[5]। ऐसे समय में जब इक्विटी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की हिस्सेदारी धीरे-धीरे ही सही, कम हो रही है, घरेलू इक्विटी बाजारों में म्यूचुअल फंडों का स्वामित्व अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। आने वाले वर्षों में घरेलू म्यूचुअल फंड उद्योग की पूर्वानुमानित तीव्र वृद्धि को देखते हुए, इस प्रवृत्ति के और सुदृढ़ होने की उम्मीद है [6]। ऐसे माहौल में, म्यूचुअल फंडों, विशेष रूप से इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड, जिन्होंने खुदरा निवेशकों का पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया है, में धन के अंतर्वाह को प्रभावित करने वाले कारकों और घरेलू वित्तीय बाजारों पर इसके प्रभावों की बारीकी से जाँच करना आवश्यक है।

इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान अध्ययन 'रैंडम फॉरेस्ट' जैसी मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके भारत में इक्विटी म्यूचुअल फंड में प्रवाह के प्रमुख निर्धारकों की जाँच करने का प्रयास करता है। जब डेटा गैर-रैखिक और परस्पर क्रियाशील प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो रैखिक मॉडलों की तुलना में रैंडम फ़ॉरेस्ट विशेषताओं के बीच जटिल परस्पर क्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम होता है। इस अभ्यास में विभिन्न संभावित चैनलों की खोज शामिल है, जैसे कि वैकल्पिक निवेश के अवसरों पर तुलनात्मक प्रतिफल, बचत का बढ़ता वित्तीयकरण, तथा वित्तीय बाजारों और कारोबारी वातावरण का समग्र दृष्टिकोण।

आलेख का शेष भाग इस प्रकार व्यवस्थित है: भाग II में इक्विटी म्यूचुअल फंड और हाल के रुझानों पर शोधपरक तथ्यों पर चर्चा की गई है। भाग III में इक्विटी म्यूचुअल फंडों पर उपलब्ध साहित्य की समीक्षा की गई है। भाग IV में इक्विटी म्यूचुअल फंडों में अंतर्वाह के निर्धारकों का विश्लेषण और म्यूचुअल फंड प्रवाह और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के बीच संबंध का आकलन शामिल है। अंत में, भाग V में समापन टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

[4] https://www.amfiindia.com/Themes/Theme1/downloads/AMFI_womensDay_Mar2024.pdf

[5] https://www.amfiindia.com/Themes/Theme1/downloads/AMFIFactbook%202024.pdf

[6] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/india-mutual-fund-industry

II. भारत में एमएफ उद्योग के शोधपरक तथ्य

म्यूचुअल फंडों में बढ़ती रुचि का अंदाजा निवेशक खातों की संख्या में वृद्धि से लगाया जा सकता है, जो दिसंबर 2014 से लगभग छह गुना बढ़कर मार्च 2025 तक 23.5 करोड़ तक पहुँच गए हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें से 91.7 प्रतिशत खाते खुदरा निवेशकों के हैं (चार्ट 2ए और 2बी)। वर्ष 2024 में विशिष्ट म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या पाँच करोड़ का आंकड़ा पार कर गई [7]।

निवेश के लिहाज से, म्यूचुअल फंड, बैंक जमाराशियों के एक संभावित प्रतिस्पर्धी के रूप में उभर रहे हैं, विशेषकर भारत में महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग के बीच। कुल जमाराशियों की तुलना में म्यूचुअल फंड उद्योग के एयूएम का अनुपात मार्च 2014 के अंत में लगभग 10 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 23.8 प्रतिशत हो गया है (चार्ट 3ए)। हालिया उच्च-वृद्धि चरण के बावजूद, म्यूचुअल फंडों के पास अभी भी आधिपत्य जमाने के लिए एक विशाल क्षेत्र है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में म्यूचुअल फंडों की आस्तियों का उनकी जीपीडी के प्रतिशत के रूप में हिस्सा, भारत की तुलना में अधिक है (चार्ट 3बी)।

घरेलू इक्विटी बाजारों के शानदार प्रदर्शन और खुदरा निवेशकों से इक्विटी-उन्मुख निधियों में निरंतर अंतर्वाह के समर्थन से इक्विटी एमएफ, गैर-इक्विटी निधियों की तुलना में तेजी से बढ़े हैं, इक्विटी एयूएम मार्च 2010 के अंत में ₹2.1 लाख करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 के अंत में ₹34.5 लाख करोड़ हो गया है (चार्ट 4ए और 4बी)।

इक्विटी की ओर खुदरा निवेशकों का झुकाव इस तथ्य में भी परिलक्षित होता है कि सभी एमएफ खातों का लगभग दो-तिहाई इक्विटी-उन्मुख आस्तियों पर केंद्रित है। निवेशक खातों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ एसआईपी में भी वृद्धि हुई है। भारतीय एमएफ के पास जून 2025 के अंत में लगभग 9.2 करोड़ एसआईपी खाते थे, जिनके माध्यम से निवेशकों ने नियमित रूप से भारतीय एमएफ योजनाओं में निवेश किया। जबकि निवेशक खातों की संख्या में वृद्धि - लघु निवेशकों के बीच एमएफ की बढ़ती लोकप्रियता को इंगित करती है, वहीं एसआईपी निवेश में एक दीर्घकालिक वृद्धि खुदरा निवेशकों की बढ़ती समझ का प्रमाण है (चार्ट 5ए)। दो ध्रुवीकरण प्रवृत्तियों यथा, इक्विटी डेरिवेटिव के

चार्ट 2: म्यूचुअल फंड (एमएफ) उद्योग खाते

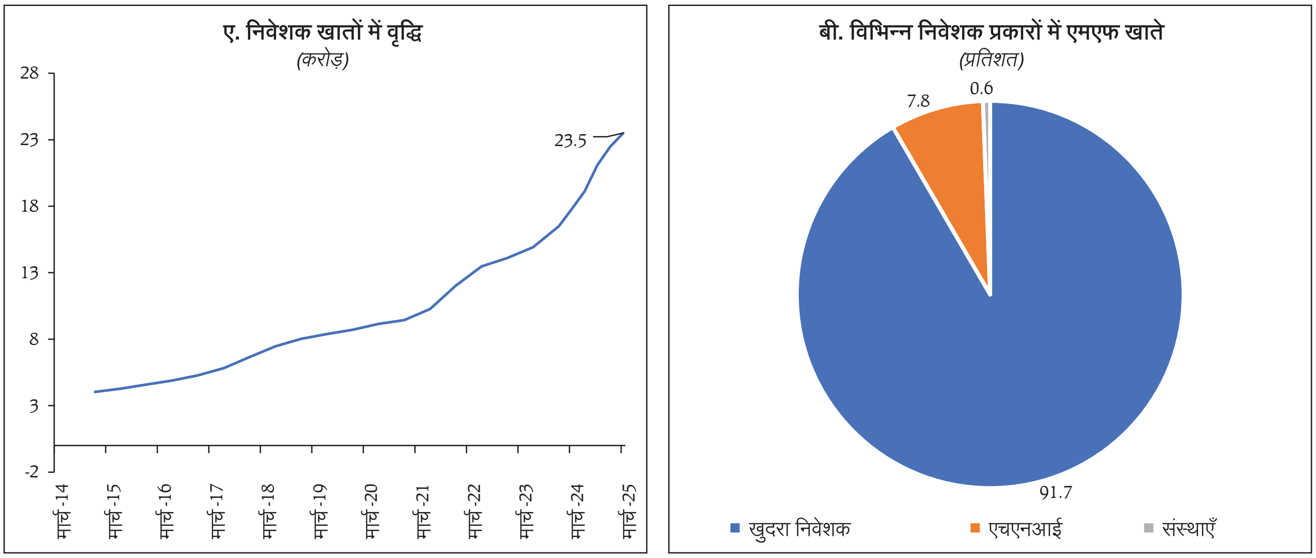

स्रोत: एएमएफआई।

[7] https://www.business-standard.com/markets/mutual-fund/mf-investor-count-crosses-50-million-after-10-million-additions-in-a-year-124102501213_1.html

[8] जमाराशियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के पास जमाराशियाँ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और शहरी सहकारी बैंकों के पास सार्वजनिक जमाराशियाँ शामिल हैं।

चार्ट 3: खुदरा निवेशकों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहे म्यूचुअल फंड

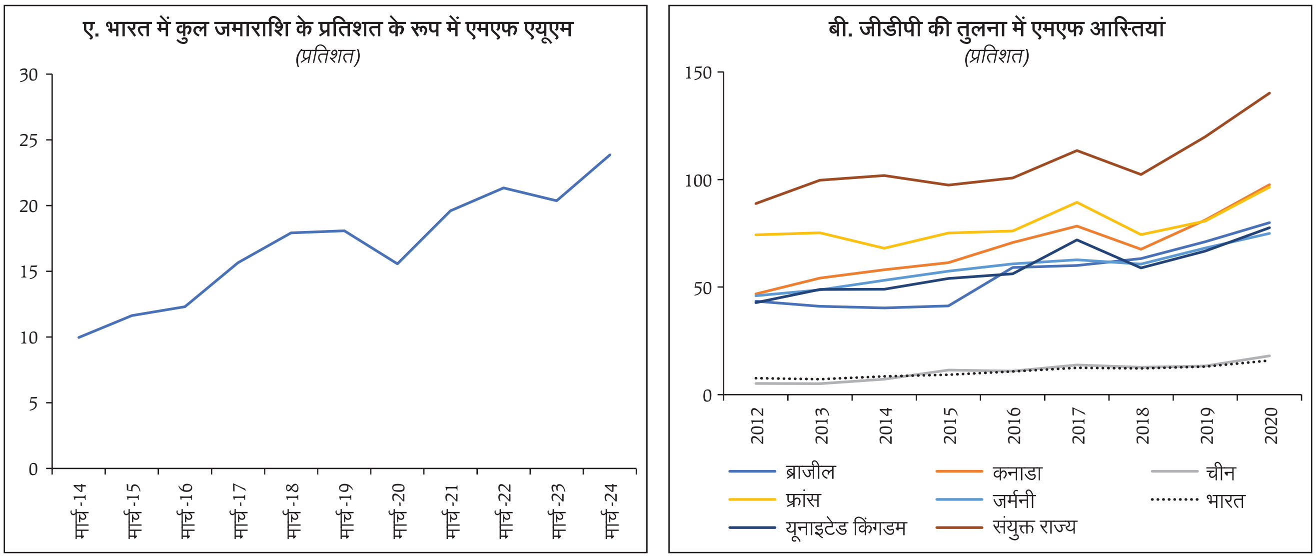

स्रोत: आरबीआई, सेबी, विश्व बैंक एवं लेखकों की गणना।

माध्यम से अल्पकालिक व्यापार और एसआईपी के माध्यम से दीर्घकालिक निवेश के लिए पसंद ने एक साथ गति पकड़ी है। यह ध्यान देने योग्य है कि जहां डेरिवेटिव ट्रेडिंग में खुदरा निवेशकों के नुकसान की चिंता रही है [9], वहीं खुदरा निवेशकों के एक वर्ग ने अधिक धैर्य दिखाया है, जो इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि खुदरा निवेशकों ने 24 महीने से अधिक की अवधि के लिए (मार्च 2025 के अंत तक) 61 प्रतिशत इक्विटी एमएफ आस्तियाँ धारित की हैं (चार्ट 5बी)। इक्विटी के साथ खुदरा निवेशकों का जुड़ाव मजबूत होने के संकेत दे रहा है क्योंकि यह हिस्सा (दो वर्ष से अधिक समय तक इक्विटी आस्तियों को धारित करने वाले खुदरा निवेशक) मार्च 2023 के अंत और मार्च 2024 के अंत में क्रमशः 44.9 प्रतिशत और 53.3 प्रतिशत था। ऐसा लगता है कि

चार्ट 4: इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड्स में वृद्धि ने डेट फंड्स को पीछे छोड़ दिया है

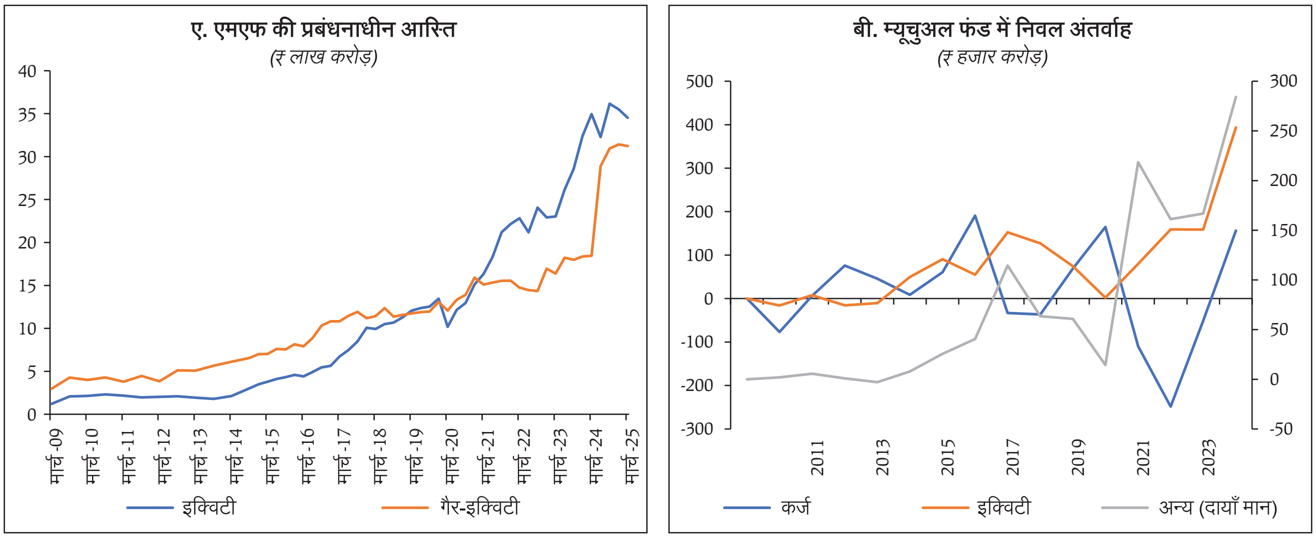

टिप्पणी: अन्य में संतुलन/संकर/समाधान-उन्मुख योजनाएं शामिल हैं।
स्रोत: एएमएफआई एवं लेखक की गणना।

[9] https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/research/jul-2025/comparative-study-of-growth-in-equity-derivatives-segment-vis-vis-cash-market-after-recent-measures_95105.html

चार्ट 5: खुदरा निवेशकों की बढ़ती परिपक्वता

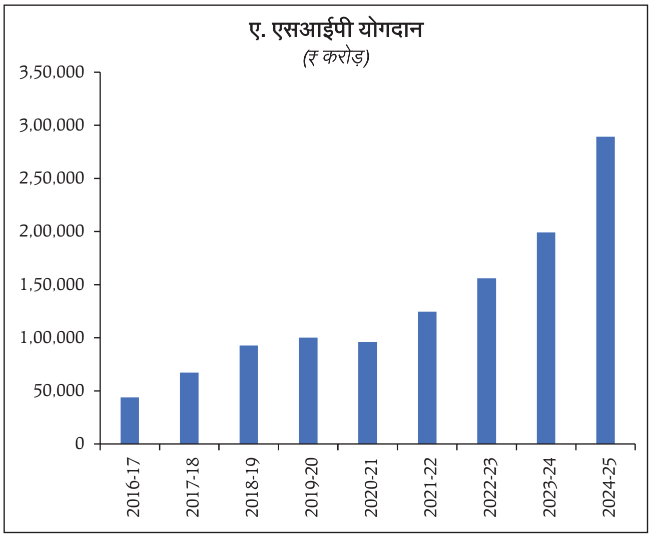

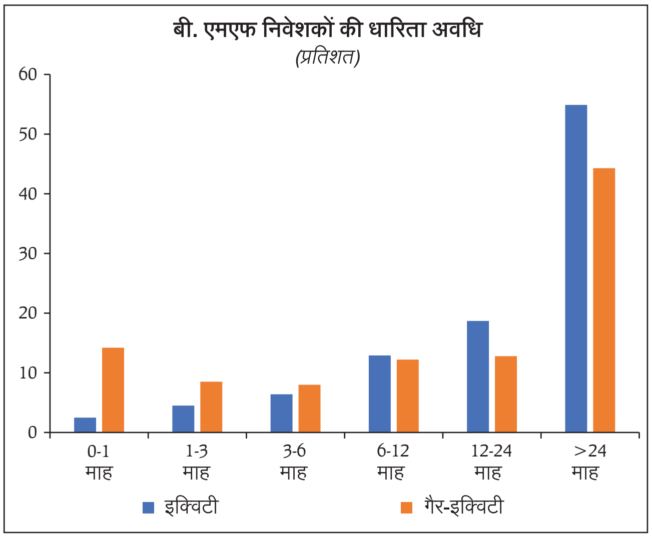

टिप्पणी: धारिता अवधि में सभी श्रेणी के निवेशकों से संबंधित डेटा शामिल है। डेटा मार्च 2025 के अंत तक का है।
स्रोत: एएमएफआई।

एमएफ ने लघु निवेशकों को दीर्घावधि के लिए निवेशित रहने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर लिया है।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मेट्रो शहरों से परे इक्विटी के लिए बढ़ती प्राथमिकता के संकेत हैं, जैसा कि टियर-2 और टियर-3 शहरों से नए डीमैट खाते खोलने की संख्या में वृद्धि से पता लगता है[10]। हालांकि छोटे शहर इक्विटी के लिए रुचि विकसित करने के शुरुआती चरण में हैं, और अधिकांश प्रवाह अभी भी कुछेक राज्यों से ही आता है, पर स्पष्ट परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इक्विटी-उन्मुख एमएफ के संबंध में, अकेले महाराष्ट्र के अंतर्गत एयूएम का एक चौथाई से अधिक हिस्सा है। घनी आबादी वाले उत्तरी और पूर्वी राज्यों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है (चार्ट 6ए)। हालांकि, एयूएम में वृद्धि दर पर एक नज़र

चार्ट 6: इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की प्रबंधनाधीन आस्तियों (AUM) का भौगोलिक वितरण

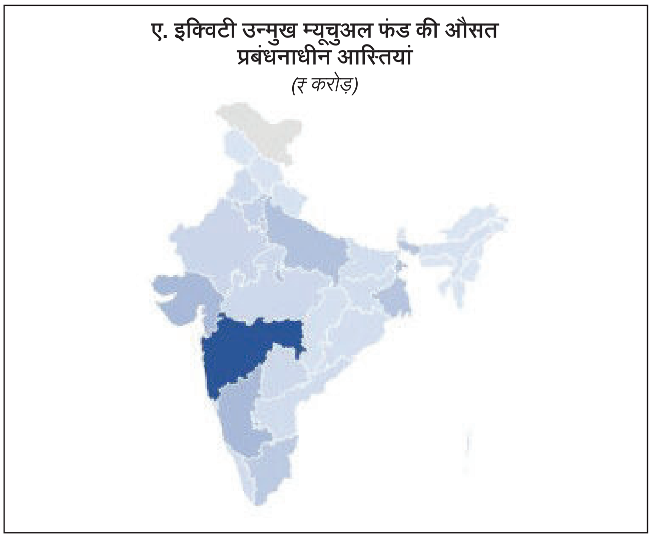

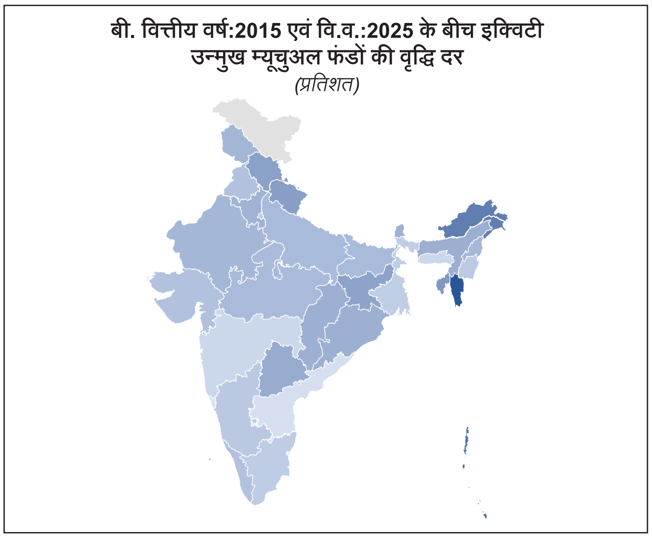

टिप्पणी: गहरे रंग उच्च मानों को दर्शाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का डेटा जम्मू और कश्मीर के साथ मिला दिया गया है।
स्रोत: एएमएफआई एवं लेखक की गणना।

[10] प्रवासी श्रमिकों द्वारा अपना पता अद्यतन न करने के कारण, आंकड़ों में इस प्रवृत्ति को थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा सकता है।

डालने से पता चलता है कि पिछड़े राज्यों ने गति पकड़ने की प्रवृत्ति दिखाई है (चार्ट 6बी)।

बाजार विनियामक और उद्योग निकाय ने टी30 शहरों से परे एमएफ के विस्तार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। जून 2025 के अंत तक, एमएफ उद्योग की 18 प्रतिशत आस्तियों के स्रोत बी30 स्थल रहे हैं। छोटे शहरों में म्यूचुयल फंड को लोकप्रिय बनाने के लिए, एमएफ वितरकों को उच्च कमीशन प्रदान करने के लिए बी30 शहरों से ₹2 लाख तक के नए अंतर्वाह पर 0.3 प्रतिशत का अतिरिक्त व्यय अनुपात प्रभार लगा सकते हैं।[11] हाल के वर्षों में, एमएफ में प्रत्यक्ष निवेश को सक्षम करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के बावजूद, खुदरा निवेशक वितरकों के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं जो प्रशासनिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। केवल 27 प्रतिशत खुदरा निवेशकों ने सीधे निवेश करना चुना (जून 2025 के अंत तक 29 प्रतिशत इक्विटी योजना आस्तियां प्रत्यक्ष मार्ग से आयी)। कॉरपोरेट घराने और एचएनआई बड़े शहरों में केंद्रित हैं, और इस प्रकार, टी30 स्थलों में अधिकांश गैर-इक्विटी आस्तियां हैं (चार्ट 7)।

चार्ट 7: आस्ति मिश्रण (जून 2025 के अंत तक)

(प्रतिशत)

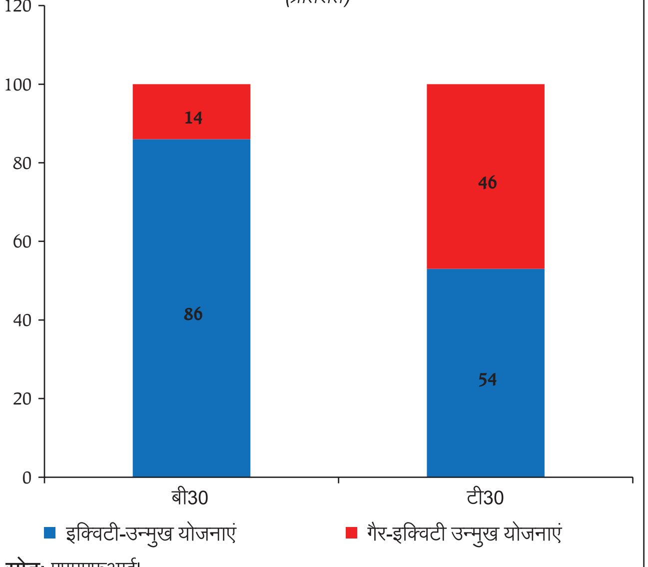

स्रोत: एएमएफआई।

[11] सेबी ने प्रोत्साहन तंत्र के कार्यान्वयन के तरीके में दुरुपयोग, विसंगतियों और कमियों के कारण 1 मार्च 2023 से अगले निदेशों तक प्रोत्साहन योजना को रोक दिया है।

चार्ट 8: एमएफ की कुल धारिता (मार्च 2025)

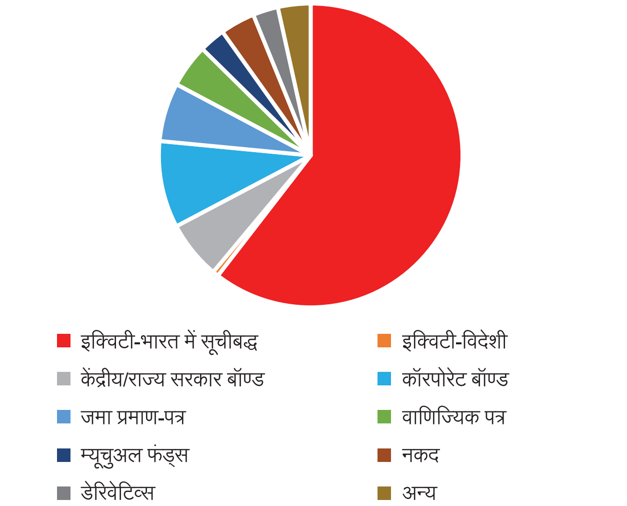

टिप्पणी: अन्य में इक्विटी-भारत में असूचीबद्ध, खजाना बिल, सावधि, मीयादी और मार्जिन जमा, कमोडिटी, वैकल्पिक निवेश निधियाँ एवं भू-संपदा निवेश न्यास (रीट्स)/अवसंरचना निवेश न्यास (इन्विट्स) शामिल हैं।
स्रोत: प्राइम डेटाबेस।

इक्विटी, एमएफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण निवेश वर्ग है, तथा बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र में एमएफ इक्विटी निवेश का एक-चौथाई से भी अधिक हिस्सा संलग्न है (चार्ट 8)।

म्यूचुअल फंड की ओर बढ़ते प्रवाह के साथ, पिछले एक दशक में घरेलू इक्विटी में उनका स्वामित्व काफी बढ़ा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध कंपनियों में म्यूचुअल फंड की शेयरधारिता मार्च 2010 के अंत के 3.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 के अंत में 10.4 प्रतिशत हो गई है (चार्ट 9)।

कंपनियों में बढ़ती शेयरधारिता और पर्याप्त मताधिकार शक्ति के साथ, म्यूचुअल फंड की यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि जिन कंपनियों में वे निवेश करते हैं, वे कॉरपोरेट अभिशासन के सिद्धांतों का पालन करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि म्यूचुअल फंड अपनी नेतृत्वकारी भूमिका से पीछे न हटें और अपने यूनिटधारकों के सर्वोत्तम हित में मतदान करें, सेबी ने 1 अप्रैल 2021 की प्रभावी तिथि से, म्यूचुअल फंडों को कॉरपोरेट अभिशासन से लेकर उन कंपनियों की पूंजी संरचना[12], जिनमें वे निवेश करते हैं, में बदलाव करने तक कई संकल्पों पर मतदान करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। दिशानिर्देशों में बदलाव के बाद, म्यूचुअल फंडों ने कॉरपोरेट संकल्पों पर

[12] https://www.sebi.gov.in/legal/circulars/mar-2021/circular-on-guidelines-for-votes-cast-by-mutual-funds_49405.html

चार्ट 9: एनएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स की शेयरधारिता बढ़ी है

(प्रतिशत)

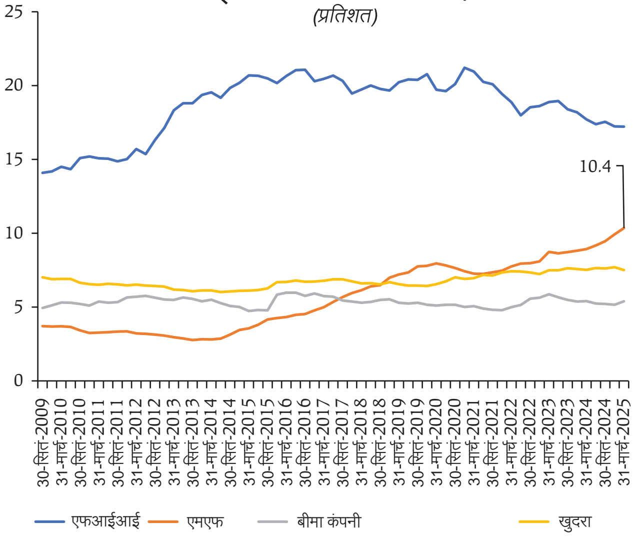

स्रोत: प्राइम डेटाबेस।

मतदान में अधिक सक्रिय और विविध भागीदारी दिखाई है, जो संकल्प के 'विरुद्ध' मतदान के बड़े अंश में भी परिलक्षित होता है। कॉरपोरेट संकल्प के विरुद्ध मतदान करने वाले म्यूचुअल फंडों की हिस्सेदारी 2014-15 के 4.4 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 11.9 प्रतिशत हो गई है, जबकि संकल्पों पर मतदान से परहेज करने वाले म्यूचुअल फंडों की हिस्सेदारी 2014-15 के 21.5 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 0.2 प्रतिशत हो गई है।

दुनिया भर में निष्क्रिय निवेश में बढ़ती रुचि एक और उल्लेखनीय प्रवृत्ति रही है। मॉर्निंगस्टार के अनुसार, वर्ष 2024 की स्थिति में निष्क्रिय निवेश, दुनिया भर में दीर्घावधि आस्तियों का 43.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वर्ष 2023 के अंत से 3.2 प्रतिशत की वृद्धि है[13]। निष्क्रिय निधियों को घरेलू निवेशकों के बीच भी पसंद किया गया है, उद्योग की आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निष्क्रिय निधियों की हिस्सेदारी मार्च 2019 के 6.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 में 17 प्रतिशत हो गई है[14]। 2024-25 के दौरान, पैसिव फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में ₹1.4 लाख करोड़ का निवल प्रवाह देखा गया, जिसका प्रमुख कारण घरेलू ईटीएफ और घरेलू इंडेक्स फंड में अंतर्वाह रहा। इक्विटी-उन्मुख ईटीएफ में संस्थागत प्रवाह द्वारा समर्थित सबसे बड़ा हिस्सा है [15] (चार्ट 10)।

म्यूचुअल फंड घरेलू निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय इक्विटी में निवेश करने और विविधीकरण के लाभ प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान घरेलू इक्विटी से

चार्ट 10: निष्क्रिय निधियों (पैसिव फंड्स) की वृद्धि

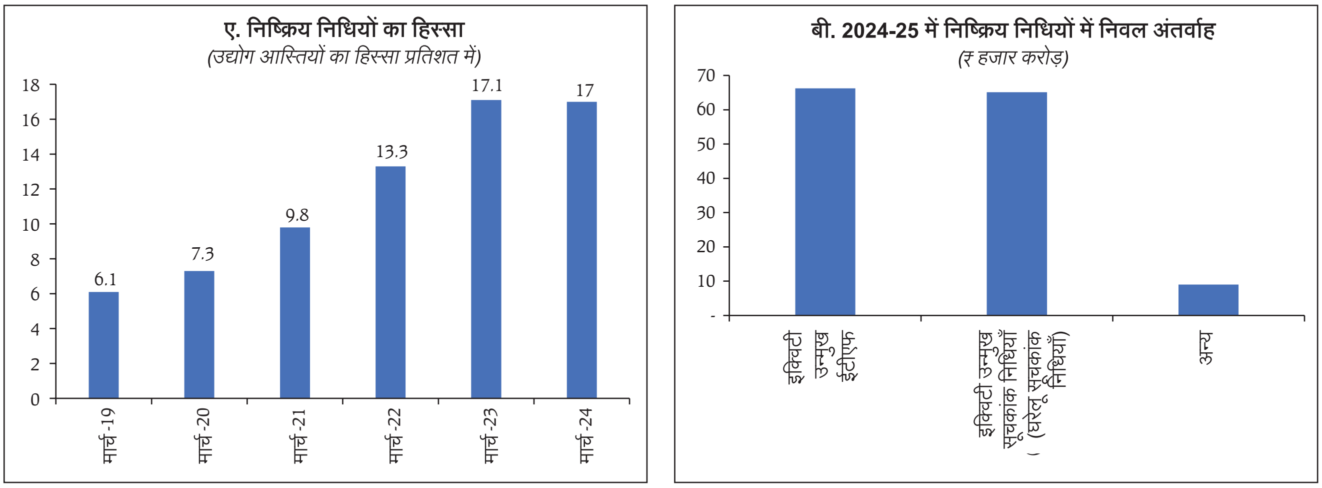

टिप्पणी: अन्य निष्क्रिय निधियों में आय/कर्ज-उन्मुख ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, निष्क्रिय निधियों में विदेशों में निवेश करने वाले फंड ऑफ फंड्स, इक्विटी-उन्मुख इंडेक्स फंड (अंतरराष्ट्रीय इंडेक्स फंड), इक्विटी-उन्मुख ईटीएफ (अंतरराष्ट्रीय ईटीएफ), आय/कर्ज-उन्मुख सूचकांक निधियाँ (लक्ष्य पर परिपक्वता वाली सूचकांक निधियों के अलावा), सक्रिय निधियों में विदेशों में निवेश करने वाले फंड ऑफ फंड्स, आय/कर्ज उन्मुख इंडेक्स फंड [लक्ष्य पर परिपक्वता वाली सूचकांक निधियाँ (इंडेक्स फंड)] शामिल हैं।
स्रोत: एएमएफआई एवं लेखक की गणना।

[13] https://www.morningstar.com/business/insights/research/global-asset-flows-report

[14] https://www.amfiindia.com/Themes/Theme1/downloads/AMFIFactbook%202024.pdf

[15] ईपीएफओ बीएसई-सेंसेक्स एवं निफ्टी50- सूचकांकों की अनुकृति करने वाले ईटीएफ के माध्यम से इक्विटी बाजारों में निवेश करता है।

चार्ट 11: म्यूचुअल फंड के माध्यम से विदेशी निवेश

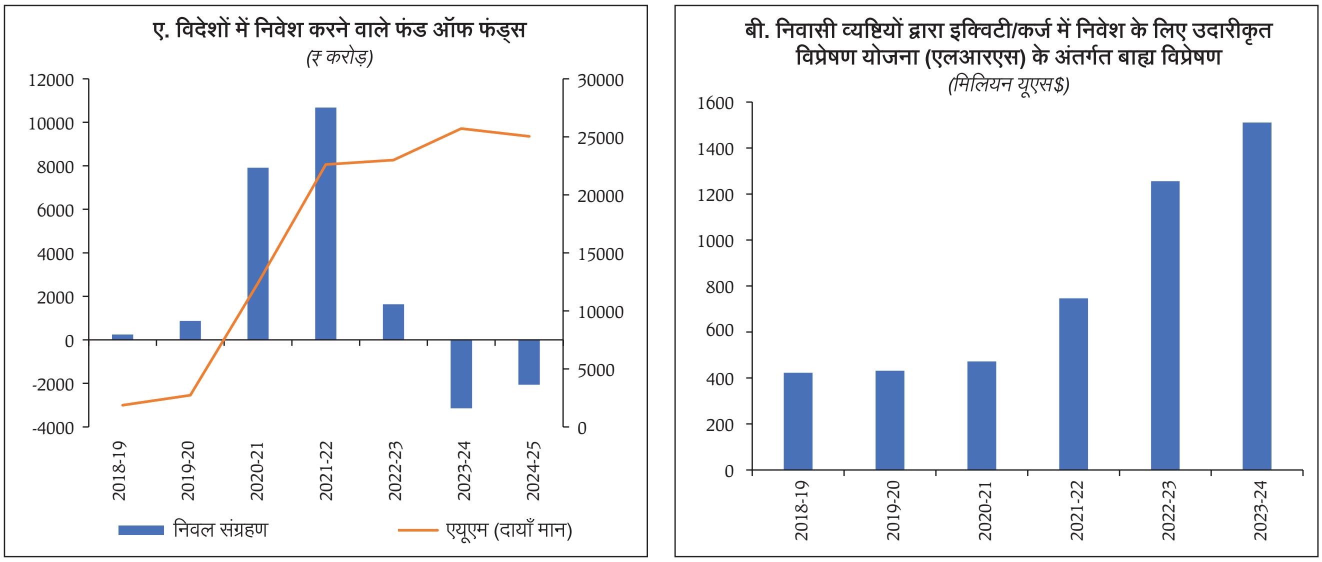

स्रोत: सेबी और आरबीआई।

परे देखने का चलन बढ़ा। हालाँकि, घरेलू इक्विटी बाजारों के बेहतर निष्पादन और म्यूचुअल फंड उद्योग के विदेशी निवेश के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा के करीब पहुँचने के कारण हाल के समय में इसमें कुछ कमी आयी है (चार्ट 11ए)। म्यूचुअल फंड के माध्यम से विदेशी निवेश पर प्रतिबंध, अनजाने में निवेशकों का रुख उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) जैसे वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ सकते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय इक्विटी में संभावित रूप से और अधिक जोखिमपूर्ण एक्सपोजर देखा जा सकता है (चार्ट 11बी)।

म्यूचुअल फंड योजनाओं के पुनर्वर्गीकरण ने निवेशकों को योजनाओं के अंतिम निवेश जगत के बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान की है। फ्लेक्सी-कैप [16] फंडों ने ओपन-एंडेड इक्विटी योजनाओं में पर्याप्त निवल अंतर्वाह देखा है, संभवतः इन योजनाओं द्वारा प्रदान किए गए अधिक लचीलेपन के कारण, जबकि सेक्टोरल/थीमैटिक फंड [17] में 2024-25 में तेजी आई (चार्ट 12)।

निरंतर एमएफ अंतर्वाह ने एफपीआई बहिर्वाह से उपजी अस्थिरता के विरुद्ध इक्विटी बाजार को सहारा देने में मदद की है। घरेलू बाजारों को प्रभावित करने की एमएफ की क्षमता मजबूत हुई है। अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि एमएफ प्रवाह स्मॉल और मिडकैप सेगमेंट[18] में इक्विटी बाजार के रिटर्न को प्रभावित करते हैं। व्यापक बाजारों में पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों की रुचि बढ़ी है, जिसमें मिडकैप और स्मॉलकैप फंड, वर्ष 2024-25 में ओपन-एंडेड इक्विटी-उन्मुख एमएफ में निवल अंतर्वाह का लगभग पांचवां

चार्ट 12: ओपन-एंडेड इक्विटी योजनाओं में निवेश

(₹ हजार करोड़)

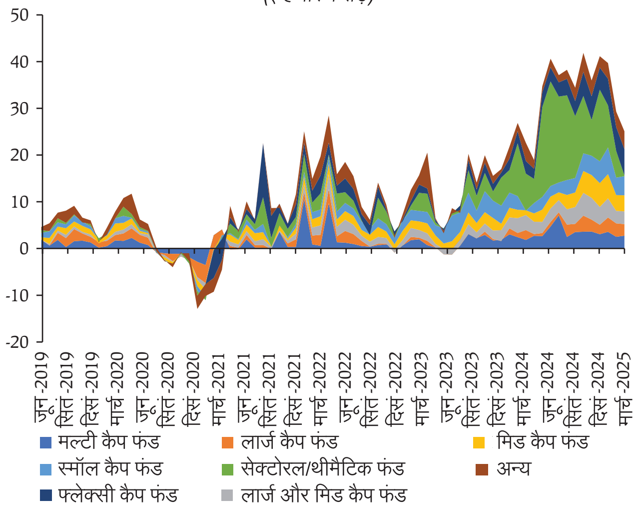

टिप्पणी: अन्य में डिविडेंड यील्ड फंड, वैल्यू फंड/कॉन्ट्रा फंड, फोकस्ड फंड और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) शामिल हैं।
स्रोत: एएमएफआई।

[16] सेबी ने नवंबर 2020 में इस श्रेणी को एक ओपन-एंडेड डाइनैमिक इक्विटी स्कीम के रूप में पेश किया, जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करती है।

[17] https://www.cnbctv18.com/personal-finance/mutual-funds-thematic-schemes-rise-in-inflows-returns-should-you-invest-19424553.htm

[18] https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=22189

चार्ट 13: मिडकैप और स्मॉलकैप योजनाओं में प्रवाह

(कुल प्रवाह का प्रतिशत)

टिप्पणी: प्रवाह डेटा केवल कुल प्रवाह के प्रतिशत के रूप में ओपन-एंडेड इक्विटी-उन्मुख योजनाओं से संबंधित है। 2020-21 में ओपन-एंडेड इक्विटी-उन्मुख योजनाओं से निवल बहिर्वाह हुआ, जिसमें से 26.1 प्रतिशत मिडकैप और स्मॉल-कैप योजनाओं से था।

स्रोत: सेबी और लेखक की गणना।

हिस्सा हैं (चार्ट 13)। एमएफ द्वारा धारित स्मॉल और मिडकैप शेयरों का बाजार मूल्य मार्च 2025 के अंत में लगभग ₹14 लाख करोड़ [19] था, जो एमएफ की इक्विटी धारिताओं/होल्डिंग्स के एक-चौथाई हिस्से से अधिक था। स्मॉल और मिडकैप खंडों में अपेक्षाकृत कम चलनिधि के मद्देनजर, तीव्र गिरावट की स्थिति में, म्यूचुअल फंडों को निकासी (redemption) दबावों के कारण बड़े चलनिधि जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वित्तीय बाजारों के अन्य खंडों पर दबाव पड़ सकता है। स्मॉल और मिडकैप फंडों के निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, सेबी ने म्यूचुअल फंडों से निवेशकों की सुरक्षा के लिए उचित और सक्रिय उपाय करने का निर्देश दिया है। इसके लिए वे अंतर्वाहों को नियंत्रित करने, पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने जैसे उपायों का उपयोग करें तथा यह सुनिश्चित करें कि बड़े पैमाने पर निकासी की स्थिति में, निवेशकों को पहले बेचने/निकासी करने वाले 'फर्स्ट मूवर एडवांटेज' से बचाया जाए। इसके अलावा, बाजार विनियामक ने इन इक्विटी योजनाओं के लिए चलनिधि दबाव परीक्षणों को नियमित कर दिया है, जो 'डेट' योजनाओं के लिए पहले से ही नियमित रूप से किया जाता रहा है।[20]

[19] प्राइम एमएफ डेटाबेस से डेटा का उपयोग करके की गई गणना के अनुसार।

[20] https://www.msn.com/en-in/news/other/latest-stress-test-shows-this-about-small-cap-mutual-funds-check-details-here/ar-AA1FMddc?ocid=BingNewsSerp

III. साहित्य समीक्षा

म्यूचुअल फंड में प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रवाह उपभोक्ता बचत पैटर्न, व्यक्तिगत धन और निवेश निर्णयों को दर्शाते हैं। ये निधि प्रबंधकों (फंड मैनेजर्स) के प्रोत्साहनों को भी प्रभावित करते हैं, निवेशक व्यवहार को प्रकट करते हैं, और वित्तीय बाजारों की समग्र दक्षता को प्रभावित करते हैं (फर्सन एवं किम, 2012; कोप्स एवं अन्य, (2015)। म्यूचुअल फंड प्रवाह पर पिछले अध्ययनों में व्यष्टि और समष्टि, दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया है। सूक्ष्म/व्यष्टि दृष्टिकोण वैयक्तिक म्यूचुअल फंड में प्रवाह के विश्लेषण पर केंद्रित है, जबकि समष्टि दृष्टिकोण समग्र रूप से म्यूचुअल फंड उद्योग में कुल अंतर्वाह और बहिर्वाह की जाँच करता है (एलेक्साकिस एवं अन्य, 2005, 2013; रेमोलोना एवं अन्य, 1997; एडवर्ड एवं झांग, 1998; वॉटसन एवं विक्रमनायके, 2012; जैंक, 2012; फोंग एवं अन्य, 2018)।

भारतीय संदर्भ में, अध्ययनों ने वैयक्तिक निधियों में प्रवाह के विश्लेषण के साथ-साथ डेट एवं इक्विटी निधियों, दोनों के मामले में म्यूचुअल फंड उद्योग में समग्र प्रवाह पर ध्यान केंद्रित किया है (कृपया कुमार एवं अन्य, 2020; मिश्रा, 2011; गुप्ता एवं अन्य, 2022 देखें)। मधुमती एवं अन्य, (2012) भारत में इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों की जाँच करते हैं। यह अध्ययन जुलाई 2005 से अगस्त 2012 की अवधि को कवर करता है, रैखिक ऑटोरिग्रैसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज (ARIMA) मॉडल का उपयोग करता है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवल प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में अस्थिरता, मात्रा, लाभांश प्रतिफल, विनिमय दर, निवेशक व्यवहार, अमेरिकी बाजार रिटर्न, कॉल दरों और पिछले निधि प्रवाहों की पहचान करता है। कुमारी और देबनाथ (2022) द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में जनवरी 2012 से दिसंबर 2020 तक के मासिक आंकड़ों का उपयोग करके बीएसई सेंसेक्स के संदर्भ में एमएफ प्रवाह के निर्धारकों की जांच की गई है। लेखकों ने पाया है कि स्टॉक रिटर्न और अस्थिरता का एमएफ प्रवाह पर एक असममित प्रभाव पड़ता है और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) का ट्रेडिंग पैटर्न विपरीत होता है, यानी एफआईआई की खरीद से एमएफ की बिक्री होती है और इसके विलोमतः होता है।

हाल के वर्षों में, भारत में वर्ष 2017 से (2020 को छोड़कर) डेट योजनाओं की तुलना में इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं

में लगातार अधिक निवल अंतर्वाह हुआ है, जो निवेशकों की पसंद में बदलाव का संकेत देता है। वर्तमान अध्ययन में, इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रवाह के निर्धारकों पर गौर करके, विशिष्ट फंड-टू-फंड बदलावों के बजाय निवेशकों की पसंद और व्यवहार में सामान्य बदलावों का आकलन करने के लिए मैक्रो दृष्टिकोण को चुना गया है।

IV. डेटा एवं कार्यप्रणाली

इक्विटी म्यूचुअल फंडों में प्रवाह के कारकों का अनुमान लगाने के लिए मासिक आवृत्ति वाले निम्नलिखित चरों का उपयोग किया गया है (सारणी 1)। यह डेटा अप्रैल 2015 से नवंबर 2024 तक का है।

म्यूचुअल फंड प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों की विविध और गतिशील प्रकृति को देखते हुए, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सबसे प्रभावशाली भविष्यवाणियों को उजागर करने के लिए उपयुक्त हैं। पारंपरिक रैखिक मॉडल, जो डेटा में जटिल इंटरैक्शन या गैर-रैखिक पैटर्न में चूक सकते हैं, के विपरीत रैंडम फ़ॉरेस्ट जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एक विशिष्ट कार्यात्मक रूप को ग्रहण किए बिना प्रभावी रूप से ऐसी जटिलताओं को संभाल सकते हैं। रैंडम फ़ॉरेस्ट एक एन्सेम्बल मशीन-लर्निंग विधि है जो इंडिविजुयल ट्री क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन (ब्रेइमन 2001) के आधार पर निर्मित है। एनसेंबल लर्निंग कई मॉडलों को मिलाकर एक अधिक सुदृढ़ और सटीक पूर्वानुमानात्मक मॉडल तैयार करती है। रैंडम फ़ॉरेस्ट के मामले में वैयक्तिक मॉडल, डिसीजन ट्री होते हैं। यह एक गैर-पैरामीट्रिक पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है तथा विचरण को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक स्थिर और विश्वसनीय मॉडल प्राप्त होता है। यह कई ट्री से प्राप्त पूर्वानुमानों के औसत निकालने की प्रकृति के कारण डेटा में आउटलायर्स के प्रति मज़बूत है और लुप्त मानों को भी संभाल सकता है।

चरों का महत्व रैंडम फॉरेस्ट मॉडल का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो भविष्यसूचक प्रदर्शन में प्रत्येक विशेषता के योगदान के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चरों के महत्व का मूल्यांकन करने के लिए, हम क्रमचय परीक्षण और शैप्ले मान (पर्म्यूटेशन टेस्ट एंड शैप्ले वैल्यूज), दोनों का उपयोग करते हैं। क्रमचय परीक्षण में किसी विशिष्ट प्रिडिक्टर के मानों में यादृच्छिक रूप से फेरबदल करके परिणामी चर के साथ उसका संबंध तोड़ा जाता है, जबकि अन्य सभी चर अपरिवर्तित रहते हैं। परिणामस्वरूप, प्रिडिक्टर एरर में वृद्धि उस चर के महत्व को इंगित करती है - अधिक वृद्धि मॉडल की सटीकता में अधिक योगदान का संकेत देती है। इसके विपरीत, कॉपरेटिव गेम सिद्धांत से प्राप्त शैप्ले मान, सभी संभावित विशेषताओं के संयोजन में भविष्यवाणी के लिए प्रत्येक विशेषता के औसत सीमांत योगदान को मापते हैं। यह दृष्टिकोण चरों के महत्व का एक सुसंगत और स्थानीय रूप से सटीक अनुमान प्रदान करता है, जो विशेषताओं के बीच अंतःक्रियाओं और निर्भरताओं का प्रभावी तरीके से पता लगाता है।

सारणी 1: चरों का विवरण

चर	परिभाषा	स्रोत
प्रवाह	प्रवाह में बढ़ती प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए मासिक निवल प्रवाह को पिछले महीने के निवल एयूएम द्वारा सामान्यीकृत किया जाता है (रेमोलोना एवं अन्य, 1997)।	एएमएफआई
सेंसेक्स रिटर्न	बीएसई सेंसेक्स में मासिक प्रतिशत परिवर्तन (एक माह के अंतराल के साथ)।	ब्लूमबर्ग
वीआईएक्स	निफ्टी अस्थिरता (निवेश जोखिम)	ब्लूमबर्ग
टर्म स्प्रेड	10-वर्षीय जी-सेक बॉण्ड प्रतिफल, 3-माह जी-सेक प्रतिफल का निवल योग।	ब्लूमबर्ग
जोखिम स्प्रेड	10-वर्षीय एएए कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल, 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल का निवल प्रतिफल।	ब्लूमबर्ग
लाभांश प्रतिफल	वित्तीय अनुपात की गणना (लाभांश/स्टॉक मूल्य) के रूप में की जाती है।	ब्लूमबर्ग
मुद्रास्फीति	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत परिवर्तन	ब्लूमबर्ग
सावधि जमा दर (सापेक्ष बाजार रिटर्न)	एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	डीबीआईई, आरबीआई
कारोबार विश्वास सूचकांक	विनिर्माण सर्वेक्षणों पर आधारित यह मानकीकृत सूचकांक, उत्पादन, ऑर्डर और इन्वेंट्री के भावी पूर्वानुमानों का संकेत देता है। 100 से अधिक का मान आशावाद का संकेत देता है; 100 से नीचे का मान निराशावाद का।	ओईसीडी
डीमैट खाते	निवेशक खातों की संख्या (लाख में)	सेबी

स्रोत: लेखक द्वारा संकलन।

इक्विटी एमएफ प्रवाह के निर्धारकों को समझने के लिए, कोप्सच एवं अन्य, (2015) के संकेतों के साथ-साथ अन्य घरेलू कारकों जैसे कि सावधि जमा दरें, कारोबार विश्वास सूचकांक और डीमैट खाता खोलने के आधार पर चरों का चयन किया जाता है। सावधि जमा दरों को इक्विटी एमएफ से रिटर्न/सापेक्ष बाजार रिटर्न के विकल्प के रूप में चुना जाता है। एक विस्तारित अवधि के लिए लगातार कम सावधि जमा दर, अंततः लोगों को उच्च रिटर्न प्रदान करने वाले अन्य आस्ति वर्गों की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिनसे इक्विटी एमएफ प्रवाह बढ़ता है। बीएसई सेंसेक्स पर प्राप्त रिटर्न ने पिछले 15 वित्तीय वर्षों में से 10 में सावधि जमा रिटर्न को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें सेंसेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स की संमिश्र वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर), वर्ष 2010-11 और 2024-25 के बीच मीयादी जमाराशियों के लिए 7 प्रतिशत की तुलना में 12 प्रतिशत है (चार्ट 14)।

डीमैट खाता खोलना वित्तीय समावेशन और इक्विटी के प्रति बढ़ती पसंद का एक प्रतिनिधि माना जा सकता है। इससे इक्विटी-उन्मुख उत्पादों की ओर अतिरिक्त प्रवाह को बढ़ावा मिलना चाहिए। कारोबार विश्वास सूचकांक से प्रवाह प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि यह भावी संवृद्धि का सूचक है और VIX संबंध अस्थिरता से है। इस प्रकार, उच्च अस्थिरता से

चार्ट 14: सेंसेक्स बनाम मीयादी जमा रिटर्न

(प्रतिशत)

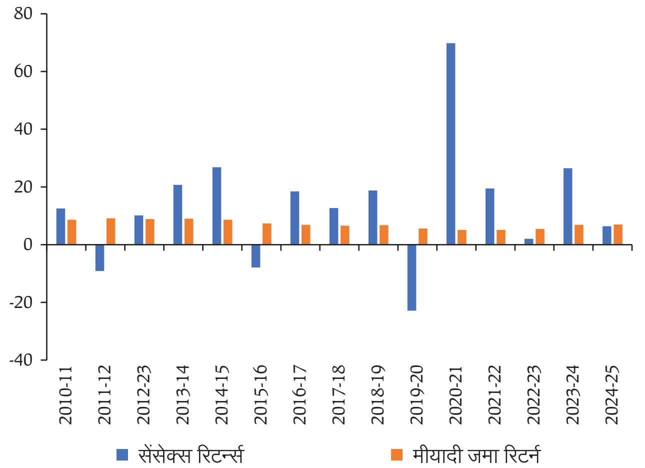

टिप्पणी: वित्तीय वर्ष के लिए सेंसेक्स रिटर्न की गणना, बीएसई सेंसेक्स कुल रिटर्न इंडेक्स का उपयोग करके की जाती है। मीयादी जमा दरें, पाँच प्रमुख बैंकों की मीयादी जमा दरों (1 से 3 वर्षीय) से संबंधित हैं।
स्रोत: आरबीआई और ब्लूमबर्ग।

इक्विटी एमएफ में प्रवाह कम हो सकता है। जैंक (2012) के अनुसार, उच्च अवधि स्प्रेड और जोखिम स्प्रेड के परिणामस्वरूप इक्विटी एमएफ में प्रवाह कम होता है। लेखक बताते हैं कि मंदी से ठीक पहले या उसके दौरान, शेयर की कीमतों में गिरावट के कारण लाभांश प्रतिफल में उछाल आता है। साथ ही, निवेशक इक्विटी पोजीशन बनाए रखने के लिए कम इच्छुक हो जाते हैं। इसलिए, इक्विटी एमएफ में लाभांश प्राप्ति और प्रवाह के बीच एक ऋणात्मक संबंध देखा जा सकता है। मुद्रास्फीति के साथ प्रवाह की दिशा निश्चित नहीं है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी, मुद्रास्फीति से बचाव करती है (अल-नासर और भट्टी, 2019; स्पाईरू, 2019)। हालाँकि, उच्च मुद्रास्फीति लोगों को शेयरों के बजाय अचल संपत्तियों में निवेश करके बचाव-व्यवस्था (हेजिंग) करने के लिए प्रेरित कर सकती है (पार्क एवं अन्य, 1990; कोप्स एवं अन्य, 2015)। इस विश्लेषण में, क्रमचय परीक्षण और शैप्ले मान, दोनों का उपयोग करते हुए, मुख्य ध्यान इस बात की पहचान करने पर है कि कौन से चर म्यूचुअल फंड प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, न कि उनके प्रभावों की दिशा (सकारात्मक या नकारात्मक) निर्धारित करने पर। उद्देश्य, मॉडल के निष्पादन को संचालित करने में प्रत्येक भविष्यवक्ता के सापेक्ष महत्व का आकलन करना है। यह विश्लेषण [21] महत्व के आधार पर क्रमबद्ध शीर्ष पाँच चरों को प्रकट करता है (चार्ट 15)।

क्रमचय परीक्षण और शैप्ले मान, दोनों के परिणाम दर्शाते हैं कि डीमैट खाते, सावधि जमा दरें और कारोबार विश्वास सूचकांक - इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रवाह के शीर्ष तीन प्रभावशाली भविष्यवक्ता हैं। इससे पता चलता है कि निवेशकों की बाजारों तक पहुँच (डीमैट खातों द्वारा प्रदर्शित), वैकल्पिक बचत विकल्प (जैसे सावधि जमा दरें) और कारोबारी वातावरण के बारे में आशावाद (जैसा कि कारोबार विश्वास सूचकांक द्वारा मापा जाता है) इक्विटी म्यूचुअल फंड में प्रवाह को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि दोनों विधियां मोटे तौर पर सबसे

[21] डेटासेट को मानकीकृत किया जाता है ताकि इसका माध्य शून्य (0) और मानक विचलन एक (1) हो। फिर डेटा को प्रशिक्षण और परीक्षण समूहों में विभाजित करने के लिए 80-20 का विभाजन किया जाता है।

चार्ट 15: रैंडम फ़ॉरेस्ट से प्राप्त चर महत्व

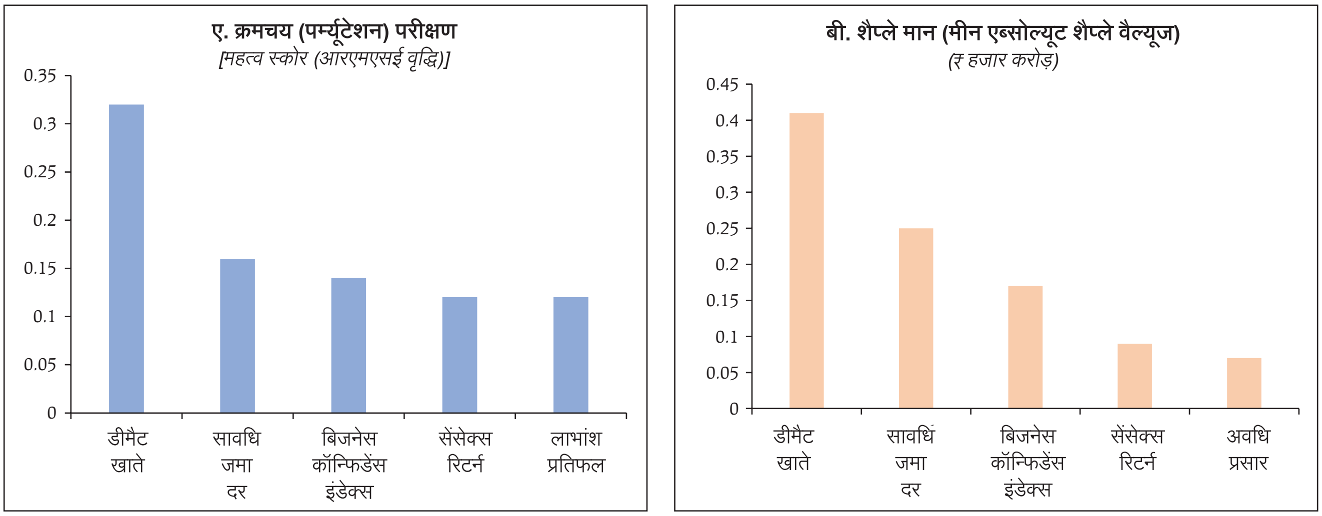

टिप्पणी: बाएँ पैनल में क्रमचय (पर्म्यूटेशन) महत्व से प्राप्त चर महत्व को दर्शाया गया है, जबकि दाएँ पैनल में शैप्ले मान से प्राप्त चर महत्व को दर्शाया गया है। प्रत्येक विधा के लिए निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार केवल शीर्ष 5 चर ही चुने गए हैं।
स्रोत: लेखक की गणना।

महत्वपूर्ण चरों पर सहमत हैं, क्रमचय परीक्षण लाभांश प्रतिफल को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उजागर करता है, जबकि शैप्ले मान सावधि स्प्रेड पर जोर देते हैं। यह विचलन दर्शाता है कि विभिन्न विधियां कैसे चरों के महत्व का पता लगाती हैं: क्रमचय महत्व भविष्यवाणी की सटीकता पर सीमांत प्रभाव पर केंद्रित है, जबकि शैप्ले मान चरों के बीच अंतःक्रियाओं और साझा योगदानों को भी ध्यान में रखते हैं।

चार्ट 16: जीडीपी वृद्धि और इक्विटी एमएफ प्रवाह

(AUM द्वारा मापी गई वृद्धि दर, प्रवाह)

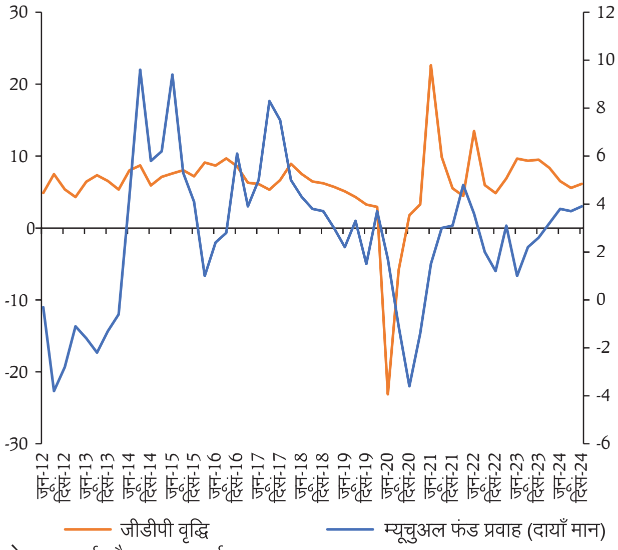

स्रोत: ब्लूमबर्ग और एएमएफआई।

इसके अतिरिक्त, इक्विटी म्यूचुअल फंड में प्रवाह और वास्तविक अर्थव्यवस्था की गतिकी के बीच संबंध को समझने के लिए, यानी कि क्या भारत के मामले में इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रवाह में वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बारे में जानकारी शामिल है या इसके विलोमतः होता है, एक अनुभवजन्य अभ्यास किया गया है, और विश्लेषण से पता चलता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रवाह में वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बारे में कोई भी जानकारी शामिल नहीं है [22]। विश्लेषण की अवधि 2012-13 की पहली तिमाही से ले कर 2024-25 की तीसरी तिमाही तक है (चार्ट 16) [23]।

एक रिड्यूस्ड-फॉर्म बाईवैरिएट VAR मॉडल का उपयोग किया गया है। प्रवाह और वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बीच ग्रेंजर कॉज़ालिटी परीक्षण के परिणाम सारणी 2 में रिपोर्ट किए गए हैं। शून्य परिकल्पना कि "प्रवाह वास्तविक जीडीपी वृद्धि को ग्रेंजर कॉज़ नहीं करते हैं" खारिज होने में विफल रहता है, यह सुझाव देते हुए कि प्रवाह के पिछले मान में वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। हालांकि, शून्य परिकल्पना कि "वास्तविक जीडीपी वृद्धि, प्रवाह को ग्रेंजर कॉज़ नहीं करती है" को पांच प्रतिशत महत्व के स्तर पर खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार, वास्तविक जीडीपी वृद्धि के पिछले मान में इक्विटी

[22] प्रवाह में बढ़ती प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए, पिछले महीने के निवल एयूएम द्वारा निवल प्रवाह को सामान्यीकृत किया जाता है (रेमोलोना एवं अन्य, 1997)।

[23] दोनों शृंखलाओं के बीच सहसंबंध गुणांक 0.17 है।

सारणी 2: प्रवाह और वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बीच ग्रेंजर कॉज़ालिटी का परीक्षण

	प्रवाह, वास्तविक जीडीपी वृद्धि के ग्रेंजर कारण नहीं बनते हैं	वास्तविक जीडीपी वृद्धि, प्रवाह का ग्रेंजर कारण नहीं बनती है
एफ स्टैटिस्टिक्स	0.27	4.23**

टिप्पणी: * p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 । उपरोक्त परिणाम केवल एक अंतराल के लिए रिपोर्ट किए गए हैं।
स्रोत: लेखक की गणना।

म्यूचुअल फंड प्रवाह की भविष्यवाणी के लिए उपयोगी जानकारी होती है। एक यूनिडायरेक्शनल ग्रेंजर कॉज़ालिटी - वास्तविक जीडीपी वृद्धि से लेकर म्यूचुअल फंड प्रवाह तक स्थापित होती है। संक्षेप में, मजबूत वास्तविक आर्थिक संवृद्धि, निवेशक की वित्तीय क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जिससे इक्विटी बाजारों में अधिक भागीदारी संभव होती है।

V. निष्कर्ष

भारत में इक्विटी निवेश, विशेष रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड (एमएफ) के माध्यम से, लगातार बढ़ रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड निरंतर वृद्धि एवं सुदृढ़ता का अनुभव कर रहे हैं। वित्तीय बाजारों के प्रति पारंपरिक रूप से सतर्क दृष्टिकोण के बावजूद, हाल के वर्षों में जनसाधारण ने अपने वैयक्तिक निवेश विकल्पों में अधिक वित्तीय जोखिम उठाने की स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाई है। वित्तीय व्यवहार में इस बदलाव को सुगम बनाने और समायोजित करने में म्यूचुअल फंड एक पसंदीदा साधन के रूप में उभरे हैं।

अनुभवजन्य विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि बढ़ता वित्तीय समावेशन (डीमैट खातों द्वारा प्रदर्शित), सावधि जमा दरें और कारोबार विश्वास - भारत में इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रवाह को आकार देने वाले तीन सबसे प्रभावशाली कारक हैं। एक वैकल्पिक विश्लेषण से पता चलता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड प्रवाह वास्तविक जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान नहीं लगाते, बल्कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि, प्रवाह का पूर्वानुमान लगाने में मदद करती है। यह दर्शाता है कि मज़बूत आर्थिक वृद्धि निवेशकों की इक्विटी बाजारों में अधिक धन आबंटित करने की क्षमता और विश्वास, दोनों को बढ़ाती है।

इस बदलते परिदृश्य में, इक्विटी म्यूचुअल फंडों के संचालकों पर कड़ी नज़र रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनका घरेलू बचत एवं घरेलू पूंजी बाज़ारों की बदलती गतिकी पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ती खुदरा भागीदारी के साथ, इन नए निवेशकों का विश्वास और भरोसा बनाए रखने के लिए निवेशक शिक्षण और संरक्षण की दिशा में और भी प्रयास जरूरी हैं। जैसे-जैसे म्यूचुअल फंडों का आकार बढ़ेगा, उनके परिचालन से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर निरंतर निगरानी पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

संदर्भ

Alexakis, C., Niarchos, N., Patra, T. and Poshakwale, S. (2005), "The dynamics between stock returns and mutual fund flows empirical evidence from the Greek market," *International Review of Financial Analysis*, Vol. 14, No. 5, pp. 559-569.

Alexakis, C., Apostolos, D. and Grose, C. (2013), "Asymmetric dynamic relations between stock prices and mutual fund units in Japan. An application of hidden cointegration technique", *International Review of Financial Analysis*, Vol. 28, pp. 1-8.

Al-Nassar, N. S., and Bhatti, R. H. (2019). Are common stocks a hedge against inflation in emerging markets? *Journal of Economics and Finance*, 43, 421-455.

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine learning*, 45(1), 5-32.

Edwards, F. R., and Zhang, X. (1998). Mutual funds and stock and bond market stability. *Journal of Financial Services Research*, 13(3), 257-282.

Ferson, W.E. and Kim, M.S. (2012). "The factor structure of mutual fund flows," *International Journal of Portfolio Analysis and Management*, Vol. 1, No. 2, pp. 112-143.

Fong, T. P. W., Sze, A. K. W., and Ho, E. H. C. (2018). Determinants of equity mutual fund flows–Evidence from the fund flow dynamics between Hong Kong and global markets. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 57, 231-247.

Gupta, M., Kumar, S., Seet, S., and Borad, A. (2022). Market Returns and Flows to Debt Mutual Funds. *RBI Bulletin October 2022*, Reserve Bank of India.

Jank, S. (2012). Mutual fund flows, expected returns, and the real economy. *Journal of Banking and Finance*, 36(11), 3060-3070.

Kopsch, F., Song, H. S., and Wilhelmsson, M. (2015). Determinants of mutual fund flows. *Managerial Finance*, 41(1), 10-25.

Kumar, P., Saxena, C., and Gupta, A. K. (2020). A study on relationship between stock market returns and mutual fund flows. *Journal of Commerce and Accounting Research*, 9(1), 1.

Kumari, M., and Debnath, P. (2022). Determinants of Mutual Fund Flows in the Indian Stock Market: Insights Through the Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds-testing Approach with Structural Breaks. *Vision.*

Madhumathi, R., Gopal, N., and Ranganatham, M. (2012). Determinants of Debt and Equity Mutual Fund Flows in India. *In XI Capital Markets Conference* (pp. 21-22).

Mishra, P. K. (2011). Dynamics of the relationship between Mutual Funds investment flow and stock market returns in India. *Vision*, 15(1), 31-40.

Park, J.Y., Mullineaux, D.J. and Chew, I.-T. (1990), "Are REITs inflation hedges?", *Journal of Real Estate Finance and Economics*, Vol. 3, No. 1, pp. 91-103.

Remolona, E. M., Kleiman, P., and Gruenstein Bocain, D. (1997). Market returns and mutual fund flows. *Economic Policy Review*, 3(2), 33-52.

Securities and Exchange Board of India. (2024). *Working paper on household savings through Indian securities market.* Department of Economic and Policy Analysis. https://www.sebi.gov.in/reportsand-statistics/research/sep-2024/working-paper-on-household-savingsthrough-indian-securities-market_86459.html

Spyrou, S. I. (2004). Are stocks a good hedge against inflation? Evidence from emerging markets. *Applied Economics*, 36(1), 41-48.

Watson, J. and Wickramanayake, J. (2012), "The relationship between aggregate managed fund flows and share market returns in Australia," *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, Vol. 22, No. 3, pp. 451-472.

ईवी नीतियां और दोपहिया ईवी अपनाना: भारतीय राज्यों से साक्ष्य

*अटल सिंह[#] , सत्यम कुमार, अभ्युदय हर्ष और तिस्ता तिवारी द्वारा^*

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाना अभी शुरुआती चरण में है, और दोपहिया वाहन (2W) टिकाऊ गतिशीलता की ओर संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालाँकि सहायक नीतियों ने ईवी को अपनाने में तेज़ी ला दी है, लेकिन क्षेत्रीय असमानताएँ अभी भी बनी हुई हैं। यह शोधपत्र 23 भारतीय राज्यों के पैनल डेटा का उपयोग करके 2W-EV अपनाने पर राज्य-स्तरीय ईवी प्रोत्साहन नीतियों के प्रभाव का परीक्षण करता है। अनुभवजन्य निष्कर्ष बताते हैं कि राज्य-स्तरीय सहायक नीतियाँ अपनाने की दरों को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा, मज़बूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मध्यम वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ मिलकर अपनाने को बढ़ावा दे सकता है।

परिचय

इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाने के लिए, सरकारों (केंद्र और राज्य दोनों) ने कई नीतियों और पहलों को लागू किया है। यह प्रयास, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज-26 में प्रस्तुत पंचामृत एजेंडे के तहत भारत की प्रतिबद्धता के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 45 प्रतिशत कम करना और 2070 तक नेट जीरो हासिल करना शामिल है। ईवी में बदलाव अन्य बातों के साथ-साथ न केवल भारत के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बल्कि घरेलू चुनौतियों जैसे तेल आयात को कम करने, वायु प्रदूषण से निपटने और एक उभरते क्षेत्र में रोजगार वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2024-25 में भारत में लगभग तीन-चौथाई वाहन पंजीकरण दोपहिया वाहनों के होंगे, भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाज़ार (यात्री और वाणिज्यिक वाहनों का) और दुनिया में दोपहिया वाहनों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता होने के नाते, 2W वाहन खंड के डीकार्बोनाइजेशन का लाभ उठाने की विशिष्ट स्थिति में है (राज्यसभा, 2023)। हालाँकि, कुल इलेक्ट्रिक वाहनों (2W+3W+4W) में 2W-EV की हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन कुल बिक्री में 2W के बराबर हिस्सेदारी हासिल करना अभी बाकी है (चार्ट 1)। अनुमान बताते हैं कि सहायक नीतियों के साथ, 2030-31 तक 80 प्रतिशत 2W इलेक्ट्रिक बन सकते हैं (जेएमके रिसर्च एंड एनालिसिस, 2022)।

इलेक्ट्रिक वाहनों को वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर बाज़ार में प्रवेश दिलाने में कई कारकों ने योगदान दिया है (चार्ट 2)। पिछले एक दशक में, वैश्विक बाज़ारों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई सहायक नीतियाँ शुरू की गई हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। ये पहल नॉर्वे में 1990 के दशक की शुरुआत में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2008 में और चीन द्वारा 2014 में शुरू की गई थीं (आईईए, 2021)।

इलेक्ट्रिक वाहनों के वैश्विक विकास में सहायक सरकारी नीतियाँ केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं, जिन्होंने उच्च अग्रिम लागत और सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बाधाओं को दूर किया है। कर प्रोत्साहन से लेकर सब्सिडी तक, ऐसे उपाय उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को सुलभ और किफायती बनाकर उन्हें अपनाने को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुए हैं (मुन्ज़ेल एट अल., 2019)। भारत में, अपनी महत्वपूर्ण बाजार क्षमता के साथ, राज्यों में राजकोषीय और बुनियादी ढाँचागत पहलों का संयोजन इस बदलाव को आगे बढ़ाने में, विशेष रूप से 2W सेगमेंट में, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये नीतियाँ स्थायी गतिशीलता की ओर बदलाव के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं।

वैश्विक स्तर पर, भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) देश दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए सबसे बड़े बाजारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2023 में,

[#] लेखक सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) से हैं।

^ लेखक आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग से हैं। लेखक डीएसआईएम के सहायक सलाहकार डॉ. अनिरबन सान्याल से प्राप्त सुझावों और प्रोत्साहन के लिए आभारी हैं। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

चार्ट 1: भारत में वाहन बिक्री

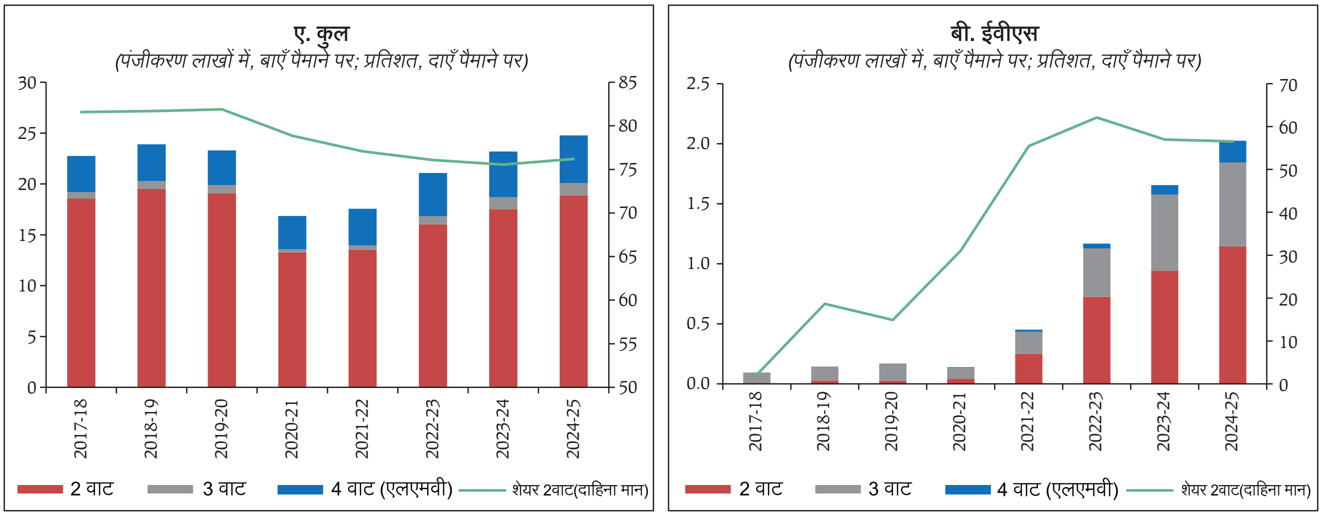

नोट: 1. हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) में 7.5 टन से कम कुल भार वाली कारें, जीपें, वैन और छोटे ट्रक शामिल हैं। यहाँ केवल यात्री एलएमवी ही शामिल हैं।
2. कुल से तात्पर्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधन चालित वाहनों और ई.वी. दोनों से है।

स्रोत: सीएमआईई इंडस्ट्री आउटलुक; और लेखक की गणना।

चीन की वैश्विक 2W-EV बिक्री में 78 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, इसके बाद भारत का स्थान था जो वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 2W-EV बाजार है। भारत में 2023 में 2W की बिक्री का लगभग पांच प्रतिशत इलेक्ट्रिक था। इलेक्ट्रिक कारें भी बढ़ती संख्या में देशों में बड़े पैमाने पर बाजार का उत्पाद बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। 2023 में, इलेक्ट्रिक कार की

चार्ट 2: इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में योगदान देने वाली ताकतें

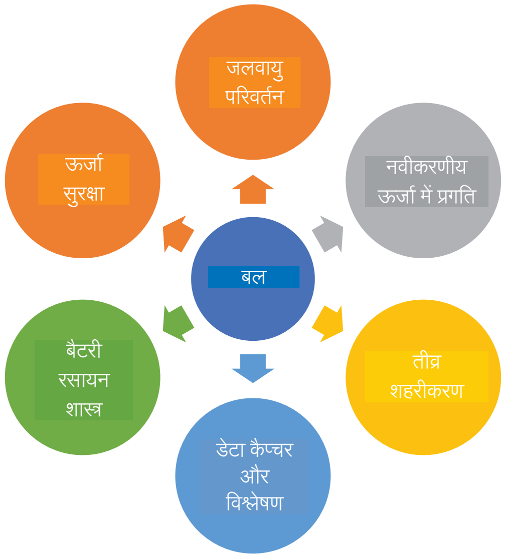

स्रोत : नीति आयोग, 2018.

अधिकांश बिक्री चीन, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई, जो वैश्विक इलेक्ट्रिक कार बिक्री का लगभग 95 प्रतिशत है। इस प्रकार, 2W-EV और इलेक्ट्रिक कार दोनों की बिक्री अभी भी भौगोलिक रूप से केंद्रित है, यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में[1]।

वैश्विक स्तर पर दूसरे सबसे बड़े 2W-EV बाज़ार के रूप में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए, 2W-EV बाज़ार में अपार संभावनाएँ हैं, और लक्षित सरकारी कार्रवाई की भूमिका उभर कर सामने आती है। परिणामस्वरूप, यह लेख भारत में 2W-EV के विकास को गति देने में राज्य सरकार की नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करता है। लेख का शेष भाग निम्नलिखित खंडों में विभाजित है। खंड II में EV नीतियों के परिदृश्य का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। खंड III में संक्षिप्त साहित्य समीक्षा प्रस्तुत की गई है। खंड IV में आँकड़ों के स्रोतों और कार्यप्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अनुभवजन्य अनुमान और परिणामों पर खंड V में चर्चा की गई है , उसके बाद खंड VI में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है।

[1] इलेक्ट्रिक कार की बिक्री चीन, यूरोप और अमेरिका में केंद्रित है, जबकि 2W-EV चीन, भारत और आसियान देशों में केंद्रित हैं।

चार्ट 3: इलेक्ट्रिक पर्सनल वाहनों की बिक्री और हिस्सेदारी

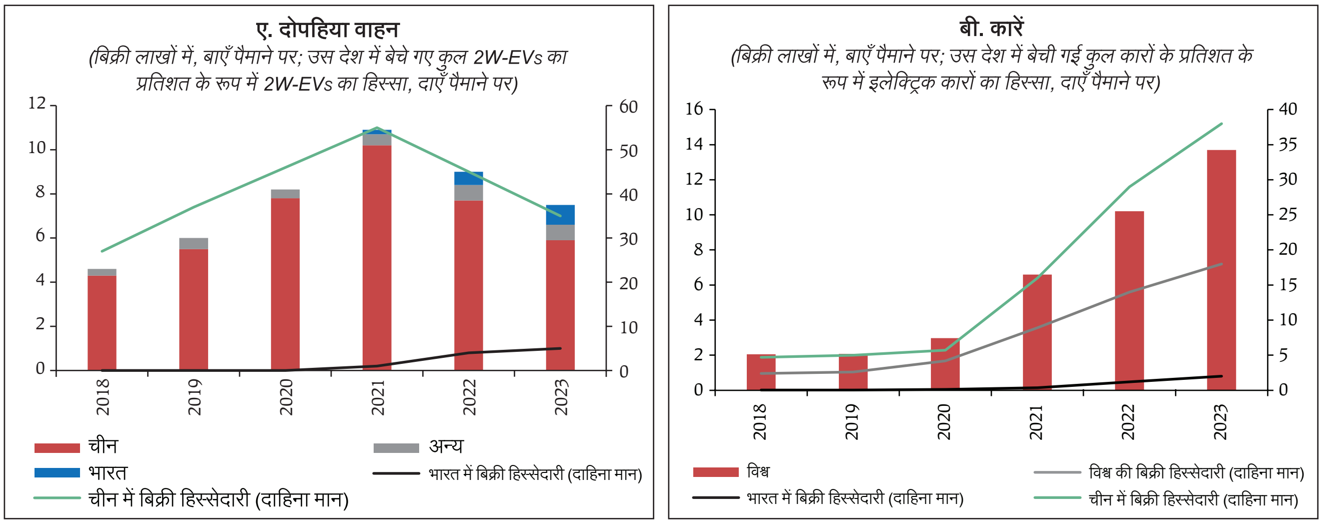

नोट: चार्ट ए में अन्य देशों में यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, वियतनाम, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका और चीनी ताइपे शामिल हैं।
स्रोत: आईईए, 2024.

II. नीति परिदृश्य

दुनिया भर के देश इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी नीतियाँ अपना रहे हैं, जैसे उत्सर्जन मानक निर्धारित करना, औद्योगिक प्रोत्साहन प्रदान करना, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना आदि। इन आपूर्ति पक्ष के उपायों के अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को अग्रिम सब्सिडी जैसे माँग पक्ष के उपाय भी साथ-साथ लागू किए जा रहे हैं (सारणी 1)। हालाँकि, सीमित राजकोषीय स्थिति के कारण अपर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन उभरते और विकासशील देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में बाधा बन सकते हैं (आईईए, 2024)।

सारणी 1: वैश्विक ईवी नीतियों में प्रमुख विकास

क्षेत्र	महत्वपूर्ण पहल	संक्षिप्त सिंहावलोकन
संयुक्त राज्य अमेरिका	मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम	स्वच्छ ऊर्जा और ईवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन, विनिर्माण से जुड़े क्रेडिट समर्थन और आपूर्ति श्रृंखला समझौते।
यूरोपीय संघ	ग्रीन डील उद्योग योजना	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना, नेट-जीरो प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना, कच्चे माल की सोर्सिंग, रीसाइक्लिंग और घरेलू बैटरी उत्पादन, ताकि 2030 तक यूरोपीय संघ की 90 प्रतिशत मांग को पूरा किया जा सके (नेट-जीरो उद्योग अधिनियम के भाग के रूप में)।
चीन	ईवी सब्सिडी कार्यक्रम	इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए उच्च प्रीमियम के साथ ट्रेड-इन सब्सिडी योजना, अन्य खंडों पर लागू खरीद कर से इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट, चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण निवेश और बैटरी विनिर्माण में नेतृत्व।
जापान	हरित विकास रणनीति	2035 तक केवल गैसोलीन वाली नई कारों की बिक्री को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, इलेक्ट्रिक और ईंधन सेल कारों के लिए सब्सिडी खरीदने तथा बैटरी आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने का लक्ष्य।
कनाडा	शून्य-उत्सर्जन वाहन (ZEV) अधिदेश	प्रांतीय ZEV अधिदेश, संघीय खरीद प्रोत्साहन, तथा बैटरियों और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति श्रृंखला निवेश।
ऑस्ट्रेलिया	राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन रणनीति	ईवी अपनाने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन, चार्जिंग नेटवर्क का विकास, तथा स्थानीय बैटरी और ईवी घटक विनिर्माण की योजना।
यूनाइटेड किंगडम	शून्य उत्सर्जन वाहन (ZEV) अधिदेश	2035 तक सभी नई कारें और वैन शून्य उत्सर्जन वाहन होंगी, राष्ट्रव्यापी चार्जिंग बुनियादी ढांचे में निवेश, और कंपनी कारों के लिए कर छूट, वाहन उत्सर्जन व्यापार योजना शून्य-उत्सर्जन कार बिक्री के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगी
नॉर्वे	ईवी कर छूट	ईवी खरीद पर पंजीकरण शुल्क, टोल और वैट से छूट; 2025 तक आंतरिक दहन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य।
भारत	फेम I और फेम II; पीएम ई-ड्राइव	मांग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, ई.वी. के लिए आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे का निर्माण और अनुसंधान एवं विकास सहायता।

स्रोत: आईईए, 2025; और लेखकों का संकलन।

सारणी 2: भारत में ईवी नीति का विकास

नीति	लक्ष्य	प्रोत्साहन
सतही परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन (एएफएसटी) [2011]	स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना।	प्रत्यक्ष अंतिम उपयोगकर्ताओं को सब्सिडी के रूप में केंद्रीय वित्तीय सहायता; अनुसंधान एवं विकास तथा घरेलू विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन।
राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना (एनईएमएमपी) 2020 [2013 में शुरू की गई]	वर्ष 2020 से प्रतिवर्ष इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री प्राप्त करना।	कर प्रोत्साहन; चार्जिंग अवसंरचना के लिए समर्थन; पायलट परियोजनाएं; बाजार सृजन; और अनुसंधान एवं विकास सहायता।
भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाना और विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना चरण I (2015) [एनईएमएमपी के हिस्से के रूप में शुरू किया गया]	चार फोकस क्षेत्र: • मांग सृजन • प्रौद्योगिकी मंच • पायलट परियोजनाएं • चार्जिंग बुनियादी ढांचा।	इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए अग्रिम-कम खरीद मूल्य, पायलट परियोजनाओं के तहत विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनुदान, अनुसंधान एवं विकास/ प्रौद्योगिकी विकास, और सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के रूप में मांग प्रोत्साहन।
फेम इंडिया योजना चरण-II (2019) [फेम इंडिया योजना चरण-I का विस्तार]	ई.वी. को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना; ई.वी. के लिए आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करना; विभिन्न जागरूकता गतिविधियां चलाना।	खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन देकर खरीदारों को वित्तीय सब्सिडी; केंद्रीय सब्सिडी के अलावा राज्य स्तरीय प्रोत्साहन; तथा अनुसंधान एवं विकास सहायता।
ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (2021)	उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना'।	उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन।
अभिनव वाहन संवर्द्धन में इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति (पीएम ई-ड्राइव) [2024]	इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना, परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना; इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाना। कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीला इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण।	2 एवं 3W-ईवी, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी के लिए सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन; उच्च ईवी प्रवेश और राजमार्गों वाले चयनित शहरों में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना।

स्रोत: पीआईबी; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई); और लेखकों का संकलन।

वैश्विक नीतिगत रुझानों के अनुरूप, भारत ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए नीतिगत समर्थन शुरू किया है (सारणी 2)। शुरुआती प्रयास 2011 में भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन (AFST) के तहत राजकोषीय प्रोत्साहनों के साथ शुरू हुए। हाल ही में, नवोन्मेषी वाहन संवर्धन में इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति (PM E-DRIVE) योजना शुरू की गई, जो 1 अक्टूबर, 2024 से लागू हुई और मार्च 2028 के अंत तक लागू रहेगी [2] (PIB, 2024)। इस योजना का उद्देश्य परिवहन संबंधी पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है, साथ ही एक कुशल और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है।

केंद्र की नीतियों के अनुरूप, राज्य सरकारों ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरक नीतियाँ शुरू की हैं। उल्लेखनीय रूप से, कर्णाटक , आंध्र प्रदेश और केरल जैसे दक्षिणी राज्य इस संबंध में शुरुआती कदम उठाने वाले राज्य रहे हैं (चार्ट 4)। राज्य स्तर पर अधिकांश नीतियाँ 2021 और 2023 के बीच शुरू की गईं। एक राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के मोटे तौर पर तीन मुख्य स्तंभ होते हैं: माँग प्रोत्साहन, चार्जिंग बुनियादी ढाँचे में सुधार और कौशल विकास एवं अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।

III. साहित्य समीक्षा

सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करते हैं, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों में, जहाँ उच्च प्रारंभिक लागत निषेधात्मक हो सकती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि छूट, कर छूट और कम पंजीकरण शुल्क जैसे मौद्रिक प्रोत्साहन उपभोक्ताओं के लिए शुरुआती खरीद लागत को कम करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देते हैं (जेन एट अल., 2018; और सिएर्ज़चुला एट अल., 2014)। यूरोप जैसे बाजारों में, लक्षित वित्तीय प्रोत्साहनों ने इलेक्ट्रिक वाहनों और पारंपरिक वाहनों के बीच मूल्य अंतर को काफी कम कर दिया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन अधिक सुलभ हो गए हैं (लेवे एट अल., 2017)।

[2] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2154408

चार्ट 4: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ईवी नीति अधिसूचनाओं की समय-सीमा

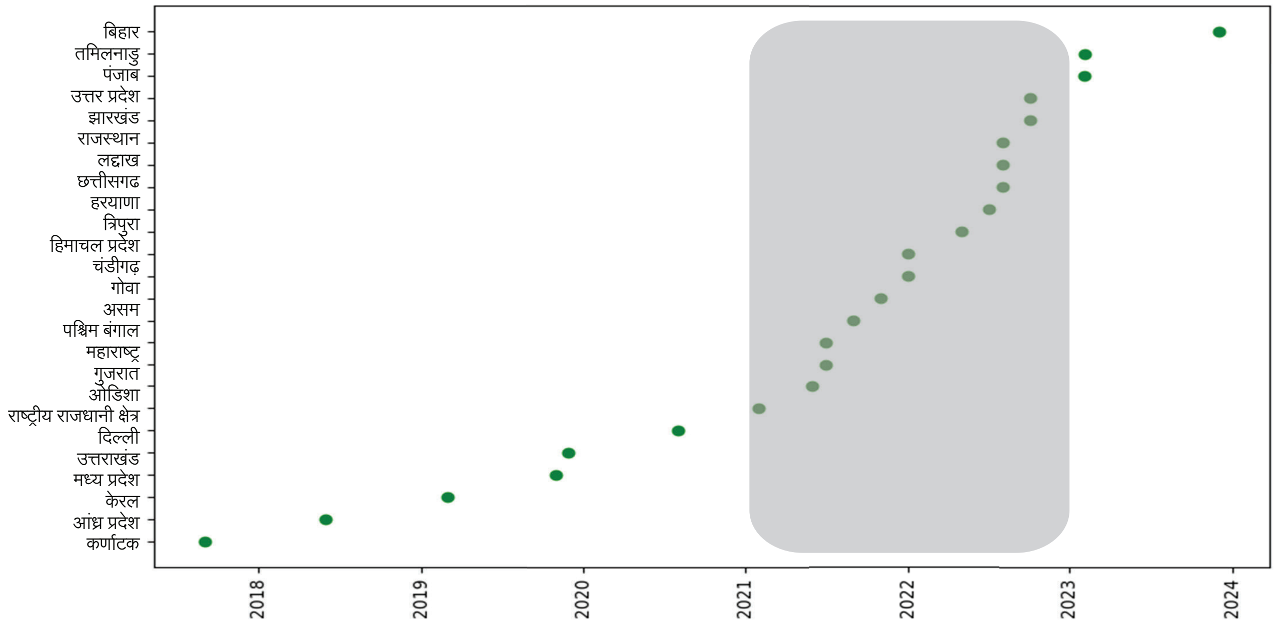

नोट: छायांकित क्षेत्र दर्शाता है कि अधिकांश राज्य नीतियां 2021 और 2023 के बीच अधिसूचित की गईं।
स्रोत: बीईई

अमेरिका से प्राप्त अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि बिक्री के बिंदु के निकट प्रोत्साहन, जैसे छूट, कर क्रेडिट की तुलना में ईवी की बिक्री को बढ़ाने में अधिक प्रभावी हैं (नरसिम्हन और जॉनसन, 2018)। वी, कॉफ़मैन और ला क्रॉइक्स (2018) ने पाया कि अमेरिका में राज्य-स्तरीय सब्सिडी में $1000 की वृद्धि से ईवी पंजीकरण में 5-11 प्रतिशत की वृद्धि होती है। इसी प्रकार, यूरोप में, मुन्ज़ेल एट अल. (2019) के एक अध्ययन में पाया गया कि वित्तीय प्रोत्साहन में €1000 की वृद्धि से ईवी बाजार हिस्सेदारी में 5-7 प्रतिशत की वृद्धि होती है, जो बाजार में प्रवेश को प्रभावित करने में मौद्रिक लाभों की उपलब्धता और परिमाण दोनों के महत्व को रेखांकित करता है। भारत में ईवी को अपनाना अभी भी प्रारंभिक चरण में है (सॉ एट अल., 2023), भारत में, परिवहन क्षेत्र को कार्बन-मुक्त बनाने और तेल आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के तहत, सरकारी नीतियाँ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर केंद्रित रही हैं। चक्रवर्ती एट अल. (2022) इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाने के लिए मूल्य सब्सिडी, रियायती कर व्यवस्था और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार जैसे मांग-पक्ष प्रोत्साहनों के महत्व को रेखांकित करते हैं। इसके अलावा, श्रीवास्तव एट अल. (2022) एक खेल-सिद्धांत मॉडल के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि मांग-पक्ष और आपूर्ति-पक्ष के उपायों, जैसे कि विभेदक करों, का एक संतुलित मिश्रण सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सकता है, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित कर सकता है, और दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बार-बार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया है। ली एट अल. (2017) ने पाया है कि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की अधिक उपलब्धता इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि से जुड़ी है, जो चार्जिंग उपलब्धता और उपभोक्ता मांग के बीच पूरकता पर ज़ोर देता है। हॉल एंड लुत्से (2017) बताते हैं कि नॉर्वे और नीदरलैंड जैसे अधिक विकसित चार्जिंग नेटवर्क वाले बाज़ारों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर काफ़ी ज़्यादा रही है। भारतीय संदर्भ में, निगम एट अल. (2024) बताते हैं कि चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को प्रभावित करती है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के बाज़ार के विकास में मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को दर्शाता है।

यह शोधपत्र भारत में अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्र, 2W-EV को अपनाने पर राज्य-स्तरीय EV प्रोत्साहन नीतियों के विभेदक प्रभाव की जाँच करके बढ़ते साहित्य में योगदान देता है। इसके अलावा, यह क्षेत्रीय अपनाने में असमानताओं की जानकारी प्रदान करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका के साथ राज्य-स्तरीय नीतिगत विविधताओं को विशिष्ट रूप से एकीकृत करता है।

IV. डेटा और कार्यप्रणाली

यह अध्ययन 2W-EVs में विकास के कई आयामों को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रिक और गैर-इलेक्ट्रिक 2W बिक्री (Q1: 2021 से Q2: 2024) के राज्यवार पंजीकरण, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या (अगस्त 2024 तक), राज्यवार सड़क की लंबाई (भारत के बेसिक रोड सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार) और राज्य ईवी नीति अधिसूचनाओं[3] पर त्रैमासिक डेटा का उपयोग करता है (सारणी 3 , अनुलग्नक 1 और 2)।

भारतीय राज्यों में 2W-EV के उपयोग का आकलन करने के लिए, एक अपनाने का अनुपात (AR) की गणना की जाती है, जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

$$AR_{i,t} = \frac{Total\ 2W\text{–}EVs\ registered\ in\ state\ i\ in\ period\ t}{Total\ non\ electric\ 2Ws\ registered\ in\ state\ i\ in\ period\ t} * 100$$

सारणी 3: डेटा के स्रोत

क्र. सं.	आंकड़े (राज्यवार)	स्रोत
1.	2- डब्ल्यू बिक्री (इलेक्ट्रिक और गैर-इलेक्ट्रिक)	वाहन पोर्टल
2.	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या	मधुमक्खी
3.	सड़क की लंबाई	भारत के बुनियादी सड़क सांख्यिकी का डेटाबेस, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
4.	ईवी नीति अधिसूचना तिथियां	मधुमक्खी

अनुपात 2W-EVs की बिक्री के अनुपात की गणना गैर-इलेक्ट्रिक 2W समकक्ष के मुकाबले करता है। उच्च AR गैर-EVs की तुलना में EV बिक्री के बड़े हिस्से को दर्शाता है, इसलिए 2W-EVs की गहरी पैठ है। राज्यों द्वारा EV नीति अपनाने के बाद AR में बदलाव को देखने के लिए, चार्ट 5 में नीति अपनाने से पहले और बाद के परिदृश्यों को दर्शाने वाला एक भौगोलिक हीट मैप प्रस्तुत किया गया है। नीति -पश्चात हीट मैप में गहरे हरे रंग के क्षेत्र यह संकेत देते हैं कि भारत के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों ने 2W-EVs को अपनाने में एक मजबूत नीति प्रभाव प्रदर्शित किया है। इसके विपरीत, उत्तरी और पूर्वी

चार्ट 5: भारत में ईवी अपनाना (राज्य ईवी नीति लागू होने से पहले और बाद में)

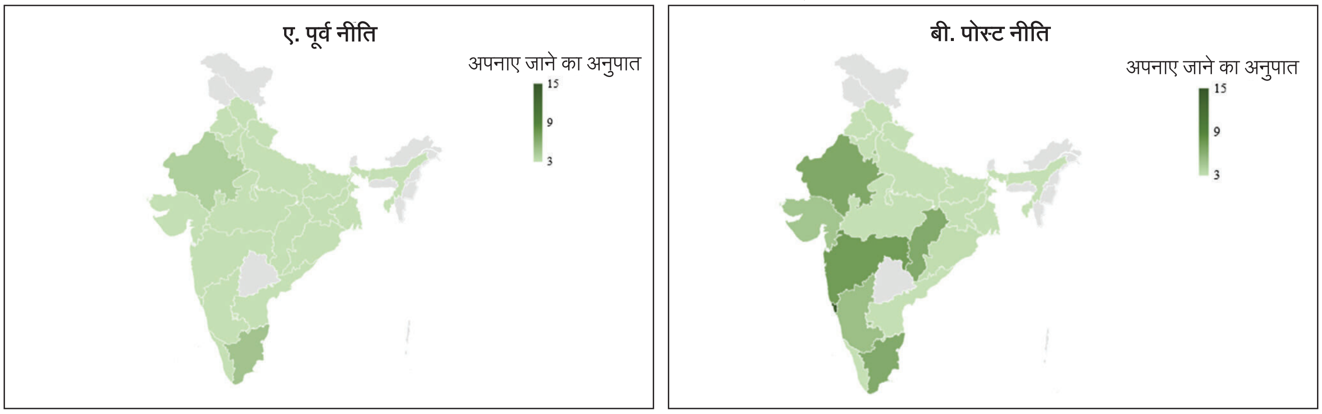

टिप्पणियाँ: 1. प्रत्येक राज्य के लिए पूर्व-नीति अपनाने के अनुपात की गणना ईवी नीति अधिसूचना तिमाही से पहले की छह तिमाहियों के औसत अपनाने के अनुपात के रूप में की जाती है।
2. प्रत्येक राज्य के लिए नीति-पश्चात अपनाने के अनुपात का निर्धारण ईवी नीति घोषणा तिमाही के बाद की छह तिमाहियों के अपनाने के अनुपातों के औसत के आधार पर किया जाता है।
3. उन राज्यों के लिए जहां ईवी नीति अध्ययन अवधि से पहले लागू की गई थी, नीति के बाद अपनाने के अनुपात की गणना मार्च 2021 तिमाही से शुरू होने वाले अपनाने के अनुपात के औसत के रूप में की जाती है।
4. जिन राज्यों में नीति मार्च 2021 और सितंबर 2022 के बीच लागू की गई है, वहां पूर्व-नीति अपनाने के अनुपात की गणना के लिए ईवी नीति अधिसूचना से पहले छह तिमाहियों या उससे कम समय के लिए औसत लिया गया था।

स्रोत: वाहन पोर्टल; बीईई; और लेखकों की गणना।

[3] इन अधिसूचनाओं में योजना की शुरुआत, मांग प्रोत्साहन से संबंधित जानकारी, चार्जिंग अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सरकार की पहल, अनुसंधान एवं विकास तथा जनशक्ति प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।

राज्यों में हीट मैप का हल्का छायांकित क्षेत्र अपनाने की दरों में तुलनात्मक रूप से मामूली वृद्धि दर्शाता है।

उपरोक्त के आलोक में, चार्ट 6 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों (उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम) [4] के लिए एआर का विकास किया गया है । भारत में 2W-EV के लिए प्राथमिकताएं कई कारकों द्वारा संचालित होती हैं। उदाहरण के लिए, कोविड-19 के बाद, व्यक्तिगत गतिशीलता की उच्च मांग ने बाइक रेंटल कंपनियों को अपने बेड़े में अधिक 2W-EV जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। [5] राज्य-स्तरीय ईवी नीतियों को तैयार करने वाले शुरुआती दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों ने अखिल भारतीय एआर की तुलना में लगातार बेहतर एआर का प्रदर्शन किया है, जबकि उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र पीछे हैं। इस प्रकार, पूरे भारत में अपनाने का प्रक्षेपवक्र स्पष्ट रूप से गैर-समान और गैर-समकालिक है, जिसे स्थानीय और कुछ सामान्य कारकों दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग तरीके से सामने आए।

चार्ट 6: क्षेत्रवार अपनाने का अनुपात

(प्रतिशत)

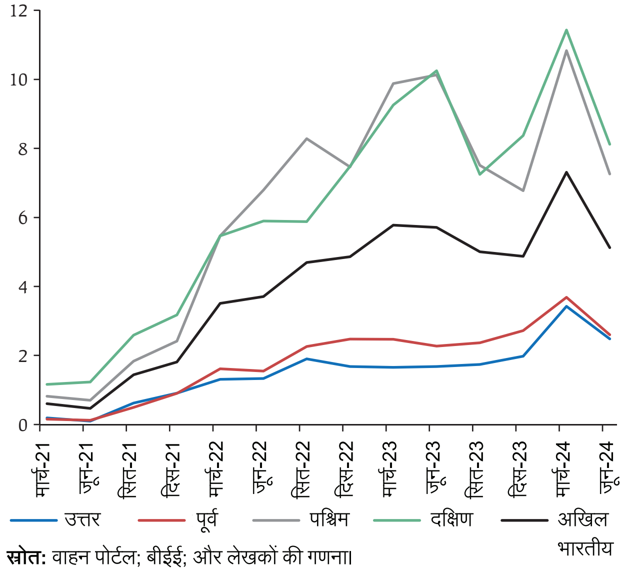

स्रोत: वाहन पोर्टल; बीईई; और लेखकों की गणना।

[4] उत्तर: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश; उत्तराखंड; दक्षिण: आंध्र प्रदेश, कर्णाटक , केरल, तमिलनाडु; पूर्व: बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल; पश्चिम: राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र।

[5] https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/voices/rise-in-ev-rental-of-2-wheelers-in-india/

आंतरिक दहन इंजन (ICI) से चलने वाले वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में एक बड़ी बाधा पर्याप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचे का अभाव है। इसे समझने के लिए, नीचे दिखाए अनुसार एक EV चार्जिंग इंडेक्स [6] बनाया गया है:

$$EV\ Charging\ Index_i = \frac{Number\ of\ public\ charging\ stations\ in\ state\ i}{Total\ road\ length\ in\ the\ state\ i} * 100$$

राज्यवार ईवी चार्जिंग सूचकांक पूरे भारत में चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थिति की तुलनात्मक तस्वीर प्रदान करता है। मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे वाले पांच अग्रणी राज्यों में से तीन राज्य अर्थात कर्णाटक , गोवा और महाराष्ट्र भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित हैं। इसके अलावा, उत्तर भारत से दिल्ली और हरियाणा शीर्ष पांच में शामिल हैं (चार्ट 7)। प्रासंगिक ईवी नीतियों को तैयार करने के अलावा, कई राज्य सरकारों ने अपने चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काम किया है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल आदि राज्य चार्जिंग स्टेशन उपकरण/मशीनरी और घटकों की कुल लागत पर 25-60 प्रतिशत के बीच पूंजीगत सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली में चार्जिंग उपकरणों की खरीद पर 100 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान है ।

जून 2023 में, केंद्र सरकार ने सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने और दीर्घकालिक रूप से अधिक टिकाऊ और आत्मनिर्भर ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीयकरण मानदंडों का पालन न करने की चिंताओं को दूर करने की अपनी रणनीति के तहत चल रही FAME II नीति के तहत 2W-EV खरीदने वाले ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया। [8] सब्सिडी को एक्स-फैक्ट्री कीमत के 15 प्रतिशत पर

[6] चार्जिंग स्टेशनों की संख्या पर समय-श्रृंखला डेटा उपलब्ध न होने के कारण यह सूचकांक अगस्त 2024 के डेटा पर आधारित है।

[7] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020 के तहत पहले 30,000 चार्जिंग पॉइंट्स के लिए प्रति चार्जिंग पॉइंट 6000 रुपये तक के चार्जिंग उपकरणों की खरीद के लिए 100% अनुदान प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

[8] https://indbiz.gov.in/govt-reduces-fame-ii-subsidies-for-electric-two-wheelers/

चार्ट 7: ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स

(सड़क की लंबाई लाख किलोमीटर में, ऊर्ध्वाधर पैमाने पर; सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या, क्षैतिज पैमाने पर)

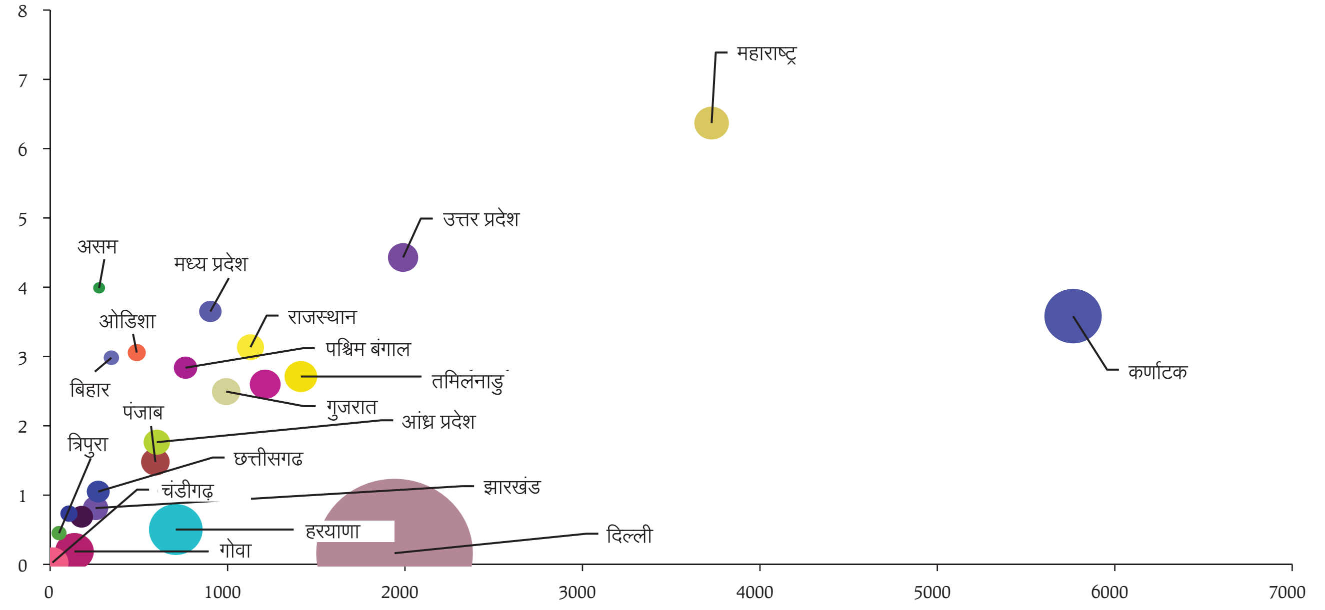

नोट: बुलबुले का आकार जितना बड़ा होगा, सड़क की प्रति किलोमीटर लंबाई पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या उतनी ही अधिक होगी।
स्रोत: भारतीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय: बीईई; तथा लेखकों का संकलन।

सीमित कर दिया गया, जो वाहन की लागत के 40 प्रतिशत की पिछली सीमा से कम है। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी की दर ₹10,000 प्रति kWh बैटरी क्षमता निर्धारित की गई, जो निर्माताओं के लिए पहले के ₹15,000 प्रति kWh के प्रोत्साहन से कम है।[9] इस कदम ने पूरे भारत में सितंबर 2023 तिमाही में बिक्री को प्रभावित किया (चार्ट 8)।

अधिकांश राज्य सरकारें हर नई 2W-EV खरीद पर कर और पंजीकरण शुल्क माफी के साथ सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन दे रही हैं। दूसरी ओर, कुछ राज्यों ने कर और पंजीकरण शुल्क माफी से परे कोई अतिरिक्त सब्सिडी नहीं दी। 23 राज्यों में 2W-EV अपनाने के अनुपात का विश्लेषण - छह राज्य जिन्होंने बिना किसी अतिरिक्त सब्सिडी के केवल कर और पंजीकरण शुल्क माफी की पेशकश की, और 17 राज्यों ने इन छूटों के साथ टॉप-अप सब्सिडी प्रदान की - अपनाने के रुझानों में उल्लेखनीय अंतर का पता चला। जून 2023 में नीति परिवर्तन के बाद, अतिरिक्त सब्सिडी के बिना छह राज्यों में औसत अपनाने का अनुपात सितंबर 2023 तिमाही में तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) 24 प्रतिशत कम हो गया।

अनुभवजन्य डिजाइन के लिए, भारत के 23 राज्यों में 2W-EV के लिए राज्यवार नीतियों के डेटा का उपयोग किया गया है, जो Q1:2021 से Q2:2024 तक की अवधि को कवर करता है, जिसमें कुल 322 अवलोकनों का नमूना आकार है। सबसे पहले, प्रत्येक राज्य के लिए नीतिगत प्रोत्साहनों के लिए एक EV नीति संकेतक चर बनाया गया था, जो नीति लागू होने के बाद की अवधि के लिए 1 का मान लेता है और अन्यथा 0। बाइनरी-स्तरीय नीति संकेतक नीतिगत साधनों के विविध सेट पर जानकारी को समाहित करता है, जिसमें मांग प्रोत्साहन, चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास, अनुसंधान एवं विकास, और संबंधित पहलू शामिल हैं जो एक राज्य में समग्र EV नीति के प्रभाव को दर्शाते हैं। नीति कार्यान्वयन और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के संयुक्त प्रभाव का पता लगाने के लिए, राज्यों को EV चार्जिंग इंडेक्स के आधार पर रैंक किया गया है

[9] https://egazette.gov.in/(S(vtvytkdyvv1cxyitlmdwjjih))/ViewPDF.aspx

चार्ट 8: अखिल भारतीय 2W-EV अपनाने का अनुपात

(प्रतिशत, बाएँ और दाएँ पैमाने पर)

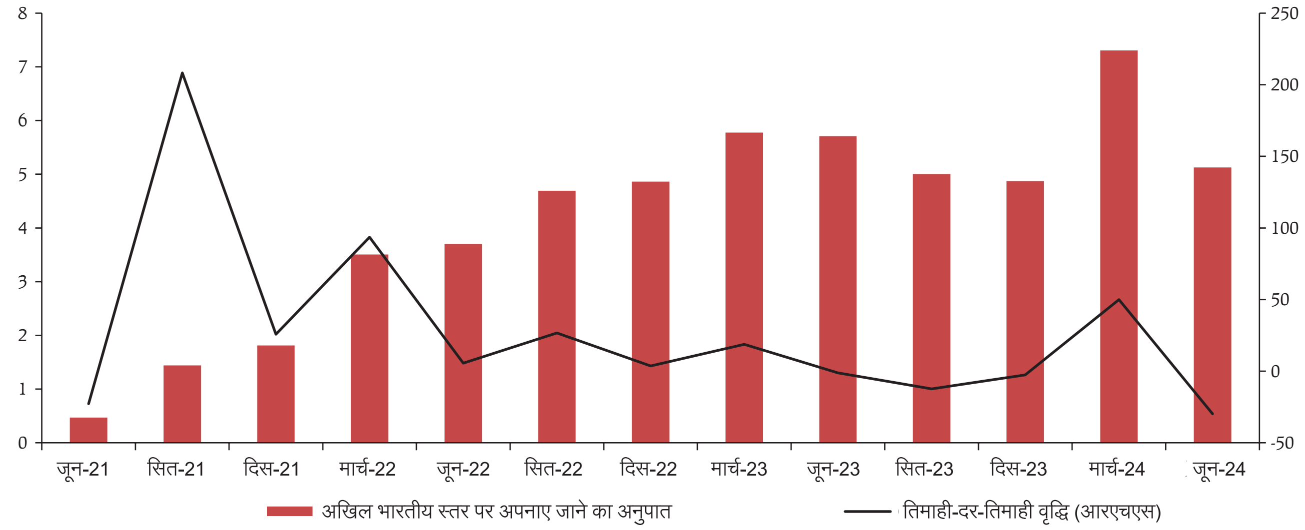

स्रोत: वाहन पोर्टल; और लेखकों की गणना।

हम एक पैनल प्रतिगमन मॉडल का उपयोग करते हैं, जिसमें दत्तक ग्रहण अनुपात (एआर) आश्रित चर के रूप में होता है, जिसे बाइनरी-प्रकार नीति सूचक चर द्वारा समझाया जाता है।

$$AR_{it} = \beta_1 \text{ Policy.Indicator}_{it} + \alpha_i + \epsilon_{it} \quad (1)$$

- β_1 नीति संकेतक के प्रभाव को अपनाने के अनुपात पर मापता है।
- α_i अपनाए जाने के अनुपात पर राज्य-विशिष्ट निश्चित प्रभावों को दर्शाता है।

अगले विनिर्देश में, नीति-घटना प्रभाव को अग्रणी राज्यों तक सीमित रखने के लिए एक डमी चर (rr) का उपयोग किया गया है, जिसमें ईवी चार्जिंग स्टेशनों की सबसे अधिक सांद्रता वाले शीर्ष सात या 12 राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रतिगमन मॉडल को औपचारिक रूप से इस प्रकार व्यक्त किया जाता है:

$$AR_{it} = \beta_1 \text{ Policy.Indicator}_{it} + \beta_2 \, rr_{it} + \beta_3 (\text{Policy.Indicator}_{it} \times rr_i) + \alpha_i + \epsilon_{it} \quad (2)$$

- β_1 , rr और राज्य-विशिष्ट प्रभावों को स्थिर रखते हुए, अपनाने के अनुपात पर नीति संकेतक के प्रभाव को मापता है।
- β_2 नीति सूचक और राज्य-विशिष्ट प्रभावों को स्थिर रखते हुए, अपनाने के अनुपात पर rr के प्रभाव को मापता है।
- β_3 नीति सूचक और rr के बीच परस्पर क्रिया के कारण अपनाने के अनुपात पर अतिरिक्त प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है।
- α_i अपनाए जाने के अनुपात पर राज्य-विशिष्ट निश्चित प्रभावों को दर्शाता है।

राज्यों द्वारा शुरू किए गए मांग-आधारित प्रोत्साहनों का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन स्वामित्व की कुल लागत को कम करना है, जिससे दोपहिया वाहन संभावित खरीदारों के लिए अधिक किफायती हो सकें। इसके लाभों में मध्यम प्रोत्साहन, जैसे पंजीकरण शुल्क में छूट और कर छूट, से लेकर अधिक आक्रामक प्रोत्साहन शामिल हैं, जिनमें छूट के अलावा सब्सिडी भी शामिल है। मांग-समर्थक नीतिगत प्रोत्साहनों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: मध्यम और आक्रामक। 'आक्रामक' के रूप में वर्गीकृत नीति सूचक का मान 1 होता है जब राज्य सरकार कर/पंजीकरण शुल्क में छूट के साथ सब्सिडी प्रदान करती है, अन्यथा 0 होता है। 'मध्यम' नीति सूचक का मान 1 होता है यदि केवल कर/पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाती है,

बिना किसी अतिरिक्त सब्सिडी के, और अन्यथा 0 होता है। इस मॉडल को औपचारिक रूप से इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

$$AR_{it} = \beta_1 \cdot policy_agg_{it} + \beta_2 \cdot policy_mod_{it} + \alpha_i + \epsilon_{it} \quad (3)$$

- $AR_{यह}$ समय *t पर एक व्यक्तिगत राज्य i* के लिए गोद लेने का अनुपात है ।
- β_1 और β_2 क्रमशः आक्रामक नीति और मध्यम नीति संकेतकों से जुड़े गुणांक हैं।
- α_i अपनाए जाने के अनुपात पर राज्य-विशिष्ट निश्चित प्रभावों को दर्शाता है।

इसके साथ ही, अगला मॉडल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक डमी वेरिएबल (rr) को शामिल करता है, जो यह दर्शाता है कि कोई राज्य ईवी चार्जिंग इंडेक्स के आधार पर शीर्ष सात में है या बारह में। यह मॉडल यह निर्धारित करने का प्रयास करता है कि प्रोत्साहनों की ये दो श्रेणियाँ—मध्यम और आक्रामक—दोपहिया-पहिया वाहनों को अपनाने पर कैसे प्रभाव डालती हैं। इस मॉडल को औपचारिक रूप से इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

$$AR_{it} = \beta_1 \cdot policy_agg_{it} + \beta_2 \cdot rr_i + \beta_3 \cdot (policy_agg_{it} \times rr_i) + \beta_4 \cdot policy_mod_{it} + \beta_5 \cdot (policy_mod_{it} \times rr_i) + \alpha_i + \epsilon_{it} \quad (4)$$

- β_1 और β_4 क्रमशः आक्रामक नीति और मध्यम नीति संकेतकों से जुड़े गुणांक हैं।
- β_2 अन्य प्रभावों को स्थिर रखते हुए, अपनाने के अनुपात पर rr के प्रभाव को मापता है।
- β_3 और β_5 क्रमशः आरआर और आक्रामक और मध्यम नीति के बीच बातचीत के कारण अपनाए जाने के अनुपात पर अतिरिक्त प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- आरआरआई एक अग्रणी राज्य आई के लिए डमी चर है, जिसके पास एक मजबूत ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचा है।
- α_i अपनाए जाने के अनुपात पर राज्य-विशिष्ट निश्चित प्रभावों को दर्शाता है।

V. परिणाम और चर्चा

मॉडल (1 और 2) के परिणाम सारणी 4 में प्रस्तुत किए गए हैं । नीति सूचक चर, अपनाने के अनुपात पर सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव दर्शाता है, जो नीति कार्यान्वयन और 2W-EV अपनाने के बीच एक सकारात्मक संबंध का संकेत देता है। बेहतर EV चार्जिंग अवसंरचना वाले राज्यों में समय पर नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रभाव को और समझने के लिए, दो पैनल प्रतिगमन मॉडल का उपयोग किया गया है। पहले मॉडल में, चार्जिंग अवसंरचना के लिए एक डमी चर (rr) का उपयोग सर्वोत्तम चार्जिंग अवसंरचना वाले शीर्ष सात राज्यों (मॉडल 2a) को दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरे मॉडल में, विश्लेषण को शीर्ष 12 राज्यों (मॉडल 2b) को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। ये दोनों विनिर्देश अवसंरचना विकास के विभिन्न स्तरों पर नीतिगत प्रभाव के तुलनात्मक मूल्यांकन की अनुमति देते हैं। इन विनिर्देशों में, बेहतर विकसित चार्जिंग अवसंरचना वाले क्षेत्रों के लिए नीति सूचक और डमी चर के बीच परस्पर क्रिया पद दर्शाता है कि चार्जिंग अवसंरचना, राज्य स्थानीयकृत नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ, 2W-EV अपनाने पर गुणक प्रभाव डालती है, जैसा कि दोनों मॉडलों में परस्पर क्रिया पद के उच्च गुणांक द्वारा प्रमाणित है, हालाँकि कम महत्व स्तरों पर।

चूंकि विभिन्न राज्य संभावित ईवी खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग मांग प्रोत्साहन प्रदान करते हैं,

सारणी 4: पैनल प्रतिगमन परिणाम

आश्रित चर: दत्तक ग्रहण अनुपात (23 राज्य)
अवधि (मार्च 2021- जून 2024) नमूना आकार = 322

व्याख्यात्मक चर	मॉडल 1	मॉडल 2a (शीर्ष 7 राज्य)	मॉडल 2b (शीर्ष 12 राज्य)
नीति संकेतक	3.1** (0.85)	1.80*** (0.47)	1.53* (0.61)
नीति संकेतक *rr		4.06^ (2.24)	2.72^ (1.49)

टिप्पणियाँ: 1. ^, *, ** और *** क्रमशः 10, 5, 1 और 0.1 प्रतिशत स्तर पर महत्व दर्शाते हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राज्य स्तर पर समूहीकृत मानक त्रुटियाँ हैं।

सारणी 5: पैनल प्रतिगमन परिणाम

आश्रित चर: दत्तक ग्रहण अनुपात (23 राज्य)
अवधि (मार्च 2021- जून 2024) नमूना आकार = 322

व्याख्यात्मक चर	मॉडल 3	मॉडल 4a (शीर्ष 7 राज्य)	मॉडल 4बी (शीर्ष 12 राज्य)
नीति आक्रामक	3.25** (0.98)	1.88*** (0.512)	1.61* (0.72)
नीति उदारवादी	2.03** (0.65)	1.02*** (0.00)	1.02*** (0.00)
नीति आक्रामक *rr		4.96^ (2.82)	2.84^ (1.72)
नीति उदारवादी *rr		1.86*** (0.00)	1.86*** (0.00)

टिप्पणियाँ: 1. ^, *, ** और *** क्रमशः 10, 5, 1 और 0.1 प्रतिशत स्तर पर महत्व दर्शाते हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े राज्य स्तर पर समूहीकृत मानक त्रुटियाँ हैं।

इसलिए इन प्रोत्साहनों को मध्यम या आक्रामक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि ऊपर वर्णित है। संबंधित मॉडल विनिर्देशों (3) और (4) के परिणाम सारणी 5 में प्रस्तुत किए गए हैं । अनुभवजन्य परिणाम दर्शाते हैं कि प्रत्यक्ष मौद्रिक सब्सिडी, 2W-EV बिक्री पर कर और पंजीकरण शुल्क माफी के साथ मिलकर, 2W-EV को अपनाने को काफी बढ़ावा देती है। कम गुणांक मूल्य वाली मध्यम प्रोत्साहन रणनीति मजबूत प्रोत्साहन रणनीति (मॉडल 3) के महत्व को रेखांकित करती है। हालांकि, मध्यम नीति और चार्जिंग बुनियादी ढांचे (आरआर) के बीच बातचीत का गुणांक महत्वपूर्ण है, जो बताता है कि मजबूत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के साथ मध्यम नीति भी 2W-EV (मॉडल 4 ए और बी) को अपनाने को बढ़ावा दे सकती है।

VI. निष्कर्ष

भारत में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2W-EV को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2W-EV को अपनाने की दिशा तय करने में राज्य-स्तरीय नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। निष्कर्ष इस बात पर ज़ोर देते हैं कि वित्तीय प्रोत्साहन, कर छूट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जैसे नीतिगत उपाय, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, खासकर जब इन्हें भारतीय बाज़ार की मूल्य-संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो।

विश्लेषण से अपनाने की दरों में स्पष्ट क्षेत्रीय असमानता का पता चलता है, दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में मज़बूत बुनियादी ढाँचे और ईवी नीतियों के शीघ्र निर्माण के कारण, ईवी अपनाने की दर में तेज़ी देखी गई है। ईवी 30@30 (भारत सरकार, 2024) लक्ष्य को प्राप्त करने और विकास को बनाए रखने के लिए, बुनियादी ढाँचे में निरंतर निवेश और चरणबद्ध नीतिगत दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण से, हमारे परिणाम बताते हैं कि मज़बूत चार्जिंग बुनियादी ढाँचे के साथ मध्यम नीतिगत समर्थन भी ईवी अपनाने को बढ़ावा दे सकता है।

संदर्भ

Bureau of Energy Efficiency. *Central Government Initiatives.* https://evyatra.beeindia.gov.in/central-govt-initiatives/

Chakraborty, R., and Chakravarty, S. (2023). Factors affecting acceptance of electric two-wheelers in India: a discrete choice survey. *Transport policy*, 132, 27-41.

Climate Trends. (2023). *Analysis of State Electric Vehicle Policies and their Impact.*

GoI. (2024). Electric Vehicles. Retrieved from https://www.psa.gov.in/mission/electric-vehicles/36

Hall, D., and Lutsey, N. (2017). Emerging best practices for electric vehicle charging infrastructure. The International Council on Clean Transportation (ICCT): Washington, DC, USA, 54.

International Energy Agency (IEA). (2021). *Global EV outlook.*

International Energy Agency (IEA). (2023). *Global EV outlook.*

International Energy Agency (IEA). (2024). *Global EV outlook.*

International Energy Agency (IEA). (2025). *Global EV outlook.*

Jenn, A., Springel, K., and Gopal, A. R. (2018). Effectiveness of electric vehicle incentives in the United States. *Energy policy*, 119, 349-356.

JMK Research & Analysis. (2022). *Accelerating Transport Electrification in India by 2030.*

Lévay, P. Z., Drossinos, Y., and Thiel, C. (2017). The effect of fiscal incentives on market penetration of electric vehicles: A pairwise comparison of total cost of ownership. *Energy policy*, 105, 524-533.

Li, S., Tong, L., Xing, J., and Zhou, Y. (2017). The market for electric vehicles: indirect network effects and policy design. *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*, 4(1), 89-133.

Mersky, A. C., Sprei, F., Samaras, C., and Qian, Z. S. (2016). Effectiveness of incentives on electric vehicle adoption in Norway. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 46, 56-68.

Münzel, C., Plötz, P., Sprei, F., and Gnann, T. (2019). How large is the effect of financial incentives on electric vehicle sales? A global review and European analysis. *Energy Economics*, 84, 104493.

Narassimhan, E., and Johnson, C. (2018). The role of demand-side incentives and charging infrastructure on plug-in electric vehicle adoption: analysis of US States. *Environmental Research Letters*, 13(7), 074032.

Nigam, N., Samanta, D., and Senapati, S. (2024). Determinants of electric vehicle adoption: insights from Indian states. *International Journal of Social Economics.*

NITI Aayog. (2018). *Zero emission vehicles (ZEVs): Towards a policy framework.*

PIB. (2024). PM E-DRIVE Scheme: Driving Towards a Greener Future.

Rajya Sabha. (2023). *Promotion of Electric Vehicles in the Country.* Department-Related Parliamentary Standing Committee on Industry.

Saw, K., and Kedia, A. (2023). Estimating the adoption of electric vehicles: A case study of four Indian states. *Competition and Regulation in Network Industries*, 24(2-3), 120-135.

Sierzchula, W., Bakker, S., Maat, K., and Van Wee, B. (2014). The influence of financial incentives and other socio-economic factors on electric vehicle adoption. *Energy policy*, 68, 183-194.

Srivastava, A., Kumar, R. R., Chakraborty, A., Mateen, A., and Narayanamurthy, G. (2022). Design and selection of government policies for electric vehicles adoption: A global perspective. Transportation Research Part E: *Logistics and Transportation Review*, 161, 102726.

Wee, S., Coffman, M., and La Croix, S. (2018). Do electric vehicle incentives matter? Evidence from the 50 US states. *Research Policy*, 47(9), 1601-1610.

अनुलग्नक 1

क्षेत्र	कुल सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन	सड़क की लंबाई (किलोमीटर में)	ईवी चार्जिंग इंडेक्स	श्रेणी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1941	16170	12.00	1
कर्णाटक	5765	358300	1.61	2
हरयाणा	708	50292	1.41	3
गोवा	137	18697	0.73	4
महाराष्ट्र	3728	636887	0.59	5
तमिलनाडु	1413	271137	0.52	6
चंडीगढ़	13	2573	0.51	7
केरल	1212	259932	0.47	8
उतार प्रदेश।	1989	442907	0.45	9
पंजाब	593	147862	0.40	10
गुजरात	992	249373	0.40	11
राजस्थान	1129	313469	0.36	12
आंध्र प्रदेश	601	176351	0.34	13
झारखंड	256	81245	0.32	14
पश्चिम बंगाल	763	283865	0.27	15
छत्तीसगढ	271	105074	0.26	16
उत्तराखंड	177	68727	0.26	17
मध्य प्रदेश	903	365045	0.25	18
ओडिशा	488	305631	0.16	19
हिमाचल प्रदेश	106	73230	0.14	20
बिहार	345	298205	0.12	21
त्रिपुरा	50	45120	0.11	22
असम	276	399122	0.07	23

स्रोत: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय; बीईई और लेखक की गणना।

अनुलग्नक 2

क्षेत्र	सब्सिडी	कर/पंजीकरण शुल्क छूट	मौद्रिक लाभ रेटिंग
गोवा	P	P	2
दिल्ली	P	P	2
कर्णाटक	O	P	1
केरल	O	P	1
महाराष्ट्र	P	P	2
तमिलनाडु	O	P	1
उतार प्रदेश।	P	P	2
आंध्र प्रदेश	O	P	1
राजस्थान	P	P	2
ओडिशा	P	P	2
मध्य प्रदेश	O	P	1
गुजरात	P	P	2
छत्तीसगढ	P	P	2
असम	P	P	2
हरयाणा	P	P	2
हिमाचल प्रदेश	O	P	1
झारखंड	P	P	2
त्रिपुरा	P	P	2
पश्चिम बंगाल	P	P	2
पंजाब	P	P	2
उत्तराखंड	P	P	2
चंडीगढ़	P	P	2
बिहार	P	P	2

टिप्पणियाँ: 1. P का अर्थ है वर्तमान और O का अर्थ है अनुपस्थिता।
2. 1 रेटिंग मध्यम दृष्टिकोण को दर्शाती है जबकि 2 आक्रामक दृष्टिकोण को दर्शाती है।

स्रोत: बीईई, क्लाइमेट ट्रेंड्स और लेखक का संकलन।

बागवानी विविधीकरण: कृषि सुदृढ़ता की ओर एक मार्ग

शिवम द्वारा ^

यह आलेख वर्ष 1992-93 से 2022-23 तक कृषि विकास के विश्लेषण की जांच करता है। यह विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि उपज में निरंतर सुधार, उच्च फसल सघनता और विविधीकरण की ओर स्पष्ट रुझान - विशेषकर बागवानी में - कृषि विकास के प्रमुख प्रेरक रहे हैं। उत्साहवर्धक रूप से, लघु और सीमांत कृषकों को भी इन रुझानों से लाभ हुआ है। सरकारी मध्यक्षेपों ने उपज में उतार-चढ़ाव, सीमित भंडारण अवसंरचना एवं बागवानी उत्पादन में मूल्य अस्थिरता जैसी चुनौतियों का समाधान करने के प्रयास किए हैं।

परिचय

आय के पिरामिड के निचले स्तर तक आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए एक जीवंत कृषि क्षेत्र अपरिहार्य बना हुआ है, क्योंकि भारत का 46.1 प्रतिशत कार्यबल कृषि क्षेत्र में संलग्न है (पीएलएफएस, 2023-24)। हालाँकि योजित सकल मूल्य (जीवीए) में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी में क्रमिक गिरावट[1] देखी गई है, फिर भी समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है (काकवानी, 1993; रैवेलियन और दत्त, 1996; थोरबेके और जंग, 1994; सोलोगा, 2006)। इस संदर्भ में, कृषि विकास के पिछले रुझानों का व्यवस्थित विश्लेषण, नीतिगत प्राथमिकताओं और रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों को दिशा देने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

यह अध्ययन पिछले तीन दशकों (1992-93 से 2022-23) के दौरान कृषि विकास का विश्लेषण करता है और इसे चार प्रमुख घटकों में विभाजित करता है: क्षेत्र विस्तार, उपज (या प्रौद्योगिकी) सुधार, मूल्य के प्रभाव और फसल विविधीकरण। एक व्यापक समझ सुनिश्चित करने के लिए, अध्ययन आठ प्रमुख फसलों - चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज, फल और सब्जियां, तिलहन, गन्ना और तंबाकू पर केंद्रित है, जो सामूहिक रूप से कुल फसल क्षेत्र का 80 प्रतिशत और उत्पादन के सकल मूल्य (जीवीओ) का 75 प्रतिशत हिस्सा हैं।[2] इस निष्कर्ष से स्पष्ट हुआ कि उपज में सुधार और विविधीकरण, विशेष रूप से बागवानी के क्षेत्र में, कृषि विकास के प्राथमिक साधन के रूप में उभरे हैं, जबकि बढ़ी हुई फसल सघनता[3] ने भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाई है।

ये परिणाम मौजूदा साहित्य (बिरथल एवं अन्य, 2008; शर्मा, 2023) से पूरी तरह मेल खाते हैं, जो फसल विविधीकरण के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करते हैं। इस बदलाव से न केवल कृषि आय में वृद्धि होती है, बल्कि यह जोखिम न्यूनीकरण और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में भी कार्य करता है (क्विरोज़ और वाल्डेस, 1995)। उच्च मूल्य वाली फसलों, विशेष रूप से फलों और सब्जियों की बढ़ती खेती - कृषि आय को बढ़ाने, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की सुदृढ़ता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है (थापा एवं अन्य, 2017; अनुजा एवं अन्य, 2020)।

विविधीकरण, मांग और आपूर्ति-पक्ष के कारकों के संगम से प्रेरित है। मांग के क्षेत्र में, बढ़ती आय, बढ़ता शहरीकरण और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएँ - पारंपरिक अनाजों से हटकर

^ लेखक भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। लेखक कोवुरी आकाश यादव, ऋषभ कुमार और आशीष खोब्रागडे को उनके मार्गदर्शन तथा एक अनाम रेफरी को उनकी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आलेख में व्यक्त विचार स्वयं लेखक के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

[1] यह गिरावट कृषि जीवीए में कमी के कारण नहीं, बल्कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र जीवीए में तेज़ी से वृद्धि के कारण है (http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/winter_session_2023/Loksabha-Contribution%20of%20Agriculture%20in%20GDP.pdf)।

[2] चावल, मोटे अनाज, दलहन, फलों और सब्जियों, तिलहन और गन्ने का कुल फसल क्षेत्र वर्ष 2024-25 तक उपलब्ध था, जबकि गेहूँ और तंबाकू का कुल फसल क्षेत्र 2023-24 तक उपलब्ध था। कुल सकल फसली क्षेत्र 2021-22 तक उपलब्ध था। उत्पादन के सकल मूल्य के लिए नवीनतम उपलब्ध आँकड़े 2022-23 तक उपलब्ध हैं, इसलिए विश्लेषण 2022-23 तक किया गया है।

[3] फसल सघनता उस सीमा को दर्शाती है जिस तक कृषि योग्य भूमि एक निर्धारित कृषि वर्ष में फसल उत्पादन में संलग्न होती है। यह उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के उपयोग की सीमा के संकेतक के रूप में कार्य करती है, जो किसी निश्चित अवधि के भीतर कृषि कार्यों की गहनता को दर्शाता है।

फलों और सब्जियों की बढ़ती खपत की ओर आहार परिवर्तन को प्रेरित कर रही हैं (सिंघा एवं अन्य, 2014)। इस बदलाव की पुष्टि घरेलू खपत संबंधी व्यय सर्वेक्षणों से होती है, जो फलों की बढ़ती मांग के साथ-साथ अनाजों की घटती मांग का संकेत देते हैं। आपूर्ति पक्ष पर, कृषि जनगणना के आँकड़े दर्शाते हैं कि छोटे और सीमांत किसान, जो भारतीय कृषि[4] का प्रमुख हिस्सा हैं, अपनी श्रम-प्रधान कृषि पद्धतियों के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी भूमि का बड़ा हिस्सा बागवानी के लिए आबंटित कर रहे हैं।

इन उत्साहजनक रुझानों के बावजूद, अध्ययन तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी प्रकाश डालता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है: उपज में उतार-चढ़ाव, कटाई के बाद भंडारण की अपर्याप्त और असमान व्यवस्था, एवं कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता। ये कारक किसानों की आय में अस्थिरता उत्पन्न करते हैं और अक्सर छोटे किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों को पूर्णतया अपनाने से हतोत्साहित करते हैं।

इस संदर्भ में, यह अध्ययन चार महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करता है:

(i) पिछले तीन दशकों (1992-93 से 2022-23) में भारत में कृषि वृद्धि के प्राथमिक स्रोत क्या हैं?

(ii) कृषि के समग्र विकास में विभिन्न फसलों का क्या योगदान है?

(iii) छोटे किसानों पर ऐसी वृद्धि के क्या प्रभाव होंगे?

(iv) विविधीकरण द्वारा संचालित इस वृद्धि से क्या चुनौतियाँ और नीतिगत सरोकार उत्पन्न होते हैं?

इस आलेख के आगे के खंड इस प्रकार संरचित हैं: खंड II में डेटा और कार्य-पद्धति की रूपरेखा दी गई है, जबकि खंड III में अनुभवजन्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। खंड IV में बागवानी की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है एवं खंड V में निष्कर्षात्मक प्रेक्षण प्रस्तुत किए गए हैं।

II. डेटा स्रोत और कार्य-पद्धति

अध्ययन में वृद्धि अपघटन पद्धति का प्रयोग किया गया है, जो उपज और मूल्य अस्थिरता के विश्लेषण द्वारा पूरित है। मिनोट (2003) की वृद्धि अपघटन पद्धति, भौतिक कारकों - क्षेत्रफल, उपज और फसल पैटर्न - तथा बाजार से संबद्ध चरों, यथा वास्तविक कीमतों और फसल विविधीकरण को शामिल करके कृषि विकास स्रोतों की सूक्ष्म समझ को सुगम बनाती है। यह दृष्टिकोण समग्र कृषि विकास में क्षेत्र विस्तार, उपज में सुधार, मूल्य प्रभावों और फसल विविधीकरण के योगदान को अलग करने में सक्षम बनाता है। यद्यपि यह पद्धति एक मजबूत ढाँचा प्रदान करती है, लेकिन इसकी कमियों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, जिनमें घटकों के बीच परस्पर क्रिया प्रभावों का पता लगाने की सीमित क्षमता और इसकी लेखांकन-आधारित संरचना के कारण सांख्यिकीय अनुमान लगाने का अभाव शामिल है (शर्मा, 2023)। इसके अतिरिक्त, मिनोट (2003) द्वारा यह दर्शाया गया कि फसलों में एक समान लागत संरचना की धारणा हमेशा सही नहीं हो सकती है, जिससे संभावित रूप से एकत्रीकरण पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकता है।

वृद्धि अपघटन के अलावा, यह अध्ययन उपज और मूल्य अस्थिरता का आकलन करता है, यह देखते हुए कि अस्थिरता कृषि की एक अंतर्निहित विशेषता है, जो काफी सीमा तक मौसम संबंधी आघातों के प्रति इसकी संवेदनशीलता के कारण है। कृषि अस्थिरता का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आपूर्ति और मांग, दोनों की गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति पक्ष पर, बढ़ी हुई अनिश्चितता किसानों को नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने या आवश्यक निवेश करने से रोक सकती है। मांग पक्ष पर, मूल्य अस्थिरता उपभोग पैटर्न को बाधित कर सकती है तथा खाद्य सुरक्षा और बाजार स्थिरीकरण पर केंद्रित नीतिगत मध्यक्षेपों को आवश्यक बना सकती है (अंजुम और मधुलिका, 2018)। अस्थिरता को आमतौर पर कड्डी-डेला वैले इंडेक्स (सीडीवीआई), विचलन के सह-गुणांक (सीवी) और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट डिफ्रेंसेज जैसी विधियों का उपयोग करके मापा जाता है, जो एक समान परिणाम उत्पन्न करते हैं (हचेट-

[4] परिचालन जोतों का औसत आकार 1970-71 के 2.28 हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर हो गया है, जो छोटे भू-जोत वाले किसानों की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है (पीआईबी, 2020)।

बॉर्डन, 2011)। यह अध्ययन CDVI का उपयोग करता है, क्योंकि यह कीमतों (हचेट-बॉर्डन, 2011) और उपज (हेज़ेल, 1982) में अक्सर देखी जाने वाली अंतर्निहित रैखिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखने की क्षमता रखता है।

II.1 डेटा स्रोत

विश्लेषण में क्षेत्रफल, उत्पादन, उपज तथा कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार शर्तों के सूचकांक (टीओटी) (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त) और उत्पादन मूल्य (राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त) के वार्षिक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। मूल्य गतिशीलता का आकलन करने के लिए, जनवरी 2002 से जनवरी 2025 की अवधि के लिए मासिक मूल्य आंकड़े सीएमआईई [5] से प्राप्त किए गए हैं।

II.2 वृद्धि के स्रोतों के विश्लेषण पर कार्यपद्धति

यह अध्ययन मिनोट (2003) और जोशी एवं अन्य (2006) द्वारा विकसित विश्लेषण विधि का उपयोग करता है जो वृद्धि को क्षेत्रफल, मूल्य, उपज (या प्रौद्योगिकी) और विविधीकरण के आधार पर विभाजित करता है। वास्तविक मूल्य का अनुमान जीवीओ को उत्पादित मात्रा से विभाजित करके लगाया जाता है। इसके बाद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का उपयोग करके वास्तविक रूप में (2011-12 के मूल्य) मूल्य निर्धारित किए गए।

मान लीजिए A_i क्षेत्रफल को दर्शाता है, Y_i उपज या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उत्पादन है, और P_i फसल i के अंतर्गत उत्पादन की प्रति इकाई (वास्तविक) कीमत है। n फसलों से, सकल राजस्व R, को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है:

$$R = \sum_{i=1}^{n} A_i P_i Y_i \qquad \text{(I)}$$

मान लीजिए a_i, कुल फसली क्षेत्र में फसल i का हिस्सा है, अर्थात, $a_i = \mathbf{A}_i / \Sigma_i A_i$, समीकरण (I) को इस प्रकार पुनः लिखा जा सकता है:

$$R = (\sum_{i=1}^{n} a_i P_i Y_i)(\sum_{i=1}^{n} A_i) \qquad \text{(II)}$$

समीकरण (II) के दोनों पक्षों के व्युत्पन्न (डेरीवेटिव) को शामिल कर, हम पाते हैं:

$$dR = (\sum_{i=1}^{n} a_i P_i Y_i)\boldsymbol{d}(\sum_{i=1}^{n} A_i) + (\sum_{i=1}^{n} A_i)(\sum_{i=1}^{n} a_i P_i \boldsymbol{d}Y_i) + (\sum_{i=1}^{n} A_i)(\sum_{i=1}^{n} a_i Y_i \boldsymbol{d}P_i) + (\sum_{i=1}^{n} A_i)(\sum_{i=1}^{n} Y_i P_i \boldsymbol{d}a_i) \qquad \text{(III)}$$

समीकरण (III) को *dR* से विभाजित किया जाता है और फिर वृद्धि के लिए सापेक्ष योगदान प्राप्त करने के लिए इसका राजस्व की वृद्धि दर (g_R) से गुणा किया जाता है।

$$g_R = \left[\frac{g_R}{dR}\right]\{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i P_i Y_i\right)\boldsymbol{d}\left(\sum_{i=1}^{n} A_i\right) + \left(\sum_{i=1}^{n} A_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} a_i P_i \boldsymbol{d}Y_i\right) + \left(\sum_{i=1}^{n} A_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} a_i Y_i \boldsymbol{d}P_i\right) + \left(\sum_{i=1}^{n} A_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} Y_i P_i \boldsymbol{d}a_i\right)\}^{6} \qquad \text{(IV)}$$

समीकरण (IV) का दायाँ मान, वृद्धि के स्रोत को दर्शाता है। दायें मान का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा टर्म क्रमशः कुल फसल क्षेत्र (क्षेत्र प्रभाव), उपज में परिवर्तन (प्रौद्योगिकी/उपज प्रभाव), वास्तविक कीमतों में परिवर्तन (मूल्य प्रभाव) और भूमि उपयोग में परिवर्तन (विविधीकरण प्रभाव) के कारण जीवीओ में वृद्धि को दर्शाता है। चौथे टर्म का धनात्मक चिह्न, विविधीकरण और जीवीओ के बीच एक सकारात्मक संबंध दर्शाता है, जो संभवतः उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर संक्रमण को दर्शाता है।

कृषि विकास संबंधी नीतियों के निर्माण में इन संवृद्धि चालकों के सापेक्ष योगदान पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है। निवल बोए गए क्षेत्र में विस्तार द्वारा संचालित कृषि विकास का दीर्घावधि में धारणीय होना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि में और वृद्धि की संभावना सीमित है। इसके विपरीत,

[5] सीएमआईई अपने आँकड़े कृषि विपणन सूचना नेटवर्क (एगमार्कनेट) और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) से प्राप्त करता है। आँकड़े बाज़ारवार और किस्मवार कीमतों के लिए दैनिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं। विभिन्न किस्मों और बाजारों में समग्र कीमतों के अखिल भारतीय अनुमानों की गणना, संदर्भ अवधि के लिए सीएमआईई द्वारा एक सामान्य औसत के रूप में की जाती है।

[6] इस समीकरण में इंटरैक्टिव टर्म को अनदेखा किया गया है। इंटरैक्टिव टर्म्स दो या अधिक इनपुट में परिवर्तन के कारण आउटपुट में परिवर्तन को मापते हैं। इंटरैक्टिव टर्म्स आमतौर पर छोटे होते हैं और इसलिए इन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। हालाँकि, इंटरैक्टिव टर्म का संचयी प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है।

फसल सघनता में वृद्धि एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान कर सकती है, क्योंकि यह एक ही भूमि के एक वर्ष के भीतर कई उपयोगों को संभव बनाती है। बढ़ती कीमतों से उत्पन्न वृद्धि का श्रेय मूल्य निर्धारण तंत्र में बदलाव या परिवहन लागत में कमी को दिया जा सकता है; हालाँकि, इस तरह की मूल्य-प्रेरित वृद्धि के धारणीय होने की संभावना कम है। इसलिए, दीर्घकालिक एवं धारणीय कृषि वृद्धि प्राप्त करने के लिए फसल की पैदावार में सुधार और उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन में विविधता लाने पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है (बिरथल एवं अन्य, 2008)।

इस अध्ययन की विलक्षणता यह है कि इसमें निरपेक्ष योगदान के बजाय सापेक्ष योगदान का प्रयोग किया गया है। यह दृष्टिकोण मुख्यतः समग्र वृद्धि पर एकल घटकों के आनुपातिक प्रभाव को दर्शाने की क्षमता के कारण अपनाया गया है। उदाहरण के लिए, 1995-96 में कुल सकल जीवीओ पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा (अर्थात, $dR < 0$)। इस अवधि के दौरान, विविधीकरण (अर्थात, चौथे टर्म) का योगदान धनात्मक रहा। यदि निरपेक्ष योगदान पर विचार किया जाता, तो उस वर्ष विविधीकरण का योगदान ऋणात्मक प्रतीत होता। हालाँकि, सापेक्ष योगदान के ढाँचे के अंतर्गत, विविधीकरण का प्रभाव धनात्मक होता है, क्योंकि dR का ऋणात्मक चिह्न, जीवीओ में ऋणात्मक वृद्धि (अर्थात, $g_R < 0$) द्वारा संतुलित हो जाता है।

II.3 अस्थिरता सूचकांक

सीडीवीआई सूचकांक का उपयोग टाइम सीरीज डेटा की अस्थिरता का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह सीवी की तुलना में एक बढ़त प्रदान करता है क्योंकि यह डेटा में अंतर्निहित प्रवृत्ति को ध्यान में रखता है। सीडीवीआई एक सेमी-लॉग लीनियर ट्रेंड मॉडल से समायोजित R^2 को शामिल करके ऐसा करता है, जिससे एक निर्धारणात्मक प्रवृत्ति की उपस्थिति में परिवर्तनशीलता का एक अधिक विश्वसनीय माप उपलब्ध होता है (कड्डी और डेला वैले, 1978)।

$$\ln Y_i = \alpha + \beta t_i + \mu_i \quad \text{(V)}$$

यहाँ, Y_i उपज (किग्रा/हेक्टेयर) या मूल्य (₹/किग्रा) निर्दिष्ट करने वाला आश्रित चर है। इंटरसेप्ट टर्म को α द्वारा इंगित किया जाता है, जबकि स्लोप टर्म को β *द्वारा दर्शाया जाता है,* तथा t_i टाइम ट्रेंड है और μ_i एरर टर्म है।

सीडीवीआई, समीकरण (V) के समायोजित R^2 को सम्मिलित करता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

$$CV_t = CV \times \sqrt{(1-R^2_{Adjusted})} \quad \text{(VI)}$$

$$CV = \sigma / x$$

यहाँ CV_t , प्रवृत्ति के इर्द-गिर्द विचलन के सह-गुणांक को दर्शाता है। इसके विपरीत, CV, माध्य के आस-पास विचलन के सह-गुणांक को दर्शाता है, और $R^2_{Adjusted}$टाइम ट्रेंड रिग्रेशन से समायोजित डिटरमिनेशन गुणांक को दर्शाता है। σ_i मानक विचलन को मापता है और x माध्य को मापता है।

III . परिणाम और चर्चा

III.1 कृषि विकास की कहानी को समझना

सारणी 1 भारत के कृषि विकास के चालकों का विश्लेषण करती है, तथा उपज, विविधीकरण (दोनों सरकारी नीतियों से जुड़े हुए), क्षेत्र (फसल की तीव्रता द्वारा मूल्यांकित) और कीमतों (कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों के सूचकांक (टीओटी) द्वारा मापी गई) के योगदान को दर्शाती है। चूंकि किसान भुगतान की गई या प्राप्त की गई कीमत के बजाय सापेक्ष कीमतों पर प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए 1980 में एमएसपी में टीओटी को शामिल किया गया (देव और राव, 2015)। 100 से ऊपर का टीओटी अनुकूल परिस्थितियों को इंगित करता है, जबकि 100 से कम का मूल्य किसानों के लिए प्रतिकूल वातावरण का सुझाव देता है। औद्योगीकरण और शहरीकरण से कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के साथ, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का विस्तार करने में अंतर्निहित सीमाएं हैं ।

सारणी 1: फसल क्षेत्र के विकास में विभिन्न स्रोतों का योगदान

अवधि	क्षेत्र	कीमत	उपज	विविधता	इंटरैक्शन
1992-93 से 2001-02	0.01	-0.79	1.72	0.76	0.26
2002-03 से 2011-12	0.83	-0.09	1.68	1.13	0.37
2012-13 से 2022-23	0.76	0.49	1.63	0.21	0.17
1992-93 से 2022-23	0.54	-0.11	1.67	0.68	0.26

स्रोत: लेखक की गणना।

प्रारंभिक दशक (1992-93 से 2001-02) में उपज में सुधार (1.72 प्रतिशत) और विविधीकरण (0.76 प्रतिशत) ने अधिकांश वृद्धि (1.96 प्रतिशत) को बढ़ावा दिया। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में मामूली गिरावट (इस अवधि में 142.6 से 140.7 मिलियन हेक्टेयर तक) के बावजूद, फसल की तीव्रता सीमा-बद्ध रही (इस अवधि में 130.1 प्रतिशत से 134.3 प्रतिशत) (चार्ट 1.बी)। एक प्रतिकूल टीओटी ने संभवतः नकारात्मक मूल्य प्रभावों में योगदान दिया (चार्ट 1.ए)। उल्लेखनीय रूप से, "स्वर्ण क्रांति" ने बागवानी और मधुमक्खी पालन में महत्वपूर्ण लाभ को बढ़ावा दिया, जिससे समग्र कृषि उपज में मजबूती आई।

दूसरी अवधि में, उपज (1.68 प्रतिशत), विविधीकरण (1.13 प्रतिशत) और क्षेत्र विस्तार (0.83 प्रतिशत) 3.92 प्रतिशत की वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता थे। इस अवधि में फसल गहनता 131.8 प्रतिशत (2002-03) से बढ़कर 138.9 प्रतिशत (2011-12) हो गई (चार्ट 1.बी)।[7] इस अवधि के दौरान टीओटी में सुधार के संकेत दिखने लगे लेकिन यह गैर-कृषि क्षेत्र के पक्ष में रहा (चार्ट 1.ए)। टीओटी में यह आंशिक सुधार कृषि विकास में कीमतों के अपेक्षाकृत बेहतर, हालांकि अभी भी नकारात्मक, योगदान का कारण हो सकता है।

तीसरी अवधि में, सभी स्रोतों - क्षेत्रफल (0.76 प्रतिशत), कीमतें (0.49 प्रतिशत), उपज (1.63 प्रतिशत) और विविधीकरण (0.21 प्रतिशत) - ने 3.25 प्रतिशत की समग्र वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया। फसल सघनता में 2012-13 के 139.15 प्रतिशत से 2021-22 में 155.4 प्रतिशत तक उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

चार्ट 1: व्यापार की शर्तें और फसल सघनता

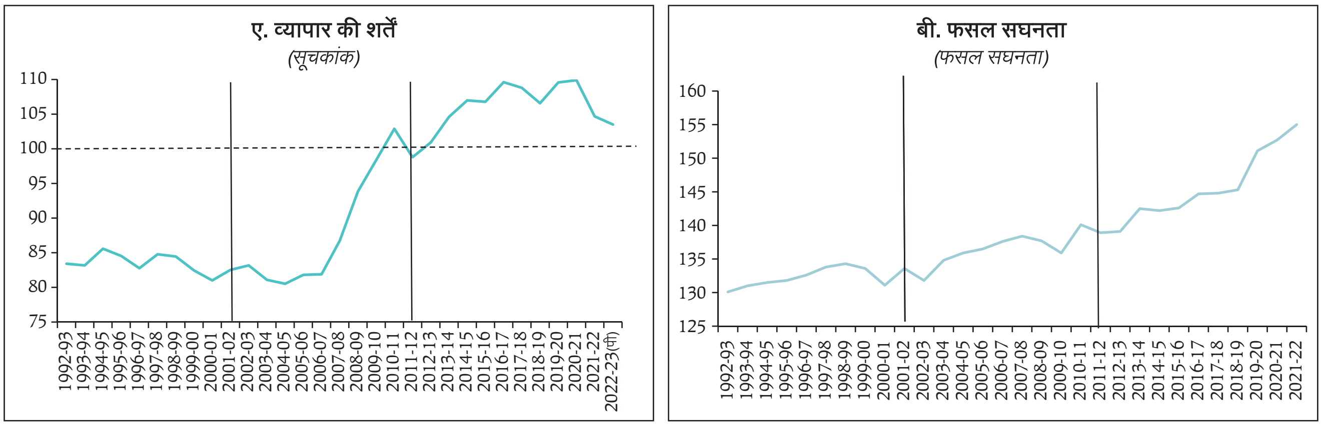

टिप्पणियाँ: 1. व्यापार शर्तों का सूचकांक दो आधार वर्षों, त्रैवार्षिक समाप्ति (TE) 1990-91 और 2011-12 में मौजूद था। TE 1990-91, 1982-83 से 2006-07 तक उपलब्ध था, जबकि TE 2011-12, 2004-05 से 2022-23 तक उपलब्ध था। आँकड़ों को TE 2011-12 में समान करने के लिए, TE 1990-91 के आँकड़ों को 0.80 (अर्थात, दो श्रृंखलाओं के बीच कॉमन फ़ैक्टर का औसत) के साथ जोड़ा गया था।
2. सूचकांक मान 100 से नीचे होने का अर्थ है कि व्यापार की शर्तें कृषि के लिए प्रतिकूल हैं, जबकि सूचकांक मान 100 से ऊपर होने का अर्थ है कि व्यापार की शर्तें कृषि के लिए अनुकूल हैं।
3. फसल सघनता कुल फसल क्षेत्र और शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के अनुपात को मापती है। फसल सघनता का मान जितना अधिक होगा, उत्पादन में उतना ही अधिक क्षेत्रफल उपयोग में लाया जाएगा।

स्रोत: कृषि सांख्यिकी: एक दृष्टि में, विभिन्न अंक; एवं लेखक की गणना।

[7] कुल फसल क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ, जो 2002-03 के 173.9 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2011-12 में 195.6 मिलियन हेक्टेयर हो गया, जबकि निवल बुवाई क्षेत्र में सामान्य वृद्धि हुई तथा इसी अवधि में वह 132 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 140.8 मिलियन हेक्टेयर हो गया।

इस अवधि के दौरान, कृषि उत्पादकता (टीओटी) अनुकूल रही, जो कृषि विकास में कीमतों के सकारात्मक योगदान की व्याख्या कर सकती है।

विचाराधीन अवधि (1992-93 से 2022-23) के दौरान, कृषि विकास के प्राथमिक चालक उपज में सुधार (1.67 प्रतिशत) और विविधीकरण (0.68 प्रतिशत) थे, इसके बाद क्षेत्र विस्तार (0.54 प्रतिशत) था। उपज में वृद्धि संभवतः आर्थिक सुधारों, उच्च उपज वाले बीजों, सिंचाई पर ध्यान, मशीनीकरण और उर्वरक सब्सिडी (जोशी, गुलाटी और बिरथल, 2007) से उपजी है। विश्लेषण तीन दशक की अवधि में सभी चयनित फसलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि का भी संकेत देता है। विविधीकरण कई कारकों से प्रेरित प्रतीत होता है, जिसमें उच्च आय समूहों के बीच आहार संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव, नीतिगत पहल जैसे कि एक समर्पित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना, और उपभोग पैटर्न में बदलाव शामिल हैं - निम्न आय वर्ग में भी बुनियादी स्टेपल से उच्च मूल्य वाली कृषि फसल की ओर (जोशी, गुलाटी और बिरथल, 2007)।

राज्य स्तर पर कृषि विकास के स्रोतों की पहचान के लिए इसी तरह का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया था। हालाँकि, विचाराधीन अवधि के लिए राज्य स्तर पर थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) के आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण, अध्ययन को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। यह अध्ययन मुख्य रूप से पैदावार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बागवानी में विविधीकरण की जाँच करता है, क्योंकि पैदावार का योगदान सर्वविदित है (शर्मा, 2023; कुमार, 2022)।

III.2 बागवानी: कृषि विकास में उज्ज्वल स्थान

यद्यपि बागवानी में फल और सब्ज़ियाँ, बागानी फसलें, फूल, सुगंधित और औषधीय पौधे, साथ ही मसाले और मसालों जैसी विविध फसलें शामिल हैं, फिर भी आँकड़ों की कमी के कारण, यह अध्ययन फलों और सब्ज़ियों (एफ़ एंड वी) पर केंद्रित है। सारणी 2 समीक्षाधीन सभी तीन दशकों में उनकी लगातार उच्च वृद्धि दर पर प्रकाश डालती है, जो कृषि प्रदर्शन को गति देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। 2022-23 में, एफ़ एंड वी ने सकल फसल क्षेत्र के मामूली 5.77 प्रतिशत पर कब्जा किया, लेकिन जीवीओ में 28.19 प्रतिशत का प्रभावशाली योगदान दिया।

सारणी 2: कृषि में फसलवार योगदान

फसल	जीसीए में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	जीवीओ में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	उत्पादन के मूल्य में वार्षिक वृद्धि			उत्पादन वृद्धि में सापेक्ष योगदान		
	2021-22	2022-23	1992-93 से 2001-02	2002-03 से 2011-12	2012-13 से 2022-23	1992-93 से 2001-02	2002-03 से 2011-12	2012-13 से 2022-23
चावल	22.77	14.28	2.25	1.76	2.38	0.51	0.28	0.40
गेहूँ	15.88	8.90	2.93	2.83	1.48	0.41	0.36	0.16
मोटे अनाज	10.96	4.01	3.59	3.03	2.73	0.19	0.12	0.08
दलहन	13.64	5.17	2.27	3.11	4.84	0.13	0.16	0.35
तिलहन	14.65	9.22	1.45	5.66	2.94	0.18	0.55	0.22
गन्ना	2.96	5.03	5.46	1.11	0.53	0.43	0.05	0.13
फल एवं सब्जियाँ	5.77	28.19	5.86	4.33	3.84	1.45	1.33	1.30
तंबाकू	0.18	0.32	-0.76	3.82	-2.32	-0.01	0.02	-0.02
अन्य फसलें	13.19	24.88	-	-	-	-	-	-
सभी फसलें	100	100	3.31	2.96	2.41	3.29	2.88	2.61

टिप्पणियाँ: 1. उत्पादन के मूल्य में वार्षिक वृद्धि में सभी फसलों की वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है, भले ही उन आठ फसलों पर विचार किया गया हो, जबकि सभी फसलों की वृद्धि के भारित योगदान को केवल आठ फसलों में ही दर्शाया गया है।
2. वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान विचाराधीन अवधि में वार्षिक वृद्धि दर का औसत लेकर लगाया जाता है।
3. उत्पादन वृद्धि के सापेक्ष योगदान को विचाराधीन फसलों के जीवीओ के कुल मूल्य को लेकर मापा जाता है। फिर, प्रत्येक फसल के जीवीओ में परिवर्तन के औसत मूल्य को जीवीओ के कुल मूल्य से विभाजित किया जाता है।

स्रोत: कृषि सांख्यिकी: एक दृष्टि में, 2023; एवं लेखक की गणना।

सारणी 2 में , उत्पादन मूल्य में वार्षिक वृद्धि का अनुमान दो चरणों में लगाया गया है। पहले चरण में, प्रत्येक फसल के लिए वर्ष-दर-वर्ष (वर्ष -दर -वर्ष) वृद्धि दर की गणना की जाती है। दूसरे चरण में, प्रत्येक फसल की औसत वृद्धि दर की गणना संबंधित अवधियों, जैसे 1992-93 से 2001-02, के लिए की जाती है। इस दृष्टिकोण के आधार पर, विचाराधीन तीनों अवधियों में फल और सब्ज़ियाँ सबसे अधिक वृद्धि दर प्रदर्शित करती हैं। तम्बाकू को छोड़कर, अन्य सभी फसलें भी वृद्धि में सकारात्मक योगदान देती हैं।

सारणी 2 में आउटपुट वृद्धि के सापेक्ष योगदान का अनुमान तीन चरणों में लगाया गया है । पहले चरण में, समग्र जीवीओ की गणना की जाती है। दूसरे चरण में, प्रत्येक फसल के जीवीओ में परिवर्तन को पहले चरण में गणना की गई समग्र जीवीओ के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। अंतिम चरण में, आउटपुट वृद्धि में प्रत्येक फसल का औसत योगदान निर्धारित किया जाता है। 1992-93 से 2022-23 तक, एफ एंड वी उत्पादन का मजबूत विस्तार कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण टेलविंड रहा है, जिसने अन्य जगहों पर संभावित मंदी को संतुलित किया है। प्रारंभिक अवधि (1992-93 से 2001-02) में, एफ एंड वी ने कुल 3.29 प्रतिशत की वृद्धि में 1.45 प्रतिशत का पर्याप्त योगदान दिया। यह मज़बूत योगदान बाद की अवधियों में भी जारी रहा, जो 2.88 प्रतिशत वृद्धि (2002-03 से 2011-12) में 1.33 प्रतिशत और 2.61 प्रतिशत वृद्धि (2012-13 से 2022-23) में 1.30 प्रतिशत रहा। खाद्य एवं कृषि (एफ़ एंड वी) के योगदान के बिना, कृषि विकास की गति काफ़ी धीमी होती।

फल और सब्ज़ियों के मज़बूत प्रदर्शन के पीछे भारतीय आहार पैटर्न में एक क्रमिक लेकिन स्पष्ट बदलाव है (सारणी 3)। आँकड़े ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कुल खाद्य व्यय में फलों की बढ़ती हिस्सेदारी को दर्शाते हैं—2004-05 में 2 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 3.9 प्रतिशत। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों की खपत काफी हद तक स्थिर रही है, लेकिन शहरी केंद्रों में इसमें थोड़ी वृद्धि देखी गई है। इसके विपरीत, अनाज और दालों पर खर्च का अनुपात नीचे की ओर रहा है, जो उच्च मूल्य वाले खाद्य पदार्थों की ओर व्यापक विविधीकरण का संकेत देता है।

III.3 विभिन्न कृषि आकारों में फसल पैटर्न और बागवानी विविधीकरण

किसानों के फसल पैटर्न का विश्लेषण , विशेष रूप से बागवानी के लिए समर्पित भूमि का हिस्सा, यह आकलन करने के लिए आवश्यक है कि क्या छोटे किसान बागवानी-आधारित विकास से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। जैसा कि चंद (2017) ने उजागर किया, एक हेक्टेयर भूमि को मुख्य फसलों से उच्च मूल्य वाली फसलों में स्थानांतरित करने से सकल लाभ ₹1,01,608 तक बढ़ सकता है। उत्साहजनक रूप से, छोटे किसान पहले से ही अपने बड़े समकक्षों की तुलना में अपनी भूमि का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा बागवानी के लिए आवंटित करते हैं (सारणी 4)। 2015-16 में, छोटे किसानों ने अपने सकल फसल

सारणी 3: मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय

मद समूह	मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का अलग-अलग विवरण (प्रतिशत में)									
	2004-05		2009-10		2011-12		2022-23		2023-24	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
अनाज और अनाज के विकल्प	18	10	13.8	8.2	10.8	6.7	4.9	3.6	5	3.8
दलहन और उनके उत्पाद	3	2	3.3	2.5	2.9	2	2	1.4	2	1.4
सब्जियाँ	6	4	8.3	5.7	6.6	4.6	5.4	3.8	6	4.1
फल	2	2	2.4	3.2	2.8	3.4	3.7	3.8	3.9	3.9

स्रोत: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

[8] छोटे किसानों के पास 1-2 हेक्टेयर के बीच भू-जोत हैं जबकि मझौले किसानों के पास 4-10 हेक्टेयर के बीच भूमि है। बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर से बड़े भू-जोत हैं।

सारणी 4: छोटे बनाम बड़े खेतों पर फसल पैटर्न (कुल फसल क्षेत्र का प्रतिशत)

खेत का आकार	अनाज	दलहन	तिलहन	गन्ना	कपास	फल	सब्ज़ियाँ	एस एंड सी [9]	अन्य	कुल
1995-96										
छोटा	64.42	8.9	10.07	2.6	3.64	1.59	2.53	1.24	7.55	100
मध्यम	58.12	10.47	13.27	2.45	6.07	1.28	1.58	1.21	7.14	100
बड़ा	50.72	12.72	15.41	1.53	6.3	1.02	0.9	1.21	11.07	100
सभी	57.77	10.71	12.84	2.16	5.22	1.3	1.69	1.22	8.77	100
2015-16										
छोटा	62.28	8.90	11.19	2.68	5.50	1.76	3.03	1.29	3.37	100
मध्यम	52.64	11.92	15.57	2.69	7.68	1.69	1.97	1.66	4.18	100
बड़ा	49.16	12.90	14.68	1.79	6.00	1.42	1.71	1.91	10.43	100
सभी	56.31	10.74	13.20	2.43	6.16	1.65	2.41	1.55	5.56	100

स्रोत: कृषि जनगणना, विभिन्न अंक।

क्षेत्र का 6.08 प्रतिशत इन फसलों के लिए समर्पित किया, जबकि बड़े किसानों के लिए यह 5.04 प्रतिशत और मध्यम किसानों के लिए 5.32 प्रतिशत था।

सभी आकार के खेतों में कुल फसल क्षेत्र में बागवानी की बढ़ती हिस्सेदारी एक व्यापक विविधीकरण प्रवृत्ति का संकेत देती है। फलों, सब्जियों और मसालों की खेती में निरंतर वृद्धि, छोटे जोतों के बढ़ते आर्थिक महत्व और बढ़ती उपभोक्ता मांग, दोनों को दर्शाती है।

नज़दीक से देखने पर पता चलता है कि छोटे किसान सब्ज़ियों की खेती की ओर ज़्यादा झुकाव रखते हैं। ये फ़सलें जल्दी मुनाफ़ा देती हैं, कम पूँजी लगाती हैं, और ज़्यादा श्रम-प्रधान होती हैं, जो छोटे किसानों के संसाधनों के अनुकूल होती हैं। इसके विपरीत, बड़े किसान फलों और कुछ मसालों को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनमें आमतौर पर ज़्यादा शुरुआती निवेश की ज़रूरत होती है और पकने की अवधि भी ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए, आम के पेड़ों को फल लगने में 3-5 साल लगते हैं, जबकि प्याज़ की कटाई लगभग छह महीने में हो जाती है।

सारणी 5 एक आकर्षक प्रवृत्ति को दर्शाती है, जहाँ 1995-96 में, छोटे किसानों ने अपनी ज़मीन का सबसे बड़ा हिस्सा बागवानी के लिए समर्पित कर दिया था, और बड़े किसानों का स्थान दूसरे स्थान पर था। 2015-16 तक, यह बढ़त और भी बढ़ गई क्योंकि छोटे किसानों ने बागवानी के अपने दायरे का विस्तार जारी रखा। यह बढ़ता हुआ आवंटन इन उच्च-मूल्य वाली फसलों में विविधता लाने की उनकी मज़बूत क्षमता और इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

सारणी 4 और 5 से पता चलता है कि छोटे किसानों ने बागवानी, खासकर सब्ज़ियों की खेती में तेज़ी से विविधता लाई है, जिससे पता चलता है कि उन्हें इस बदलाव से फ़ायदा हुआ होगा। हालाँकि, इन सकारात्मक रुझानों के बावजूद, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनका विश्लेषण अगले भाग में किया गया है।

सारणी 5: खेत की श्रेणियों में बागवानी के अंतर्गत क्षेत्र का वितरण (प्रतिशत)

	कुल फसल क्षेत्र	फल	सब्ज़ियाँ	एस एंड सी
1995-96				
छोटा	38.6	47.2	57.6	39.1
मध्यम	23.9	23.4	22.4	23.7
बड़ा	37.5	29.4	20.0	37.2
सभी	100.0	100.0	100.0	100.0
2000-01				
छोटा	41.1	47.3	56.7	39.8
मध्यम	24.0	24.1	18.8	23.4
बड़ा	37.5	28.6	24.5	36.7
सभी	100.0	100.0	100.0	100.0
2015-16				
छोटा	48.3	51.6	60.7	40.2
मध्यम	23.4	23.9	19.2	24.9
बड़ा	28.3	24.4	20.1	34.9
सभी	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत: कृषि जनगणना, विभिन्न अंक।

[9] एस एंड सी, मसालों एवं स्वादवर्धक मसालों (कॉन्डिमेंट्स) को संदर्भित करता है, जो बागवानी में शामिल है।

IV. चुनौतियाँ और नीति फोकस [10]

बागवानी में जहाँ महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं, वहीं यह अध्ययन अब तीन प्रमुख चुनौतियों की ओर ध्यान केंद्रित करता है: उपज की अनिश्चितता, भंडारण की अपर्याप्त संरचना और कीमतों में उतार-चढ़ाव। अध्ययन में इन बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से सरकार की नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर भी चर्चा की गई है।

IV.1 उपज में उतार-चढ़ाव

बागवानी में एक महत्वपूर्ण चुनौती पैदावार में अंतर्निहित परिवर्तनशीलता है (अनुलग्नक सारणी 1)। फलों की पैदावार, विशेष रूप से, काफी उतार-चढ़ाव दिखाती है, जैसा कि 1992-93 और 2021-22 के बीच नींबू, मौसम्बी, संतरे, अंगूर, लीची, आम और चीकू जैसी फसलों में देखा गया है। उल्लेखनीय रूप से, इस अवधि में अंगूर और चीकू की पैदावार में गिरावट आई है, जो स्थिरीकरण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। जबकि सब्जी की पैदावार आम तौर पर ऊपर की ओर बढ़ी है (मटर और टैपिओका जैसे अपवादों के साथ), फल और सब्जी की पैदावार में समग्र वृद्धि काफी हद तक सब्जियों द्वारा संचालित होती है। इस उपज अस्थिरता के अंतर्निहित कारणों की गहन जांच की आवश्यकता है, जो इस अध्ययन के दायरे से बाहर है।

सारणी 6 , सीडीवीआई द्वारा प्रमाणित प्रमुख फल और सब्जियों की पैदावार में अस्थिरता को दर्शाती है। सब्जियों के लिए, 2002-03 और 2011-12 के बीच अस्थिरता में कमी आई (प्याज को छोड़कर)। हालाँकि, इस अवधि के दौरान फलों की पैदावार में अस्थिरता बढ़ी (केला, संतरे और पपीते को छोड़कर)। इसके बाद के दशक (2012-13 से 2021-22) में फलों की अस्थिरता में कमी देखी गई, जबकि सब्जियों में मिश्रित स्थिति देखी गई - बैंगन, टमाटर और टैपिओका के लिए अस्थिरता बढ़ी, लेकिन गोभी, मटर, प्याज और आलू के लिए अस्थिरता में कमी आई।

सारणी 6: प्रमुख फलों और सब्जियों की उपज में अस्थिरता

फसलें	1992-93 से 2001-02	2002-03 से 2011-12	2012-13 से 2021-22	1992-93 से 2021-22
सेब	0.08	0.15	0.12	0.14
केला	0.06	0.06	0.03	0.06
नींबू	0.06	0.17	0.05	0.12
मौसम्बी	0.13	0.21	0.07	0.23
संतरा	0.18	0.15	0.05	0.19
अंगूर	0.13	0.24	0.01	0.20
अमरूद	0.04	0.05	0.04	0.08
आम	0.05	0.10	0.06	0.15
पपीता	0.12	0.05	0.04	0.10
कुल फल	**0.06**	**0.06**	**0.05**	**0.10**
बैंगन	0.03	0.01	0.03	0.03
पत्ता गोभी	0.09	0.02	0.01	0.08
फूलगोभी	0.12	0.02	0.02	0.07
मटर	0.14	0.04	0.03	0.13
टमाटर	0.05	0.03	0.06	0.06
प्याज	0.06	0.10	0.06	0.10
आलू	0.08	0.07	0.05	0.07
टैपिओका	0.05	0.03	0.21	0.15
कुल सब्जियां	**0.04**	**0.02**	**0.02**	**0.03**

स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; एवं लेखक की गणना।

बागवानी में उपज में उतार-चढ़ाव को दूर करने के लिए, सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) शुरू किया है। इस व्यापक योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री [11] और टिशू कल्चर [12] इकाइयाँ प्रदान करने, खेती के क्षेत्रों का विस्तार करने और उन्नत बागवानी तकनीक को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। [13] इसके अतिरिक्त, 2021 में शुरू किए गए बागवानी क्लस्टर

[10] इस उपखंड में, अध्ययन अलग-अलग फसलों पर केंद्रित है। 2024-25 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, कुल फल उत्पादन (113.2 मिलियन मीट्रिक टन) में केला (37.7 मिलियन मीट्रिक टन), अमरूद (5.4 मिलियन मीट्रिक टन), आम (22.7 मिलियन मीट्रिक टन), पपीता (5.4 मिलियन मीट्रिक टन), अंगूर (4.1 मिलियन मीट्रिक टन), सेब (2.7 मिलियन मीट्रिक टन), नींबू (3.8 मिलियन मीट्रिक टन), मौसम्बी (3.9 मिलियन मीट्रिक टन) और संतरे (6.1 मिलियन मीट्रिक टन) ने 81 प्रतिशत का योगदान दिया। बैंगन (13 मिलियन मीट्रिक टन), पत्तागोभी (10.4 मिलियन मीट्रिक टन), फूलगोभी (9.9 मिलियन मीट्रिक टन), मटर (6.8 मिलियन मीट्रिक टन), टमाटर (21.5 मिलियन मीट्रिक टन), प्याज (28.9 मिलियन मीट्रिक टन), आलू (59.6 मिलियन मीट्रिक टन) और टैपिओका (6.3 मिलियन मीट्रिक टन) ने कुल सब्जी उत्पादन (214.5 मिलियन मीट्रिक टन) में 70 प्रतिशत का योगदान दिया। इस खंड में इन फसलों को शामिल किया गया है।

[11] गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री को 'बीज या वानस्पतिक विधियों द्वारा उगाई गई एक-समान, स्वस्थ, रोगमुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका समग्र लक्ष्य हितधारकों के लिए उपलब्ध पौधे की शारीरिक और पादप-स्वच्छता गुणवत्ता को बढ़ाकर उत्पादकता बढ़ाना है' (आईसीएआर-सीएएफआरआई, 2019)।

[12] ऊतक संवर्धन (टिश्यू कल्चर) विशेष रूप से तैयार पोषक माध्यमों पर पादप कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों का संवर्धन है। उपयुक्त परिस्थितियों में, एक एकल कोशिका (आईएसएएए) से एक संपूर्ण पौधे का पुनर्जनन किया जा सकता है।

[13] https://www.myscheme.gov.in/schemes/midh

विकास (एचसीडी) कार्यक्रम का उद्देश्य 55 चिन्हित क्लस्टरों में बाजार-संचालित विकास करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।[14] इसके साथ ही अनुसंधान और विकास पर ज़ोर दिया जा रहा है, जिसका प्रमाण समर्पित संस्थानों, अनुसंधान केंद्रों और निदेशालयों की बढ़ती संख्या है।

IV.2 फसल-उपरांत भंडारण क्षमता का अभाव

भारत फसल कटाई के बाद होने वाले भारी नुकसान से जूझ रहा है, जिसका अनुमान लगभग ₹1.5 ट्रिलियन प्रतिवर्ष है (गुलाटी एट अल., 2024), और अपर्याप्त शीत भंडारण के कारण फलों और सब्जियों को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है (नेगी और आनंद, 2017)। फसल कटाई के बाद होने वाले इन नुकसानों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक दोहरे दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शीत श्रृंखला अवसंरचना का विस्तार और कृषि वस्तुओं के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना शामिल है।

2022 तक, भारत की कोल्ड स्टोरेज क्षमता 38.2 मिलियन मीट्रिक टन (एमटी) थी, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संकेंद्रण को प्रदर्शित करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश (38.9 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (15.6 प्रतिशत), गुजरात (10.2 प्रतिशत) और पंजाब (6.4 प्रतिशत) का कुल 71 प्रतिशत हिस्सा है। चतुर्थक वितरण का उपयोग करते हुए चार्ट 2 इन क्षेत्रीय असमानताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आश्चर्यजनक रूप से, मौजूदा कोल्ड स्टोरेज का लगभग 75 प्रतिशत आलू के लिए समर्पित है, जो अन्य खराब होने वाली वस्तुओं के लिए सीमित क्षमता और भारतीय खपत में आलू की प्रमुखता दोनों को उजागर करता है (तिवारी, 2021)। इसके अलावा, उत्पादन केंद्रों के पास इन सुविधाओं का स्थान कुशल परिवहन नेटवर्क पर उनकी निर्भरता को रेखांकित करता है।

फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने और कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए, सरकार ने कई प्रमुख पहल शुरू की हैं। 2020 में स्थापित कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

चार्ट 2: राज्य-वार शीत भंडारण (कोल्ड स्टोरेज) क्षमता (हजार मीट्रिक टन में)

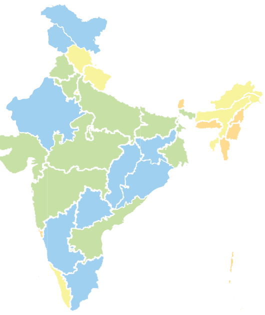

टिप्पणियाँ: 1. लद्दाख में शीत भंडारण की संख्या जम्मू-कश्मीर के समान ही मानी जाती है।
2. राज्यों का वर्गीकरण शीतगृहों की संख्या के आधार पर किया गया है। प्रथम क्वार्टाइल में शामिल राज्यों की भंडारण क्षमता 8.2 हज़ार मीट्रिक टन से कम है। द्वितीय क्वार्टाइल में भंडारण क्षमता 8.2 से 236.7 हज़ार मीट्रिक टन के बीच है। तृतीय और चतुर्थ क्वार्टाइल में क्रमशः 236.7 से 781.7 हजार मीट्रिक टन और 781.7 मीट्रिक टन से अधिक भंडारण क्षमता है।

स्रोत: भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी पुस्तिका, आरबीआई।

ने पहले ही 48,000 से अधिक भंडारण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिससे 94 मिलियन टन की क्षमता जुड़ गई है।[15] इस पहल को और मज़बूत करते हुए, केंद्रीय बजट 2025-26 में बागवानी निर्यात को समर्थन देने के लिए एक हवाई कार्गो सुविधा की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) और मेगा फ़ूड पार्क पहल जैसी पूरक योजनाओं का उद्देश्य प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग और मूल्यवर्धन में सुधार करना है। व्यापक दायरे के बावजूद, इन हस्तक्षेपों से बागवानी क्षेत्र को व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है।

IV.3 कीमतों में अस्थिरता[16]

कीमतें किसानों के लिए जीवन रेखा हैं, जो उनके उत्पादन और निवेश संबंधी निर्णयों को दिशा देती हैं। हालाँकि, कीमतों में उतार-चढ़ाव एक महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा करता है, जो फसल के चुनाव, इनपुट के उपयोग और तकनीक अपनाने को प्रभावित करता है, साथ ही कृषि मूल्य श्रृंखला में अनिश्चितता भी पैदा करता है (शर्मा एट अल., 2024)।

[14] https://nhb.gov.in/CDPMap.aspx

[15] https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=152061&ModuleId=3®=3&lang=1

[16] आँकड़ों की उपलब्धता को देखते हुए, इस उपखंड में विश्लेषण वर्ष 2002-03 से 2021-22 तक विस्तारित है, जिसमें चावल और गेहूँ को बागवानी फसलों के संदर्भ में तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है।

सारणी 7 प्रमुख फलों और सब्जियों की मूल्य अस्थिरता के दिलचस्प रुझानों को उजागर करती है। उल्लेखनीय है कि 2012-13 से 2022-23 के दौरान फलों की कीमतों में अस्थिरता पिछले दशक की तुलना में कम हुई है। इसके विपरीत, मटर और फूलगोभी को छोड़कर, इसी अवधि में सब्जियों की कीमतों में अस्थिरता आम तौर पर बढ़ गई।

चावल और गेहूँ की कीमतों में स्थिरता और वृद्धि, जैसा कि चार्ट 3 में दर्शाया गया है , एक आकर्षक विरोधाभास प्रस्तुत करती है। भारतीय खाद्य निगम (एफ़सीआई) का प्राथमिक खरीद केंद्र इन अनाजों पर केंद्रित है, इसलिए आश्वस्त खरीदार, कम कीमतों में उतार-चढ़ाव और बढ़ती कीमतों के रुझान के संयोजन से किसानों द्वारा अधिक अस्थिर फलों और सब्जियों की तुलना में इन फसलों को लगातार प्राथमिकता देने की संभावना बढ़ जाती है।

सारणी 7: प्रमुख फलों और सब्जियों की कीमतों में अस्थिरता

फसलें		2002-03 से 2011-12	2012-13 से 2022-23	2002-03 से 2022-23
अनाज	चावल	0.08	0.04	0.08
	गेहूँ	0.06	0.05	0.06
फल	केले	0.15	0.09	0.15
	अमरूद	0.16	0.05	0.1
	आम	0.09	0.06	0.07
	पपीता	0.11	0.05	0.08
	अंगूर	0.09	0.04	0.05
	सेब	0.13	0.10	0.14
	नींबू	0.26	0.13	0.19
	मौसम्बी	0.13	0.05	0.09
	संतरा	0.15	0.06	0.11
	तरबूज	0.09	0.04	0.07
सब्ज़ियाँ	बैंगन	0.05	0.06	0.08
	प्याज	0.18	0.28	0.27
	आलू	0.25	0.34	0.34
	टमाटर	0.07	0.16	0.16
	टैपिओका	0.14	0.16	0.18
	पत्ता गोभी	0.09	0.10	0.12
	फूलगोभी	0.06	0.05	0.09
	मटर	0.11	0.09	0.09

स्रोत: सीएमआईई एवं लेखक की गणना।

बागवानी में कीमतों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न चुनौतियों को समझते हुए, भारत सरकार ने 'ऑपरेशन ग्रीन्स' शुरू किया। शुरुआत में टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) पर केंद्रित इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को संकटग्रस्त बिक्री से बचाना और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना है। बाद में 2021-22 में इसका दायरा बढ़ाकर सभी फलों और सब्जियों को 'टोटल' के अंतर्गत शामिल कर दिया गया।

V. निष्कर्ष

पिछले तीन दशकों (1992-93 से 2022-23) में, कृषि विकास को उपज (या तकनीकी) सुधार, विविधीकरण और बढ़ी हुई फसल सघनता से महत्वपूर्ण रूप से गति मिली है। उल्लेखनीय रूप से, बागवानी की ओर रुझान विकास का एक प्रमुख इंजन रहा है, जिससे विशेष रूप से छोटे किसानों को लाभ हुआ है। हालाँकि, यह क्षेत्र अभी भी उपज और कीमतों में उतार-चढ़ाव से जूझ रहा है, जो अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज के कारण और भी बदतर हो गया है। एनएचएम और एचसीडी जैसी सरकारी पहल उपज स्थिरता को लक्षित करती हैं, जबकि एआईएफ और पीएमएफएमई का उद्देश्य कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को मजबूत करना है - जो आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

भविष्य में, किसानों और निर्यात बाज़ारों के साथ-साथ शहरी उपभोक्ताओं के बीच मज़बूत संबंध स्थापित करना कृषि विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त, बागवानी और गैर-बागवानी फसलों की अंतर-फसलीय खेती से पैदावार में सुधार, मृदा स्वास्थ्य में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि की संभावना है। जलवायु परिवर्तन और कीट प्रबंधन जैसी उभरती चुनौतियों का समाधान करने वाली तकनीकों के विकास के लिए कृषि अनुसंधान को मज़बूत करना और साथ ही उत्पादकता में सुधार करना भी अनिवार्य है। कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों का विकास उच्च निर्यात वृद्धि की संभावनाओं को खोल सकता है, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम कर सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोज़गार के अवसर पैदा कर सकता है।

चार्ट 3: विभिन्न वस्तुओं की कीमतें

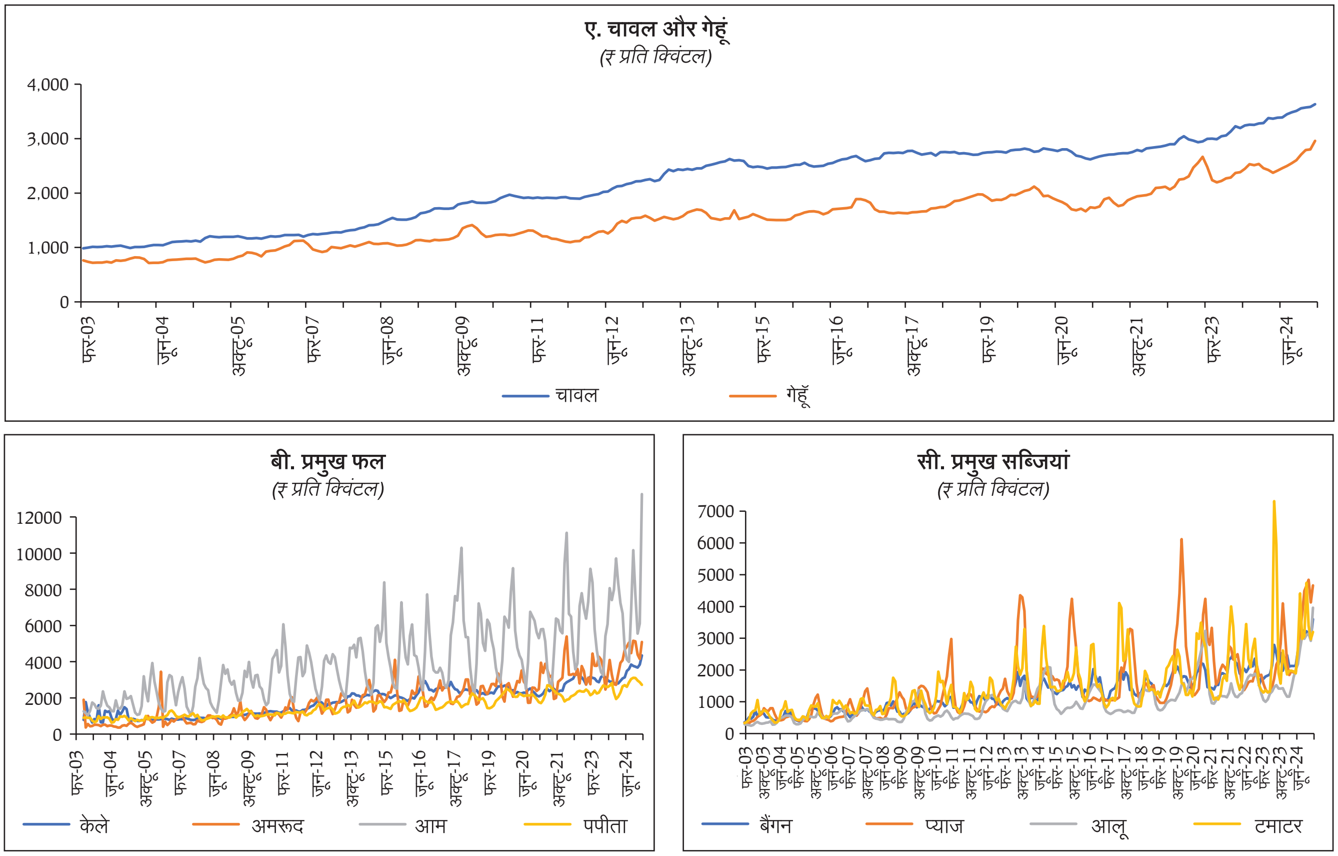

टिप्पणी: चूंकि चावल और गेहूं भारत में सबसे अधिक उत्पादित फसलों में से एक हैं, इसलिए इनकी कीमत को प्रमुख फलों और सब्जियों के साथ तुलना करने के लिए एक मानक के रूप में उपयोग किया जाता है।
स्रोत: सीएमआईई।

संदर्भ:

Ali, M., and Abedullah, D. (2002). Nutritional and Economic Benefits of Enhanced Vegetable Production and Consumption. *Journal of Crop Production, 6(1-2),* 145-176.

Anjum, S., and Madhulika (2018). Growth and instability analysis in Indian agriculture. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 5*(11), 119-125.

Anuja, A. R., Kumar, A., Saroj, S., and Singh, K. N. (2020). The Impact of Crop Diversification towards High-value Crops on Economic Welfare of Agricultural Households in Eastern India. *Current Science, 118(10),* 1575-1582.

Bellon, M. R., Kotu, B. H., Azzarri, C., and Caracciolo, F. (2020). To Diversify or Not to Diversify, that is the Question. Pursuing Agricultural Development for Smallholder Farmers in Marginal Areas of Ghana. *World Development, 125, 104682.*

Birthal, P. S., Hazrana, J., and Negi, D. S. (2020). Diversification in Indian Agriculture Towards High Value Crops: Multilevel Determinants and Policy Implications. *Land Use Policy, 91, 104427.*

Birthal, P. S., Joshi, P. K., Chauhan, S., & Singh, H. (2008). Can Horticulture Revitalise Agricultural Growth?, *Indian Journal of Agricultural Economics, 63*(3).

Birthal, P. S., Joshi, P. K., Roy, D., and Thorat, A. (2013).

Diversification in Indian Agriculture toward High Value Crops: The Role of Small Farmers. *Canadian Journal of Agricultural Economics*, *61*(1), 61-91.

Birthal, P. S., Roy, D., and Negi, D. S. (2015). Assessing the Impact of Crop Diversification on Farm Poverty in India. *World Development*, *72*, 70-92.

Chand, R. (2017). Presidential Address: Doubling Farmers' Income: Strategy and Prospects. *Indian Journal of Agricultural Economics*, *71*(1), 1-23.

Chand, R. (2022). Agricultural challenges and policies for the 21st century. *NABARD Research and Policy Series*, (2), 36.

Cuddy, J. D., and Della Valle, P. A. (1978). Measuring the instability of time series data. *Oxford Bulletin of Economics & Statistics*, *40*(1).

Deogharia, P. C. (2018). Diversification of agriculture: a review. *Journal of Economic & Social Development*, *15*(1), 46-59.

DEV, S. M., & RAO, N. C. (2015). Improved terms of trade for agriculture: Results from revised methodology. *Economic and Political Weekly*, 19-22.

Gulati, A., Das, R., and Winter-Nelson, A. (2024). Reducing Post-Harvest Losses in Indian Agriculture-A Case Study of Selected Crops (No. 20). *Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER)*, New Delhi, India.

Hazell, P. B. (1982). Instability in Indian foodgrain production (Vol. 30). *International Food Policy Research Institute.*

Himanshu (2019, November 7). *India's farm crisis: Decades old and with deep roots.* Ideas for India. https://www.ideasforindia.in/topics/agriculture/indias-farm-crisis-decades-old-and-with-deep-roots.html

Huchet-Bourdon, M. (2011). Agricultural commodity price volatility: an overview. *OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers.*

Joshi, P. K., Birthal, P. S., & Minot, N. (2006). Sources of Agricultural Growth in India: Role of Diversification towards High-Value Crops. *International Food Policy Research Institute (IFPRI).*

Joshi, P. K., Gulati, A., and Birthal, P. S. (2007). Agricultural Diversification in India: Status, Nature and Pattern in India.

Kakwani, N. (1993). Statistical Inference in the Measurement of Poverty. *The Review of Economics and Statistics*, 632-639.

Kumar, V. (2022). Five decades of India's agricultural growth across crops: emerging trends and patterns. *NABARD, Department of Economic Analysis and Research, Mumba*, 1-27.

Minot, N. (2003). Income Diversification and Poverty Reduction in the Northern Uplands of Vietnam. *American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Montreal, Canada.*

Negi, S., and Anand, N. (2017). Post-Harvest Losses and Wastage in Indian Fresh Agro Supply Chain Industry: A Challenge. *IUP Journal of Supply Chain Management*, *14*(2).

Quiroz, J. A., & Valdés, A. (1995). Agricultural diversification and policy reform.

Ravallion, M., and Datt, G. (1996). How Important to India's Poor is the Sectoral Composition of Economic Growth? *The World Bank Economic Review*, *10*(1), 1-25.

Sharma, H. R. (2023). Patterns, sources and determinants of agricultural growth in India. *Indian Journal of Agricultural Economics*, *78*(1), 26-70.

Sharma, H. R., Basantaray, A. K., & Acharya, S. (2023). Characteristics and Performance of Agricultural Households Diversifying to High Value Crops: Evidence from Rural India. *Indian Journal of Agricultural Economics, 70(3)*, 591-607.

Sharma, P., Yeasin, M., Paul, R. K., and M. E. (2024). *Food Price Volatility in India* (No. 349209). ICAR National Institute of Agricultural Economics and Policy Research (NIAP).

Singha, K., Choudhary, R., & Vishnu, K. (2014). Growth and diversification of horticulture crops in Karnataka: An inter-district analysis. *SAGE Open*, *4*(3), 2158244014548018.

Soloaga, I. (2006). Agricultural growth and poverty reduction: The case of Mexico. *International Association of Agricultural Economists Conference, Gold Coast, Australia.*

Thapa, G., Kumar, A., and Joshi, P. K. (2017). Agricultural Diversification in Nepal: Status, Determinants, and its Impact on Rural Poverty (Vol. 1634). *International Food Policy Research Institute.*

Thorbecke, E., and Jung, H. S. (1996). A Multiplier Decomposition Method to Analyze Poverty Alleviation. *Journal of Development Economics, 48(2)*, 279-300.

Tiwari, A., Afroz, S. B., & Kumar, V. (2021). Market vulnerabilities and potential of horticulture crops in India: With special reference to top crops. *Indian Journal of Agricultural Marketing*, *35*(3), 1-20.

अनुलग्नक:

सारणी 1: विभिन्न बागवानी फसलों की औसत पैदावार

(मीट्रिक टन/हेक्टेयर)

बागवानी	1992-93 से 2001-02	2002-03 से 2011-12	2012-13 से 2021-22	1992-93 से 2021-22
कुल फल	**11.5**	**11**	**14.2**	**12.5**
सेब	5.5	7.5	7.7	7
केला	30.1	33.6	35.6	33.7
नींबू*	8.9	8.8	10.7	9.7
मोसंबी*	11.9	10.1	15.5	12.7
संतरे*	8.7	7.7	12	10.1
अंगूर	22.2	19.9	21.6	21.2
अमरूद	11.1	11.2	15	12.9
लीची	6.8	6.7	7	6.9
आम	7.5	6.4	8.5	7.5
पपीता	24.3	35.8	41.5	36
अनानास	14.6	15.3	16.5	15.6
अनार	-	7	11.1	10.1
चीकू	12	8.5	11.1	10
कुल सब्जियाँ	**14**	**15.9**	**17.8**	**16.3**
बैंगन*	15.6	17	17.9	17
पत्ता गोभी	20.1	22	22.7	21.9
फूलगोभी	16.5	18.5	19.4	18.4
ओकरा	9.7	10.6	11.9	10.9
मटर	9.1	8.1	9.9	9.2
टमाटर	15.6	18.4	23.8	20.2
प्याज	10.6	14.8	16.9	15.2
आलू	17.3	19.4	23	20.4
शकरकंद	8.5	9	10.9	9.4
टैपिओका	24.9	32.7	30.2	29.2

टिप्पणियाँ: 1. *: 1993-94 के बाद से डेटा उपलब्ध है।
2. -: उपलब्ध नहीं है.
3. यहाँ, उपज की गणना औसत उत्पादन को उस अवधि के दौरान खेती के औसत क्षेत्रफल से विभाजित करके की जाती है। इस अध्ययन में जानबूझकर किसी विशिष्ट वर्ष की उपज की तुलना नहीं की गई है क्योंकि उस वर्ष की उपज मौसम संबंधी घटनाओं, कीटों और रोगों आदि जैसे बाह्य कारकों से प्रभावित हो सकती है।
4. पीला रंग उपज में गिरावट को दर्शाता है, जबकि हरा रंग उपज में वृद्धि को दर्शाता है। 2002-03 से 2011-12 की उपज की तुलना 1992-93 से 2001-02 तक की उपज से की गई है, जबकि 2012-13 से 2021-22 की उपज की तुलना 2002-03 से 2011-12 तक की उपज से की गई है। 1992-93 से 2021-22 तक की कुल उपज की तुलना 1992-93 से 2001-02 तक की उपज से की गई है।

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय; तथा लेखक की गणना।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

आवसरिक शृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	127
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	128
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	129
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	130
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	131
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	131
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	132
7	मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) के स्रोत	133
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	134
9	कुल चलनिधि राशियाँ	135
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	136
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	136
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	137
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	137
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	138
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	139
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	140
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	141
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	142
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	142
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	142
21	थोक मूल्य सूचकांक	143
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	147
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	147
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	148
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	148
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	149
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	150
28	वाणिज्यिक पत्र	150
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	150
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	151

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	152
32	विदेशी मुद्रा भंडार	152
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ	152
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	153
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण	153
36	भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक	154
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण	155
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	156
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (₹ करोड़)	157
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	158
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (₹ करोड़)	159
42	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	160
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	161
	आवसरिक शृंखलाएं	
44	लघु बचत	163
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	164
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	165
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	166
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	167
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	168
50 (ए)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह-लिखत-वार	169
50 (बी)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक-चुनिंदा संकेतक	172

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।
– = शून्य/नगण्य
प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम   आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2024-25	2023-24		2024-25	
		ति3	ति4	ति3	ति3
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.4	8.0	7.3	6.5	6.8
1.1.1 कृषि	4.6	1.5	0.9	6.6	5.4
1.1.2 उद्योग	4.5	12.6	9.9	3.5	4.7
1.1.3 सेवाएं	7.5	8.5	8.0	7.5	7.9
1.1ए अंतिम खपत व्यय	6.5	5.3	6.3	8.3	4.7
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	7.1	9.3	6.0	5.2	9.4
	2024-25	2024		2025	
		मई	जून	मई	जून
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	4.0	6.3	4.9	1.9	1.5
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियाँ	10.6	12.2	10.7	10.1	10.3
	(10.3)	(12.7)	(11.1)	(9.9)	(10.1)
2.1.2 ऋण#	12.1	16.1	13.9	9.9	10.4
	(11.0)	(19.8)	(17.4)	(9.0)	(9.5)
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण#	12.0	16.2	13.9	9.8	10.2
	(11.0)	(19.8)	(17.4)	(8.8)	(9.3)
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	10.6	8.8	7.4	9.2	9.2
	(9.7)	(10.3)	(8.6)	(8.5)	(8.8)
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	4.3	5.8	7.4	6.1	4.9
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	9.6	12.1	9.7	9.5	9.6
	(9.4)	(12.5)	(10.1)	(9.3)	(9.5)
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.50	4.50	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.3	5.0	5.1	4.5	4.4
	(4.3)	(4.9)	(5.1)	(4.5)	(4.4)
3.4 ऋण-जमा अनुपात	79.1	77.5	77.3	77.4	77.4
	(80.8)	(79.6)	(79.3)	(78.9)	(78.9)
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात#	89.2	59.2	58.4	11.0	31.6
	(86.1)	(57.3)	(56.0)	(7.3)	(28.7)
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5	29.0	28.8	28.8	28.5
	(29.7)	(29.3)	(28.9)	(28.9)	(28.6)
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	29.5	13.4	9.4	1.7	0.0
	(28.1)	(12.6)	(6.4)	(1.5)	(-0.1)
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रेपो दर	6.25	6.50	6.50	6.00	5.50
4.२ स्थायी रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर*	6.00	6.25	6.25	5.75	5.25
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.50	6.75	6.75	6.25	5.75
4.5 बैंक दर	6.50	6.75	6.75	6.25	5.75
4.6 आधार दर	9.10/10.40	9.10/10.25	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.30
4.7 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.15/8.45	8.00/8.60	8.10/8.60	8.15/8.25	7.95/8.25
4.8 मीयादी जमा दर >1 वर्ष	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.30	6.00/6.85	5.85/6.70
4.9 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/2.75	2.50/2.75
4.10 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.35	6.56	6.67	5.80	5.29
4.11 91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	6.52	6.85	6.80	5.62	5.41
4.12 182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	6.52	7.01	6.92	5.63	5.54
4.13 364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	6.47	7.04	6.96	5.63	5.57
4.14 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों सममूल्य प्रतिफल (एफबीआईएल)	6.62	7.01	7.04	6.23	6.34
5 संदर्भ दर और वायदा प्रीमियम					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	85.58	83.30	83.45	85.48	85.56
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	92.32	90.12	89.25	96.94	100.20
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमियम 1-माह (%)	3.12	1.08	1.10	2.01	1.65
3-माह (%)	2.56	1.22	1.14	1.87	1.66
6-माह (%)	2.28	1.34	1.26	1.83	1.79
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.6	4.8	5.1	2.8	2.1
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.39	3.9	3.7	2.9	2.5
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	2.3	2.7	3.4	0.1	-0.1
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	5.2	7.4	9.2	-1.8	-3.4
6.3.2 ईंधन और बिजली	-1.3	1.0	0.5	-4.8	-2.7
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	1.7	1.0	1.5	2.1	2.0
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	6.2	7.3	4.6	-1.7	-3.7
7.2 निर्यात	0.1	13.3	2.4	-2.8	-0.1

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार 31 मार्च 2018 से जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

#: 3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक सभी पखवाड़ों के लिए चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया गया है।

कोष्टकों में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

*: दिनांक 8 अप्रैल 2022 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2022-2023/41 के अनुसार।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2024-25	2024	2025				
		जुला.	जून 27	जुला. 04	जुला. 11	जुला. 18	जुला. 25
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	3683836	3502874	3783575	3783770	3787633	3773600	3763742
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	10	18	17	18	17	16
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**3683847**	**3502885**	**3783593**	**3783786**	**3787651**	**3773617**	**3763757**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 स्वर्ण	235379	176856	255940	256703	256442	257948	262726
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	3448129	3325806	3527205	3526711	3530927	3515466	3500580
1.2.3 रुपया सिक्का	340	223	448	372	282	202	451
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियाँ	1709285	1702094	1803255	1782659	1767751	1784027	1811847
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	100	100	101	100	101	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	42	43
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	943060	976073	933483	931978	930199	984796	918229
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7776	8282	8300	8259	8078	8037	7969
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	5963	5278	4984	5234	5049	4994	5061
2.1.1.7 अन्य बैंक	46963	49426	47375	47518	47621	47335	47638
2.1.1.8 अन्य	593085	538460	715693	692957	676113	641067	720791
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	112296	124433	93278	96570	100547	97656	112014
2.1.2 अन्य देयताएं	2150508	1723581	2183725	2184406	2190245	2206803	2249693
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**3859793**	**3425675**	**3986980**	**3967065**	**3957996**	**3990831**	**4061540**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	10	18	17	18	17	16
2.2.2 विदेशों में धारित राशियाँ	1413591	1625418	1590460	1554686	1553945	1579733	1627461
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	26284	21239	20066	30956	20431	26294	24026
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	251984	7161	1065	1282	1223	951	1906
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	36426	9062	7031	6237	5901	6171	10320
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	111768	124192	93636	96709	100592	97655	112123
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1560630	1322437	1787779	1790646	1789719	1790931	1787703
2.2.6 अन्य आस्तियां	459101	316156	486926	486533	486166	489079	497986
2.2.6.1 स्वर्ण	429510	306207	466434	467825	467349	470094	478801

* डेटा अनंतिम हैं।

सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तन-शील रेपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जून 2025	-	-	-	-	922	231621	-	-	-	-230699
जून 2, 2025	-	-	5150	-	1109	292229	-	-	-	-285970
जून 3, 2025	-	-	5019	-	447	314265	-322	-	-	-309121
जून 4, 2025	-	-	4271	-	622	299291	49	-	-	-294349
जून 5, 2025	-	-	4138	-	580	316403	-	-	-	-311685
जून 6, 2025	-	-	3550	-	1977	326946	-	-	-	-321419
जून 7, 2025	-	-	-	-	58	197270	-	-	-	-197212
जून 8, 2025	-	-	-	-	25	196222	-	-	-	-196197
जून 9, 2025	-	-	3711	-	2123	258855	-	-	-	-253021
जून 10, 2025	-	-	3853	-	16	272671	-1513	-	-	-270315
जून 11, 2025	-	-	-	-	1124	267414	1663	-	-	-264628
जून 12, 2025	-	-	-	-	1095	285659	-	-	-	-284564
जून 13, 2025	-	-	-	-	2248	373129	-	-	-	-370881
जून 14, 2025	-	-	-	-	8	219212	-	-	-	-219204
जून 15, 2025	-	-	-	-	48	205124	-	-	-	-205076
जून 16, 2025	-	-	-	-	1289	277831	-	-	10	-276532
जून 17, 2025	-	-	-	-	1297	299971	-	-	-	-298674
जून 18, 2025	-	-	-	-	1389	296073	-1139	-	-	-295823
जून 19, 2025	-	-	-	-	1323	322568	-175	-	-	-321420
जून 20, 2025	-	-	-	-	2659	303886	-125	-	-	-301352
जून 21, 2025	-	-	-	-	946	235683	-	-	-	-234737
जून 22, 2025	-	-	-	-	285	196522	-	-	-	-196237
जून 23, 2025	-	-	-	-	906	251686	-	-	-	-250780
जून 24, 2025	-	-	-	-	1090	267171	-	-	-	-266081
जून 25, 2025	-	-	-	-	1309	255293	-599	-	-	-254583
जून 26, 2025	-	-	-	-	1826	279877	577	-	-	-277474
जून 27, 2025	-	-	-	84975	1065	223883	-	-	-	-307793
जून 28, 2025	-	-	-	-	436	155844	-	-	-	-155408
जून 29, 2025	-	-	-	-	141	153631	-	-	-	-153490
जून 30, 2025	-	-	-	-	5705	189751	237	-	-	-183809

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय

i) तटीय/ अपतटीय ओटीसी खंड में परिचालन

मद	2024-25	2024	2025	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	-34511	-2107	1764	-3661
1.1 क्रय (+)	364200	15936	9124	1164
1.2 विक्रय (-)	398711	18043	7360	4825
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (₹ करोड़)	-291233	-17688	14562	-31808
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-34511	-1532	104	-3557
(₹ करोड़)	-291233	-13016	-73	-31881
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-84345	-15835	-65215	-60390

ii) मुद्रा वायदा खंड में परिचालन

मद	2024-25	2024	2025	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	31415	2338	0	0
1.2 विक्रय (-)	31415	2338	0	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	0	-1974	0	0

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	30 जून 2025 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	0	2540	-2540
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	0	11845	-11845
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	0	25905	-25905
4. 1 वर्ष से अधिक	0	20100	-20100
कुल (1+2+3+4)	**0**	**60390**	**-60390**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(₹ करोड़)

मद	रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2024-25	2024	2025					
		जुला 26	फर. 21	मार्च 21	अप्रै. 18	मई 30	जून 27	जुला 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	9961	2021	500	9961	2003	1540	1065	1906
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	9900	9900	9900	9900	14900	14900	14900	14900
3.2 बकाया	9517	9062	9096	9517	7999	8595	7010	10299
4 अन्य								
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	19478	11083	9596	19478	10002	10135	8075	12205

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2024-25	2024	2025		
		जून 28	मई 30	जून 13	जून 27
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3630751	3446055	3736896	3744990	3722652
1.1 संचलन में नोट	3686799	3528333	3797410	3808950	3782437
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	35889	33322	36548	36548	36909
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	93696	116948	98902	102371	98575
2 जनता की जमाराशियाँ	2953329	2842003	3241663	3110721	3324072
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियाँ	2840023	2746237	3131530	3001877	3215375
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	113307	95766	110133	108844	108697
3 एम1 (1+2)	**6584081**	**6288057**	**6978559**	**6855711**	**7046725**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियाँ	212331	199223	212331	212331	212331
5 एम2 (3+4)	**6796412**	**6487280**	**7190890**	**7068042**	**7259056**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियाँ	20643062	19413650	20956339	20987083	21131104
	(20702508)	(19503047)	(21011378)	(21040863)	(21183731)
7 एम3 (3+6)	27227143	25701708	27934898	27842794	28177829
	(27286589)	(25791104)	(27989937)	(27896574)	(28230456)
8 कुल डाकघर जमाराशियाँ	1443555	1351212	1443555	1443555	1443555
9 एम4 (7+8)	28670698	27052920	29378453	29286349	29621384
	(28730144)	(27142316)	(29433492)	(29340129)	(29674011)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम$_3$) के स्रोत

(₹ करोड़)

स्रोत	मार्च 31 / माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2024-25	2024	2025		
		जून 28	मई 30	जून 13	जून 27
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**8463065**	**7424141**	**8446563**	**8556270**	**8473446**
1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(8510825)	(7489485)	(8493151)	(8602857)	(8520033)
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1508105	1026142	1479315	1602562	1513361
1.1.1 सरकार पर दावे	1591591	1355438	1839456	1804247	1806229
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1558903	1348151	1811974	1788285	1786164
1.1.1.2 राज्य सरकारें	32688	7286	27482	15962	20066
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियाँ	83485	329296	360141	201685	292869
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	83443	329254	360099	201643	292826
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	6954959	6397999	6967248	6953707	6960086
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण (विलय सहित)	(7002720)	(6463344)	(7013836)	(7000295)	(7006672)
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**18646762**	**17148762**	**18690046**	**18715304**	**18888886**
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(19068129)	(17648993)	(19089019)	(19113760)	(19283371)
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	38246	10922	14393	10263	9029
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	18608516	17137840	18675653	18705041	18879856
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंक ऋण (विलय सहित)	(19029883)	(17638071)	(19074626)	(19103496)	(19274342)
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	17822605	16385798	17888404	17915507	18091714
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण (विलय सहित)	(18243972)	(16886029)	(18287377)	(18313963)	(18486200)
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	766659	733421	768000	770519	769075
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	19252	18621	19249	19014	19067
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश (विलय सहित)	(19252)	(18621)	(19249)	(19014)	(19067)
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**6148527**	**5653720**	**6350876**	**6449305**	**6437976**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	5550947	5287013	5753296	5851725	5840396
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	5550956	5287015	5753292	5851722	5840398
3.1.2 विदेशी देयताएं	9	2	-4	-4	2
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	597580	366707	597580	597580	597580
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**36632**	**34065**	**37291**	**37291**	**37652**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**6067843**	**4558981**	**5589878**	**5915376**	**5660130**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (विलय सहित)	(6477524)	(5035160)	(5980400)	(6306639)	(6048576)
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	2147427	1631829	2099222	2181690	2168644
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	3920417	2927152	3490656	3733686	3491487
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट) (विलय सहित)	(4330098)	(3403331)	(3881177)	(4124949)	(3879932)
एम$_3$ (1+2+3+4-5)	**27227143**	**25701708**	**27934898**	**27842794**	**28177829**
एम$_3$ (1+2+3+4-5) (विलय सहित)	(27286589)	(25791104)	(27989937)	(27896574)	(28230456)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2024-25	2024	2025		
		जून 28	मई 30	जून 13	जून 27
	1	2	3	4	5
समग्र मौद्रिक राशियाँ					
एनएम$_1$ (1.1 + 1.2.1+1.3)	6584081	6288057	6978559	6855711	7046725
एनएम$_2$ (एनएम$_1$ + 1.2.2.1)	15741937	14915653	16278082	16167286	16423308
एनएम$_2$ (एनएम$_1$ + 1.2.2.1) (विलय सहित)	(15768688)	(14955882)	(16302849)	(16191486)	(16446990)
एनएम$_3$ (एनएम$_2$ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	27850121	26224953	28539892	28386562	28733795
एनएम$_3$ (एनएम$_2$ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5) (विलय सहित)	(27909568)	(26314350)	(28594932)	(28440341)	(28786422)
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3446055	3736896	3744990	3722652
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ	23190815	21918672	23797136	23694264	24052227
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ (विलय सहित)	(23250261)	(22008068)	(23852176)	(23748044)	(24104854)
1.2.1 मांग जमाराशियाँ	2840023	2746237	3131530	3001877	3215375
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	20350792	19172435	20665606	20692388	20836852
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(20410239)	(19261832)	(20720646)	(20746167)	(20889478)
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	9157856	8627596	9299523	9311574	9376583
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(9184607)	(8667824)	(9324291)	(9335775)	(9400265)
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	527375	407354	516544	479167	516691
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	11192936	10544839	11366083	11380813	11460269
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(11225631)	(10594007)	(11396355)	(11410392)	(11489213)
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	113307	95766	110133	108844	108697
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	915248	764461	895727	838463	850218
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	28333316	26021154	28414468	28590246	28607768
2.1 देशी ऋण (विलय सहित)	(28802443)	(26586730)	(28860029)	(29035289)	(29048840)
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8463065	7424141	8446563	8556270	8473446
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(8510825)	(7489485)	(8493151)	(8602857)	(8520033)
2.1.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1508105	1026142	1479315	1602562	1513361
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	6954959	6397999	6967248	6953707	6960086
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण (विलय सहित)	(7002720)	(6463344)	(7013836)	(7000295)	(7006672)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	19870251	18597013	19967905	20033976	20134322
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(20291618)	(19097244)	(20366878)	(20432432)	(20528808)
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण	38246	10922	14393	10263	9029
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	19832006	18586092	19953512	20023713	20125292
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण (विलय सहित)	(20253372)	(19086322)	(20352485)	(20422168)	(20519778)
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	1208294	1432378	1259726	1278661	1208081
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	36632	34065	37291	37291	37652
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5605462	5180420	5821083	5867041	5954722
2.3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5287013	5753296	5851725	5840396
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	54514	-106593	67787	15316	114326
2.4 पूंजी खाता	4481192	4258925	4956419	5035068	5040017
2.5 अन्य मदें (निवल)	2053777	1227940	1167053	1464211	1214776

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 9: चलनिधि समग्र राशियाँ

(₹ करोड़)

समग्र राशियाँ	2024-25	2024	2025		
		जून	अप्रै.	मई	जून
	1	2	3	4	5
1 एनएम$_3$	**27837333**	**26224953**	**28152487**	**28539892**	**28733795**
	(27896780)	(26314350)	(28211019)	(28594932)	(28786422)
2 डाकघर जमाराशियाँ	756786	713570	756786	756786	756786
3 एल$_1$ (1 + 2)	**28594119**	**26938523**	**28909273**	**29296678**	**29490581**
	(28653566)	(27027920)	(28967805)	(29351718)	(29543208)
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	95148	68179	102284	116492	113786
4.1 सावधि मुद्रा उधार	10	748	4	4	5
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	80810	54670	87705	101755	98755
4.3 सावधि जमाराशियाँ	14328	12761	14575	14733	15026
5 एल$_2$ (3 + 4)	**28689268**	**27006703**	**29011557**	**29413170**	**29604367**
	(28748714)	(27096099)	(29070089)	(29468210)	(29656993)
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियाँ	121178	109284	..	..	129567
7 एल$_3$ (5 + 6)	**28810446**	**27115987**	**..**	**..**	**29733934**

टिप्पणी : 1. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2024-25	2024	2025		
		जून 28	मई 30	जून 13	जून 27
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	3724448	3563002	3835798	3847361	3821227
1.2 आरबीआई के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	991488	1036368	1016571	993358	994142
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	926001	973455	956086	932453	933483
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	113307	95766	110133	108844	108697
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4829243	4695137	4962501	4949563	4924066
2 स्रोत					
2.1 आरबीआई के देशी ऋण	1389090	1005887	1271136	1242237	1214662
2.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1508105	1026142	1479315	1602562	1513361
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल आरबीआई ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1475460	1018898	1451876	1586643	1493338
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1558574	1347914	1811677	1787961	1785715
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1558574	1347914	1811677	1787961	1785715
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	329	237	297	324	449
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियाँ	83443	329254	360099	201643	292826
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल आरबीआई ऋण	32646	7244	27439	15919	20023
2.1.2 बैंकों पर आरबीआई के दावे	-157261	-31176	-222572	-370589	-307728
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-157261	-31176	-222572	-370589	-307728
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई के ऋण	38246	10922	14393	10263	9029
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	9182	9061	8595	8471	7010
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	36632	34065	37291	37291	37652
2.3 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5287013	5753296	5851725	5840396
2.3.1 स्वर्ण	668162	471350	721351	743180	722374
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4882794	4815665	5031941	5108541	5118023
2.4 पूंजी खाता	1875114	1728614	2091368	2164551	2127550
2.5 अन्य मदें (निवल)	272313	-96785	7854	17139	41094

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	2024-25	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2024	2025				
		जून 28	मई 30	जून 6	जून 13	जून 20	जून 27
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4829243	4695137	4962501	4957029	4949563	4937712	4924066
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	3724448	3563002	3835798	3851625	3847361	3829879	3821227
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियाँ	991488	1036368	1016571	998639	993358	999821	994142
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	113307	95766	110133	106766	108844	108012	108697
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1508105	1026142	1479315	1576499	1602562	1524619	1513361
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-157261	-31176	-222572	-323564	-370589	-301224	-307728
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	38246	10922	14393	12551	10263	9113	9029
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5287013	5753296	5803137	5851725	5877121	5840396
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	36632	34065	37291	37291	37291	37291	37652
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	2147427	1631829	2099222	2148884	2181690	2209208	2168644

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार / माह के रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2024-25	2024	2025		
		जून 28	मई 30	जून 13	जून 27
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियाँ	22228885	20954884	22826770	22721308	23078766
	(22288331)	(21044281)	(22881810)	(22775087)	(23131393)
1.1.1 मांग जमाराशियाँ	2698049	2601677	2988921	2859234	3072874
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	19530836	18353206	19837850	19862074	20005892
	(19590283)	(18442603)	(19892889)	(19915853)	(20058519)
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	8788876	8258943	8927032	8937933	9002651
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	527375	407354	516544	479167	516691
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	10741960	10094264	10910817	10924141	11003241
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	915248	764461	895727	838463	850218
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	25687563	23918212	25817693	25870437	25978666
	(26156690)	(24483787)	(26263254)	(26315479)	(26419739)
2.1.1 सरकार को ऋण	6649537	6091725	6659581	6644387	6649761
	(6697298)	(6157070)	(6706169)	(6690975)	(6696348)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	19038025	17826487	19158112	19226049	19328905
	(19459392)	(18326718)	(19557085)	(19624504)	(19723391)
2.1.2.1 बैंक ऋण	17822605	16385798	17888404	17915507	18091714
	(18243972)	(16886029)	(18287377)	(18313963)	(18486200)
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	17786074	16351894	17817823	17847902	18027325
	(18207441)	(16852125)	(18216796)	(18246357)	(18421811)
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	15458	16136	18396	40274	37618
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	630	1137	548	569	454
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1199332	1423416	1250763	1269699	1199119
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	54514	-106593	67787	15316	114326
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	529621	304848	530021	477976	577466
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियाँ	292270	241215	290733	294696	294252
2.2.3 ओवरसीज़ विदेशी मुद्रा उधार	182837	170226	171501	167964	168887
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	791777	1109609	1265837	1393514	1327882
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	882415	973455	956086	932453	933483
2.3.2 उपलब्ध नकदी	81874	104977	87179	90472	86671
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	172512	-31176	-222572	-370589	-307728
2.4 पूंजी खाता	2581908	2506141	2840880	2846347	2888296
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	807812	695742	587940	873149	603594
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	878795	759345	863072	938066	877929
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	118268	148564	115343	140380	135597

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(₹ करोड़)

मद	21 मार्च, 2025 की स्थिति	2024	2025		
		जून 28	मई 30	जून 13	जून 27
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	6697928	6158207	6706717	6691544	6696802
	(6650167)	(6092862)	(6660129)	(6644956)	(6650215)
2 अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ (गैर-एसएलआर)	165500	157944	165432	160229	160012
3 वाणिज्यिक पत्र	63163	51636	87088	70960	63802
4 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	13874	13259	13263	13249	13929
4.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	95984	92861	98704	98749	98319
4.3 अन्य	7664	7014	7959	7806	7740
5 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
5.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	130308	119057	138380	138077	145868
5.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	248138	248618	254057	254353	260092
5.3 अन्य	150000	134187	157501	159546	152387
6 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
6.1 म्यूचुअल फंड	119867	66115	127914	161081	91749
6.2 वित्तीय संस्थाएं	204865	178493	204927	207844	205220

टिप्पणी : कॉलम सं. (1), (2) व (3)में दिया गया डेटा अंतिम है और कॉलम सं.(4) व (5)में दिया गया डेटा अनंतिम है।

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में, एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2024-25	2024	2025		2024-25	2024	2025	
		जून	मई	जून		जून	मई	जून
	1	2	3	4	5	6	7	8
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	208	208	208	194	135	135	135	120
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**458011**	**513092**	**507039**	**502819**	**451305**	**508732**	**500764**	**496493**
1.1 बैंकों से माँग और मीयादी जमाराशियाँ	315675	286043	370999	376973	309414	281970	365140	371106
1.2 बैंकों से उधार राशि	112027	150174	110574	100647	111976	150168	110552	100641
1.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	30310	76875	25466	25199	29916	76594	25071	24746
2 अन्य के प्रति देयताएं	**25053097**	**23563072**	**25610676**	**25831794**	**24557481**	**22979438**	**25102843**	**25322680**
2.1 कुल जमाराशियाँ	23055487	21847651	23662774	23916413	22580601	21285397	23172543	23425645
	(22996040)	(21758255)	(23607734)	(23863786)	(22521155)	(21196001)	(23117503)	(23373019)
2.1.1 माँग	2748263	2659582	3038379	3121680	2698049	2601677	2988921	3072874
2.1.2 मीयादी	20307224	19188070	20624394	20794732	19882552	18683720	20183622	20352771
2.2 उधार	920568	769330	900194	854691	915248	764461	895727	850218
2.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	1077042	946090	1047708	1060690	1061632	929579	1034574	1046816
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**311466**	**102741**	**6516**	**1065**	**311466**	**102741**	**6516**	**1065**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	311466	102741	6516	1065	311466	102741	6516	1065
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	985044	1101330	1064842	1041975	964289	1078432	1043265	1020154
4.1 उपलब्ध नकदी	84399	107944	89605	89278	81874	104977	87179	86671
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	900645	993386	975237	952697	882415	973455	956086	933483
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**432645**	**456033**	**494019**	**490913**	**348496**	**376530**	**403817**	**398514**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेषराशि	273720	255065	331989	340579	215801	200529	266765	273831
5.1.1 चालू खाते में	13239	16365	13853	25103	10619	12536	11435	22785
5.1.2 अन्य खातों में	260481	238700	318135	315476	205182	187993	255331	251046
5.2 माँग और अल्पसूचना पर मुद्रा	44772	31977	40689	42285	25838	11606	22813	24041
5.3 बैंकों को अग्रिम	43856	51727	38542	33677	39504	50288	36148	31558
5.4 अन्य आस्तियां	70296	117264	82799	74373	67353	114106	78092	69084
6 निवेश	**6850574**	**6356686**	**6861687**	**6854341**	**6697928**	**6158207**	**6706717**	**6696802**
	(6802814)	(6291341)	(6815099)	(6807755)	(6650167)	(6092862)	(6660129)	(6650215)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	6842024	6343630	6853140	6845977	6697298	6157070	6706169	6696348
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	8550	13056	8547	8365	630	1137	548	454
7 बैंक ऋण	**18708286**	**17413067**	**18753741**	**18956024**	**18243972**	**16886029**	**18287377**	**18486200**
	(18286919)	(16912836)	(18354768)	(18561538)	(17822605)	(16385798)	(17888404)	(18091714)
7ए खाद्यान्न ऋण	87145	84526	122554	116363	36531	33904	70581	64389
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	18370704	17088089	18412982	18613283	17909851	16564523	17949958	18146380
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	76523	69416	80744	80511	74963	68064	79467	79560
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	222320	214682	223957	225234	221059	213232	222449	223845
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	15357	17139	14063	14007	15122	16909	13866	13787
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	23382	23741	21995	22988	22977	23301	21636	22627

टिप्पणी: 1. कॉलम सं. (4) व (8) में दिया गया डेटा अनंतिम है।
2. जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल
3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 21, 2025	2024	2025		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जून 28	मई 30	जून 27	2025-26	2025
	1	2	3	4	%	%
I. बैंक ऋण (II+III)	**18243936**	**16880782**	**18287597**	**18483098**	**1.3**	**9.5**
	(17822569)	(16385798)	(17888624)	(18088612)	(1.5)	(10.4)
II. खाद्यान्न ऋण	**36531**	**33904**	**70581**	**64389**	**76.3**	**89.9**
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	**18207404**	**16846879**	**18217016**	**18418709**	**1.2**	**9.3**
	(17786038)	(16351894)	(17818043)	(18024223)	(1.3)	(10.2)
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	**2287071**	**2159559**	**2298815**	**2305993**	**0.8**	**6.8**
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	**3937149**	**3728156**	**3881567**	**3932773**	**-0.1**	**5.5**
	(3925089)	(3712270)	(3869110)	(3917824)	(-0.2)	(5.5)
2.1 सूक्ष्म और लघु	791721	731625	837079	872577	10.2	19.3
2.2 मध्यम	360475	316322	365914	357618	-0.8	13.1
2.3 बड़े	2784953	2680209	2678574	2702578	-3.0	0.8
3. सेवाएं	**5161462**	**4707069**	**5090833**	**5130831**	**-0.6**	**9.0**
	(5094021)	(4616040)	(5018221)	(5060940)	(-0.6)	(9.6)
3.1 परिवहन परिचालक	258409	242193	263377	256635	-0.7	6.0
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	32915	26677	33981	36232	10.1	35.8
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्टरां	83091	78351	85206	84781	2.0	8.2
3.4 शिपिंग	7305	7019	7793	8042	10.1	14.6
3.5 विमानन	46026	45360	46326	50750	10.3	11.9
3.6 पेशेवर सेवाएं	195956	172138	196476	196406	0.2	14.1
3.7 व्यापार	1186787	1059459	1167392	1174129	-1.1	10.8
3.7.1 थोक व्यापार[1]	648619	557604	634298	629888	-2.9	13.0
3.7.2 खुदरा व्यापार	538168	501856	533094	544241	1.1	8.4
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	532757	483297	549874	555519	4.3	14.9
	(488689)	(421756)	(505800)	(513412)	(5.1)	(21.7)
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)[2] जिसमें से	1636098	1555496	1562646	1596490	-2.4	2.6
3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	323146	328232	308740	331346	2.5	0.9
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएं (पीएफआई)	228678	197127	207146	211702	-7.4	7.4
3.10 अन्य सेवाएं[3]	1182118	1037078	1177763	1171848	-0.9	13.0
	(1166422)	(1018174)	(1157271)	(1152057)	(-1.2)	(13.1)
4. व्यक्तिगत ऋण	**5952299**	**5486107**	**6061987**	**6150295**	**3.3**	**12.1**
	(5610478)	(5091342)	(5748146)	(5840710)	(4.1)	(14.7)
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23402	24123	23715	23376	-0.1	-3.1
4.2 आवास	3010477	2798568	3037366	3067120	1.9	9.6
	(2689068)	(2427447)	(2742752)	(2776336)	(3.2)	(14.4)
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	141101	126533	142479	145540	3.1	15.0
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	10080	9357	9412	9886	-1.9	5.7
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	284366	273044	290678	292602	2.9	7.2
4.6 शिक्षा	137456	121990	138122	139587	1.6	14.4
4.7 वाहन ऋण	622794	588575	637766	652285	4.7	10.8
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण	208735	123776	251369	277025	32.7	123.8
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1513889	1420142	1531082	1542875	1.9	8.6
	(1493525)	(1396591)	(1511895)	(1524110)	(2.0)	(9.1)
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां[4]	2287804	2186829	2277560	2274259	-0.6	4.0
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम[5]	2240503	2020474	2410013	2460012	9.8	21.8
(iii) मध्यम उद्यम[6]	601451	511467	610129	591992	-1.6	15.7
(iv) आवास	746651	752911	750390	856626	14.7	13.8
	(665107)	(661668)	(671007)	(776086)	(16.7)	(17.3)
(v) शिक्षा ऋण	62825	61269	63146	64355	2.4	5.0
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	10325	6279	12250	12563	21.7	100.1
(vii) सामाजिक अवसंरचना	1316	2949	827	828	-37.1	-71.9
(viii) निर्यात ऋण	12361	11721	12021	13047	5.5	11.3
(ix) अन्य	47900	60871	48675	46467	-3.0	-23.7
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1820904	1716930	1832723	1825579	0.3	6.3

नोट:

(1) आंकड़े अनंतिम हैं। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण आंकड़े धारा-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को कवर करते हैं, जबकि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित, सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा देने वाले चुनिंदा बैंकों को कवर करते हैं।

(2) 28 जुलाई, 2023 से आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

(3) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को शामिल नहीं करते हैं।

1 थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर खाद्य खरीद ऋण शामिल हैं।

2 एनबीएफसी में एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई), स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।

3 "अन्य सेवाओं" में म्यूचुअल फंड (एमएफ), एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग और वित्त, और अन्य सेवाएँ शामिल हैं जो सेवाओं के अंतर्गत कहीं और इंगित नहीं की गई हैं।

4 एक बैंक ने मई 2024 से, खुदरा खंड के तहत कृषि ऋण की एक श्रेणी के वर्गीकरण को "स्वर्ण के आभूषणों पर ऋण" में बदल दिया है।

5 प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।

6 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।

7 प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 21, 2025	2024	2025		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जून 28	मई 30	जून 27	2025-26	2025
	1	2	3	4	%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	3937149	3728156	3881567	3932773	-0.1	5.5
	(3925089)	(3712270)	(3869110)	(3917824)	(-0.2)	(5.5)
2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	56756	55600	53904	56945	0.3	2.4
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	219527	206410	223657	223136	1.6	8.1
2.2.1 चीनी	28522	24945	25414	22862	-19.8	-8.4
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	20927	18123	20413	21342	2.0	17.8
2.2.3 चाय	5084	5853	4923	4950	-2.6	-15.4
2.2.4 अन्य	164994	157490	172908	173983	5.4	10.5
2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	35513	30518	34191	34636	-2.5	13.5
2.4 वस्त्र	277267	255274	272922	277281	0.0	8.6
2.4.1 सूती वस्त्र	107227	96345	103651	105615	-1.5	9.6
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	4288	4245	4324	4411	2.9	3.9
2.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	49091	45229	47882	49102	0.0	8.6
2.4.4 अन्य वस्त्र	116661	109456	117065	118153	1.3	7.9
2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	12980	12621	13164	13207	1.7	4.6
2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	27826	24222	28239	28303	1.7	16.8
2.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	52848	47584	52519	52731	-0.2	10.8
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक ईंधन	154178	150054	137814	154602	0.3	3.0
2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	267814	254950	268394	271055	1.2	6.3
2.9.1 उवर्रक	32011	36925	32607	31958	-0.2	-13.5
2.9.2 औषधि और दवाइयां	88738	81818	85831	86613	-2.4	5.9
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	26892	25356	31822	31955	18.8	26.0
2.9.4 अन्य	120172	110852	118134	120529	0.3	8.7
2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	103464	88917	101907	102610	-0.8	15.4
2.11 कांच और कांच के सामान	13443	12340	13673	13243	-1.5	7.3
2.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	59752	60571	59400	59183	-1.0	-2.3
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	433502	398182	430541	442055	2.0	11.0
2.13.1 लोहा और स्टील	300156	281763	293133	301600	0.5	7.0
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	133345	116419	137409	140455	5.3	20.6
2.14 सभी अभियांत्रिकी	240135	203490	239968	248780	3.6	22.3
2.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	52862	45351	52810	55370	4.7	22.1
2.14.2 अन्य	187272	158139	187158	193411	3.3	22.3
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	119057	113222	117522	121183	1.8	7.0
2.16 रत्न और आभूषण	85734	84039	86968	88818	3.6	5.7
2.17 निर्माण	150701	137097	150908	150855	0.1	10.0
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1322831	1323860	1304228	1316796	-0.5	-0.5
2.18.1 बिजली	682953	646566	683712	695401	1.8	7.6
2.18.2 दूरसंचार	118940	132542	101263	104278	-12.3	-21.3
2.18.3 सड़क	311219	335841	316339	316840	1.8	-5.7
2.18.4 हवाई अड्डा	9156	7779	9428	9355	2.2	20.3
2.18.5 बंदरगाह	5916	6483	5182	5530	-6.5	-14.7
2.18.6 रेलवे	13595	13275	11487	11510	-15.3	-13.3
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	181052	181374	176817	173882	-4.0	-4.1
2.19 अन्य उद्योग	303822	269206	291648	277354	-8.7	3.0

टिप्पणी : (1) 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।
(2) कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं है।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(₹ करोड़)

मद	रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति							
	2024-25	2024	2025					
		मई 31	मार्च 28	अप्रै 04	अप्रै 18	अप्रै 25	मई 02	मई 16	मई 30
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	34	33	34	34	34	34	34	34	34
1 कुल जमाराशियाँ (2.1.1.2+2.2.1.2)	**146871.0**	**135938.7**	**146871.0**	**148566.3**	**145054.5**	**147251.7**	**147608.7**	**147866.9**	**145985.2**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**29215.6**	**28297.6**	**29215.6**	**29503.5**	**27277.2**	**26936.5**	**28452.9**	**27298.2**	**26758.2**
2.1.1 जमाराशियाँ									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	9022.9	7482.3	9022.9	9328.0	8714.1	8298.2	8119.3	8033.8	7428.2
2.1.1.2 अन्य	14063.9	15241.7	14063.9	14165.7	13668.7	14069.6	14316.8	13861.7	11836.7
2.1.2 बैंकों से उधार	700.0	154.9	700.0		350.0		1289.0	824.2	2912.2
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	5428.9	5418.7	5428.9	6009.9	4544.4	4568.8	4727.9	4578.4	4581.2
2.2 मीयादी देयताएं	**201100.7**	**187897.4**	**201100.7**	**203978.3**	**199471.9**	**199412.2**	**199704.6**	**200375.1**	**199917.5**
2.2.1 जमाराशियाँ									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	66874.3	65382.8	66874.3	68122.4	66627.7	64779.7	64977.2	64945.2	64334.4
2.2.1.2 अन्य	132807.1	120697.0	132807.1	134400.6	131385.8	133182.1	133291.9	134005.2	134148.5
2.2.2 बैंकों से उधार	643.9	663.8	643.9	618.0	615.5	615.5	615.5	615.5	615.5
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	775.4	1153.8	775.4	837.3	842.9	834.9	820.0	809.2	819.0
3 रिज़र्व बैंक से उधार	699.5		699.5	699.8	499.9	499.8	499.8	499.8	499.8
4 अधिसूचित बैंक/ सरकार से उधार	126928.5	84175.6	126928.5	123828.0	120340.2	117224.0	113687.2	112391.9	113039.0
4.1 मांग	53459.8	23112.7	53459.8	51798.7	50684.0	50291.4	48334.5	47731.0	47805.0
4.2 मीयादी	73468.7	61062.9	73468.7	72029.3	69656.2	66932.6	65352.6	64660.9	65234.0
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	**13390.9**	**12165.3**	**13390.9**	**15154.0**	**15967.2**	**19115.8**	**12935.0**	**15919.7**	**16813.3**
5.1 उपलब्ध नकदी	1052.1	714.6	1052.1	1157.2	813.7	741.3	970.1	756.2	772.5
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	12338.8	11450.7	12338.8	13996.8	15153.5	18374.6	11964.9	15163.5	16040.7
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेषराशि	**1656.3**	**1528.5**	**1656.3**	**1727.6**	**1856.2**	**1487.3**	**1306.3**	**1197.9**	**1102.6**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**77220.1**	**76376.5**	**77220.1**	**77215.6**	**79265.3**	**78742.6**	**78309.8**	**79425.0**	**79798.1**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**26531.1**	**21180.5**	**26531.1**	**30596.7**	**22162.6**	**20185.1**	**22926.3**	**53472.9**	**21442.9**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**174828.8**	**135733.7**	**174828.8**	**174139.0**	**174573.0**	**185733.8**	**173379.6**	**173468.6**	**173065.3**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**174590.4**	**135524.3**	**174590.4**	**173853.1**	**174312.5**	**185468.1**	**173105.4**	**173203.9**	**172775.8**
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	124607.6	136109.4	124607.6	121776.9	119426.7	118050.3	116990.1	116484.5	116407.6
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	238.4	209.4	238.4	285.8	260.5	265.6	274.2	264.7	289.5

कीमत और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2024-25			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	जूला 24	जून 25	जूला 25 (अ)	जूला 24	जून 25	जूला 25 (अ)	जून 24	मई 25	जून 25 (अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**198.6**	**205.3**	**201.1**	**200.4**	**194.9**	**198.4**	**208.3**	**203.5**	**207.0**	**203.3**	**198.1**	**201.6**
1.1 अनाज और उत्पाद	195.0	193.7	194.6	191.4	197.1	197.0	191.2	197.5	197.3	191.3	197.2	197.1
1.2 मांस और मछली	222.3	231.9	225.7	227.1	227.0	225.5	237.4	237.9	236.3	230.7	230.8	229.3
1.3 अंडा	192.8	197.5	194.6	192.5	192.9	196.4	197.2	198.8	202.3	194.3	195.2	198.7
1.4 दूध और उत्पाद	186.3	187.0	186.6	185.6	190.0	190.4	186.6	191.6	192.2	186.0	190.6	191.1
1.5 तेल और चर्बी	175.4	165.5	171.8	163.4	193.7	197.9	157.1	179.4	182.0	161.1	188.4	192.1
1.6 फल	188.3	194.2	191.0	181.4	203.8	210.1	192.4	211.9	217.2	186.5	207.6	213.4
1.7 सब्जी	222.1	269.6	238.2	248.8	175.0	196.3	303.4	219.0	242.6	267.3	189.9	212.0
1.8 दाल और उत्पाद	208.0	213.5	209.8	211.5	184.6	182.8	218.0	189.0	187.2	213.7	186.1	184.3
1.9 चीनी और उत्पाद	130.4	132.6	131.2	130.4	134.7	134.7	132.3	136.4	136.4	131.0	135.3	135.3
1.10 मसाले	228.5	223.9	227.0	229.4	221.7	221.7	225.0	219.0	219.2	227.9	220.8	220.9
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	185.2	173.9	180.5	183.0	190.0	190.9	172.1	180.0	180.5	178.4	185.8	186.6
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	199.4	209.7	204.2	197.6	204.6	205.3	207.2	216.7	217.4	202.1	210.2	210.9
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**207.3**	**212.6**	**208.7**	**206.5**	**211.0**	**211.6**	**212.9**	**217.3**	**217.9**	**208.2**	**212.7**	**213.3**
3 कपड़ा और जूते	**197.9**	**186.7**	**193.5**	**196.7**	**201.0**	**201.3**	**185.5**	**190.4**	**190.8**	**192.3**	**196.8**	**197.1**
3.1 कपड़ा	198.8	188.8	194.9	197.5	202.0	202.2	187.6	192.6	193.0	193.6	198.3	198.6
3.2 जूते	192.7	174.7	185.2	191.8	195.1	195.5	173.8	177.9	178.2	184.3	188.0	188.3
4 आवास	**--**	**181.5**	**181.5**	**--**	**--**	**--**	**180.0**	**184.8**	**185.7**	**180.0**	**184.8**	**185.7**
5 ईंधन और बिजली	**181.2**	**169.7**	**176.9**	**180.0**	**184.1**	**184.0**	**169.5**	**175.4**	**175.2**	**176.0**	**180.8**	**180.7**
6 विविध	**189.3**	**180.7**	**185.1**	**187.9**	**196.7**	**197.4**	**179.3**	**187.4**	**188.1**	**183.7**	**192.2**	**192.9**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	185.7	177.1	181.6	184.3	188.1	188.4	175.6	180.5	180.9	180.2	184.5	184.9
6.2 स्वास्थ्य	198.4	193.2	196.4	196.5	204.5	205.4	191.4	199.3	200.3	194.6	202.5	203.5
6.3 परिवहन और संचार	175.5	164.8	169.9	175.5	179.0	179.4	164.8	167.9	168.1	169.9	173.2	173.5
6.4 मनोरंजन	180.1	175.5	177.5	179.0	182.3	182.8	174.2	178.6	178.7	176.3	180.2	180.5
6.5 शिक्षा	190.8	186.2	188.1	190.6	195.8	196.7	185.0	192.1	193.5	187.3	193.6	194.8
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और संबंधित सामन	204.3	206.2	205.1	199.8	228.6	229.8	201.3	230.8	231.9	200.4	229.5	230.7
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**194.9**	**190.0**	**192.6**	**195.3**	**195.5**	**197.6**	**190.3**	**192.6**	**194.2**	**193.0**	**194.2**	**196.0**

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2024-25	2024	2025	
				जून	मई	जून
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	142.6	141.4	144.0	145.0
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2019	9.69	-	132.2	133.1	134.1
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2019	9.78	-	132.1	133.4	134.4

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में स्वर्ण और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2024-25	2024	2025	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	75842	72014	94590	97176
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	89131	88666	96026	105444

स्रोत: मुंबई में स्वर्ण और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2024-25	2024	2025		
			जुला	मई	जून (अ)	जुला (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	**100.000**	**154.9**	**155.3**	**153.7**	**153.8**	**154.4**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**192.5**	**197.8**	**184.8**	**185.8**	**188.0**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**205.3**	**213.1**	**196.8**	**197.8**	**199.7**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	210.1	208.1	204.0	203.0	204.1
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	241.4	277.6	203.8	212.2	220.9
1.1.1.3 दूध	4.440	185.8	186.0	190.1	189.7	190.1
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	173.4	173.7	176.6	174.0	171.8
1.1.1.5 मसाले	0.529	232.7	237.0	200.8	199.5	200.0
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	213.6	207.8	224.9	222.8	221.0
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**161.7**	**158.9**	**158.5**	**160.9**	**164.3**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	161.4	163.9	163.5	163.2	165.0
1.1.2.2 तिलहन	1.115	181.5	180.2	184.0	190.6	197.8
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	138.7	137.1	137.8	137.7	137.7
1.1.2.4 पुष्पोत्पादन	0.204	277.4	232.6	198.5	210.9	234.5
1.1.3 खनिज	**0.833**	**229.0**	**226.6**	**228.4**	**231.5**	**229.0**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	219.2	212.4	219.9	223.9	219.6
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	263.4	276.5	257.9	258.1	261.7
1.1.4 कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	**2.410**	**151.3**	**157.9**	**138.8**	**136.8**	**140.3**
1.2 ईंधन और बिजली	**13.152**	**150.0**	**148.2**	**142.9**	**143.0**	**144.6**
1.2.1 कोयला	**2.138**	**135.6**	**135.6**	**136.7**	**136.9**	**136.3**
1.2.1.1 कुकिंग कोयला	0.647	143.4	143.4	146.4	146.4	146.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोयला	1.401	125.8	125.8	126.6	126.6	126.6
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	232.4	232.0	224.5	227.3	215.0
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**156.2**	**157.4**	**146.6**	**146.7**	**149.6**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**144.1**	**132.9**	**137.9**	**137.8**	**137.3**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**142.6**	**141.7**	**145.0**	**144.8**	**144.6**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**172.0**	**166.1**	**178.4**	**177.5**	**177.3**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	155.7	155.7	157.2	158.2	158.4
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	144.9	141.9	146.2	146.2	146.6
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	132.6	131.8	136.0	135.7	135.9
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	168.5	149.3	185.7	182.6	182.2
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	180.8	178.5	183.5	183.9	183.8
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	186.9	184.9	186.1	185.5	185.7
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	167.0	169.4	156.8	154.1	152.8
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	170.5	167.3	176.4	176.7	176.6
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	139.1	138.3	144.1	143.2	143.0
1.3.1.10 कोकोआ, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	160.6	155.2	176.4	178.7	177.3
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	156.7	150.8	158.7	159.7	160.6
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	190.7	205.9	199.9	201.7	198.9
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	192.6	191.6	189.8	189.4	190.6
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	152.7	151.9	156.5	156.2	156.6
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	185.1	184.6	187.2	189.4	187.8
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	204.1	207.4	199.0	199.6	200.8
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**134.1**	**133.5**	**135.4**	**135.6**	**135.2**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	136.0	135.1	138.9	138.7	138.3
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	138.7	138.2	140.0	139.4	140.1
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी का उत्पादन	0.275	127.5	127.3	126.6	127.8	126.4
1.3.3 तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण	**0.514**	**177.8**	**176.7**	**181.8**	**181.1**	**179.9**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	177.8	176.7	181.8	181.1	179.9

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2024-25	2024	2025		
			जुला	मई	जून (अ)	जुला (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**136.3**	**136.8**	**136.3**	**136.6**	**136.6**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	121.4	122.4	120.3	120.3	119.9
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	158.3	158.2	159.9	160.6	161.0
1.3.4.3 बुने हुए और क्रोशिए से बना कपड़ा	0.193	124.0	125.0	124.7	125.2	125.3
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	160.4	159.1	160.7	160.9	161.1
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	142.7	141.1	150.7	151.8	155.3
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	134.9	136.7	132.8	132.1	133.1
1.3.5 तैयार वस्त्र का विनिर्माण	**0.814**	**153.4**	**152.2**	**155.2**	**155.6**	**156.0**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर, तैयार वस्त्र (बुने हुए) का विनिर्माण	0.593	150.9	150.1	153.3	153.7	154.1
१.३.५.२ बुने हुए और क्रोशिए से बने वस्त्र	0.221	160.1	157.7	160.2	160.5	161.0
1.3.6 चमड़ा और संबंधित उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**125.3**	**124.4**	**127.6**	**127.6**	**127.6**
१.३.६.१ चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगाई	0.142	106.1	103.8	112.4	112.3	112.1
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और हार्नेस	0.075	142.5	141.9	141.1	141.3	141.0
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	129.7	129.4	131.2	131.2	131.3
१.३.७ लकड़ी व लकड़ी और कॉर्क के उत्पादों का विनिर्माण	**0.772**	**149.2**	**149.4**	**150.2**	**150.4**	**150.1**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	141.1	140.2	142.3	142.6	141.6
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड, लैमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड का विनिर्माण	0.493	148.6	149.0	149.3	149.4	149.3
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	215.3	215.6	215.4	215.4	215.3
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	140.6	141.2	142.5	143.3	142.7
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पादों का विनिर्माण	**1.113**	**139.2**	**138.5**	**140.1**	**140.5**	**139.8**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और पेपर बोर्ड	0.493	144.6	144.7	144.6	144.3	143.8
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	147.3	144.9	151.2	151.2	151.1
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	122.4	121.9	121.5	123.4	121.9
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**187.3**	**186.5**	**189.0**	**189.6**	**190.3**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	187.3	186.5	189.0	189.6	190.3
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	**6.465**	**136.5**	**136.7**	**137.2**	**137.2**	**137.0**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	138.6	137.6	142.3	141.8	141.2
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	143.1	143.4	143.3	143.0	142.9
1.3.10.3 प्लास्टिक और प्राथमिक रूप में सिंथेटिक रबड़	1.001	133.6	135.3	133.3	133.8	134.6
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	128.8	128.9	132.6	132.1	131.2
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	139.5	140.2	137.3	137.2	136.3
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	139.7	138.8	141.9	142.3	142.6
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	135.4	136.1	133.5	133.6	133.1
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	104.9	107.0	101.3	102.9	103.5
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**144.3**	**144.7**	**145.9**	**145.9**	**146.0**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	144.3	144.7	145.9	145.9	146.0
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	**2.299**	**129.0**	**129.1**	**129.3**	**129.4**	**129.1**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रिट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	115.6	114.6	116.0	115.9	115.2
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	112.1	112.9	113.5	113.2	114.3
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	138.1	138.5	138.0	138.3	137.9
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**131.5**	**130.0**	**133.6**	**133.2**	**133.5**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	163.2	163.4	163.6	163.6	163.5
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	121.6	118.8	123.4	123.1	123.7
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	124.4	119.0	133.5	131.0	129.3
1.3.13.4 चीनी मिट्टी और चीनी मिट्टी के उत्पाद	0.222	124.6	124.6	125.9	125.8	125.6
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	130.4	128.7	133.0	132.3	133.1

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2024-25	2024	2025		
			जुला	मई	जून (अ)	जुला (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	139.2	138.3	140.6	140.2	139.5
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	134.4	133.2	137.3	138.8	138.0
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	95.2	95.7	94.2	94.6	94.9
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**139.7**	**140.8**	**140.2**	**138.8**	**137.5**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	133.6	135.6	132.9	131.8	131.2
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	141.8	148.4	133.2	129.5	128.6
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	117.9	118.7	118.5	117.2	116.2
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	140.4	139.7	138.7	137.4	135.4
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	134.2	138.8	135.4	134.6	133.0
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	135.4	136.5	135.9	134.2	130.8
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील - अर्ध निर्मित	0.924	131.1	130.8	137.5	128.8	122.6
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	164.7	166.3	167.5	167.2	163.2
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	157.4	156.2	160.2	161.3	162.7
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	144.9	145.2	143.4	144.0	143.4
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	172.2	171.6	176.6	177.9	173.9
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**136.0**	**136.3**	**137.7**	**137.2**	**136.6**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	130.8	131.1	132.2	131.5	131.5
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	149.5	151.4	153.4	151.5	149.7
1.3.15.3 वाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	109.8	111.5	112.2	112.1	112.5
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैम्पिंग और रोल फॉरमिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	138.0	135.6	135.6	136.7	133.8
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	102.0	101.7	103.6	104.7	104.8
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	144.9	145.1	147.2	146.6	147.2
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**121.5**	**121.1**	**122.0**	**122.3**	**122.5**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	117.9	117.7	120.6	120.3	120.8
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	134.2	136.0	131.4	131.4	131.4
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	146.0	145.4	146.8	146.9	147.0
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	101.1	100.5	100.8	100.8	100.6
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	119.9	118.1	121.9	126.6	126.6
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	167.9	163.1	174.0	173.7	173.3
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	114.4	111.1	111.7	109.9	115.4
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	107.4	106.7	111.2	114.6	118.1
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**133.7**	**133.4**	**134.4**	**134.6**	**134.6**
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	132.3	131.1	132.9	133.0	132.7
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	141.3	141.7	144.4	144.3	144.8
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	118.6	120.7	115.5	114.5	115.7
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	154.4	154.4	157.6	158.2	158.6
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	118.4	119.0	118.4	118.5	118.2
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	131.8	132.1	129.8	130.1	130.4
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	123.4	123.3	125.9	126.0	125.5
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**130.8**	**130.5**	**131.9**	**132.3**	**132.3**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	132.8	133.0	135.1	136.6	136.6
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	134.5	134.5	134.6	134.4	134.8
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	118.5	118.2	119.5	119.5	120.2
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	128.5	128.0	129.0	130.7	130.0
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	86.6	86.7	88.1	87.9	88.2
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने – उतारने वाले उपकरण	0.285	130.0	130.3	131.2	131.0	131.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2024-25	2024	2025		
			जुला	मई	जून (अ)	जुला (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	145.3	146.8	144.9	143.8	141.8
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	145.5	143.5	146.8	146.8	146.4
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	123.2	122.7	126.0	126.2	127.4
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	89.8	89.0	92.5	92.9	93.0
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	126.1	126.0	126.3	126.3	128.0
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	141.4	139.3	138.9	139.6	139.6
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	144.9	145.3	145.8	146.9	147.5
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	69.2	69.7	69.2	69.4	69.4
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**129.9**	**130.0**	**130.6**	**130.5**	**130.7**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	130.6	130.8	131.1	131.0	131.2
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	129.1	129.2	130.0	130.0	130.1
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**145.2**	**144.6**	**149.7**	**150.4**	**151.1**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली – वस्तुओं का निर्माण	0.117	180.5	177.9	190.7	190.7	190.7
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	108.9	109.8	109.7	109.8	110.0
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	146.0	145.3	150.6	151.3	152.1
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	134.9	136.0	136.7	137.1	138.2
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	163.2	160.2	165.9	165.8	165.9
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**160.3**	**158.7**	**163.6**	**163.8**	**164.8**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	160.3	158.7	163.6	163.8	164.8
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**183.8**	**178.8**	**219.3**	**224.3**	**226.8**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	185.4	180.0	223.2	228.6	231.1
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	201.9	200.0	202.1	204.3	204.3
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	164.9	163.0	171.0	171.4	171.9
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	163.1	162.2	162.4	162.6	160.2
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और संबंधित सामग्री	0.049	158.6	158.6	158.6	157.6	162.1
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**192.9**	**195.5**	**189.9**	**190.2**	**191.3**

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)

उद्योग	भार	2023-24	2024-25	अप्रै.-जून		जून	
				2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	146.7	152.6	151.2	154.2	151.0	153.3
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	128.9	132.8	134.1	130.1	134.9	123.2
1.2 विनिर्माण	77.63	144.7	150.6	147.2	152.2	146.6	152.3
1.3 बिजली	7.99	198.3	208.6	221.4	217.1	222.8	217.1
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	147.7	153.5	156.4	153.9	156.0	151.3
2.2 पूंजीगत माल	8.22	106.6	112.6	103.9	114.3	111.3	115.2
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	157.3	164.0	159.8	167.8	159.1	167.9
2.4 इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं	12.34	176.3	188.2	185.1	196.7	184.9	198.3
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	118.6	128.0	125.6	128.9	127.1	130.8
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	153.7	151.4	150.0	148.0	145.2	144.6

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खजाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(₹ करोड़)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - जून			
	2025-26 (संशोधित अनुमान)	2025-26 (वास्तविक आंकड़े)	2024-25 (वास्तविक आंकड़े)	बजट अनुमानों का प्रतिशत	
				2025-26	2024-25
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**3420409**	**913377**	**829677**	**26.7**	**26.5**
1.1 कर राजस्व (निवल)	2837409	540316	549633	19.0	21.3
1.2 करेतर राजस्व	583000	373061	280044	64.0	51.3
2 गैर कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां	**76000**	**28018**	**4520**	**36.9**	**5.8**
2.1 ऋण की वसूली	29000	5395	4516	18.6	16.1
2.2 अन्य प्राप्तियां	47000	22623	4	48.1	0.0
3 कुल प्राप्तियां (लिए गए उधार को छोड़कर) (1+2)	**3496409**	**941395**	**834197**	**26.9**	**26.0**
4 राजस्व व्यय जिसमें से :	3944255	946995	788858	24.0	21.3
4.1 ब्याज भुगतान	1276338	386037	264052	30.2	22.7
5 पूंजी व्यय	1121090	275132	181051	24.5	16.3
6 कुल व्यय (4+5)	**5065345**	**1222127**	**969909**	**24.1**	**20.1**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**523846**	**33618**	**-40819**	**6.4**	**-7.0**
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	**1568936**	**280732**	**135712**	**17.9**	**8.4**
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	**292598**	**-105305**	**-128340**	**-36.0**	**-28.5**

स्रोत: महालेखानियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2024-25	2024	2025					
		जून 28	मई 23	मई 30	जून 6	जून 13	जून 20	जून 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	26554	10411	21845	22722	19435	19575	18639	18898
1.2 प्राथमिक व्यापारी	25258	24135	34187	36058	37041	25717	21671	18582
1.3 राज्य सरकारें	40315	46310	64691	62591	59491	64991	71291	80904
1.4 अन्य	115688	88554	101268	92319	89624	96108	96090	95120
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	44887	54590	53966	50567	50446	49643	51017	49943
2.2 प्राथमिक व्यापारी	62218	66312	59786	61807	61074	60332	55998	57055
2.3 राज्य सरकारें	11078	14592	10688	11688	13688	16888	18888	16888
2.4 अन्य	104994	123098	89848	90226	90580	91925	93886	92901
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	72304	92592	71496	69501	72281	70431	71580	71571
3.2 प्राथमिक व्यापारी	86939	143140	74280	73306	72817	73170	74466	76439
3.3 राज्य सरकारें	37389	38191	46232	46344	46279	46093	44898	45967
3.4 अन्य	162757	156268	156223	160193	158903	161399	160754	159789
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	188072	204835	146825	134728	126187	161628	156490	155018
4.4 अन्य	572	592	879	2166	1244	150	1297	428
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	790381	858193	784511	777323	771658	776272	779176	784059

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियाँ			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य (₹)	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2025-26										
मई 28	9000	102	30939	2819	37	8981	2819	11800	98.62	5.6200
जून 4	9000	125	43277	4524	33	8976	4524	13500	98.63	5.5796
जून 11	9000	132	33117	7520	42	8980	7520	16500	98.68	5.3694
जून 18	9000	133	36084	6320	46	8980	6320	15300	98.68	5.3575
जून 25	9000	126	26870	11516	66	8984	11516	20500	98.67	5.4094
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2025-26										
मई 28	5000	73	24766	2018	17	4982	2018	7000	97.27	5.6287
जून 4	5000	71	21002	4007	17	4993	4007	9000	97.28	5.5998
जून 11	5000	72	12546	5215	39	4985	5215	10200	97.36	5.4334
जून 18	5000	89	23389	2810	36	4990	2810	7800	97.35	5.4575
जून 25	5000	93	15026	6	50	4994	6	5000	97.31	5.5350
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2025-26										
मई 28	5000	110	29969	175	18	4948	175	5123	94.69	5.6288
जून 4	5000	77	24942	74	24	4943	74	5017	94.71	5.5995
जून 11	5000	61	10620	127	45	4957	127	5083	94.80	5.5000
जून 18	5000	94	24305	1037	31	4983	1037	6020	94.80	5.5000
जून 25	5000	87	19867	1531	45	4981	1531	6512	94.74	5.5687

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा	भारित औसत दरें
	उधार लेना / उधार देना	उधार लेना / उधार देना
	1	2
जून 02 ,2025	4.85-5.85	5.79
जून 03 ,2025	4.85-6.65	5.77
जून 04 ,2025	4.85-5.85	5.75
जून 05 ,2025	4.85-5.85	5.75
जून 06 ,2025	4.85-5.50	5.42
जून 09 ,2025	4.75-5.40	5.30
जून 10 ,2025	4.75-5.35	5.30
जून 11 ,2025	4.80-5.35	5.30
जून 12 ,2025	4.35-5.40	5.29
जून 13 ,2025	4.75-5.36	5.31
जून 16 ,2025	4.75-5.35	5.30
जून 17 ,2025	4.50-5.35	5.26
जून 18 ,2025	4.75-5.35	5.27
जून 19 ,2025	4.70-5.35	5.26
जून 20 ,2025	4.75-5.35	5.27
जून 21 ,2025	4.50-5.30	5.04
जून 23 ,2025	4.75-5.35	5.27
जून 24 ,2025	4.75-5.35	5.27
जून 25 ,2025	4.75-5.35	5.29
जून 26 ,2025	4.75-5.35	5.27
जून 27 ,2025	4.75-5.60	5.38
जून 30 ,2025	4.75-5.70	5.50
जुला 01 ,2025	4.75-5.40	5.31
जुला 02 ,2025	4.70-5.35	5.27
जुला 03 ,2025	4.75-5.35	5.26
जुला 04 ,2025	4.75-5.35	5.26
जुला 05 ,2025	4.70-5.30	4.91
जुला 07 ,2025	4.75-5.35	5.26
जुला 08 ,2025	4.50-5.35	5.26
जुला 09 ,2025	4.80-5.45	5.32
जुला 10 ,2025	4.75-5.45	5.35
जुला 11 ,2025	4.75-5.55	5.45
जुला 14 ,2025	4.75-5.40	5.31
जुला 15 ,2025	4.75-5.50	5.38

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा शामिल

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2024	2025			
	जुला 26	जून 13	जून 27	जुला 11	जुला 25
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	424747.21	483064.43	517439.00	525253.75	508451.73
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (₹ करोड़)	23643.34	40924.08	85607.74	18575.50	18550.54
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	7.02-7.26	5.65-7.04	5.77-6.63	5.67-6.49	5.59-6.63

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2024	2025					
	जून 30	मई 15	मई 31	जून 15	जून 30	जुला 15	जुला 31
	1	2	3	4	5	6	7
1 बकाया राशि (र करोड़)	422447.45	541591.10	553874.25	549258.30	500000.60	534009.15	547229.30
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (₹ करोड़)	56023.85	48973.55	81053.80	102447.00	58021.75	79530.05	73858.50
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.99-15.06	6.44-10.14	5.97-12.23	5.67-11.63	5.71-13.84	5.51-12.67	5.57-13.84

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(₹ करोड़)

मद	2024-25	2024	2025					
		जून 28	मई 23	मई 30	जून 6	जून 13	जून 20	जून 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	18990	23962	29606	26805	23489	31335	24157	28538
2 नोटिस मुद्रा	2506	3722	231	6439	209	219	6749	307
3 मीयादी मुद्रा	941	613	2302	1687	785	1951	903	990
4 त्रिपक्षीय रेपो	692068	799629	666649	824530	659923	784601	802836	702250
5 बाजार रेपो	578912	663566	607184	719036	597129	759880	763218	632175
6 कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो	5212	3558	6682	6308	5913	9944	9639	8409
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	131877	135891	125401	140910	136313	128179	118707	165416
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	56065	107938	153621	131774	109308	168382	132864	121551
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	3971	9999	12737	7015	12804	6683	5182	4910
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	2514	8036	4847	6333	5534	6572	6647	3997
10.2 182-दिवसीय	2218	5128	6110	2619	3721	7784	4672	3436
10.3 364-दिवसीय	1854	4984	4542	3368	3377	3940	3093	1967
10.4 नकदी प्रबंधन बिल		0	0	0	0	0	0	0
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	66622	136084	181858	151109	134743	193361	152459	135862
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	1715	948	4324	54	850	769	816	596

सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2024-25		2024-25 (अप्रै.-जून)		2025-26 (अप्रै.-जून) *		जून 2024		जून 2025 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**464**	**210190**	**112**	**41280**	**73**	**23059**	**38**	**3571**	**40**	**15867**
1.1 पब्लिक	322	190478	75	36381	45	15464	22	2521	24	9526
1.2 राइट्स	142	19712	37	4899	28	7594	16	1051	16	6341
2 बॉण्ड और डिबेंचर के सार्वजनिक निर्गम	**43**	**8149**	**10**	**2454**	**9**	**1436**	**3**	**560**	**1**	**83**
3 कुल (1+2)	**507**	**218339**	**122**	**43734**	**82**	**24495**	**41**	**4131**	**41**	**15951**
3.1 पब्लिक	365	198627	85	38835	54	16900	25	3081	25	9609
3.2 राइट्स	142	19712	37	4899	28	7594	16	1051	16	6341

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।
2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़े कुल में न जुड़ पाने की संभावना है।
3. सारणी में केवल इक्विटी और ऋण के पब्लिक और राइट्स निर्गम शामिल हैं। इसमें ऋण के निजी प्लेसमेंट, पात्र संस्थागत प्लेसमेंट और अधिमान्य आवंटन के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम है।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31 : विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2024-25	2024	2025				
			जून	फर	मार्च	अप्रै	मई	जून
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	₹ करोड़	3701070	293505	320532	363598	328021	327855	301901
	यूएस $ मिलियन	437416	35163	36820	41968	38338	38485	35144
1.1 तेल	₹ करोड़	534917	45821	49785	42467	61423	47820	39650
	यूएस $ मिलियन	63341	5489	5719	4902	7179	5613	4616
1.2 तेल से इतर	₹ करोड़	3166153	247684	270747	321131	266598	280035	262251
	यूएस $ मिलियन	374075	29673	31101	37066	31159	32872	30529
2 आयात	₹ करोड़	6089909	467413	443663	550211	555329	516260	463159
	यूएस $ मिलियन	720241	55997	50964	63507	64904	60601	53916
2.1 तेल	₹ करोड़	1570226	125703	103528	164684	177212	125635	118534
	यूएस $ मिलियन	185779	15060	11892	19008	20712	14748	13799
2.2 तेल से इतर	₹ करोड़	4519683	341709	340135	385527	378117	390624	344624
	यूएस $ मिलियन	534462	40938	39071	44499	44193	45853	40118
3 व्यापार शेष	₹ करोड़	-2388839	-173907	-123131	-186613	-227308	-188405	-161257
	यूएस $ मिलियन	-282825	-20834	-14144	-21539	-26567	-22116	-18772
3. 1 तेल	₹ करोड़	-1035309	-79882	-53743	-122217	-115789	-77815	-78884
	यूएस $ मिलियन	-122438	-9570	-6173	-14107	-13533	-9134	-9183
3. 2 तेल से इतर	₹ करोड़	-1353530	-94025	-69388	-64395	-111519	-110590	-82373
	यूएस $ मिलियन	-160387	-11264	-7971	-7433	-13034	-12982	-9589

टिप्पणी: सारणी में डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय

सं. 32: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

मद	इकाई	2024	2025					
		अग 02	जून 20	जून 27	जुला 04	जुला 11	जुला 18	जुला 25
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल आरक्षित निधियां	**₹ करोड़**	**5652457**	**6043697**	**6007745**	**5975266**	**5978149**	**5992373**	**6040880**
	यूएस $ मिलियन	**674919**	**697935**	**702784**	**699736**	**696672**	**695489**	**698192**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	₹ करोड़	4958347	5100971	5084809	5049185	5052566	5062860	5095487
	यूएस $ मिलियन	592039	589069	594823	591287	588810	587609	588926
1.2 स्वर्ण	₹ करोड़	503330	742482	722374	724528	723791	728042	741528
	यूएस $ मिलियन	60099	85743	84504	84846	84348	84499	85704
	मात्रा (मीट्रिक टन)	846.18	879.58	879.98	879.98	879.98	879.98	879.98
1.3 एसडीआर	एसडीआर मिलियन	13699	13707	13707	13707	13707	13707	13707
	₹ करोड़	152096	161685	160963	161120	161343	160975	162741
	यूएस $ मिलियन	18161	18672	18830	18868	18802	18683	18809
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	₹ करोड़	38685	38559	39598	40432	40448	40496	41125
	यूएस $ मिलियन	4620	4452	4628	4735	4711	4698	4753

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन की वजह से है।
टिप्पणी : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और नेक्सस ग्लोबल पेमेंट्स के वित्तपोषण के लिए आरबीआई का योगदान शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा को आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2024-25	2024	2025		2024-25	2025-26
		जून	मई	जून (अ)	अप्रै.-जून	अप्रै.-जून (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियाँ	**164677**	**155782**	**166720**	**168327**	**4025**	**3614**
1.1 एफसीएनआर (बी)	32809	27414	33252	33583	1681	774
1.2 एनआर (ई) आरए	100733	100111	101862	102750	1582	1991
1.3 एनआरओ	31135	28257	31606	31993	762	850

अ: अनंतिम।

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2024-25	2024-25	2025-26 (अ)	2024 (अ)	2025 (अ)	
		अप्रै.-जून	अप्रै.-जून	जून	मई	जून
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**959**	**6224**	**4916**	**2242**	**-5**	**1075**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.1.2)	**29130**	**10606**	**12789**	**3557**	**2159**	**3554**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह / सकल निवेश	**80615**	**22777**	**25178**	**7615**	**7173**	**9261**
1.1.1.1.1 इक्विटी	50993	16402	18852	5489	5232	6987
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	2208	209	1360	118	60	1004
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	34686	11764	13527	3244	3494	5337
1.1.1.1.1.3 शेयरों का अधिग्रहण	13124	4205	3740	2052	1603	571
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	975	224	224	75	75	75
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	22759	5225	5225	1742	1742	1742
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	6863	1151	1101	384	200	533
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	**51486**	**12171**	**12389**	**4057**	**5014**	**5707**
1.1.1.2.1 इक्विटी	49525	11673	11991	3891	4855	5623
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	1960	498	398	166	159	84
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**28171**	**4382**	**7872**	**1316**	**2165**	**2479**
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	16945	2728	4396	844	655	1919
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	6846	1712	1712	571	571	571
1.1.2.3 अन्य पूंजी	7955	1090	2405	283	1006	445
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	3575	1147	640	382	67	455
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**3564**	**945**	**847**	**5449**	**1554**	**2390**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	3283	897	1638	5433	1700	2378
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	-281	-48	791	-16	146	-12
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**4523**	**7168**	**5763**	**7690**	**1549**	**3465**

अ: अनंतिम।

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2024-25	2024	2025		
		जून	अप्रै	मई	जून
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**29563.12**	**2181.85**	**2481.41**	**2313.16**	**2127.39**
1.1 जमाराशियाँ	705.26	39.02	94.15	54.65	42.12
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	322.82	18.77	44.69	41.69	37.75
1.3 इक्विटी / कर्ज में निवेश	1698.94	120.22	203.44	104.94	206.12
1.4 उपहार	2938.69	228.81	290.89	233.30	190.51
1.5 दान	11.81	2.01	1.57	1.98	1.26
1.6 यात्रा	16964.57	1275.63	1270.44	1389.23	1235.17
1.7 निकट संबंधियों से संबंधित खर्चे	3722.03	270.72	397.97	322.54	262.97
1.8 चिकित्सा उपचार	81.19	6.42	5.08	6.72	5.59
1.9 विदेश में शिक्षा	2918.91	177.07	163.56	149.78	138.76
1.10 अन्य	198.90	43.19	9.61	8.32	7.15

सं. 36: भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक

मद	2023-24	2024-25	2024	2025	
			जुला	जून	जुला
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा समूह (आधार: 2015-16 = 100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	90.75	91.02	91.91	86.94	86.57
1.2 रीर	103.71	105.26	107.42	99.68	100.07
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.13	93.52	94.38	89.08	88.63
2. 2 रीर	101.22	102.34	104.45	97.08	97.34
6- मुद्रा समूह (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16 =100					
1.1 नीर	83.62	82.38	83.39	79.06	78.58
1.2 रीर	101.66	102.72	104.42	98.05	98.35
2 आधार : 2022-23 = 100					
2.1 नीर	97.31	95.87	97.04	92.01	91.44
2.2 रीर	99.86	100.90	102.57	96.31	96.60

नोट: 2024-25 और 2025-26 के लिए अब तक का डेटा अनंतिम है।

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन यूएस$ में)

मद	2024-25	2024	2025	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1328	121	100	112
1.2 राशि	47800	1811	2739	2733
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	51	4	0	1
2.2 राशि	13384	1005	0	750
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1379	125	100	113
3.2 राशि	61184	2816	2739	3483
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.05	5.80	4.80	4.90
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 अस्थिर दर के ऋणों@ के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर पर भारित औसत मार्जिन	1.48	1.36	1.46	1.70
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-11.67	0.00-11.00	0.00-10.00	0.00-10.50
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉरपोरेट विनिर्माण	13900	603	1201	954
II. कॉरपोरेट - बुनियादी संरचना	15462	808	717	1819
ए) परिवहन	614	0	0	5
बी) ऊर्जा	6900	745	0	155
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	28	27	0	0
डी) संचार	13	0	0	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	184	17	1	7
एफ) अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी	5356	19	305	0
जी) अन्य उप-क्षेत्र	2367	0	411	1652
III. कॉरपोरेट सेवा क्षेत्र	3226	37	242	19
IV. अन्य संस्थाएं	1026	19	0	0
ए) एसईज़ेड में इकाई	26	19	0	0
बी) सिडबी	0	0	0	0
सी) एक्जिम बैंक	1000	0	0	0
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी के अलावा)	0	0	0	0
VII. एनबीएफसी	26318	1311	566	682
ए) एनबीएफसी - आईएफसी / एएफसी	12389	1062	0	97
बी) एनबीएफसी - एमएफआई	459	38	86	18
सी) एनबीफसी - अन्य	13470	211	480	567
VIII. गैर -सरकारी संगठन (एनजीओ)	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
X. अन्य	1252	38	13	9

टिप्पणी: ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों के आधार पर जिन्हें निर्धारित अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की गई है।
@ 01 जुलाई, 2023 से लागू, बेंचमार्क दर को बदलकर वैकल्पिक संदर्भ दर कर दिया गया है।

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	जन.- मार्च 2024			जन.- मार्च 2024 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**502221**	**471468**	**30754**	**521618**	**512829**	**8789**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**253534**	**248967**	**4567**	**264919**	**251469**	**13451**
1.1 पण्य	**121626**	**173645**	**-52019**	**116283**	**175762**	**-59478**
1.2 अप्रत्यक्ष मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**131908**	**75322**	**56586**	**148636**	**75707**	**72929**
1.2.1 सेवाएं	89356	46672	42684	102019	48711	53308
1.2.1.1 यात्रा	9961	8063	1898	9097	7934	1162
1.2.1.2 परिवहन	7771	7829	-58	8151	8385	-234
1.2.1.3 बीमा	927	650	277	886	762	124
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	129	315	-186	165	330	-165
1.2.1.5 विविध	70568	29814	40753	83720	31299	52421
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	41551	4908	36643	46917	5434	41483
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	22620	16388	6232	29432	16221	13212
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1599	1269	330	1989	795	1193
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	498	506	-7	731	533	198
1.2.2 अंतरण	32097	3378	28719	34717	3214	31504
1.2.2.1 आधिकारिक	51	282	-231	31	376	-345
1.2.2.2 निजी	32046	3096	28950	34686	2838	31848
1.2.3 आय	10455	25272	-14817	11900	23782	-11882
1.2.3.1 निवेश आय	8523	24233	-15710	9873	22750	-12877
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1932	1039	893	2027	1032	995
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**248044**	**222501**	**25543**	**255786**	**261361**	**-5574**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**159056**	**145366**	**13691**	**144464**	**149956**	**-5492**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	20179	17881	2299	18494	18127	366
2.1.1.1 भारत में	19474	11411	8063	17527	7474	10053
2.1.1.1.1 इक्विटी	12762	10934	1829	9610	7199	2411
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	5332		5332	6165		6165
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1379	477	902	1751	275	1476
2.1.1.2 विदेश में	706	6470	-5764	967	10653	-9686
2.1.1.1.1 इक्विटी	706	3208	-2503	967	6321	-5354
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	0	1446	-1446	0	1712	-1712
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	0	1815	-1815	0	2620	-2620
2.1.2 संविभाग निवेश	138877	127485	11392	125970	131829	-5859
2.1.2.1 भारत में	138217	126638	11579	124923	130917	-5995
2.1.2.1.1 एफआईआई	138217	126638	11579	124923	130917	-5995
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	120784	119426	1358	101683	115225	-13541
2.1.2.1.1.2 ऋण	17432	7212	10221	23239	15693	7547
2.1.2.1.2 एडीआर / जीडीआर	0		0	0		0
2.1.2.2 विदेश में	660	847	-187	1048	912	136
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**31787**	**27899**	**3888**	**56056**	**50511**	**5544**
2.2.1 बाह्य सहायता	3587	1562	2025	3712	1641	2071
2.2.1.1 भारत द्वारा	8	31	-23	6	25	-19
2.2.1.2 भारत को	3579	1531	2048	3706	1616	2090
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	15121	13472	1649	38786	30910	7876
2.2.2.1 भारत द्वारा	3401	4308	-907	23141	22668	473
2.2.2.2 भारत को	11719	9164	2555	15645	8242	7403
2.2.3 भारत को अल्पावधि	13079	12865	214	13558	17961	-4403
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	12000	12865	-865	13558	16205	-2647
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	1079	0	1079	0	1755	-1755
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**40722**	**33811**	**6911**	**33573**	**42550**	**-8977**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	39768	33811	5957	33573	42331	-8758
2.3.1.1 आस्तियां	9220	12330	-3110	6486	17652	-11166
2.3.1.2 देयताएं	30548	21481	9067	27087	24678	2408
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	26041	20678	5363	26288	23458	2830
2.3.2 अन्य	955	0	955	0	219	-219
2.4 रुपया कर्ज चुकौती		**7**	**-7**		**7**	**-7**
2.5 अन्य पूंजी	**16479**	**15418**	**1060**	**21694**	**18336**	**3358**
3 भूल-चक	**643**	**0**	**643**	**912**	**0**	**912**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	**0**	**30754**	**-30754**	**0**	**8789**	**-8789**
4.1 आई.एम.एफ.	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)		30754	-30754		8789	-8789

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	जन.-मार्च 2024			जन.-मार्च 2025 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**4169814**	**3914475**	**255339**	**4519960**	**4443804**	**76155**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**2105027**	**2067106**	**37921**	**2295597**	**2179044**	**116553**
1.1 पण्य	**1009832**	**1441729**	**-431897**	**1007628**	**1523023**	**-515395**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**1095194**	**625377**	**469817**	**1287969**	**656021**	**631948**
1.2.1 सेवाएं	741899	387502	354397	884018	422093	461925
1.2.1.1 यात्रा	82705	66948	15758	78826	68754	10072
1.2.1.2 परिवहन	64519	65002	-483	70629	72660	-2031
1.2.1.3 बीमा	7698	5395	2303	7675	6603	1071
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	1073	2616	-1543	1432	2860	-1429
1.2.1.5 विविध	585904	247541	338363	725457	271215	454242
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	344986	40752	304234	406549	47084	359465
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	187807	136067	51740	255039	140555	114484
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	13280	10537	2743	17232	6892	10339
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4136	4197	-61	6333	4618	1715
1.2.2 अंतरण	266491	28049	238442	300834	27848	272987
1.2.2.1 आधिकारिक	423	2344	-1921	273	3259	-2986
1.2.2.2 निजी	266068	25705	240363	300561	24588	275973
1.2.3 आय	86804	209826	-123022	103117	206080	-102963
1.2.3.1 निवेश आय	70763	201199	-130436	85554	197135	-111581
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	16041	8627	7414	17563	8945	8618
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**2059444**	**1847368**	**212076**	**2216458**	**2264761**	**-48303**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**1320601**	**1206932**	**113669**	**1251821**	**1299413**	**-47592**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	167544	148458	19086	160253	157078	3175
2.1.1.1 भारत में	161684	94741	66943	151875	64767	87108
2.1.1.1.1 इक्विटी	105963	90780	15183	83277	62383	20894
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	44274	0	44274	53422	0	53422
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	11447	3960	7487	15176	2384	12792
2.1.1.2 विदेश में	5860	53718	-47858	8378	92311	-83933
2.1.1.2.1 इक्विटी	5860	26638	-20778	8378	54774	-46396
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	12009	-12009	0	14831	-14831
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	15071	-15071	0	22706	-22706
2.1.2 संविभाग निवेश	1153057	1058474	94583	1091568	1142335	-50767
2.1.2.1 भारत में	1147577	1051439	96139	1082489	1134435	-51945
2.1.2.1.1 एफआईआई	1147577	1051439	96139	1082489	1134435	-51945
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	1002841	991563	11278	881113	998454	-117341
2.1.2.1.1.2 ऋण	144736	59875	84861	201376	135981	65395
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	5480	7035	-1555	9079	7900	1178
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**263920**	**231641**	**32279**	**485737**	**437694**	**48043**
2.2.1 बाह्य सहायता	29784	12969	16816	32166	14220	17945
2.2.1.1 भारत द्वारा	66	255	-188	52	217	-166
2.2.1.2 भारत को	29718	12714	17004	32114	14003	18111
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	125543	111856	13688	336088	267839	68248
2.2.2.1 भारत द्वारा	28241	35769	-7528	200522	196420	4102
2.2.2.2 भारत को	97302	76086	21216	135565	71419	64146
2.2.3 भारत को अल्पावधि	108592	106817	1775	117484	155634	-38150
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	99631	106817	-7185	117484	140424	-22940
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	8961	0	8961	0	15210	-15210
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**338106**	**280721**	**57384**	**290917**	**368705**	**-77788**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	330180	280721	49459	290917	366806	-75889
2.3.1.1 आस्तियां	76548	102370	-25822	56203	152962	-96758
2.3.1.2 देयताएं	253632	178351	75281	234713	213844	20870
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	216214	171683	44531	227792	203268	24524
2.3.2 अन्य	7926	0	7926	0	1899	-1899
2.4 रुपया ऋण चुकौती	**0**	**60**	**-60**	**0**	**62**	**-62**
2.5 अन्य पूंजी	**136818**	**128013**	**8804**	**187982**	**158886**	**29096**
3 भूल-चूक	**5343**	**0**	**5343**	**7905**	**0**	**7905**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	**0**	**255339**	**-255339**	**0**	**76155**	**-76155**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	255339	-255339	0	76155	-76155

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन यूएस $)

मद	जन.-मार्च 2024			जन.-मार्च 2025 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	**253531**	**248945**	**4586**	**264919**	**251439**	**13480**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**210982**	**220317**	**-9334**	**218302**	**224473**	**-6171**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**121626**	**173645**	**-52019**	**116283**	**175762**	**-59478**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	121327	164054	-42727	116068	166261	-50193
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	300	0	300	216	0	216
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		9591	-9591		9501	-9501
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**89356**	**46672**	**42684**	**102019**	**48711**	**53308**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	352	18	335	280	46	235
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	55	456	-401	98	292	-193
1.अ.ख.3 परिवहन	7771	7829	-58	8151	8385	-234
1.अ.ख.4 यात्रा	9961	8063	1898	9097	7934	1162
1.अ.ख.5 निर्माण	1658	791	867	1553	820	733
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	927	650	277	886	762	124
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1599	1269	330	1989	795	1193
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	319	3365	-3046	376	4358	-3981
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	42137	5707	36430	47738	6309	41430
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	22620	16388	6232	29432	16221	13212
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	1253	1496	-243	1270	1470	-199
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	129	315	-186	165	330	-165
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	575	324	251	983	990	-7
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**10455**	**25272**	**-14817**	**11900**	**23782**	**-11882**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1932	1039	893	2027	1032	995
1.आ.2 निवेश आय	6758	23555	-16797	7800	22296	-14497
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	2518	13929	-11411	2743	13132	-10389
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	94	2383	-2289	110	1937	-1827
1.आ.2.3 अन्य निवेश	874	7015	-6141	846	7048	-6203
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	3272	229	3043	4101	179	3923
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1765	678	1087	2074	454	1620
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**32093**	**3356**	**28737**	**34717**	**3184**	**31532**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	32046	3096	28950	34686	2838	31848
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	31301	2324	28977	33936	2096	31839
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	745	772	-27	750	741	9
1.इ.2 सामान्य सरकार	48	260	-212	31	347	-316
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**182**	**138**	**44**	**198**	**279**	**-81**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	21	50	-30	16	112	-96
2.2 पूँजी अंतरण	161	87	74	182	166	16
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**247865**	**253139**	**-5274**	**255589**	**269900**	**-14311**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**20179**	**17881**	**2299**	**18494**	**18127**	**366**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	19474	11411	8063	17527	7474	10053
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	18095	10934	7161	15776	7199	8576
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	12762	10934	1829	9610	7199	2411
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	5332		5332	6165		6165
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1379	477	902	1751	275	1476
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1379	477	902	1751	275	1476
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	706	6470	-5764	967	10653	-9686
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	706	4655	-3949	967	8033	-7066
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	706	3208	-2503	967	6321	-5354
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		1446	-1446		1712	-1712
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1815	-1815	0	2620	-2620
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1815	-1815		2620	-2620
3.2 संविभाग निवेश	**138877**	**127485**	**11392**	**125970**	**131829**	**-5859**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	138217	126638	11579	124923	130917	-5995
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	120784	119426	1358	101683	115225	-13541
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	17432	7212	10221	23239	15693	7547
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	660	847	-187	1048	912	136
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**6126**	**9280**	**-3154**	**4928**	**12389**	**-7461**
3.4 अन्य निवेश	**82683**	**67739**	**14944**	**106197**	**98766**	**7430**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	26996	20678	6318	26288	23677	2611
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज मूवमेंट; एनआरजी)	955	0	955	0	219	-219
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	26041	20678	5363	26288	23458	2830
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	32434	28167	4267	49782	51423	-1641
3.4.3अ भारत को ऋण	29025	23828	5197	26636	28731	-2095
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	3409	4339	-929	23147	22693	454
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	54	85	-31	56	630	-574
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	13079	12865	214	13558	17961	-4403
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	10120	5945	4175	16512	5076	11437
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0			0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**30754**	**-30754**	**0**	**8789**	**-8789**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए			0			0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए			0			0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	30754	-30754	0	8789	-8789
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**247865**	**253139**	**-5274**	**255589**	**269900**	**-14311**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	146425	145227	1198	124457	144387	-19929
4.2 ऋण लिखत	91320	71214	20107	114619	111649	2970
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	10120	36698	-26578	16512	13864	2648
5. निवल भूल-चूक	**643**	**0**	**643**	**912**	**0**	**912**

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़)

मद	जन.-मार्च 2024			जन.-मार्च 2025 (प्रा)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	**2104999**	**2066922**	**38077**	**2295593**	**2178790**	**116804**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**1751732**	**1829231**	**-77500**	**1891646**	**1945116**	**-53470**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**1009832**	**1441729**	**-431897**	**1007628**	**1523023**	**-515395**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	1007344	1362098	-354753	1005759	1440693	-434934
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	2488	0	2488	1868	0	1868
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	79632	-79632	0	82330	-82330
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**741899**	**387502**	**354397**	**884018**	**422093**	**461925**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	2923	146	2778	2429	397	2032
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	455	3786	-3331	852	2528	-1676
1.अ.ख.3 परिवहन	64519	65002	-483	70629	72660	-2031
1.अ.ख.4 यात्रा	82705	66948	15758	78826	68754	10072
1.अ.ख.5 निर्माण	13763	6567	7196	13459	7104	6355
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	7698	5395	2303	7675	6603	1071
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	13280	10537	2743	17232	6892	10339
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	2648	27942	-25294	3261	37760	-34499
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	349851	47384	302467	413664	54665	358999
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	187807	136067	51740	255039	140555	114484
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	10404	12421	-2016	11007	12735	-1729
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	1073	2616	-1543	1432	2860	-1429
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	4771	2691	2081	8514	8579	-64
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**86804**	**209826**	**-123022**	**103117**	**206080**	**-102963**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	16041	8627	7414	17563	8945	8618
1.आ.2 निवेश आय	56107	195572	-139465	67585	193203	-125618
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	20904	115646	-94742	23767	113792	-90025
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	782	19786	-19004	951	16786	-15835
1.आ.2.3 अन्य निवेश	7255	58240	-50985	7328	61075	-53747
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	27166	1900	25266	35540	1549	33990
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	14656	5627	9029	17969	3932	14037
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**266464**	**27865**	**238599**	**300830**	**27593**	**273237**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	266068	25705	240363	300561	24588	275973
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	259885	19295	240591	294061	18164	275897
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	6183	6410	-227	6501	6424	76
1.इ.2 सामान्य सरकार	396	2160	-1764	269	3005	-2736
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**1509**	**1144**	**364**	**1714**	**2414**	**-699**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	171	419	-248	136	971	-835
2.2 पूँजी अतंरण	1338	725	613	1578	1443	135
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**2057963**	**2101748**	**-43785**	**2214747**	**2338757**	**-124010**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**167544**	**148458**	**19086**	**160253**	**157078**	**3175**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	161684	94741	66943	151875	64767	87108
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	150237	90780	59457	136699	62383	74316
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	105963	90780	15183	83277	62383	20894
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	44274	0	44274	53422	0	53422
3.1.अ.2 ऋण लिखत	11447	3960	7487	15176	2384	12792
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	11447	3960	7487	15176	2384	12792
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	5860	53718	-47858	8378	92311	-83933
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	5860	38647	-32787	8378	69605	-61227
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	5860	26638	-20778	8378	54774	-46396
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	12009	-12009	0	14831	-14831
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	15071	-15071	0	22706	-22706
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	15071	-15071	0	22706	-22706
3.2 संविभाग निवेश	**1153057**	**1058474**	**94583**	**1091568**	**1142335**	**-50767**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	1147577	1051439	96139	1082489	1134435	-51945
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1002841	991563	11278	881113	998454	-117341
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	144736	59875	84861	201376	135981	65395
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	5480	7035	-1555	9079	7900	1178
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**50865**	**77053**	**-26187**	**42703**	**107351**	**-64648**
3.4 अन्य निवेश	**686496**	**562423**	**124073**	**920223**	**855837**	**64386**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	224139	171683	52457	227792	205167	22625
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज मूवमेंट; एनआरजी)	7926	0	7926	0	1899	-1899
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	216214	171683	44531	227792	203268	24524
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	269294	233863	35431	431378	445598	-14220
3.4.3अ भारत को ऋण	240986	197839	43147	230804	248960	-18156
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	28307	36024	-7717	200574	196638	3936
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	448	704	-257	484	5456	-4972
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	108592	106817	1775	117484	155634	-38150
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	84023	49357	34667	143085	43982	99102
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**255339**	**-255339**	**0**	**76155**	**-76155**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	255339	-255339	0	76155	-76155
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**2057963**	**2101748**	**-43785**	**2214747**	**2338757**	**-124010**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	1215731	1205783	9948	1078457	1251149	-172693
4.2 ऋण लिखत	758209	591269	166940	993206	967470	25736
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	84023	304696	-220673	143085	120138	22947
5. निवल भूल-चूक	**5343**	**0**	**5343**	**7905**	**0**	**7905**

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन यूएस $)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2024-25		2024				2025	
			मार्च		दिसं.		मार्च	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	270441	556812	242271	542952	260755	547104	270441	556812
1.1 इक्विटी पूंजी*	173559	521931	153343	511142	166493	512997	173559	521931
1.2 अन्य पूंजी	96882	34881	88927	31810	94262	34107	96882	34881
2. संविभाग निवेश	13763	272061	12469	277239	12173	276521	13763	272061
2.1 इक्विटी	8727	141938	10942	162061	9356	155573	8727	141938
2.2 ऋण	5036	130123	1527	115178	2817	120948	5036	130123
3. अन्य निवेश	186700	640384	132617	574786	170526	619693	186700	640384
3.1 व्यापार ऋण	33422	131203	33413	123722	33213	135606	33422	131203
3.2 ऋण	25891	250551	17547	221396	22523	240588	25891	250551
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	79332	167598	53519	154787	68630	165713	79332	167598
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	48055	91032	28138	74880	46160	77785	48055	91032
4. आरक्षित निधियाँ	668326		646419		635701		668326	
5. कुल आस्तियां/देयताएं	1139230	1469257	1033776	1394977	1079156	1443318	1139230	1469257
6. निवल आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)	-330027		-361201		-364162		-330027	

टिप्पणी: * इक्विटी पूंजी में निवेश निधि और पुनर्निवेशित अर्जन का शेयर शामिल है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2024	2025		वि.व. 2024-25	2024	2025	
		जून	मई	जून		जून	मई	जून
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	47.40	4.36	5.48	5.30	296218030	22580094	29656042	30959727
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.10.1 से 1.1.3)	17.87	1.60	1.94	1.77	185733719	15107943	17500816	17946468
1.1.1 आउटराइट	10.56	0.97	1.28	1.05	16056018	1372786	1875057	1611829
1.1.2 रेपो	4.72	0.42	0.45	0.51	77286611	6414226	7645792	7894091
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.58	0.21	0.21	0.21	92391091	7320931	7979967	8440549
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	28.06	2.67	3.44	3.39	100639565	6953169	11363617	11968143
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.46	0.09	0.10	0.14	9844746	518982	791608	1045117
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	3024.55	231.84	274.71	254.88	201387682	16037694	17013770	19012360
1.1 ग्राहक लेनदेन	3010.32	230.72	273.46	253.73	181153129	14570686	15219873	16983278
1.2 अंतर्बैंक लेनदेन	14.23	1.12	1.25	1.15	20234553	1467008	1793897	2029082
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	2061014.91	155567.02	203656.72	200519.84	79781976	6073917	7146649	6957478
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.64	0.30	0.31	0.30	190	16	17	16
2.2 एपीबीएस $	32964.43	2929.34	2786.17	2841.94	554034	43676	50985	48247
2.3 आईएमपीएस	56249.68	5167.51	4636.60	4481.05	7139110	577794	640867	606356
2.4 एनएसीएच जमा $	16938.86	1311.11	1243.57	1325.97	1670223	113888	147380	134188
2.5 एनईएफटी	96198.05	7307.34	8215.47	7920.52	44361464	3331461	3793103	3764742
2.6 यूपीआई @	1858660.25	138851.42	186774.60	183950.06	26056955	2007081	2514297	2403931
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	17.24	1.41	1.79	1.18	185	15	33	21
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	21659.95	1697.73	1895.74	1891.36	2208583	171469	206368	210754
3.1 भीम आधार पे @	230.08	21.07	19.51	18.27	6907	581	641	615
3.2 एनएसीएच नामे $	19762.28	1544.59	1723.65	1728.39	2199327	170756	205535	209956
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1667.59	132.07	152.58	144.70	2349	132	192	183
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	63861.15	5003.43	5827.40	5672.82	2605110	200081	226810	218552
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	47740.76	3579.49	4676.93	4587.10	2109197	158822	189832	183088
4.1.1 पीओएस आधारित $	24571.10	1895.40	2359.14	2338.70	795022	59417	69607	67468
4.1.2 अन्य $	23169.66	1684.10	2317.79	2248.41	1314175	99405	120224	115620
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	16120.39	1423.94	1150.47	1085.72	495914	41259	36978	35463
4.2.1 पीओएस आधारित $	11980.33	1063.58	861.57	812.90	332556	27629	24735	23079
4.2.2 अन्य $	4140.06	360.36	288.90	272.82	163358	13629	12243	12384
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	70254.08	5236.08	7106.39	6868.39	216751	15897	20722	20740
5.1 वालेट	52898.40	4038.05	5474.25	5338.82	154066	11298	16668	17308
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	17355.68	1198.03	1632.13	1529.57	62686	4599	4053	3432
5.2.1 पीओएस आधारित $	8240.14	650.89	650.54	595.05	11512	946	981	888
5.2.2 अन्य $	9115.54	547.14	981.59	934.51	51174	3653	3072	2544
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6095.38	484.42	481.93	447.43	7113350	553834	596239	550176
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6095.38	484.42	481.93	447.43	7113350	553834	596239	550176
6.2 अन्य	0.00	–	–	–	–	–	–	–
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2222885.46	167988.69	218968.18	215399.84	91925771	7015198	8196787	7957700
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2225910.01	168220.52	219242.89	215654.72	293313453	23052892	25210557	26970060
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2219814.63	167736.10	218760.96	215207.29	286200103	22499058	24614318	26419884

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2024-25	2024	2025		वि.व. 2024-25	2024	2025	
		जून	मई	जून		जून	मई	जून
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	1756976.91	132846.07	173238.90	170054.63	39206221	3029193	3641750	3385251
1.1 अंतबैंक $	110801.96	8784.73	9743.77	8974.93	7207439	557266	638772	529331
1.2 अंतर-बैंक $	1646174.95	124061.34	163495.14	161079.71	31998782	2471927	3002978	2855919
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	47478.09	3780.42	3668.66	3635.82	131858133	10487118	11661241	12824960
2.1 अंतबैंक @	13056.37	1029.33	851.54	839.90	69086996	5573973	6068349	6918867
2.2 अंतर-बैंक @	34421.72	2751.09	2817.12	2795.92	62771136	4913144	5592892	5906093
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी $ (3.1 से 3.3)	60308.11	5076.57	4604.61	4382.08	3063077	255229	246201	229907
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना $	97.25	8.29	6.70	6.28	5084	426	370	345
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	59965.70	5045.81	4579.88	4358.58	3046987	253844	244945	228735
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	245.16	22.47	18.03	17.22	11005	959	886	827
4 पीओएस पर नकद निकासी $ (4.1 से 4.2)	3.58	0.28	0.15	0.14	37	3	2	1
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना $	3.33	0.27	0.13	0.11	35	3	1	1
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना $	0.25	0.02	0.03	0.02	3	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11640.55	973.79	1017.25	944.62	296622	24426	27668	25646
5.1 एईपीएस @	11640.55	973.79	1017.25	944.62	296622	24426	27668	25646

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2025 तक	2024	2025	
		जून	मई	जून
	1	2	3	4
Payment System Infrastructures				
1 Number of Cards (1.1 to 1.2)	11006.97	10662.37	11115.67	11163.78
1.1 Credit Cards	1098.85	1038.13	1111.98	1111.97
1.2 Debit Cards	9908.12	9624.24	10003.70	10051.80
2 Number of PPIs @ (2.1 to 2.2)	13396.53	15051.30	13513.51	13520.65
2.1 Wallets @	8673.62	11375.61	8692.12	8681.92
2.2 Cards @	4722.91	3675.69	4821.38	4838.73
3 Number of ATMs (3.1 to 3.2)	2.56	2.56	2.57	2.51
3.1 Bank owned ATMs $	2.20	2.21	2.21	2.15
3.2 White Label ATMs $	0.36	0.35	0.36	0.36
4 Number of Micro ATMs @	14.82	15.25	14.78	14.59
5 Number of PoS Terminals	110.98	89.67	115.89	117.91
6 Bharat QR @	67.18	61.64	66.64	67.21
7 UPI QR *	6579.30	5770.15	6698.20	6782.51

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

टिप्पणियां: 1. डेटा अनंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवबंर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तलुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधनं के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।
भाग I-ए. निपटान प्रणाली
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।
भाग I-बी. भुगतान प्रणाली
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल है।
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।
6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।
6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।
भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल
1: मोबाइल भुगतान -
बैंकों के मोबाइल ऐप्स और यूपीआई ऐप्स के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।
भाग II-बी. एटीएम
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।
भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

आवसरिक शृंखला

सं. 44 लघु बचत

(₹ करोड़)

प्रणाली		2023-24	2024		2025	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**232460**	**14570**	**11133**	**12581**	**11379**
	बकाया	**1865029**	**1819758**	**1982465**	**1994553**	**2005585**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**161344**	**10025**	**8734**	**9178**	**8077**
	बकाया	**1298795**	**1268920**	**1395484**	**1404661**	**1412738**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	17229	1520	1090	2702	814
	बकाया	191692	218498	201999	204701	205515
1.1.2 सुकन्या समृद्धि योजना	प्राप्तियां	35174	2233	2244	2347	2282
	बकाया	157611	109222	177007	179354	181636
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	26696	1927	827	1279	1045
	बकाया	269007	267205	282142	283421	284466
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	38167	2153	1531	1922	1952
	बकाया	175472	173476	194605	196527	198479
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25341	2632	2125	2853	2108
	बकाया	305776	303000	330912	333764	335872
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	140423	138552	159174	161578	163358
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	11967	11730	14299	14476	14637
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	8932	8782	10308	10487	10645
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	144454	143936	147131	147223	147232
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	18713	-420	1025	-1831	-25
	बकाया	197134	195727	207269	205438	205413
1.1.9 डाक घर संचयी मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	8	-20	-108	-95	-100
	बकाया	1754	1444	1195	1100	1000
1.1.11 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन	प्राप्तियां	16	0	0	1	1
	बकाया	349	348	355	356	357
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**56069**	**3940**	**2226**	**3019**	**2858**
	बकाया	**418021**	**414597**	**438074**	**440601**	**443112**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	16853	1446	430	796	762
	बकाया	183905	180181	192621	193417	194179
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	20939	1428	1113	1376	1247
	बकाया	220560	219498	228707	230083	231330
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.7 एम.एस. प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	18277	1066	683	847	849
	बकाया	18277	17235	25303	26150	26999
1.2.8 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	-4721	-2317	-8557	-9049	-9396
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**15047**	**605**	**173**	**384**	**444**
	बकाया	**148213**	**136241**	**148907**	**149291**	**149735**

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं, अर्थात सकल प्राप्तियों से सकल भुगतान को घटाने पर प्राप्त।

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

सं. 45 केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां

श्रेणी	2024				2025
	मार्च	जून	सितं	दिसं	मार्च
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	**10740389**	**10946860**	**11271589**	**11422728**	**11642652**
1. वाणिज्यिक बैंक	37.66	37.52	37.55	37.98	36.18
2. सहकारी बैंक	1.47	1.42	1.35	1.36	1.29
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.66	0.70	0.77	0.65	0.76
4. बीमाकृत कंपनियां	25.98	26.11	25.95	26.14	25.81
5. म्यूच्युअल फंड	2.90	2.87	3.14	3.11	2.68
6. भविष्य निधियां	4.47	4.41	4.25	4.25	4.24
7. पेंशन निधि	4.52	4.74	4.86	5.05	4.91
8. वित्तीय संस्थाएं	0.55	0.57	0.63	0.64	0.71
9. कॉरपोरेट	1.35	1.44	1.60	1.45	1.49
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	2.34	2.34	2.80	2.81	3.12
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	12.31	11.92	11.16	10.55	12.78
12. अन्य	5.79	5.97	5.92	6.01	6.01
12.1 राज्य सरकार	2.04	2.13	2.19	2.21	2.25

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां

श्रेणी	2024				2025
	मार्च	जून	सितं	दिसं	मार्च
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	**5646219**	**5727482**	**5909490**	**6055711**	**6399564**
1. वाणिज्यिक बैंक	34.14	33.85	34.39	35.11	35.40
2. सहकारी बैंक	3.39	3.38	3.29	3.22	3.08
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.60	0.59	0.60	0.53	0.61
4. बीमाकृत कंपनियां	26.14	25.85	25.56	25.16	24.07
5. म्यूच्युअल फंड	2.09	2.08	1.93	1.89	1.93
6. भविष्य निधियां	22.35	22.94	23.02	22.90	23.60
7. पेंशन निधि	4.76	4.87	4.87	4.82	5.07
8. वित्तीय संस्थाएं	1.59	1.58	1.57	1.58	1.48
9. कॉरपोरेट	2.02	2.03	1.95	1.97	2.05
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.07	0.05	0.04	0.03	0.05
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.63	0.62	0.60	0.58	0.55
12. अन्य	2.20	2.17	2.18	2.19	2.10
12.1 राज्य सरकार	0.25	0.26	0.26	0.26	0.25

खज़ाना बिल

श्रेणी	2024				2025
	मार्च	जून	सितं	दिसं	मार्च
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	**871662**	**858193**	**747242**	**760045**	**790381**
1. वाणिज्यिक बैंक	58.53	47.79	44.74	40.45	46.58
2. सहकारी बैंक	1.67	1.49	1.58	1.22	2.17
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	1.66	2.69	2.28	1.41	2.09
4. बीमाकृत कंपनियां	5.06	5.78	5.26	4.73	4.23
5. म्यूच्युअल फंड	11.89	14.50	15.06	15.41	16.15
6. भविष्य निधियां	0.15	0.60	0.26	0.04	0.20
7. पेंशन निधि	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02
8. वित्तीय संस्थाएं	7.16	6.56	6.36	6.77	7.73
9. कॉरपोरेट	4.50	4.79	4.66	4.56	4.50
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.01	0.20	0.15	0.12	0.09
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अन्य	9.36	15.59	19.65	25.29	16.23
12.1 राज्य सरकार	5.88	11.55	14.95	20.11	11.23

नोट: (1) बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फार्मेट संशोधित किया है।
(2) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों में विशेष प्रतिभूतियां और सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड शामिल हैं।
(3) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।
(4) वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है।
(5) अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।
(6) सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (सं.अ.)	2024-25 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**5410887**	**6353359**	**7098451**	**7880522**	**9110725**	**9800798**
1.1 विकास संबंधी	3074492	3823423	4189146	4701611	5514584	5862996
1.1.1 राजस्व	2446605	3150221	3255207	3574503	3965270	4195108
1.1.2 पूंजी	588233	550358	861777	1042159	1453849	1526993
1.1.3 ऋण	39654	122844	72163	84949	95464	140895
1.2 गैर-विकास संबंधी	2253027	2442941	2810388	3069896	3467270	3800321
1.2.1 राजस्व	2109629	2271637	2602750	2895864	3266628	3537378
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	955801	1060602	1226672	1377807	1562660	1711972
1.2.2 पूंजी	141457	169155	175519	171131	196073	259346
1.2.3 ऋण	1941	2148	32119	2902	4569	3597
1.3 अन्य	83368	86995	98916	109015	128871	137481
2. कुल प्राप्तियां	**5734166**	**6397162**	**7156342**	**7855370**	**9054999**	**9650488**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3851563	3688030	4823821	5447913	6379349	7209647
2.1.1 कर प्राप्तियां	3231582	3193390	4160414	4809044	5456913	6142276
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	2012578	2076013	2626553	2865550	3248450	3631569
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1216203	1114805	1530636	1939550	2204462	2506181
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	2800	2572	3225	3943	4001	4526
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	619981	494640	663407	638870	922436	1067371
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	31137	33448	35250	42975	49552	57273
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	110094	64994	44077	62716	86733	118239
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	59515	16951	27665	15970	55895	45125
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	50578	48044	16412	46746	30839	73114
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**1449230**	**2600335**	**2230553**	**2369892**	**2644642**	**2472912**
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1440548	2530155	2194406	2332768	2619811	2456959
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	571872	890012	627255	687904	346483	…
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	190241	107493	350911	529	-257913	…
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	868676	1640143	1567151	1644864	2273328	…
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	8682	70180	36147	37124	24832	15952
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1440548	2530155	2194406	2332768	2619811	2456959
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	971378	1696012	1213169	1651076	1962969	1983757
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	209232	458801	526693	358764	434151	447511
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	38280	41273	28100	13880	21386	19857
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	10411	4545	42153	68803	52385	-33653
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	-14227	25682	42203	51989	35819	-10138
3ख.1.6 नकद शेष	-323279	-43802	-57891	25152	55726	150310
3ख.1.7 अन्य	548753	347643	399980	163104	57374	-100684
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	8682	70180	36147	37124	24832	15952
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल वितरण	*26.9*	*32.0*	*30.1*	*29.2*	*30.8*	*30.0*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियां	*28.5*	*32.2*	*30.3*	*29.1*	*30.7*	*29.6*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां	*19.2*	*18.6*	*20.4*	*20.2*	*21.6*	*22.1*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियां	*16.1*	*16.1*	*17.6*	*17.8*	*18.5*	*18.8*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल वित्तीय घाटा	*7.2*	*13.1*	*9.5*	*8.8*	*9.0*	*7.6*

… : उपलब्ध नहीं। सं.अ. संशोधित अनुमान, ब.अ. बजट अनुमान।

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।

टिप्पणी : जीडीपी डेटा 2011-12 के आधार पर है। 2024-25 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2024-25 से है।
डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।
1 और 2: डेटा केंद्र सरकार (एनएसएसएफ को पुनर्भुगतान सहित) और राज्य सरकारों के निवल पुनर्भुगतान का है।
1.3: राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर और समनुदेशन का प्रतिनिधित्व करता है।
2: डेटा केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में निवल भिन्नता को दर्शाता है और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियां शामिल हैं।
3ए.1.1: आरबीआई रिकॉर्ड के अनुसार डेटा।
3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार।
3बी.1.2: राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवल निवेश को दर्शाता है।
नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण यह डेटा पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।
3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।
3बी.1.7: ट्रेजरी बिल, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकद शेष निवेश खाता शामिल हैं।

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जून 2025 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	5259.07	28	1662.97	8	3117.88	3
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	422.98	29	257.53	4
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	18.86	21	478.83	21	-	-
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	1370.57	30	807.70	16	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	3027.77	17	-	-	-	-
16	मणिपुर	69.73	16	163.71	9	-	-
17	मेघालय	303.85	14	82.50	1	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	217.51	11	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	3330.73	23	376.59	1	-	-
23	राजस्थान	2682.97	21	409.27	3	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	4568.60	30	1386.67	21	738.44	5
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	721.61	30	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणीयां : 1) राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेष तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

3) राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

4) प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

5) -: नगण्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जून 2025 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	11908	1173	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	3032	8	0	3400
3	असम	7618	93	0	0
4	बिहार	12846	-	0	11500
5	छत्तीसगढ़	8466	986	0	7130
6	गोवा	1157	471	0	0
7	गुजरात	15780	686	0	2500
8	हरियाणा	2689	1749	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	37	36	0	0
11	झारखंड	3085	-	0	780
12	कर्नाटक	20831	773	0	70564
13	केरल	3329	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1315	0	1500
15	महाराष्ट्र	73492	2215	0	0
16	मणिपुर	71	144	0	0
17	मेघालय	1312	112	0	0
18	मिज़ोरम	520	82	0	0
19	नगालैंड	1948	47	0	0
20	उड़ीसा	18859	2104	0	12236
21	पुदुचेरी	596	-	0	1950
22	पंजाब	10372	948	0	0
23	राजस्थान	2408	375	0	5750
24	तमिलनाडु	3562	-	0	1450
25	तेलंगाना	8130	1779	0	0
26	त्रिपुरा	1356	31	0	0
27	उत्तरप्रदेश	5460	266	0	0
28	उत्तराखंड	15085	2247	0	15000
29	पश्चिम बंगाल	14241	1064	0	10000
	कुल	**248188**	**18704**	**0**	**143759**

टिप्पणियाँ: 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।
2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।
3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।

सं. 49: राज्य सरकारों की बाजार उधारियाँ

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य	2023-24		2024-25		2025-26						2025-26 में ली गई कुल राशि	
						अप्रै.		मई		जून			
		ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	68400	55330	78205	57123	5750	4750	6822	4322	14000	13000	26572	22072
2	अरुणाचल प्रदेश	902	672	1010	704	-	-130	-	-	-	-	-	-130
3	असम	18500	16000	19000	13850	900	-50	2600	2600	-	-	3500	2550
4	बिहार	47612	29910	47546	30890	-	-	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	32000	26213	24500	16913	1970	1970	1000	1000	1000	1000	3970	3970
6	गोवा	2550	1560	1050	250	-	-150	100	-50	100	100	200	-100
7	गुजरात	30500	11947	38200	16280	-	-2560	8500	4500	1500	300	10000	2240
8	हरियाणा	47500	28364	49500	31710	2000	2000	5000	3100	3000	425	10000	5525
9	हिमाचल प्रदेश	8072	5856	7359	4725	2200	1550	-	-	800	800	3000	2350
10	जम्मू और कश्मीर	16337	13904	13170	11416	1000	1000	800	300	705	705	2505	2005
11	झारखंड	1000	-2505	3500	-2005	-	-	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	81000	63003	92025	71525	-	-	-	-	-	-1000	-	-1000
13	केरल	42438	26638	53666	37966	2000	-	5000	3500	5000	4000	12000	7500
14	मध्य प्रदेश	38500	26264	63400	47206	-	-	5000	5000	3277	2277	8277	7277
15	महाराष्ट्र	110000	79738	123000	90917	13500	13500	-	-3500	8000	6500	21500	16500
16	मणिपुर	1426	1076	1500	1037	-	-200	750	750	-	-	750	550
17	मेघालय	1364	912	1882	997	350	250	-	-	500	430	850	680
18	मिज़ोरम	901	641	1169	939	-	-	-	-	125	50	125	50
19	नगालैंड	2551	2016	1550	950	-	-	-	-100	-	-100	-	-200
20	उड़ीसा	0	-4658	20780	17780	-	-	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	1100	475	1600	880	-	-	-	-	200	200	200	200
22	पंजाब	42386	29517	40828	32466	5800	4200	5500	4600	4500	2858	15800	11658
23	राजस्थान	73624	49718	75185	49479	5500	3500	8600	6600	9500	4938	23600	15038
24	सिक्किम	1916	1701	1951	1621	-	-	-	-	-	-	-	-
25	तमिलनाडु	113001	75970	123625	89894	4000	1000	7300	1300	13000	9750	24300	12050
26	तेलंगाना	49618	39385	56209	42199	4400	3400	4500	1152	8500	7200	17400	11752
27	त्रिपुरा	0	-550	0	-150	500	500	300	300	-	-	800	800
28	उत्तरप्रदेश	97650	85335	45000	23185	3000	-1000	3000	1000	-	-3233	6000	-3233
29	उत्तराखंड	6300	3800	10400	8000	1000	1000	-	-	1000	250	2000	1250
30	पश्चिम बंगाल	69910	48910	76500	54600	-	-1000	-	-1500	7500	6000	7500	3500
	कुल	1007058	717140	1073310	753345	53870	33530	64772	34874	82207	56449	200849	124853

- : शून्य।

टिप्पणी: 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रुप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देयताएं जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देयताओं के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2022-23				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**287802.7**	**297217.6**	**293954.9**	**451660.3**	**1330635.4**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.4*	*4.6*	*4.3*	*6.4*	*4.9*
I. वित्तीय आस्तियां	**577822.4**	**632335.6**	**748109.7**	**968986.1**	**2927253.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*8.9*	*9.8*	*11.0*	*13.6*	*10.9*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**185429.1**	**317361.2**	**280233.1**	**325852.7**	**1108876.2**
(ए) बैंक जमाराशि	**163172.4**	**299532.7**	**256399.7**	**307866.8**	**1026971.5**
i. वाणिज्यिक बैंक	158613.3	300565.0	248459.8	284968.0	992606.2
ii. सहकारी बैंक	4559.0	-1032.4	7939.8	22898.9	34365.3
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**22256.8**	**17828.6**	**23833.5**	**17985.9**	**81904.7**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**6504.8**	**2076.7**	**8081.6**	**2234.0**	**18897.1**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	4230.6	3267.2	3246.9	3945.8	14690.4
ii. आवास वित्त कंपनियां	2274.2	-1190.5	4834.7	-1711.8	4206.6
2. जीवन बीमा निधियाँ	**73357.5**	**151737.1**	**167581.7**	**156268.5**	**548944.9**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**146719.1**	**118171.9**	**136388.4**	**216513.6**	**617793.1**
4. मुद्रा	**66438.9**	**-54579.3**	**76760.1**	**148990.1**	**237609.7**
5. निवेश	**51502.6**	**48530.1**	**49778.6**	**64150.6**	**213961.9**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	35443.5	44484.0	40205.9	58954.5	179087.8
(बी) इक्विटी	13560.9	1378.2	6434.1	1664.9	23038.1
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**54375.1**	**51114.5**	**37367.7**	**57210.6**	**200068.0**
II. वित्तीय देयताएँ	**290019.7**	**335118.0**	**454154.8**	**517325.8**	**1596618.3**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.5*	*5.2*	*6.7*	*7.3*	*5.9*
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**289781.5**	**334879.7**	**453916.6**	**517087.5**	**1595665.3**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**234235.0**	**263450.2**	**370782.9**	**383843.2**	**1252311.4**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	230283.8	261265.3	368304.6	331291.0	1191144.8
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**55546.4**	**71429.5**	**83133.7**	**133244.3**	**343353.9**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	30531.7	36650.3	55791.7	94565.3	217539.1
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	22336.7	33031.2	24903.3	36745.8	117017.0
iii. बीमा कंपनियाँ	2678.0	1747.9	2438.7	1933.2	8797.8
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**33.7**	**33.7**	**33.7**	**33.7**	**135.0**
3. सामान्य सरकार	**204.5**	**204.5**	**204.5**	**204.5**	**818.0**

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2023-24				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**349607.1**	**283994.4**	**294431.6**	**666547.4**	**1594580.4**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.8*	*3.9*	*3.8*	*8.4*	*5.3*
I. वित्तीय आस्तियां	**671244.1**	**810128.8**	**805066.2**	**1187279.1**	**3473718.2**
जीडीपी का प्रतिशत	*9.3*	*11.2*	*10.4*	*14.9*	*11.5*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**266680.3**	**407948.0**	**296931.3**	**406706.9**	**1378266.4**
(ए) बैंक जमाराशि	**253004.1**	**501768.5**	**277432.0**	**390720.4**	**1422924.9**
i. वाणिज्यिक बैंक	243833.9	502260.7	280096.7	383460.6	1409651.9
ii. सहकारी बैंक	9170.2	-492.2	-2664.7	7259.8	13273.0
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**13676.2**	**-93820.5**	**19499.4**	**15986.5**	**-44658.5**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**-485.4**	**-107982.1**	**5337.7**	**1824.9**	**-101304.9**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	6119.3	4782.3	4895.8	1942.9	17740.3
ii. आवास वित्त कंपनियां	-6604.7	-112764.4	441.9	-118.0	-119045.2
2. जीवन बीमा निधियाँ	**157301.9**	**140356.8**	**160135.2**	**189267.6**	**647061.4**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**163686.0**	**148356.1**	**153435.1**	**253882.9**	**719360.2**
4. मुद्रा	**-48636.2**	**-36700.8**	**56719.0**	**146643.8**	**118025.7**
5. निवेश	**41014.3**	**72664.6**	**79238.2**	**108336.6**	**301253.8**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	32085.6	55768.8	60134.6	90973.0	238962.1
(बी) इक्विटी	3756.7	7146.3	9941.1	8236.1	29080.1
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**91197.8**	**77504.1**	**58607.4**	**82441.4**	**309750.7**
II. वित्तीय देयताएँ	**321637.1**	**526134.4**	**510634.6**	**520731.7**	**1879137.8**
जीडीपी का प्रतिशत	*4.5*	*7.3*	*6.6*	*6.5*	*6.2*
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**321519.8**	**526016.2**	**510516.4**	**520613.5**	**1878665.8**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**213606.3**	**868873.9**	**402647.1**	**392330.5**	**1877457.7**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	208026.5	875654.0	389898.0	382557.9	1856136.4
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**107913.6**	**-342857.7**	**107869.2**	**128283.0**	**1208.0**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	81448.8	59683.7	85031.8	100836.5	327000.7
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	23784.0	-404294.0	21233.4	25852.9	-333423.7
iii. बीमा कंपनियाँ	2680.7	1752.6	1604.0	1593.6	7631.0
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**33.7**	**34.7**	**34.7**	**34.7**	**138.0**
3. सामान्य सरकार	**83.5**	**83.5**	**83.5**	**83.5**	**334.0**

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2024-25				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	**551994.2**	**496676.1**	**271043.1**	**674489.0**	**1994202.4**
जीडीपी का प्रतिशत	*7.0*	*6.3*	*3.2*	*7.6*	*6.0*
I. वित्तीय आस्तियां	**840665.3**	**901135.4**	**689663.5**	**1129381.1**	**3560845.4**
जीडीपी का प्रतिशत	*10.6*	*11.5*	*8.1*	*12.8*	*10.8*
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	**274567.9**	**403591.4**	**158320.8**	**418183.6**	**1254663.6**
(ए) बैंक जमाराशि	**254885.4**	**388328.6**	**141290.0**	**401577.5**	**1186081.4**
i. वाणिज्यिक बैंक	251171.1	389734.0	147864.7	395337.4	1184107.2
ii. सहकारी बैंक	3714.3	-1405.4	-6574.7	6240.0	1974.2
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	**19682.4**	**15262.8**	**17030.8**	**16606.1**	**68582.2**
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	**7461.4**	**3041.8**	**4809.8**	**4385.1**	**19698.2**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	6289.7	3230.0	4444.5	4220.0	18184.2
ii. आवास वित्त कंपनियां	1171.7	-188.2	365.4	165.1	1514.0
2. जीवन बीमा निधियाँ	**175427.0**	**178835.2**	**90159.4**	**90393.0**	**534814.6**
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	**170218.2**	**170219.6**	**170758.3**	**281332.6**	**792528.6**
4. मुद्रा	**34212.5**	**-57615.2**	**70840.8**	**162236.1**	**209674.1**
5. निवेश	**120638.2**	**152637.1**	**159255.2**	**103720.8**	**536251.4**
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	106987.0	137618.0	124132.0	97193.0	465930.0
(बी) इक्विटी	14448.0	15645.0	36063.1	7410.3	73566.5
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	**65601.6**	**53467.4**	**40329.0**	**73515.0**	**232913.0**
II. वित्तीय देयताएँ	**288671.1**	**404459.3**	**418620.4**	**454892.1**	**1566642.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*3.7*	*5.2*	*4.9*	*5.2*	*4.7*
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	**288492.4**	**404280.6**	**418441.7**	**454713.3**	**1565928.0**
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**205040.4**	**322147.7**	**319626.6**	**387045.6**	**1233860.3**
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	208525.3	321241.4	302569.3	379856.5	1212192.4
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	**83452.0**	**82132.9**	**98815.0**	**67667.7**	**332067.7**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	65813.7	65488.7	75764.5	39833.9	246900.8
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	15125.2	14233.6	20561.4	25756.8	75677.0
iii. बीमा कंपनियाँ	2513.1	2410.7	2489.1	2077.1	9489.9
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	**34.7**	**34.7**	**34.7**	**34.7**	**139.0**
3. सामान्य सरकार	**144.0**	**144.0**	**144.0**	**144.0**	**576.0**

टिप्पणियां: 1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत से तात्पर्य निवल वित्तीय परिसपंत्तियों से है, जिन्हें वित्तीय परिसपंत्ति और देयताओं के प्रवाह के बीच अतंर के रूप में मापा जाता है।
2. 2024-25 के लिए प्रारंभिक अनुमान और 2022-23 और 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान।
3. एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, 2024-25 के पहले संशोधित अनुमान जारी होने के साथ 2023-24 के प्रारंभिक अनुमानों में संशोधन किया जाएगा।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ, सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2022	सितं-2022	दिसं-2022	मार्च-2023
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**25621348.1**	**26423992.1**	**27187715.6**	**27844981.1**
जीडीपी का प्रतिशत	*102.8*	*102.6*	*103.3*	*103.5*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**11843527.1**	**12143059.7**	**12399459.4**	**12707326.2**
i. वाणिज्यिक बैंक	10987692.1	11288257.2	11536717.0	11821685.0
ii. सहकारी बैंक	855834.9	854802.6	862742.4	885641.2
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**216170.0**	**218246.7**	**226328.2**	**228562.2**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	74794.2	78061.4	81308.3	85254.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	141375.8	140185.3	145020.0	143308.2
(सी) जीवन बीमा निधि	**5325967.3**	**5559681.9**	**5786592.6**	**5795430.6**
(डी) मुद्रा	**2950343.2**	**2895763.9**	**2972524.0**	**3121514.1**
(ई) म्यूचुअल फंड	**2048097.3**	**2260209.7**	**2355315.8**	**2367792.5**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**851913.4**	**858591.1**	**864730.6**	**939449.0**
(जी) पेंशन निधि	**744459.2**	**796454.0**	**853412.0**	**898343.0**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**1640870.6**	**1691985.1**	**1729352.9**	**1786563.5**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**8911860.9**	**9246740.6**	**9700657.2**	**10217744.7**
जीडीपी का प्रतिशत	*35.8*	*35.9*	*36.9*	*38.0*
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**7095467.7**	**7358918.0**	**7729700.9**	**8113544.1**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	6620073.1	6881338.5	7249643.0	7580934.1
ii. सहकारी बैंक	473897.0	476024.8	478486.9	530915.0
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**1816393.1**	**1887822.6**	**1970956.3**	**2104200.7**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	869174.9	905825.3	961617.0	1056182.3
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	835181.3	868212.5	893115.8	929861.7
iii.बीमा निगम	112036.9	113784.8	116223.5	118156.7

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2023	सितं-2023	दिसं-2023	मार्च-2024
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**28754605.9**	**29637615.0**	**30737884.8**	**32025210.0**
जीडीपी का प्रतिशत	*104.2*	*104.4*	*105.0*	*106.3*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**12960330.3**	**13462098.8**	**13739530.7**	**14130251.1**
i. वाणिज्यिक बैंक	12065518.9	12567779.6	12847876.2	13231336.9
ii. सहकारी बैंक	894811.4	894319.2	891654.5	898914.3
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**228076.8**	**120094.7**	**125432.4**	**127257.3**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	91373.3	96155.6	101051.4	102994.3
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	136703.5	23939.1	24381.0	24263.0
(सी) जीवन बीमा निधि	**6064436.9**	**6255801.1**	**6553726.0**	**6820611.8**
(डी) मुद्रा	**3072877.9**	**3036177.0**	**3092896.0**	**3239539.8**
(ई) म्यूचुअल फंड	**2626046.1**	**2829859.3**	**3156299.3**	**3387208.3**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**955060.6**	**960343.6**	**964851.5**	**1051376.5**
(जी) पेंशन निधि	**970016.0**	**1017975.0**	**1091276.0**	**1172651.0**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**1877761.2**	**1955265.4**	**2013872.8**	**2096314.2**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**10539264.5**	**11065280.7**	**11575797.1**	**12096410.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*38.2*	*39.0*	*39.6*	*40.2*
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**8327150.3**	**9196024.2**	**9598671.3**	**9991001.8**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	7788960.6	8664614.6	9054512.6	9437070.5
ii. सहकारी बैंक	536409.2	529527.7	542240.6	551852.1
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**2212114.2**	**1869256.5**	**1977125.7**	**2105408.7**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1137631.1	1197314.8	1282346.6	1383183.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	953645.7	549351.7	570585.1	596438.0
iii.बीमा निगम	120837.4	122590.0	124194.0	125787.7

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2024	सितं-2024	दिसं-2024	मार्च-2025
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ़+जी+एच)	**33253098.6**	**34421189.5**	**34532805.6**	**35264710.9**
जीडीपी का प्रतिशत	*107.9*	*109.6*	*107.2*	*106.6*
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	**14385136.5**	**14773465.1**	**14914755.1**	**15316332.6**
i. वाणिज्यिक बैंक	13482508.0	13872242.0	14020106.6	14415444.1
ii. सहकारी बैंक	902628.6	901223.2	894648.5	900888.5
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	**134718.7**	**137760.5**	**142570.3**	**146955.5**
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	109284.0	112514.0	116958.5	121178.5
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	25434.7	25246.5	25611.9	25777.0
(सी) जीवन बीमा निधि	**7123527.6**	**7385938.1**	**7272871.3**	**7293099.1**
(डी) मुद्रा	**3273752.3**	**3216137.1**	**3286977.8**	**3449213.9**
(ई) म्यूचुअल फंड	**3866386.1**	**4291914.4**	**4224091.7**	**4128924.5**
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	**1059829.5**	**1063056.1**	**1064212.0**	**1157449.2**
(जी) पेंशन निधि	**1247832.0**	**1337535.0**	**1371615.0**	**1443509.0**
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	**2161915.8**	**2215383.2**	**2255712.2**	**2329227.2**
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	**12384902.9**	**12789183.5**	**13207625.1**	**13662338.5**
जीडीपी का प्रतिशत	*40.2*	*40.7*	*41.0*	*41.3*
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	**10196042.2**	**10518189.9**	**10837816.5**	**11224862.1**
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	9645595.7	9966837.1	10269406.4	10649262.8
ii. सहकारी बैंक	548284.4	549069.4	566104.4	573131.8
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	**2188860.7**	**2270993.6**	**2369808.7**	**2437476.4**
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1448996.8	1514485.5	1590250.0	1630083.9
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	611563.2	625796.8	646358.2	672115.0
iii.बीमा निगम	128300.7	130711.4	133200.5	135277.5

टिप्पणियाँ: 1. जीडीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना एनएसओ द्वारा 30 मई 2025 को जारी राष्ट्रीय आय 2024-25 के अनंतिम अनुमान के आधार पर की गई है।
2. पेंशन निधि में राष्ट्रीय पेंशन योजना की निधि शामिल है।
3. लघु बचत के साथ बकाया जमा राशि भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक से प्राप्त की जाती है।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं। बकाया जमा के लिए आंकड़े केवल अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6 : वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं ।
3.5 और 3.7 : वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह / वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.10 से 4.12 : माह/ वित्त वर्ष के अंतिम नीलामी दिन से संबंधित है।
4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
7.1 और 7.2 : यूएस डॉलर में विदेशी व्यापार से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियाँ और अल्पावधि प्रतिभूतियाँ / बॉण्ड जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी, शामिल है।

सारणी सं. 4

http ://nsdp.rbi.org.in के ‘रिज़र्व टैम्पलेट’ के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य अर्थात एक्सिम बैंक को विशेष पुनर्वित्त सुविधा 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।
2.2 : आईएमएफ खाता सं. 1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4 : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्ड शामिल है।

सारणी सं. 8

एनएम$_2$ और एनएम$_3$ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4 : चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल$_1$ और एल$_2$ मासिक आधार पर और एल$_3$ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कॉलम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़े अंतिम और कॉलम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14
कॉलम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17
2.1.1 : राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।
2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।
4: आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24
प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30
प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं
1 : बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।
2 : संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32
आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। आरक्षित निधि में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) की मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए अमेरिकी डॉलर में विदेशी मुद्रा आस्तियों को लिया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34
1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान
1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान
'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं / शाखाओं के बीच के ऋण सबंधी लेनदेन से संबंधित है।
हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35
1.10 : पत्र-पत्रिकाओं के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36
सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि और विपरीत क्रम का संकेतक है। 6- मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2022-23 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतित किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। नीर//रीर सूचकांकों के संकलन के लिए प्रयुक्त कार्यप्रणाली का ब्यौरा आरबीआई बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में उपलब्ध है।

सारणी सं. 37
ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I-ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर 2018 से किया गया है।

भाग II-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: वॉलेट के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद और निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह से संबंधित है।

भाग II-ए अन्य भुगतान चैनल

1 : मोबाइल भुगतान -

- इसमें बैंकों के मोबाइल ऐप और यूपीआई ऐप के जरिए किए गए लेनदेन शामिल हैं।
- जुलाई 2017 के बाद के डेटा में केवल मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत किए गए व्यक्तिगत भुगतान और कॉरपोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉरपोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2 : इंटरनेट भुगतान - 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी. एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलए को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): शून्य/ नगण्य को दर्शाता है।

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से सारणी के फार्मेट को संशोधित किया है।

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में विशेष प्रतिभूतियाँ और सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड शामिल हैं।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है।

'अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।

सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक में एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

सारणी सं. 46

जीडीपी डेटा वर्ष 2011-12 के आधार पर आधारित है। वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2023-24 से ली गई है। डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन: चुकौती सहित) और राज्य सरकार की निवल चुकौती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डेटा केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।

3बी. 1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में किए गए निवल निवेश को दर्शाते हैं।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी. 1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी. 1.7: खजाना बिल, वित्तीय संस्थानों से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकदी शेष निवेश खाता सहित।

सारणी सं. 47

विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए प्राप्त की जाती है।

अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्पकालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए दिया जाता है।

ओवरड्राफ्ट राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिया जाता है।

औसत राशि प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ / डब्ल्यूएमए / ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, द्वारा प्राप्त होती है।

-: नगण्य।

सारणी सं. 48

समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों के खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी के लिए अवधारणाएं और कार्यप्रणाली आरबीआई मासिक बुलेटिन की वर्तमान सांख्यिकी के लिए व्यापक मार्गदर्शिका में उपलब्ध हैं **(https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618)**

'वर्तमान सांख्यिकी' का समय श्रृंखला डेटा https://data.rbi.org.in पर उपलब्ध है।
विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ आरबीआई द्वारा जारी प्रासंगिक प्रेस प्रकाशनियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों/विज्ञप्तियों जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका** में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2025	₹350 एक प्रति ₹250 एक प्रति (रियायती दर*) ₹4,000 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,000 (एक वर्ष रियायती दर*)	15 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति 150 अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्तः 2024-25 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (कांउटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2023-24	₹575 एक प्रति (कांउटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 45, सं. 1, 2024	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. पंचायती राज संस्थाओं का वित्त	₹300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
8. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24	आरबीआई बुलेटिन जनवरी, 2025 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
9. वार्षिक रिपोर्ट 2024-25	आरबीआई बुलेटिन जून, 2025 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
10. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट-जून 2025	आरबीआई बुलेटिन जुलाई, 2025 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
11. मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अप्रैल 2025	आरबीआई बुलेटिन अप्रैल 2025 में शामिल है।	
12. नगर निगम वित्त पर रिपोर्ट - नवंबर 2024	₹300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
13. बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी)	₹100 एक प्रति (कांउटर पर) ₹150 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (https://data.rbi.org.in) |
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-2008 (5 खंड), भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक / शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य अनुदेश

1. सभी संचार निम्न को संबोधित किए जाएँ:
   निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग,
   आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीआरकेडी, डीईपीआर),
   भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, तल मंजिल,
   सर पी. एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स सं. 1036. मुंबई- 400 001
   टेलीफोन: 022-2260 3000 विस्तार: 4002, ईमेल: spsdepr@rbi.org.in
2. बिक्री के लिए प्रकाशन प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) उपलब्ध हैं।
3. प्रकाशनों को कैश ऑन डिलीवरी के आधार पर नहीं दिया जाएगा।
4. एक बार बेचे गए प्रकाशनों को वापस नहीं लिया जाएगा।
5. प्रकाशन के पिछले अंक आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं।
6. जहां रियायती मूल्य का संकेत नहीं दिया गया है, भारत में छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक/ अकादमिक संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है, बशर्ते पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
7. सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए एनईएफटी को प्राथमिकता दी जाए और भुगतानकर्ता के नाम, सदस्यता संख्या (यदि कोई हो), खाता संख्या, तारीख और राशि सहित लेनदेन विवरण **spsdepr@rbi.org.in** पर ईमेल किया जाए या डाक द्वारा भेजा जाए।

   ए. एनईएफटी ट्रांसफर के लिए अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा और पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाता प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19

   बी. गैर- डिजिटल मोड के माध्यम से सदस्यता के मामले में, कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के नाम पर मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/ चेक भेजें।
8. 'प्रकाशन प्राप्त न होने' संबंधी शिकायतें दो माह की अवधि के अंदर भेजी जाएं।